ISSN - 0974-0118

जनवरी-जून 2025 वर्ष- 17, अंक - 01

मेकल मीमांसा

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय
अमरकंटक (म. प्र.)

ISSN - 0974-0118
अंतर- अनुशासनात्मक डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड
यूजीसी केयर सूचीबद्ध अर्धवार्षिक शोध पत्रिका
http://www.igntu.ac.in/mekalmimansa.aspx

मेकल मीमांसा

अंतर- अनुशासनात्मक डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड यूजीसी केयर सूचीबद्ध अर्धवार्षिक शोध पत्रिका

संरक्षक

प्रोफेसर ब्योमकेश त्रिपाठी
प्रभारी कुलपति
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश

प्रधान संपादक

प्रोफेसर भूमि नाथ त्रिपाठी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग

कार्यकारी संपादक

प्रोफेसर रक्षा सिंह, अर्थशास्त्र विभाग

संपादकीय मंडल सदस्य

डॉ. मोहनलाल चढार, एसोसिएट प्रोफेसर, एआईएचसी और पुरातत्वविभाग
डॉ. मनोहर बी. येरकलवार, एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानवशास्त्र विभाग
डॉ. सतीश मोदी, एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग
डॉ. देवेंद्र कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग
डॉ. प्रवीण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग
डॉ. शिखा बनर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग
डॉ. प्रणय सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, भैषजिक विज्ञान विभाग
डॉ. मालती लोधी, एसोसिएट प्रोफेसर, नर्सिंग विभाग

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय
अमरकंटक, (म. प्र.)

© इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश -484887

प्रकाशक :

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय

अमरकंटक, (म. प्र.)- 484887

http://www.igntu.ac.in/mekalmimansa.aspx

ध्यानार्थ :

मेकल मीमांसा में प्रकाशन संबंधी निर्णय संपादक मण्डल द्वारा सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। प्रकाशित लेखकों के विचार उनके अपने हैं, जिनसे संपादक मण्डल की सहमति होना अनिवार्य नहीं है। संपादक मण्डल को प्रकाशित होनी वाली सामग्री में संशोधन या परिवर्तन करने का अधिकार होगा। मेकल मीमांसा राष्ट्रभाषा हिंदी में गुणवत्तापरक एवं मौलिक शोधपत्रों के प्रकाशन के माध्यम से ज्ञान के प्रदीपन और विस्तार हेतु संकल्पित है। मेकल मीमांसा डबल ब्लाइन्ड पीयर रीव्यू पद्धति का अनुसरण करती है। पत्रिका लेखकीय गरिमा का सम्मान करती है।

संपादक की कलम से (From the Editor's Desk)

मानवीय सभ्यता-संस्कृति में नदियों, पहाड़ों–पर्वतों की भूमिका सबसे अहम रही है। वह जीवनदायनी है। भारतीय सभ्यता–संस्कृति में नर्मदा और मेकल पर्वत की वैश्विक पहचान है। जीवनमूल्यों के निर्माण, विकास और संवर्धन में नर्मदा की बहती धारा और मेकल की बायोडवर्सिटी का तंत्र भारत के जनजीवन को पल्लवित, पुष्पित और फलित करता है। मानवीय कलाओं ने मानवीय जीवन को उत्कृष्ट, गंभीर, सौंदर्यपरक एवं उत्सवपूर्ण बनाया है। उनके गहन चिंतन-मनन को अकादमिक और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय बनाने में पत्रिकाओं का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। 'मेकल मीमांसा' उन्हीं प्रयासों में से एक है। मेकल की पवित्र भूमि, अमरकंटक से नर्मदा की अविरल प्रवाह धारा आरंभ होती है। इस अविरल धारा की कल-कल से प्रस्फुटित ज्ञान की ध्वनि को सहेजने के लिए 'मेकल मीमांसा' का प्रकाशन प्रारंभ हुआ है। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक की यह शोध पत्रिका अकादमिक चेतना का प्रतिबिंब है, जो भारतीय स्वदेशी ज्ञान, संस्कृति, समाज और समकालीन विमर्शों को एक साझा मंच प्रदान करती है। 'मेकल मीमांसा' का उद्देश्य केवल ज्ञान का संकलन नहीं, बल्कि संवाद और चिंतन की एक सतत परंपरा को आगे बढ़ाना है।

मेकल मीमांसा सदैव से ही एक ऐसा मंच रहा है जहाँ शोधार्थी, अध्यापक, अकादमिक और चिंतक समाज, संस्कृति तथा स्वदेशी ज्ञान परंपराओं के विविध आयामों पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। आपके सम्मुख इसे प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है।

इस अंक में प्रकाशित आलेख न केवल अकादमिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि जनजातीय जीवन, पर्यावरणीय संतुलन, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक पुनरुत्थान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास, संचार, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, जैसे अन्य विषयों पर गहन विमर्श प्रस्तुत करते हैं। हमारी यह कोशिश रही है कि इस मंच का ऐसा विस्तार हो जहाँ चिंतन-मनन का स्वरूप स्थानीय से लेकर वैश्विक, विविधतापूर्ण और भिन्न-भिन्न दृष्टि एवं मौलिक चिंतन की अभिव्यक्ति हो। संपादक मण्डल के सदस्यों ने यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया है। विषय की विविधता, मौलिकता और उत्कृष्टता का सदैव ख्याल रखा गया है।

इस दिशा में सहयोग देने वाले सभी लेखकों, समीक्षकों, संपादकीय सदस्यों एवं पाठकों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिनके सहयोग से यह अंक प्रकाशित हो रहा है। इस यात्रा में विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति(प्रभारी) प्रो. ब्योमकेश त्रिपाठी का मार्गदर्शन, प्रेरणा और सतत सहयोग विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है। उनके शैक्षणिक दृष्टिकोण, प्रोत्साहन और शोधपरक चिंतन ने मेकल मीमांसा को निरंतर नई दिशा प्रदान किया है। आपके नेतृत्व में विश्वविद्यालय में अनुसंसाधन, नवाचार और स्वदेशी अध्ययन के क्षेत्र में जो वातावरण निर्मित हुआ है। वह सदा स्मरणीय है और उसका बिम्ब पत्रिका की प्रगति के मूल आधार में है।

आशा है कि यह अंक पाठकों के मन में नई दृष्टि और विचार की ज्योति प्रज्वलित करेगा।

— संपादक
प्रोफेसर भूमि नाथ त्रिपाठी

अंतर- अनुशासनात्मक डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड यूजीसी केयर सूचीबद्ध अर्धवार्षिक शोध पत्रिका

इस अंक में

क्रम संख्या	लेख का शीर्षक	लेखक	पृष्ठ संख्या
1	जनपदकौशाम्बी, उत्तरप्रदेश में फसल प्रतिरूप का स्थानिक एवं कालिक परिवर्तन	अरुणकुमार ,डॉ. चंद्रमौलि	1 – 10
2	सीकरजिले में जल जीवन मिशन की स्थिति का विश्लेषण	डॉ. दिलभाग	11 – 15
3	बुन्देलखण्डमें पर्यटन उद्योग के अवसर एवं चुनौतियाँ : महोबा जिले के विशेष संदर्भ में	डॉ.महेन्द्र सिंह	16 – 22
4	मध्यप्रदेशके अनुसूचित जनजातियों में कौशल विकास की चुनौतियाँ एवं संभावनाओं का अध्ययन	अक्षय,डॉ.विनोद सेन,संजीत कुमार	23 – 30
5	कोशीतटबंध के किनारे जल जमाव: जीवोपार्जन और आजीविका की संभावनाएं	आनंदविजेता, मुकुन्द कुमार	31 – 34
6	खेलपरिधान अनुसंधान में नवीनतम प्रवृत्तियाँ: एक ग्रंथसूची विश्लेषण	सूरज कुमार, डॉ. नेहा सिंह, अनुपम कुमार सिंह ,राहुल कुमार पासवान, शीतल टोपनो, प्रोफेसर. राजीव चौधरी	35 – 46
7	बॉलीवुडमें महिला केंद्रित फ़िल्मों में महिला पात्रों की स्थिति का विश्लेषण	रश्मिपाल, डॉ. सुनीता सिंह	47 – 51
8	उच्चतरमाध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता का योग साधना सेसंबन्ध का अध्ययन	डॉ.शिव शंकर यादव , डॉ. सुशील कुमार	52 – 56
9	डांगजिले की आदिवासी महिलाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण की समस्याएँ और समाधान	डॉ.पिन्कल चौधरी , जिज्ञासा चौधरी	57 – 66
10	डी-मार्टखुदरा स्टोर के उपभोक्ता क्रय व्यवहार पर एक अध्ययन	डॉ.धर्मेन्द्र सिंह , डॉ. हरजिन्दर पाल सिंह सलूजा , विकास कुमार देवांगन	67 – 76
11	पूर्वीराजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के विकासात्मक प्रभाव एवं चुनौतियों का अध्ययन	डॉ.गिरीश शास्त्री	77 – 83
12	धातुकार:पूर्वमध्यकालीन उत्तरी भारत के सामाजिकार्थिक संदर्भ	डॉ.नैरंजना श्रीवास्तव	84 – 88
13	उच्चऔर निम्न उपलब्धि वाले खिलाड़ियों के बीच आत्मविश्वास का तुलनात्मक अध्ययन	डॉ.आलोक कुमार सिंह,डॉ. महेंद्र प्रताप गौड़,डॉ. दिलीप कुमार चौधरी,डॉ. राकेशप्रसाद	89 – 92
14	जांजगीरका लघु-विष्णु मंदिर: एक अध्ययन (हसदेव नदी घाटी के विशेष संदर्भ में)	नीलिमामरकाम	93 – 98
15	महिलाओंद्वारा संचालित सामुदायिक मीडिया का वैयक्तिक अध्ययन (अप्पन समाचार और खबरलहरिया के विशेष संदर्भ में)	डॉ.शिवेंद्र कुमार मिश्रा , डॉ. भावना उपाध्याय	99 – 105

जनपद कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में फसल प्रतिरूप का स्थानिक एवं कालिक परिवर्तन

अरुण कुमार*
डॉ. चंद्रमौलि**

सारांश

फसल प्रतिरूप एक स्थानिक एवं कालिक गत्यात्मक अवधारणा है। फसल प्रतिरूप का अभिप्राय किसी निश्चित समय में विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र के अनुपात से है। फसल प्रतिरूप एक गतिशील अवधारणा है क्योंकि यह समय, स्थान और व्यक्ति की इच्छा के साथ बदलता रहता है। फसल प्रतिरूप में परिवर्तन का तात्पर्य विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र के अनुपात में बदलाव से है। अध्ययन के लिए कौशाम्बी जनपद को चुना गया है जिसका उद्देश्य कौशाम्बी जनपद में फसल प्रतिरूप का स्थानिक एवं कालिक विश्लेषण करना है। अध्ययन में 2000-01 से 2020-21 के बीच विकासखण्ड स्तर पर बदलते फसल प्रतिरूप का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन का मुख्य आधार मुख्यतः द्वितीयक एवं बदलते फसल प्रतिरूप के लिए वास्तविक स्थितियों और प्रेरक कारकों को समझने के लिए क्षेत्र भ्रमण और व्यक्तिगत निरीक्षण के आकड़ों पर आधारित है। आकड़ों के विश्लेषण के द्वारा 2000-01 से 2020-21 के बीच जनपद में कुल कृषित क्षेत्र में महत्वपूर्ण धनात्मक परिवर्तन प्रदर्शित होता हैं। पिछले बीस वर्षों में फसल प्रतिरूप बदल गया है- गेहूं, चावल एवं सब्जियों के साथ-साथ चारा एवं तिलहन फसलों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज किया गया है जबकि दलहन, मोटे अनाज, जौ एवं वाणिज्यिक फसलों के क्षेत्र में नकारात्मक परिवर्तन पाया गया। फसल प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारकों में, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, सिंचाई जैसी आधारभूत सुविधाओं में परिवर्तन के साथ-साथ अन्य आर्थिक एवं तकनीकी कारक प्रमुख हैं।

बीज शब्द:फसल प्रतिरूप,फसल प्रतिरूप में परिवर्तन, कुल कृषित क्षेत्र, आधारभूत कारक

प्रस्तावना

'कृषि' मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण प्राथमिक अर्थिक क्रिया कलाप है जिससे जीवन के लिए आधारभूत आवश्यकता के साथ आर्थिक पूरकता के लिए प्राचीन काल से मनुष्य विभिन्न फसलों का उत्पादन कर रहा है। भूगोलवेत्ताओं के लिए कृषि फसलों का अध्ययन मनुष्य के स्थानिक एवं कालिक विकास क्रम की दृष्टि से अत्यंत प्रचलित विषय रहा है। फसलों का प्रतिरूप मनुष्य की पोषकता एवं आर्थिक उन्नति की स्थिति का परिचायक होती है। फसल प्रतिरूप एक स्थानिक एवं कालिक परिवर्तन की अवधारणा है जो मुख्यतः फसलों के उत्पादन की प्राकृतिक अनुकूलता, मनुष्य की आवश्यकता एवं तकनीक के सामंजस्य पर आधारित होती है। फसल प्रतिरूप एक लम्बे समय से फसलों के स्थान एवं काल के अनुसार उत्पादन करने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। फसल प्रतिरूप वर्तमान आधुनिक वैज्ञानिक युग में मनुष्य की परिवर्तित आवश्यकता पर निर्भर होने लगा है। फसल प्रतिरूप का भौगोलिक अभिप्राय किसी निश्चित समय में विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र एवं समय के अनुपात से है। फसल प्रतिरूप एक गतिशील अवधारणा है क्योंकि यह स्थान, समय, आवश्यकता और आधुनिकता के साथ बदलता रहता है। फसल प्रतिरूप में परिवर्तन का तात्पर्य विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र के अनुपात में बदलाव से है (कुमार & इन्दिरा, 2014)।

क्षेत्र के समग्र कृषि-पर्यावरण और कृषि-स्थानिक विविधता को जानने के लिए फसल प्रतिरूप और परिवर्तन की पहचान आवश्यक हैं, जो योजनाकारों और नीति निर्माताओं को कृषि भूमि के संभावित उपयोग, फसलों की उपयुक्तता विश्लेषण और भविष्य की फसल प्रतिरूप योजना का आकलन करने में मदद करता है (ज्योथि व अन्य, 2020)।एक निश्चित समय में किसी क्षेत्र विशेष या क्षेत्र में विभिन्न फसलों की व्यवस्था को फसल प्रतिरूप के रूप में समझा जाता है। फसल प्रतिरूप पर्यावरणीय कारकों (जलवायु, मिट्टी, स्थलाकृति), आर्थिक कारकों (बाजार की मांग, आदानों की लागत, बुनियादी ढांचा), सामाजिक कारकों (श्रम उपलब्धता, सांस्कृतिक प्राथमिकताएं), तकनीकी कारकों (कृषि में प्रगति, विस्तार सेवाएं), नीति और संस्थागत कारकों (सरकारी नीतियां, भूमि स्वामित्व, ऋण सुविधाएं) और वैश्विक कारकों (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जलवायु परिवर्तन) से प्रभावित होते हैं।

*अरुण कुमार, शोध छात्र, भूगोल विभाग, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश।

**डॉ. चंद्रमौलि, सह आचार्य, भूगोल विभाग, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश।

ये तत्व उगाई जाने वाली फसलों के प्रकार, उनकी स्थानिक व्यवस्था और खेती के समय को निर्धारित करते हैं ताकि स्थिरता सुनिश्चित करते हुए उपज और लाभप्रदता को अनुकूलित किया जा सके। फसल प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारकों में साल-दर-साल उतार-चढ़ाव होता रहता है। उदाहरण के लिए, भारत में फसल प्रतिरूप काफी हद तक मानसून पर निर्भर करता है। अनुकूल मानसून के मौसम के दौरान, चावल की खेती पूरे देश में फलती-फूलती है, जबकि कमजोर मानसून के दौरान, बाजरा, मक्का, मूंगफली, उड़द, तिल आदि जैसी सूखी फसलें अधिक प्रचलित हो जाती हैं, जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है, मुख्य रूप से खेती की जाती है।

जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि का विभाजन नए फसल प्रतिरूप को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इसके अतिरिक्त, आधुनिक तकनीकी और उच्च उपज देने वाली किस्म (HYV) बीज फसल उत्पादन बढ़ाते हैं, जिससे फसल प्रतिरूप प्रभावित होता है **(खान & अहमद, 2019)**। जनपद कौशाम्बी में कृषि प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप है। 2011 की जनगणना के अनुसार, जनपद कौशाम्बी में कृषि में लगे लोगों की कुल संख्या लगभग 75 प्रतिशत है। जनपद का आर्थिक विकास कृषि की प्रगति जैसे फसल उत्पादन एवं उसके परिवर्तित प्रकारों पर निर्भर करता है। जनपद कौशाम्बी गंगा-यमुना दोआब की उपजाऊ भूमि पर स्थित है, जहां पिछले कुछ वर्षों में कृषि सुविधाओं में सुधार जैसे सिंचाई सुविधाओं में सुधार, पर्याप्त उर्वरक का उपयोग, उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग और सरकारी नीतियों के साथ कृषकों के आर्थिक लाभ प्राप्ति की जिज्ञासा के कारण काफी प्रगति हुई है। जनपद में फसल उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ फसल प्रतिरूप में भी काफी बदलाव आया है। वर्तमान फसल प्रतिरूप बाज़ारों की आवश्यकता जैसे कृषि प्रोद्योगिकी प्रसंस्करण पर आधारित होता जा रहा है।

साहित्य समीक्षा

साहित्य अवलोकन से ज्ञात हुआ की प्रस्तुत विषय पर अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों के द्वारा अध्ययन किया गया है जिनमें प्रमुख रूप से निम्नवत है जैसे **दीन एवं बाला (2021)** ने हरियाणा में प्रमुख खाद्य फसलों का स्थानिक-कालिक विश्लेषण किया, जिसमें फसल प्रतिरूप में बदलाव पर प्रकाश डाला गया। उनके अध्ययन में समय के साथ जिलों में गेहूं उत्पादन की पैदावार में महत्वपूर्ण बदलाव सामने आए। निष्कर्ष में कृषि प्रथाओं की गतिशील प्रकृति को रेखांकित करते हैं और संधृत फसल उत्पादन का समर्थन करने के लिए सूचित नीति हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हैं। **ज्योथि व अन्य (2020)** का अध्ययन उपग्रह आकड़ों का उपयोग करके कृष्णा डेल्टा क्षेत्र में फसल प्रतिरूप में परिवर्तन की व्याख्या करते है। फसल की खेती में अस्थायी बदलावों का विश्लेषण करने में सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के महत्व को रेखांकित करतें है। शोध में बेहतर उत्पादकता और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए अनुकूलित फसल प्रतिरूप पर आधारित संधृत कृषि पद्धतियों के महत्व पर जोर दिया गया है। **हाशेमी व अन्य (2019)**ने अध्ययन में पाया कि विभिन्न कृषि विकल्प किस तरह से सूखे क्षेत्रों में जल स्तर और किसानों की आय को प्रभावित करते हैं। उन्होंने बताया कि अंगूर जैसी कुछ फसलें किसानों को अधिक पैसा कमाने में मदद करती हैं, जबकि गेहूं जैसी अन्य फसलें अधिक वित्तीय लाभ दिए बिना अधिक पानी की हानि का कारण बनती हैं। **ओसामा व अन्य (2017)** ने मिस्र के पुराने क्षेत्रों से शुद्ध वार्षिक लाभ को अधिकतम करने के लिए एक रैखिक अनुकूलन मॉडल विकसित किया।

उनका अध्ययन लाभप्रदता बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा समस्याओं को दूर करने के लिए फसल प्रतिरूप में बदलाव का प्रस्ताव देकर सतत कृषि विकास में योगदान देता है। **मान (2017)** ने 1966-67 से 2014-15 तक पंजाब में फसल प्रतिरूप का अध्ययन कियाजिसमें चावल और गेहूं की खेती के प्रभुत्व पर प्रकाश डाला गया। अध्ययन में इन फसलों पर अत्यधिक निर्भरता से उत्पन्न सामाजिक-आर्थिक और पारिस्थितिक चुनौतियों पर जोर दिया गया है, भले ही प्रति हेक्टेयर उनका उत्पादन कम हो। उन्होंने किसानों की आजीविका में सुधार और भूजल की कमी को दूर करने के लिए उच्च मूल्य उत्पादन वाली फसलों के बदलाव का आह्वान किया। प्रस्तुत अध्ययन पंजाब के फसल प्रतिरूप में विविधता लाने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। **शिन्दे व अन्य (2015)** का अध्ययन कलवंडे लघु सिंचाई योजना में फसल प्रतिरूप का विश्लेषण करता है, जिसमें रबी धान की जगह सब्जियों, दालों और बागवानी फसलों के संयोजन की सिफारिश की गई है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य जल दक्षता को बढ़ाना और सतत कृषि के लिए शुद्ध लाभ को अधिकतम करना है। **घोष (2011)** ने 1970-71 से 2006-07 तक भारतीय कृषि में फसल प्रतिरूप में परिवर्तन का अध्ययन किया, उनका अध्ययन कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए फसल विविधीकरण के महत्व को रेखांकित करता है। **निशी भुवनदास व अन्य (2010)** ने रैखिक प्रोग्रामिंग मॉडल का उपयोग करके काकरापार के दाहिने किनारे के मुख्य नहर कमांड क्षेत्र में फसल प्रतिरूप को अनुकूलित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। फसल क्षेत्र और पानी की आवश्यकताओं जैसी बाधाओं पर विचार करते हुए कृषि उत्पादन से शुद्ध राजस्व को अधिकतम करके, अध्ययन स्थायी जल संसाधन प्रबंधन में योगदान देता है।

उद्देश्य

1. जनपद कौशाम्बी में फसल प्रतिरूप एवं स्थानिक एवं कालिक परिवर्तन का अध्ययन करना
2. जनपद कौशाम्बी के फसल प्रतिरूप में परिवर्तन के कारकों का विश्लेषण एवं प्रबंधन प्रस्तुत करना

विधि तंत्र

वर्तमान अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक आकड़े पर आधारित है जो जनपद कौशाम्बी की जनपद सांख्यिकीय पुस्तिका तथा अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार के आकड़ों से प्राप्त किया गया है। इसके अलावा मानचित्र सम्बन्धी आकड़े भारतीय सर्वेक्षण विभाग एवं जनसंख्या के लिए आकड़े भारतीय जनगणना विभाग से प्राप्त किए गये हैं। बदलते फसल प्रतिरूप के लिए वास्तविक स्थितियों और प्रेरक कारकों को समझने के लिए व्यक्तिगत निरीक्षण किया गया हैं। अध्ययन के लिए फसलों को 9 महत्वपूर्ण वर्गों में वर्गीकृत किया गया है - चावल, गेहूं, जौ, मोटे अनाज, दलहन, तिलहन, वाणिज्यिक फसलें, सब्जियां एवं चारा इत्यादि। गन्ना, तंबाकू, कपास और हल्दी को वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत रखा गया है। मोटे अनाज

में ज्वार, बाजरा, मक्का और सांवा शामिल हैं। अध्ययन में सम्मिलित मुख्य दलहन फसलें उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर और अरहर हैं। तिलहन में सरसों, अलसी, तिल, मूंगफली तथा सूरजमुखी शामिल हैं। इसके अलावा, आलू और प्याज सहित अन्य सब्जियां के अंतर्गत क्षेत्र को सम्मिलित रूप से सब्जियां के क्षेत्र में शामिल किया गया है। वर्ष 2000-01 और 2020-21 में कुल फसली क्षेत्र में विभिन्न फसलों के तहत प्रतिशत क्षेत्र की गणना की गई है, साथ ही 20 वर्षों में फसल प्रतिरूप में परिवर्तन का आकलन भी किया गया है। एम.एस.ऑफिस और आर्क जी.आई.एस.10.2 साफ्टवेयर का उपयोग आकड़ा विश्लेषण और मानचित्रों के सृजन में किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन के लिए जनपद कौशाम्बी को क्षेत्र के रूप में चुना गया है। जनपद कौशाम्बी उत्तर प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित है। जनपद कौशाम्बी का अक्षांशीय विस्तार 25°15' से 25°47' उत्तरी अक्षांश के बीच है और 81°12' से 81°47' पूर्वी देशांतर के बीच विस्तृत है। अध्ययन क्षेत्र निचली गंगा-यमुना दोआब में स्थित है, जिसकी उत्तरी सीमा पर गंगा नदी बहती है, जो इसकी प्राकृतिक सीमा बनाती है। वहीं दक्षिण में यमुना नदी इसकी प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है। राजनीतिक आधार पर, जिले को तीन तहसीलों में विभाजित किया गया है: मंझनपुर, सिराथू और चायल। तहसीलों को कुल आठ विकास खंडों में विभाजित किया गया है। मंझनपुर तहसील में सरसवां, मंझनपुर और कौशाम्बी; सिराथू तहसील में कड़ा और सिराथू एवं चायल तहसील में मूरतगंज, नेवादा और चायल विकास खण्ड शामिल हैं। जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1,779 वर्ग किमी. एवं कुल जनसंख्या 15,99,596 (2011) है। जनपद कौशाम्बी का जनसंख्या घनत्व 899 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. है, तथा दशकीय वृद्धि दर 23.7% है।

मानचित्र 1: अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति

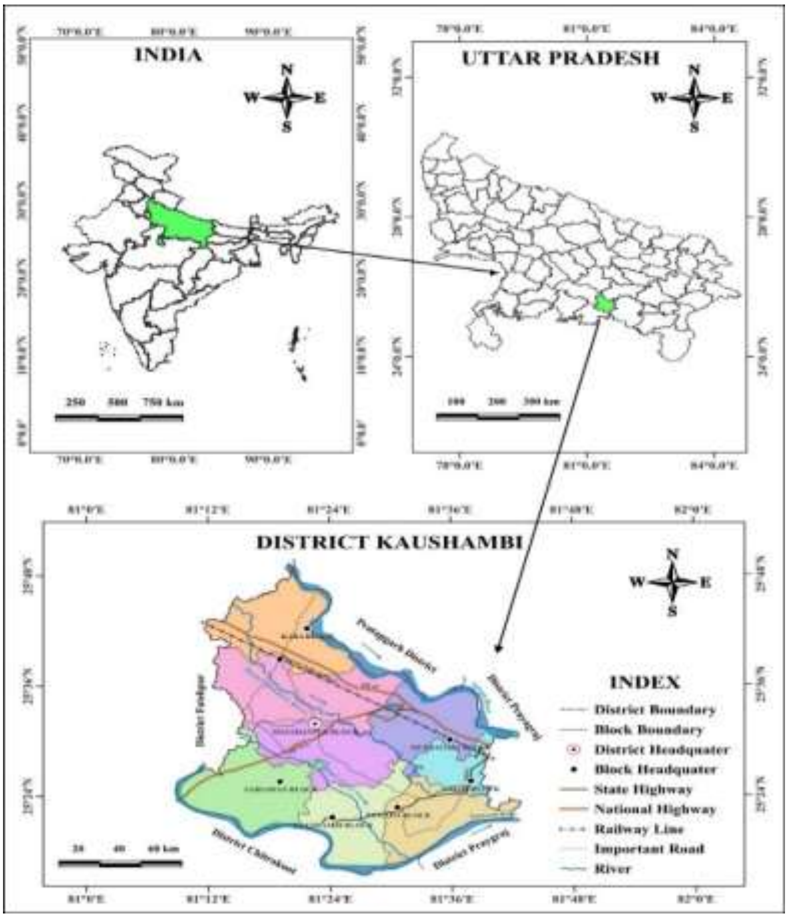

Source:Survey of India&CensusofIndia

परिणाम एवं विश्लेषण

फसल प्रतिरूप

अध्ययन क्षेत्र में निम्नलिखित फसल प्रतिरूप मुख्य रूप से प्रचलित है जो कृषकों के द्वारा अपनाये गये है-

1. **गेहूं (Wheat):**गेहूंजनपद की मुख्य खाद्यान्न फसल है जो रबी की फसल के अंतर्गत बोयाजाता है। जनपद में विभिन्न फसलों के अंतर्गत को तालिका-1 एवं चित्र-1 में दर्शाया गया है। वर्ष 2000-01 में जनपद कौशाम्बी में कुल कृषित क्षेत्र 1,60,314 हेक्टेयर था, जिसमें सर्वाधिक क्षेत्र पर गेहूं (36.51%) बोया गया था। वर्ष 2000-01 में विभिन्न फसलों के अंतर्गत विकासखण्डवार क्षेत्र को तालिका-2 एवं मानचित्र-2 में दर्शाया गया है। वर्ष 2000-01 में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कड़ा (43.41%) एवं सिराथू (41.93%) में वहीं सबसे कम सरसवां (27.69%) एवं चायल (28.9%) विकासखंड में देखने को मिलता है।वर्ष 2020-21 में जनपद कौशाम्बी में कुल कृषित क्षेत्र 1,87,861 हेक्टेयर था जिसमें सर्वाधिक क्षेत्र पर गेहूं (41.58%) बोया गया था। वर्ष 2020-21 में विभिन्न फसलों के अंतर्गत विकासखण्डवार क्षेत्र को तालिका-3 एवं मानचित्र-2 में दर्शाया गया है। वर्ष 2020-21 मेंविकासखण्ड स्तर पर सर्वाधिक मूरतगंज (50.38%) एवं नेवादा (48.75%) में जबकि सबसे कम सरसवां (37.27%) एवं चायल (37.23%) विकासखंड में देखने को मिलता है।
2. **चावल (Rice):** चावल जनपद की दूसरी मुख्य खाद्यान्न फसल है जो यहाँ केवल खरीफ की फसल के अंतर्गत बोया जाता है। वर्ष 2000-01 में जनपद कौशाम्बी में कुल कृषित क्षेत्र का 19.11% चावल के अंतर्गत बोया गया था। वहीं विकासखण्ड स्तर पर सबसे ज्यादा मंझनपुर (28.7%) एवं कौशाम्बी (24.8%) में जबकि सबसे कम कड़ा (11.6%) एवं नेवादा (11.7%) में देखने को मिलता है। वर्ष 2020-21 में कुल कृषित क्षेत्र का 27.8% चावल के अंतर्गत बोया गया था, वहीं विकासखण्ड स्तर पर सबसे ज्यादा मंझनपुर (34.54%) एवं सरसवां (28.88%) में जबकि सबसे कम मूरतगंज (22.17%) एवं नेवादा (22.7%) में देखने को मिलता है।
3. **दलहन (Pulses):** वह फसल जिससे दाल तैयार की जाती है दलहन फसल कही जाती है। दलहन फसलें प्रोटीन का सस्ता एवं सुलभ स्रोत हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के गुण के कारण दलहनी फसलें भूमि के लिए संजीवनी हैं जो भूमि की प्राकृतिक उर्वरता अक्षुण्य रखती हैं। जनपद में गेहूं, चावल के बाद क्रमशः दलहन फसलें प्रमुख हैं।जनपद की मुख्य दलहन फसल अरहर है जो खरीफ के फसल के अंतर्गत बोया जाता है। उड़द, मूंग, मसूर, चना एवं मटर अन्य दलहनी फसलें हैं। जनपद में उड़द एवं मूंग की खेती खरीफ एवं जायद दोनों फसलों के अंतर्गत की जाती है, जबकि मसूर, चना एवं मटर को रबी की फसलों के अंतर्गत बोया जाता है। वर्ष 2000-01 में जनपद कौशाम्बी में कुल कृषित क्षेत्र का 17.74% दलहन फसलों के अंतर्गत बोया गया था वहीं विकासखण्ड स्तर पर सबसे ज्यादा नेवादा (20.13%) एवं सरसवां (19.96%) में जबकि सबसे कम मंझनपुर (13.41%) एवं कड़ा (15.24%) में देखने को मिलता है। वर्ष 2020-21 में कुल कृषित क्षेत्र का 11.82% दलहन फसलों के अंतर्गत बोया गया था वहीं विकासखण्ड स्तर पर सबसे ज्यादा सरसवां (14.99%) एवं कौशाम्बी (14.58%) में जबकि सबसे कम मूरतगंज (7.75%) एवं मंझनपुर (8.41%) में देखने को मिलता है।
4. **मोटे अनाज (Millets):** छोटे-छोटे दानों के रूप में मिलने वाले अनाज को मोटे अनाज या मिलेट्स (millets) कहा जाता है।मिलेट को 'चमत्कारिक अनाज' (miracle grain) या 'भविष्य की फसल' (crops of the future) भी कहा जाता हैं क्योंकि इनमें अनुकूलन की अद्भुत क्षमता होती हैं। इन्हें उन जगहों पर भी उगाया जा सकता है जहाँ बारिश कम होती है या मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा के कारण यह श्री अन्न भी कहलाता है। इसके अंतर्गत ज्वार, बाजरा, मक्का एवं सांवां को सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2000-01में जनपद कौशाम्बी में कुल कृषित क्षेत्र का 16.61% मोटे अनाज के अंतर्गत बोया गया था वहीं विकासखण्ड स्तर पर सबसे ज्यादा चायल (19.83%) एवं सिराथू (18.95%) जबकि सबसे कम मंझनपुर (12.22%) एवं कौशाम्बी (15.33%) में देखने को मिलता है। वर्ष 2020-21 में कुल कृषित क्षेत्र का 7.4% मोटे अनाज के अंतर्गत बोया गया था वहीं विकासखण्ड स्तर पर सबसे ज्यादा मंझनपुर (8.55%) एवं कड़ा (8.46%) में जबकि सबसे कम नेवादा (4.57%) एवं सिराथू (6.29%) में देखने को मिलता है।

तालिका 1: जनपद कौशाम्बी में विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र

क्र. स.	फसलें	2000-01		2020-21		परिवर्तन (%)
		क्षेत्र (हे.)	%	क्षेत्र (हे.)	%	
1	गेहूं	58,531	36.51	78,113	41.58	5.07
2	चावल	30,636	19.11	52,225	27.80	8.69
3	दलहन	28,440	17.74	22,205	11.82	-5.92
4	मोटे अनाज	26,628	16.61	13,902	7.40	-9.21
5	जौ	5,707	3.56	1,259	0.67	-2.89
6	सब्जियां	3,543	2.21	13,507	7.19	4.99
7	वाणिज्यिक फसलें	2,805	1.75	695	0.37	-1.38
8	चारा	2,020	1.26	2,536	1.35	0.09
9	तिलहन	2,004	1.25	3,419	1.82	0.57
कुल कृषित क्षेत्र		**1,60,314**	**100**	**1,87,861**	**100**	**27,547**

Source: Calculated from the Statistical Handbook of Kaushambi District (2002 & 2022)

चित्र 1 : विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र

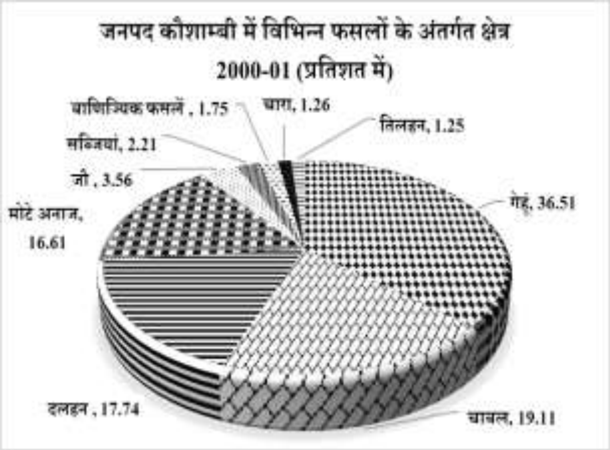

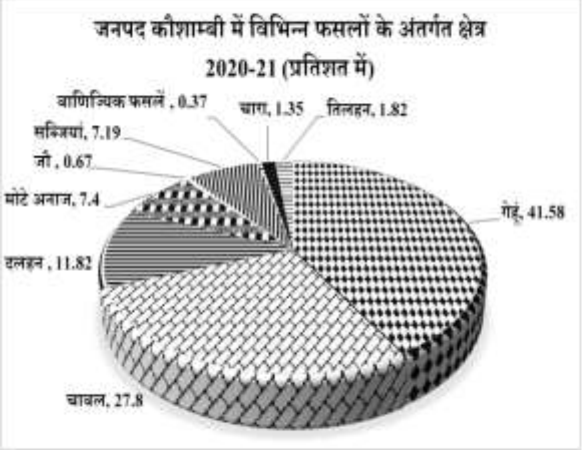

Source: Calculated from the Statistical Handbook of Kaushambi District (2002 & 2022)

5. **जौ (Barley):** भारत मेंजौ की खेती समशीतोष्ण क्षेत्रों में गर्मियों की फसल के रूप में और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्दियों की फसल के रूप में की जाती है। जनपद कौशाम्बी में जौ रबी की फसल के अंतर्गत बोया जाता है जो वर्ष 2000-01 में जनपद कौशाम्बी में कुल कृषित क्षेत्र का 3.56% है । वहीं विकासखण्ड स्तर पर सबसे ज्यादा नेवादा (5.47%) एवं मूरतगंज (5.32%) जबकि सबसे कम सिराथू (1.93%) एवं मंझनपुर (2.67%) विकासखण्ड में देखने को मिलता है। वर्ष 2020-21 में कुल कृषित क्षेत्र का 0.67% जौ के अंतर्गत बोया गया था वहीं विकासखण्ड स्तर पर सबसे ज्यादा सरसवां (1.38%) एवं कौशाम्बी (1.8%) में जबकि सबसे कम चायल (0.25%) एवं मूरतगंज (0.31%) में देखने को मिलता है।

6. **सब्जियाँ (Vegetables):** जनपद कौशाम्बी में सब्जियां रबी, खरीफ, जायद तीनों फसल के अंतर्गत लगाया जाता है। मुख्यतः आलू एवं प्याज सहित विभिन्न प्रकार की सब्जियां जनपद में उगाई जाती हैं। वर्ष 2000-01में जनपद कौशाम्बी में कुल कृषित क्षेत्र का 2.21% सब्जियों के अंतर्गत बोया गया था वहीं विकासखण्ड स्तर पर सबसे ज्यादा कड़ा (5.15%) एवं सिराथू (3.17%) में जबकि सबसे कम चायल (1.05%) एवं मूरतगंज (1.13%) में देखने को मिलता है। वर्ष 2020-21में कुल कृषित क्षेत्र का 7.19% सब्जियों के अंतर्गत बोया गया था वहीं विकासखण्ड स्तर पर सबसे ज्यादा कड़ा (10.7%) एवं चायल (10.09%) में जबकि सबसे कम कौशाम्बी (4.9%) एवं सिराथू (5.85%) में देखने को मिलता है।

तालिका 2: 2000-01 में विकासखण्ड-वार विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र (प्रतिशत में)

विकासखण्ड	कुल कृषित क्षेत्र (In Hectares)	गेहूं	चावल	दलहन	मोटेअनाज	जौ	सब्जियां	वाणिज्यिक फसलें	चारा	तिलहन
कड़ा	19,005	43.41	11.6	15.24	16.89	3.05	5.15	0.22	1.02	3.43
सिराथू	27,280	41.93	12.9	16.87	18.95	1.93	3.17	1.5	1.1	1.64
सरसवां	26,468	27.69	24.66	19.96	15.67	3.05	1.57	5.5	1.13	0.78
मंझनपुर	19,219	37.41	28.7	13.41	12.22	2.67	1.99	1.31	0.92	1.37
कौशाम्बी	22,907	32.29	24.8	18.63	15.33	3.68	1.3	1.68	1.46	0.84
मूरतगंज	15,105	40.81	15.48	19.09	16.29	5.32	1.13	0.2	1.17	0.52
चायल	11,619	28.9	22.76	18.56	19.83	5.3	1.05	0.53	2.26	0.81
नेवादा	18,711	39.61	11.78	20.13	18.62	5.47	1.64	0.9	1.48	0.37
कुल	**1,60,314**	**36.51**	**19.11**	**17.74**	**16.61**	**3.56**	**2.21**	**1.75**	**1.26**	**1.25**

Source: Calculated from the Statistical Handbook of Kaushambi District (2002)

तालिका 3: 2020-21 में विकासखण्ड-वार विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र (प्रतिशत में)

विकासखण्ड	कुल कृषित क्षेत्र (In Hectares)	गेहूं	चावल	दलहन	मोटेअनाज	जौ	सब्जियां	वाणिज्यिक फसलें	चारा	तिलहन
कड़ा	21,898	39.65	25.91	11.12	8.46	0.64	10.7	0.1	0.79	2.64
सिराथू	31,457	42.54	28.68	13.44	6.29	0.46	5.85	0.28	0.68	1.78
सरसवां	32,638	37.23	28.88	14.99	7.61	1.38	6.28	0.43	0.76	2.45
मंझनपुर	27,020	38.83	34.54	8.41	8.55	0.44	6.85	0.21	0.75	1.43
कौशाम्बी	23,837	38.82	28.5	14.58	8.26	1.08	4.9	0.46	1.3	2.11
मूरतगंज	20,722	50.38	22.17	7.75	7.8	0.31	8.07	0.15	2.14	1.23
चायल	9,704	37.92	27.98	11.16	7.73	0.25	10.09	0.56	3.16	1.15
नेवादा	20,585	48.75	22.7	10.74	4.57	0.34	7.84	0.94	3.08	1.05
कुल	**1,87,861**	**41.58**	**27.8**	**11.82**	**7.4**	**0.67**	**7.19**	**0.37**	**1.35**	**1.82**

Source: Calculated from the Statistical Handbook of Kaushambi District (2022)

7. वाणिज्यिक फसलें (Commercial Crops): जनपद में गन्ना प्रमुख वाणिज्यिक फसल है।वर्ष 2000-01 में जनपद कौशाम्बी में कुल कृषित क्षेत्र का 1.75% वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत बोया गया था वहीं विकासखण्ड स्तर पर सबसे ज्यादा सरसवां (5.5%) एवं कौशाम्बी (1.68%) में जबकि सबसे कम मूरतगंज (0.2%) एवं कड़ा (0.22%) में देखने को मिलता है। वर्ष 2020-21 में कुल कृषित क्षेत्र का 0.37% वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत बोया गया था वहीं विकासखण्ड स्तर पर सबसे ज्यादा नेवादा (0.94%) एवं चायल (0.56%) में जबकि सबसे कम कड़ा (0.1%) एवं मूरतगंज (0.15%) में देखने को मिलता है।

मानचित्र 2: फसल प्रतिरूप,वर्ष 2000-01 एवं 2020-21

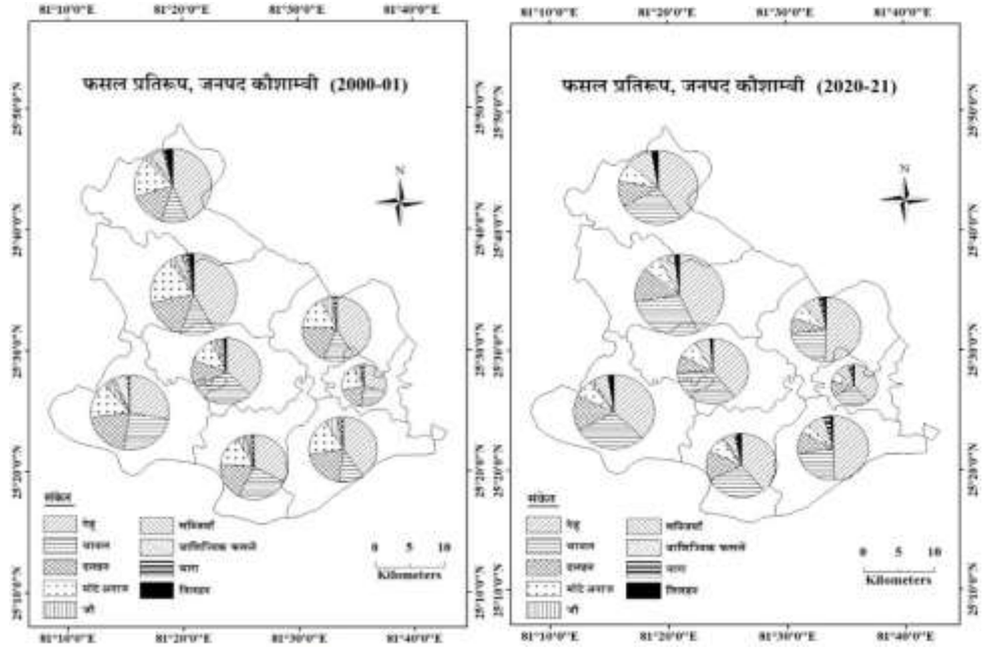

Source: Statistical Handbook of Kaushambi District (2002 & 2022)

8. चारा (Fodder): जनपद में चारे की फसल रबी, खरीफ एवं जायद तीनों फसलों के अंतर्गत बोया जाता है। वर्ष 2000-01 में जनपद कौशाम्बी में कुल कृषित क्षेत्र का 1.26% चारा फसलों के अंतर्गत बोया गया था वहीं विकासखण्ड स्तर पर सबसे ज्यादा चायल (2.26%) एवं नेवादा (1.48%) जबकि सबसे कम मंझनपुर (0.92%) एवं कड़ा (1.02%) में देखने को मिलता है। वर्ष 2020-21 में कुल कृषित क्षेत्र का 1.35% चारा फसलों के अंतर्गत बोया गया था वहीं विकासखण्ड स्तर पर सबसे ज्यादा चायल (3.16%) एवं नेवादा (3.08%) में जबकि सबसे कम सिराथू (0.68%) एवं सरसवां (0.76%) में देखने को मिलता है।

9. **तिलहन (Oilseed):** जनपद में सरसों मुख्य तिलहन फसल है जिसका उत्पादन रबी की फसल के अंतर्गत किया जाता हैं। अन्य तिलहन फसलों में अलसी की फसल रबी के अंतर्गत, तिल एवं मूंगफली खरीफ के अंतर्गत जबकि सूरजमुखी जायद फसलों के अंतर्गत बोया जाता है। वर्ष 2000-01 में जनपद कौशाम्बी में कुल कृषित क्षेत्र का 1.25% तिलहन फसलों के अंतर्गत बोया गया था वहीं विकासखण्ड स्तर पर सबसे ज्यादा कड़ा (3.41%) एवं सिराथू (1.64%) जबकि सबसे कम नेवादा (0.37%) एवं मूरतगंज (0.52%) में देखने को मिलता है। वर्ष 2020-21 में कुल कृषित क्षेत्र का 1.82% तिलहन फसलों के अंतर्गत बोया गया था वहीं विकासखण्ड स्तर पर सबसे ज्यादा कड़ा (2.64%) एवं सरसवां (2.45%) में जबकि सबसे कम नेवादा (1.05%) एवं चायल (1.15%) में देखने को मिलता है।

फसल प्रतिरूप में परिवर्तन

पिछले बीस वर्षों में फसल प्रतिरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है, गेहूं, चावल एवं सब्जियों के साथ-साथ चारा एवं तिलहन की फसलों में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज किया गया है जबकि दलहन, मोटे अनाज, जौ एवं वाणिज्यिक फसलों के क्षेत्र में कमी दर्ज किया गया है।जनपद कौशाम्बी में वर्ष 2000-01 से 2020-21 के दौरान कुल कृषित क्षेत्र में 1,60,314 हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज की गयी है।जनपद कौशाम्बी में विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र में परिवर्तन सम्बन्धी आकडों को तालिका-4 एवं मानचित्र-3 में दर्शाया गया है।

जनपद कौशाम्बी में वर्ष 2000-01 से 2020-21के दौरान गेंहू के क्षेत्र में 5.07% की वृद्धि दर्ज की गयी। विकासखण्ड स्तर पर सर्वाधिक मूरतगंज (9.57%) एवं सरसवां (9.54%) में जबकि सबसे कम सिराथू (0.61%) एवं मंझनपुर (1.42%) में वृद्धि दर्ज की गयी, कड़ा विकासखंड में गेहूं के क्षेत्र में 3.76% कमी दर्ज की गयी। वहीं चावल के क्षेत्र में 8.69% की वृद्धि दर्ज की गयी है। विकासखण्ड स्तर पर देखा जाये तो सभी विकासखण्ड में चावल के क्षेत्र में वृद्धि दर्ज किया गया है जिसमें सबसे ज्यादा सिराथू (15.74%) एवं कड़ा (14.31%) जबकि सबसे कम कौशाम्बी (3.71%) एवं सरसवां (4.22%) में दर्ज किया गया है।

तालिका 4: 2000-01से 2020-21के बीच विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र में परिवर्तन (प्रतिशत में)

विकासखण्ड	कुल कृषित क्षेत्र (In Hectares)	गेहूं	चावल	दलहन	मोटेअनाज	जौ	सब्जियां	वाणिज्यिक फसलें	चारा	तिलहन
कड़ा	2,893	-3.76	14.31	-4.12	-8.43	-2.41	5.55	-0.12	-0.24	-0.79
सिराथू	4,177	0.61	15.78	-3.44	-12.66	-1.47	2.67	-1.23	-0.41	0.14
सरसवां	6,170	9.54	4.22	-4.98	-8.06	-1.67	4.71	-5.07	-0.37	1.67
मंझनपुर	7,801	1.42	5.84	-5	-3.68	-2.23	4.86	-1.1	-0.17	0.05
कौशाम्बी	9,30	6.53	3.7	-4.05	-7.06	-2.6	3.6	-1.22	-0.17	1.28
मूरतगंज	5,617	9.57	6.7	-11.34	-8.49	-5.01	6.94	-0.04	0.97	0.71
चायल	-1,915	9.02	5.22	-7.4	-12.1	-5.05	9.04	0.02	0.9	0.35
नेवादा	1,874	9.15	10.92	-9.4	-14.05	-5.13	6.21	0.04	1.59	0.68
कुल	**27,547**	**5.07**	**8.69**	**-5.92**	**-9.21**	**-2.89**	**4.99**	**-1.38**	**0.09**	**0.57**

Source: Calculated from the Statistical Handbook of Kaushambi District (2002&2022)

जनपद कौशाम्बी में वर्ष 2000-01 से 2020-21के दौरान दलहन के क्षेत्र में 5.92% की कमी दर्ज किया गया है।विकासखण्ड स्तर पर देखा जाये तो सभी विकासखण्ड में दलहन के क्षेत्र में कमी दर्ज किया गया है जिसमें सबसे ज्यादा मूरतगंज (11.34%) एवं नेवादा (9.4%) जबकि सबसे कम सिराथू (3.44%) एवं कौशाम्बी (4.05%) में दर्ज किया गया है। इसी प्रकार मोटे अनाज के क्षेत्र में भी 9.21% की कमी दर्ज किया गया है। विकासखण्ड स्तर पर देखा जाये तो सभी विकासखण्ड में मोटे अनाज के क्षेत्र में कमी दर्ज किया गया है जिसमें सबसे ज्यादा नेवादा (14.05%) एवं सिराथू (12.66%) जबकि सबसे कम मंझनपुर (3.68%) एवं कौशाम्बी (7.06%) में दर्ज किया गया है। मोटे अनाज यहाँ की परम्परागत फसलों के रूप में उगाया जाता रहा है, हरित क्रांति आने के बाद से इनका स्थान गेहूं एवं चावल ने ले लिया।

जनपद कौशाम्बी में वर्ष 2000-01 से 2020-21के दौरान जौ के क्षेत्र में -2.89% की कमी दर्ज किया गया है। विकासखण्ड स्तर पर देखा जाये तो सभी विकासखण्ड में जौ के क्षेत्र में कमी दर्ज किया गया है जिसमें सबसे ज्यादा चायल (5.05%) एवं मूरतगंज (5.01%) जबकि सबसे कम सरसवां (1.67%) एवं सिराथू (1.47%) में दर्ज किया गया है। गेहूं की अधिक उत्पादन और लाभदायकता के कारण किसानों ने जौ की खेती से गेहूं की खेती की ओर स्थानांतरित कियाहै। वर्ष 2000-01 से 2020-21 के दौरान सब्जियों के क्षेत्र में 4.99% की वृद्धि दर्ज की गयी है। विकासखण्ड स्तर पर देखा जाये तो सभी विकासखण्ड में सब्जियों के क्षेत्र में वृद्धि दर्ज किया गया है जिसमें सबसे ज्यादा चायल (9.04%) एवं मूरतगंज (6.94%) जबकि सबसे कम सिराथू (2.67%) एवं कौशाम्बी (3.6%) में दर्ज किया गया है।

मानचित्र 3: फसल प्रतिरूपमें परिवर्तन 2000-01 से 2020-21

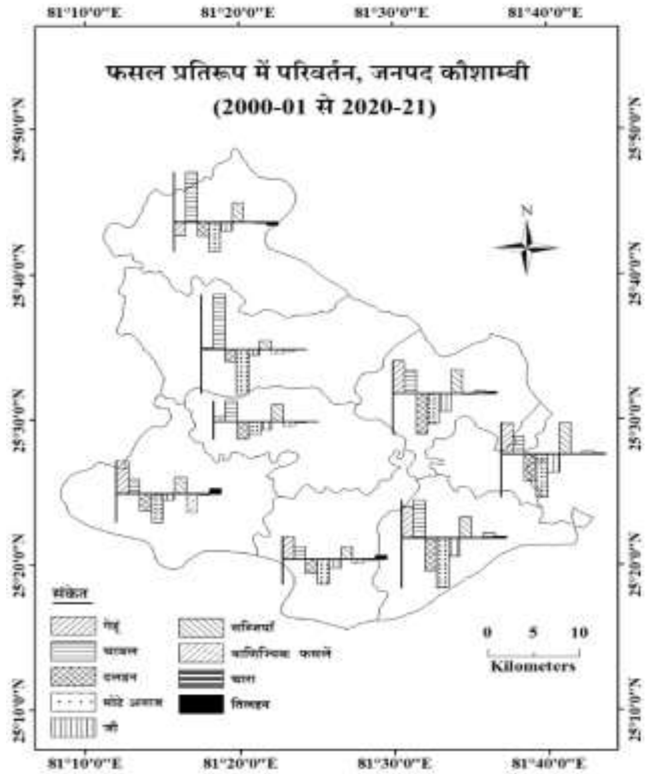

Source: Calculated from the Statistical Handbook of Kaushambi District (2002 & 2022)

वर्ष 2000-01 से 2020-21के दौरान वाणिज्यिक फसलों के क्षेत्र में 1.38% की कमी दर्ज किया गया है। विकासखण्ड स्तर पर वाणिज्यिक फसलों के क्षेत्र में चायल (0.02%) एवं नेवादा (0.04%) में थोड़ा वृद्धि के साथ साथ अन्य सभी विकासखण्ड में कमी दर्ज किया गया है जिसमें सबसे ज्यादा कमी सरसवां (5.07%) एवं सिराथू (1.23%) में दर्ज किया गया है। जनपद में चीनी मिलों के बंद हो जाने, गन्ने के उचित मूल्य न मिलने के कारण किसान गन्ने की खेती से दिन प्रतिदिन दूर हो रहें हैं।

इसी प्रकार जनपद में चारा फसलों के क्षेत्र में 0.09%की कमी दर्ज किया गया है। चारा फसलों के क्षेत्र में नेवादा (1.59%), मूरतगंज (0.97%) एवं चायल (0.9%) में वृद्धि दर्ज किया गया है जबकि अन्य सभी विकासखण्ड में चारा फसलों के क्षेत्र में कमी दर्ज किया गया है, सर्वाधिक कमी सिराथू (0.41%) एवं सरसवां (0.37%) में दर्ज किया गया है। जबकि तिलहन के क्षेत्र में 0.57% की वृद्धि दर्ज की गयी। विकासखण्ड स्तर पर सर्वाधिक सरसवां (1.67%) एवं कौशाम्बी (1.28%) में जबकि सबसे कम मंझनपुर (0.05%) एवं सिराथू (0.14%) में वृद्धि दर्ज की गयी, कड़ा विकासखंड में तिलहन के क्षेत्र में 0.79% कमी दर्ज की गयी। जनपद में तिलहन फसलों, जैसे सरसों, तिल, मूंगफली और सूरजमुखी के उच्च बाजार मूल्य और बढ़ती मांग के कारण किसान इन फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

निष्कर्ष

कृषक मुख्य रूप से फसलों का उत्पादन अपने प्रतिदिन खाद्यान्न की आवश्यकता के साथ आर्थिक लाभ के लिए करता है, इसके उत्पादन में अन्य महत्वपूर्ण कारक जो प्रभावी रूप से प्रभावित करते है उनमें मुख्य रूप से स्थानीय भौगोलिक स्थितियां, बाज़ार एवं वाणिज्यिक सुविधाओं की स्थिति, परिवहन की सुगमता, भण्डारण की सुविधा, विपणन की आधुनिक सुविधा, स्थानीय कृषि औद्योगिक प्रसंस्करण इकाई की सुविधा, तकनीकी की सस्ती सुलभता, उन्नत कृषि बीजों की उपलब्धता, सहकारी समितियों का सहयोग, सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यन्वयन की स्थिति, सामाजिक आवश्यकता, धर्म, संस्कृति एवं प्रचलन के द्वारा निर्धारित होता है। कृषक मुख्यतः धान और गेहूं जैसी उच्च उपज और उच्च समर्थन मूल्य वाली फसलों को प्राथमिकता देते हैं। यह दालों और मोटे अनाज की तुलना में अधिक आर्थिक लाभ प्रदान करने के साथ उत्पादन प्रक्रिया में कम जोखिम के साथ उत्पन्न हो जाता है। जोखिम के अंतर्गत जलवायु, घुमक्कड़ी पशु, कीटों का प्रकोप तथा रोग इत्यादि मुख्य है।

कृषक दालों एवं मोटे अनाज में रूचि होने के बाद भी उत्पादन इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि दालों और मोटे अनाज की कीमतों में अनिश्चित उतार-चढ़ाव के साथ मुख्यतः स्थानीय मौसम, रोग एवं घुमक्कड़ी पशु मुख्य रूप से उत्पादन क्षेत्र को प्रभावित करते है, जिससे किसानों को आर्थिक जोखिम का सामना करना पड़ता है। जनपद में उन्नतिशील बीजों की कम उपलब्धता या जागरूपता की कमी एवं उनके भोजन उपयोग में

कमी की प्रवृत्ति के कारण दलहन एवं मोटे अनाज के उत्पादकता में कमी पायी जाती है जिससे इन फसलों के प्रति किसानों का आकर्षण कम हुआ है।उपभोग की आदतों में बदलाव और शहरीकरण के कारण मोटे अनाज की मांग में निरंतर कमी हो रही है।

वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत जनपद में गन्ना, हल्दी, कपास और तम्बाकू का उत्पादन किया जाता है जिसमें गन्ना मुख्य वाणिज्यिक फसल है। जनपद में चीनी मिलों के बंद हो जाने एवं दूर स्थित मीलों तक गन्ना पहुंचाने में परिवहन व्यय में वृद्धि के साथ-साथ वजन में कमी होने से गन्ने के उचित मूल्य न मिलने के कारण किसान गन्ने की खेती से दूर हो रहें हैं।तिलहन फसलों, जैसे सरसों, तिल, मूंगफलीऔर सूरजमुखीके उच्च बाजार मूल्य और बढ़ती मांग के कारण किसान इन फसलों की ओर आकर्षित हो रहे है और आधुनिक बीजों के उपयोग का प्रतिफल उत्पादन पर जनपद में सकारात्मक रूप में परिलक्षित हुआ है।

अध्ययन क्षेत्र में संतुलित फसल प्रतिरूप एवं फसल विविधीकरण की आवश्यकता है एक ओर खाद्यान्न फसल मुख्यतः गेहूं एवं चावल में वृद्धि जनसंख्या के भरण पोषण के लिए अच्छा है। वही दलहन फसल एवं मोटे अनाजों के कमी से खाद्य संतुलन एवं पोषण की उपलब्धता के लिए समस्या है। दलहन और तिलहन मानव स्वास्थ्य के लिए विशिष्ट प्रकार के पोषण प्रदान करने के साथ-साथ मृदा की पोषकता को संतुलित करके प्राकृतिक उत्पादकता को बनाये रखने में महत्वपूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। मोटे अनाज उगाने से अनाज के साथ-साथ पशुओं के लिए चारा भी मिलता है इसी प्रकार दलहन फसलों के उगाने से दाल के साथ-साथ भूमि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी मदद मिलती है जिससे भूमि कि उर्वरता बनी रहती है अतः इन फसलों को उगाये जाने की आवश्यकता है। जनपद में वाणिज्यिक फसलों के प्रोत्साहन की आवश्यकता है जिससे किसानों को अधिक आय प्राप्त होगी और आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी। चारा फसलों के अंतर्गत और सुधार की आवश्यकता है जिससे पशुपालन, पशु स्वास्थ्य एवं पोषण ठीक रहे। इसप्रकार संतुलित फसल प्रतिरूप एवं फसल विविधीकरण को अपनाकर खाद्य संतुलन एवं पोषकता में सुधार किया जा सकता हैक्यूंकि फसल प्रतिरूप क्षेत्र विशेष के स्थानिक एवं कालिक पोषकता की उपलब्धता एवं समाज के उपभोग की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।

जनपद में फसल प्रतिरूप में संतुलन एवं प्रबंधन की आवश्यकता जिसके लिए महत्वपूर्ण रूप से सिंचाई की निश्चितता, उन्नत बीज की स्थानीय जलवायु के अनुसार उपलब्धता, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की सुविधाओं का विस्तार, उचित भण्डारण की सुविधा, तकनीकी सुविधाओं की उपलब्धता पर ध्यान, कृषि उद्योगों का विकास, कृषि ऋण का सरलीकरण, पशुपालन को प्रोत्साहन, सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों का उचित कार्यान्वयन, कृषि वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों के द्वारा शिक्षण-प्रशिक्षण, कृषकों को व्यापारिक फसलों के प्रति जागरूक करना, जैविक कीटनाशकों की सुलभता, रासायनिक एवं जैविक उर्वरक की उपलब्धता, कृषि फसलों का बीमाकरण करना, परम्परागत कृषि पद्धतियों को आधुनिकता से सामंजस्य स्थापित करना, जैव आधारित कृषि विकास एवं आधारभूत सुविधाओं को विकसित करना, आदि महत्वपूर्ण नीति निर्धारक कदम उठाये जाने चाहिए जिससे कृषि उत्पादन एवं संधृत विकास की कल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भविष्य में मानवता एवं पर्यावरणीय उन्नयन के लिए संभव हो सकेगा।

सन्दर्भ सूची

Kumar, L.M., & Indira, M. (2014). An analysis of the Influence of Agricultural Policy on Changing Cropping Pattern in India. International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences,3, pp. 76.

Jyothi, V., Rani, P.P., Ramana, K.V., Prasad, P.R., & Rekha, M.V. (2020). Cropping Pattern Changes: A case study in Krishna Delta region of Andhra Pradesh. International Journal of Chemical Studies. 8(1), pp. 494.

Khan, M. & Ahmad, A. (2019). Changing Cropping Pattern in Kheri District, Uttar Pradesh, India. Economic Affairs,64(4), pp. 804.

Deen, S., & Bala, S. (2021). Changing Cropping Pattern in Haryana: A Spatio-Temporal Analysis of Major Food Crops. International Journal of All Research Education and Scientific Methods, 9(3), pp. 212-213.

Jyothi, V., Rani, P.P., Ramana, K.V., Prasad, P.R., & Rekha, M.V. (2020). Cropping Pattern Changes: A case study in Krishna Delta region of Andhra Pradesh. International Journal of Chemical Studies. 8(1), pp. 494-500.

Hashemi, M., Zadeh, H.M., Arasteh, P.D., & Zarghami, M. (2019). Economic and Environmental Impacts of Cropping Pattern Elements Using Systems Dynamics. Civil Engineering Journal, pp.1020-1032. DOI: 10.28991/cej-2019-03091308.

Osama, S., Elkholy, M., & Kansoh, R. M. (2017). Optimization of the Cropping Pattern in Egypt. Alexandria Engineering Journal. https://doi.org/10.1016/j.aej.2017.04.015

Mann, R. S. (2017). Cropping Pattern in Punjab (1966-67 to 2014-15). Economic & Political Weekly, 31(3), pp 30-33.

Shinde, S. E., Ingle, P. M., Mane, M. S., Thokal, R. T., & Ayare, B. L. (2015). Optimal cropping pattern for sustainable water use in canal command. Research Journal of Recent Sciences, 3(4), pp. 25-28.

Ghosh, B. K. (2011). Determinants of the Changes in Cropping Pattern in India: 1970-71 to 2006-07. Bangladesh Development Studies, 34(2), pp. 87–98.

Nishi Bhuvandas, A., Mirajkar, B., Timbadiya, P., & Patel, P. (2010). Optimal Cropping Pattern in Command Area of Kakrapar right bank main canal. National Conference on Sustainable Development of Urban Infrastructure, pp. 408-413.

सीकर जिले में जल जीवन मिशन की स्थिति का विश्लेषण

डॉ. दिलभाग

सारांश

सीकर जिले राजस्थान में पेयजल उपलब्धता की दृष्टि से पिछड़ा है। ग्रीष्मकाल में जिले में पेयजल समस्या उत्पन्न हो जाती है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई जल जीवन मिशन के माध्यम से सीकर जिले के प्रत्येक ग्रामीण घर में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इस शोध पत्र के माध्यम से अध्ययन क्षेत्र सीकर जिले में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन कवरेज की यथा स्थिति विश्लेषण किया गया है। सीकर जिला राजस्थान राज्य के जयपुर संभाग में उत्तर-पश्चिम भाग में स्थित है। जिले में अरावली पर्वत माला का भी विस्तार है शेष अधिकांश भाग मरुस्थली है। सीकर जिला 27°21’ उत्तरी अक्षांश से 28°12’ उत्तरी अक्षांश तथा 74°44’ पूर्वी देशान्तर से 75°25’ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। सीकर जिले का जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 7742.43 वर्ग किलोमीटर है। यह शोध पत्र द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। प्रस्तुत शोध पत्र के निष्कर्ष के रूप में स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में अधिकतम बस्तियों में सीधे पाइप लाइन के द्वारा जलापूर्ति हो रही है परन्तु जिले में लगभग आधे घर आज भी नल के माध्यम से पेयजल प्राप्त करने से वंचित है।

बीज शब्द:पेयजल, जलापूर्ति, जल जीवन मिशन, कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन, हर घर जल

प्रस्तावना

एफएचटीसी (FHTC) का अर्थ है "कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन", जो किसी क्षेत्र में उन परिवारों के प्रतिशत या संख्या को दर्शाता है जिनके घरों में पाइप के माध्यम से व्यक्तिगत नल कनेक्शन से जल आपूर्ति की जा रही है। यह कवरेज सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता और लोगों की पहुंच का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। एफएचटीसी कवरेज सरकार द्वारा सभी नागरिकों को जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDG) 6 को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक सभी के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छता की सुनिश्चित पहुंच प्रदान करना है। । भारत सरकार द्वारा इस दिशा में ‘जल जीवन मिशन (JJM)’ की शुरुआत की गई। जल जीवन मिशन देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 15 अगस्त, 2019 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। मिशन का प्राथमिक उद्देश्य 2024 तक "हर घर जल" (हर घर में पानी) सुनिश्चित करना है। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य राजस्थान के सीकर जिले जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन कवरेज स्थिति का विश्लेषण करना है साथ ही यह भी जानने का प्रयास किया गया है कि सीकर जिले में 01 अप्रेल 2024 तक कितने घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन स्थापित किए जा चुके हैं।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है। इस शोध पत्र में द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया गया है। इन द्वितीयक आंकड़ों के अंतर्गत सीकर जिले में ब्लॉक अनुसार बस्तियों और उनमें विद्यमान घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शनों की संख्या सम्बन्धी आंकड़े शामिल किये गये हैं। अध्ययन क्षेत्र में जल जीवन मिशन अंतर्गत घरेलू कार्यात्मक नल कनेक्सन सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन भारत सरकार के ‘जल शक्ति मंत्रालय’ के अंतर्गत ‘पेयजल एवं स्वच्छता विभाग’ द्वारा संचालित ‘जल जीवन मिशन कार्यक्रम’ की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त किए गए हैं।

*डॉ. दिलभाग , सहायक आचार्य - भूगोल (वि.सं.यो.), राजकीय महाविद्यालय, भिनाय (अजमेर), राजस्थान।

अध्ययन क्षेत्र

सीकर जिला राजस्थान राज्य के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित है, जो जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। सीकर जिला 27°21' उत्तरी अक्षांश से 28°12' उत्तरी अक्षांश तथा 74°44' पूर्वी देशान्तर से 75°25' पूर्वी देशान्तर के मध्य अवस्थित है। जिले की सीमाएं उत्तर में झुंझुनूं, दक्षिण में जयपुर, पूर्व में अलवर और पश्चिम में नागौर जिले से मिलती हैं। भौगोलिक दृष्टि से सीकर अरावली पर्वतमाला की श्रृंखलाओं तथा शुष्क एवं अर्द्ध-शुष्क मरुस्थलीय मैदानों से घिरा हुआ है। यहाँ की जलवायु शुष्क एवं अर्ध-शुष्क है, जिसमें गर्मियों में तापमान 45°C तक पहुँच जाता है और सर्दियों में 5°C तक गिर जाता है। वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण-पश्चिमी मानसून के दौरान होती है, जिसकी औसत वार्षिक मात्रा लगभग 450-500 मिमी है। जिले का प्रशासनिक मुख्यालय सीकर शहर शिक्षा एवं वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। जनांकिकीय दृष्टि से सीकर जिले की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 26 लाख थी, जिसमें पुरुषों का अनुपात 52% और महिलाओं का 48% है। यहाँ की साक्षरता दर लगभग 72.98% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 85.37% एवं महिला साक्षरता दर 59.23% है। जनसंख्या घनत्व लगभग 361 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जिले की प्रमुख भाषाएँ हिंदी और राजस्थानी (मारवाड़ी, शेखावाटी) हैं। सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि से यह जिला विविधता से परिपूर्ण है, जहाँ विभिन्न जातीय एवं धार्मिक समुदायों का समावेश है।

शोध परिणाम:

अध्ययन क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 01 अप्रेल 2024 को पाइप द्वारा जल आपूर्ति और बिना पाइप जल आपूर्ति वाली बस्तियों की संख्या का विश्लेषण तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 1 : अध्ययन क्षेत्र सीकर जिले में ब्लॉक अनुसार PWS एवं NonPWS बस्तियों की संख्या

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	कुल बस्तियों की संख्या (01/04/24)	बिनापाइप जल आपूर्ति (Non PWS) बस्तियां		पाइपजल आपूर्ति (PWS) बस्तियां	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	दांतारामगढ़	335	4	1.19	331	98.81
2	धोद	320	1	0.31	319	99.69
3	फतेहपुर	284	0	0.00	284	100.00
4	खंडेला	635	5	0.79	630	99.21
5	लछमनगढ़	254	1	0.39	253	99.61
6	नेछवा	196	0	0.00	196	100.00
7	पलसाना	203	7	3.45	196	96.55
8	पिपराली	232	1	0.43	231	99.57
	कुल	**2459**	**19**	**0.77**	**2440**	**99.23**

स्रोत: जल जीवन मिशन का आधिकारिक वेबसाइट (19 जनवरी 2025)

अध्ययन क्षेत्र में सीकर जिले में 1 अप्रैल 2024 को कुल 2,459 बस्तियों में से 19 बस्तियां पाइपलाइन द्वारा जल आपूर्ति से वंचित थी जो कुल बस्तियों का मात्र 0.77% है इसमें सर्वाधिक बस्तियां पलसाना ब्लॉक में 3.45% थी। वहीं अध्ययन क्षेत्र में को 2,440 (99.23%) बस्तियां पाइप द्वारा जल आपूर्ति प्राप्त कर रही थी। इसमें फतेहपुर व नेछवा ब्लॉक में शत प्रतिशत बस्तियां पाइप लाइन द्वारा जल आपूर्ति प्राप्त कर रही थी। इसी प्रकार अध्ययन क्षेत्र सीकर जिले में पाइप जल आपूर्ति वाली बस्तियों में कुल घरों की संख्या एवं उपलब्ध नल कनेक्सन की स्थिति का विश्लेषण तालिका 2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2 : अध्ययन क्षेत्र सीकर जिले में ब्लॉक अनुसार PWS बस्तियों में नल कनेक्सन की स्थिति

. सं.	ब्लॉक का नाम	PWS बस्तयों में कुल गृहों की संख्या	नल कनेक्शन वाले गृहोंकी संख्या	
			संख्या	प्रतिशत
1	दांतारामगढ़	31517	19196	60.91
2	धोद	47888	24987	52.18
3	फतेहपुर	34094	14464	42.42
4	खंडेला	49331	25754	52.21
5	लछमनगढ़	34703	10057	28.98
6	नेछवा	19624	10876	55.42
7	पलसाना	26796	19462	72.63
8	पिपराली	24222	21005	86.72
	कुल	**268175**	**145801**	**54.37**

स्रोत: जल जीवन मिशन का आधिकारिक वेबसाइट (19 जनवरी 2025)

अध्ययन क्षेत्र पाइप जल आपूर्ति (PWS) बस्तियों में कुल घरों की संख्या 2,68,175 है जिनमें नल कनेक्शन वाले घरों की संख्या 1,45,801 (54.37%) है। इसमें सर्वाधिक नल कनेक्शन वाले घरों की संख्या पिपराली ब्लॉक में है जिसमें 24222 में से 21,005 (86.72) प्रतिशत है तथा सबसे कम लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक में 34,703 में से 10,057 (28.98%) है। अध्ययन क्षेत्र में ऐसी बस्तयों की पहचान भी की गई है

जहाँ पाइप जल आपूर्ति तो है परन्तु किसी भी घर में कार्यात्मक नल कनेक्सन उपलब्ध नहीं है। अग्र तालिका में 0 प्रतिशत घरेलू नल कनेक्सन कवरेज वाली बस्तियों की संख्या एवं उनमें घरों की संख्या का विवरण दर्शाया गया है

तालिका 3 : सीकर जिले में PWS बस्तियों में 0 प्रतिशत घरेलू नल कनेक्सन वाली बस्तियों की संख्या एवं घरों की संख्या

क्र. सं.	**ब्लॉक का नाम**	**बस्तियों की संख्या**	**घरों की संख्या**
1	दांतारामगढ़	181	8786
2	धोद	188	20110
3	फतेहपुर	184	11946
4	खंडेला	297	16880
5	लछमनगढ़	167	15930
6	नेछवा	121	6159
7	पलसाना	81	5045
8	पिपराली	35	2122
	कुल	**1254**	**86978**

स्रोत: जल जीवन मिशन का आधिकारिक वेबसाइट (19 जनवरी 2025)

तलिका में दर्शाए गये आंकड़ों से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र सीकर जिले में कुल 1254 इसी बस्तियां है है जहाँ पर पाइप द्वारा जलापूर्ति तो होती है परन्तु घरेलू नल कनेक्सन एक भी नहीं है। इन 1254 बस्तयों में 86,978 घरों की आबादी है जिनमे किसी भी घर में नल कनेक्सन नहीं है। ब्लॉक अनुसार देखा जाये तो ऐसी सर्वाधिक बस्तियां खंडेला ब्लॉक में सर्वाधिक है जबकि सबसे कम पिपराली ब्लॉक में हैं जिनमें घरों की संख्या क्रमशः 297 व 35 है। इसी प्रकार जिले में 0 से 24 प्रतिशत घरों में नल कनेक्सन वाली बस्तियों एवं उनमें उपलब्ध घरेलू नल कनेक्शनों की संख्या का विश्लेषण तालिका 4 में दर्शाया गया है।

तालिका 4 : सीकर जिले में PWS बस्तियों में नल कनेक्सन की स्थिति (24 प्रतिशत तक)

क्र. सं.	**ब्लॉक का नाम**	**बस्तियों की संख्या**	**घरों की संख्या**	**घरों में FHTC**	**कुल घरों का प्रतिशत**
1	दांतारामगढ़	7	1069	107	10.01
2	धोद	8	1270	127	10.00
3	फतेहपुर	16	3833	394	10.28
4	खंडेला	31	4048	574	14.18
5	लछमनगढ़	18	4943	436	8.82
6	नेछवा	13	1947	131	6.73
7	पलसाना	4	345	65	18.84
8	पिपराली	4	63	5	7.94
	कुल	**101**	**17518**	**1839**	**10.50**

स्रोत: जल जीवन मिशन का आधिकारिक वेबसाइट (19 जनवरी 2025)

अध्ययन क्षेत्र में 0 से 24% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन कवरेज वाली बस्तियों की कुल संख्या 101 है जिनमें कुल गृहों की संख्या 17,518 है। उल्लेखनीय है इन 17,518 घरों में से केवल 1,839 (10.50%) घरों में ही कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन है। अध्ययन क्षेत्र में इस वर्ग में सर्वाधिक बस्तियों वाला खंडेला ब्लॉक है। इस ब्लॉक में कुल 31 बस्तियां हैं जिसमें कुल 4,048 घर है, वहीं न्यूनतम बस्ती वाले क्रमशः पलसाना व पिपराली है। इन ब्लॉक में चार-चार बस्तियों जो इस श्रेणी में है और इन बस्तियों में घरों की संख्या क्रमशः 345 व 63 है। अध्ययन क्षेत्र सीकर जिले में इसी प्रकार जिले में 25 प्रतिशत से 49 प्रतिशत घरों में नल कनेक्सन वाली बस्तियों एवं उनमें उपलब्ध घरेलू नल कनेक्शनों की संख्या का विश्लेषण तालिका 5 में दर्शाया गया है।

तालिका 5 : सीकर जिले में PWS बस्तियों में नल कनेक्सन की स्थिति (25 से 49 प्रतिशत तक)

क्र. सं.	**ब्लॉक का नाम**	**बस्तियों की संख्या**	**घरों की संख्या**	**घरों में FHTC**	**कुल घरों का प्रतिशत**
1	दांतारामगढ़	5	442	140	31.67
2	धोद	4	960	465	48.44
3	फतेहपुर	20	4402	1734	39.39
4	खंडेला	21	3511	1313	37.40
5	लछमनगढ़	16	4168	1745	41.87
6	नेछवा	8	170	64	37.65
7	पलसाना	7	837	256	30.59
8	पिपराली	5	303	131	43.23
	कुल	**86**	**14793**	**5848**	**39.53**

स्रोत: जल जीवन मिशन का आधिकारिक वेबसाइट (19 जनवरी 2025)

अध्ययन क्षेत्र में 24 से 49% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन कवरेज वाली बस्तियों की कुल संख्या 86 है जिनमें कुल घरों की संख्या 14,793 है इनमें से केवल 5,848 (39.53%) घरों में ही कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति होती है। अध्ययन क्षेत्र में इस प्रकार की सर्वाधिक बस्तियां खंडेला ब्लॉक में है वहीं न्यूनतम बस्तियां दातारामगढ़ और पिपराली ब्लॉक में 5-5 है। अध्ययन क्षेत्र सीकर जिले में इसी प्रकार जिले में 50 से 74 प्रतिशत घरों में नल कनेक्सन वाली बस्तियों एवं उनमें उपलब्ध घरेलू नल कनेक्शनों की संख्या का विश्लेषण तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 6 : सीकर जिले में PWS बस्तियों में नल कनेक्सन की स्थिति (50 से 74 प्रतिशत तक)

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	बस्तियों की संख्या	घरों की संख्या	घरों में FHTC	कुल घरों का प्रतिशत
1	दांतारामगढ़	10	5798	3869	66.73
2	धोद	13	1999	1391	69.58
3	फतेहपुर	10	2571	1577	61.34
4	खंडेला	13	1143	706	61.77
5	लछमनगढ़	11	3214	1788	55.63
6	नेछवा	6	570	316	55.44
7	पलसाना	8	3025	1839	60.79
8	पिपराली	8	1745	946	54.21
	कुल	**79**	**20065**	**12432**	**61.96**

स्रोत: जल जीवन मिशन का आधिकारिक वेबसाइट (19 जनवरी 2025)

अध्ययन क्षेत्र में 50 से 74% तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन कवरेज वाली बस्तियों की संख्या 79 है। इन 79 बस्तियों में कुल 20,065 घर हैं जिसमें केवल 12,432 (61.96%) घरों में ही कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। ब्लॉक अनुसार देखा जाये तो ऐसी बस्तियों की सर्वाधिक संख्या धोद व खंडेला ब्लॉक में 13-13 है। धोद व खंडेला ब्लॉक में क्रमशः 1,999 तथा 1,143 घर है वहीं न्यूनतम बस्तियां नेछवा ब्लॉक में है जहां 6 बस्तियां हैं जिनमें 570 घर हैं। इसी प्रकार अध्ययन क्षेत्र में 75 से 99 प्रतिशत घरों में नल कनेक्सन वाली बस्तियों एवं उनमें उपलब्ध घरेलू नल कनेक्शनों की संख्या का विश्लेषण तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 7 : सीकर जिले में PWS बस्तियों में नल कनेक्सन की स्थिति (75 से 99 प्रतिशत तक)

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	बस्तियों की संख्या	घरों की संख्या	घरों में FHTC	कुल घरों का प्रतिशत
1	दांतारामगढ़	12	3616	3274	90.54
2	धोद	19	4714	4169	88.44
3	फतेहपुर	21	7857	7274	92.58
4	खंडेला	28	6260	5672	90.61
5	लछमनगढ़	18	2947	2587	87.78
6	नेछवा	24	7582	7169	94.55
7	पलसाना	22	5669	5427	95.73
8	पिपराली	3	437	371	84.90
	कुल	**147**	**39082**	**35943**	**91.97**

स्रोत: जल जीवन मिशन का आधिकारिक वेबसाइट (19 जनवरी 2025)

अध्ययन क्षेत्र में 75 से 99% तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन कवरेज वाली बस्तियों की कुल संख्या 147 है जिनमें कुल घरों की संख्या 39,082 है इनमें से 35,943 (91.97%) घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जाती है। अध्ययन क्षेत्र में इस प्रकार की सर्वाधिक बस्तियां खंडेला ब्लॉक में 28 है जिनमें से कुल 6,260 घर हैं। वहीं इस श्रेणी में न्यूनतम बस्तियां पिपराली ब्लॉक में 03 है जिसमें 437 घरों की आबादी हैं।

तालिका 8 : सीकर जिले में PWS बस्तियों में नल कनेक्सन की स्थिति (शत प्रतिशत तक)

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	बस्तियों की संख्या	घरों की संख्या	घरों में FHTC	कुल घरों का प्रतिशत
1	दांतारामगढ़	116	11806	11806	100
2	धोद	87	18835	18835	100
3	फतेहपुर	33	3485	3485	100
4	खंडेला	240	17489	17489	100
5	लछमनगढ़	23	3501	3501	100
6	नेछवा	24	3196	3196	100
7	पलसाना	74	11875	11875	100
8	पिपराली	176	19552	19552	100
	कुल	**773**	**89739**	**89739**	**100**

स्रोत: जल जीवन मिशन का आधिकारिक वेबसाइट (19 जनवरी 2025)

अध्ययन क्षेत्र में शत प्रतिशत कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन कवरेज वाली बस्तियों की कुल संख्या 773 है। इन 773 बस्तियों में 89,739 घर है और इन सभी घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के द्वारा पेयजल हेतु जल आपूर्ति की जा रही है। अध्ययन क्षेत्र में इस प्रकार की सर्वाधिक बस्तियां खंडेला ब्लॉक में 240 हैं जिनमें कुल 17,489 घर है। वहीं लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक में न्यूनतम बस्तियां हैं जिनकी संख्या 23 है इनमें कुल 3,501 घर हैं।

निष्कर्ष

अध्ययन क्षेत्र सीकर जिले में केंद्र प्रायोजित जल जीवन मिशन अंतर्गत के फलस्वरूप जिले की लगभग सभी बस्तियों को सीधे पाइप लाइन के द्वारा नल के द्वारा जलापूर्ति हो रही है जिले में PWS वाली बस्तियों के आधे से अधिक घरों में नल से जलापूर्ति हो रही है। जिले मात्र 19 बस्तियां ही शेष है जहाँ पाइप वाटर सप्लाई की सुविधा नहीं है। जिले की फतेहपुर एवं नेछवा ब्लॉक की सभी बस्तियों में पाइप वाटर सप्लाई उपलब्ध है। वहीं पीपराली एवं पलसाना ब्लॉक में अधिकतम स्तर तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन है जिले में अभी भी काफी बड़ी आबादी कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन से वंचित है। जिले में भौगोलिक एवं अन्य कारणों से योजना के क्रियान्वयन से संबंधित समस्याएँ आयी है हालाँकि इस योजना के अंतर्गत वंचित घरों तक नल द्वारा जल पहुँचाने का कार्य प्रगति पर है।

सन्दर्भ सूची

Ministry of Jal Shakti (2019). Jal Jeevan Mission: Guidelines for implementation. New Delhi: Ministry of Jal Shakti

United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York, NY: United Nations.

https://jaljeevanmission.gov.in/

Sharma, S. K., Seetharaman, A., & Maddulety, K. (2021). Framework for sustainable urban water management in context of governance, infrastructure, technology and economics. Water Resources Management, 35(12), 3903-3913.

Sarkar, S. K., & Bharat, G. K. (2021). Achieving Sustainable Development Goals in water and sanitation sectors in India. Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development, 11(5), 693-705.

https://ejalshakti.gov.in/JJM/JJMReports/Physical/JJMRep_FHTCCoverage.aspx

 वर्ष-17, अंक – 01 जनवरी-जून – 2025 ISSN – 0974-0118

बुन्देलखण्ड में पर्यटन उद्योग के अवसर एवं चुनौतियाँ : महोबाजिले के विशेष संदर्भ में

डॉ. महेन्द्र सिंह*

सारांश

पर्यटन एक ऐसा साधन है, जो आनन्द देने के साथ ही प्रकृति, समाज, संस्कृति, इतिहास, अध्यात्म आदि की जानकारी भी उपलब्ध कराता है। पर्यटन उद्योग रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, क्षेत्रीय आर्थिक असमानता को कम करना व विदेशी मुद्रा अर्जन के साथ ही राष्ट्रीय सम्पदा का बिना निर्यात किए राष्ट्रीय एकता व अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने में सहायक है। पर्यटन उद्योग, विभिन्न उद्योग का सामूहिक संगठन है। इस उद्योग में ताँगा चलाने वाले से लेकर वायुयान चालक तक, बाबर्ची से लेकर कालीन और रेशमी साड़ी के व्यवसायी तक, मजदूर से लेकर अधिकारी तक, सेवक से स्वामी तक सभी अपनी-अपनी इकाई के साथ लगे रहते हैं। पर्यटन उद्योग में उच्च कौशल युक्त श्रम से लेकर अनपढ़ श्रमिक तक को रोजगार उपलब्ध है। इस उद्योग में लगे हुए सभी लोगों का एक ही कार्य, पर्यटकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। इस शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य महोबा जिले में पर्यटन उद्योग की संभावनओं एवं चुनौतियों का विश्लेषण करना और सुझाव प्रस्तुत करना। प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक आकड़ों पर आधारित है, जिसका संकलन संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व पर्यटन संगठन (WTO) की रिपोर्ट, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की रिपोर्ट, अन्य संबंधित शोध पत्रों, समाचार पत्रों एवं पुस्तकों आदि से किया गया है। आकड़ों के विश्लेषण हेतु ई-व्यूज़ सांख्यिकीय साफ्टवेयर का उपयोग करते हुए साधारण प्रतिशत विधि का प्रयोग किया गया है। महोबा जिले में विभिन्न पर्यटन गंतव्य उपलब्ध हैं, परन्तु चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। महोबा जिले का पर्यटन उद्योग वर्ष 2022 तक कोविड-19 महामारी से पूर्व की स्थिति को नही प्राप्त कर पाया है। हमें आशा है कि महोबा जिले के पर्यटन उद्योग के लिए सरकार द्वारा कुछ अमूलचूल परिवर्तन करके पर्यटन उद्योग की संवृद्धि को बढ़ाया जाएगा।

बीज शब्द: पर्यटन उद्योग, आर्थिक विकास, विदेशी मुद्रा अर्जन, रोजगार सृजन

प्रस्तावना

प्रकृति की गोद में स्थित बुन्देलखण्ड उत्तर प्रदेश के दक्षिण और मध्य प्रदेश के पूर्वोत्तर विभिन्न खनिजों, पर्वत, वन, नदियों, तालाबों, घाटियों, बाँधों एवं प्राकृतिक सम्पदा से सुसज्जित क्षेत्र है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के उत्तर में यमुना नदी, मध्य में विन्ध्य पर्वत श्रंखला, पूर्व में बेतवा नदी और पश्चिम में टोंस या तमसा नदी इसकी सौन्दर्यता में चार चाँद लगाती हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्वतंत्रता से पूर्व अनेक छोटी-बड़ी रियासतें विद्यमान थीं। इन रियासतों के शासकों द्वारा अनेक विश्व प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण करवाया था, जो वर्तमान में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यद्यपि बुन्देलखण्ड एक शुष्क क्षेत्र है, परन्तु उतना सुखा क्षेत्र नहीं है, जितना कि प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया द्वारा एक फोटो , जिसमें सूखी दरारों से युक्त मिट्टी के रूप में प्रकाशित करके दिखाया जाता है। बुन्देलखण्ड के कुछ क्षेत्रों में पानी की समस्या है, परन्तु समूचा बुन्देलखण्ड ऐसा नहीं है। यदि बुन्देलखण्ड के तालाबों एवं बांधों की व्यवस्था को सूक्ष्मता से देखा जाय तो जल प्रबंधन के मामले में बुन्देलखण्ड एक रोल मॉडल के रूप में हमारे सम्मुख दिखाई देता है। बुन्देलखण्ड के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के चित्रकूट, बॉदा, महोबा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन झॉसी एवं मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, दतिया, सागर, टीकमगढ़, दमोह आदि जिलों को शामिल किया जाता है।

बुन्देलखण्ड के पर्यटन स्थलों में खजुराहो अवस्थित कन्दरिया महादेव मन्दिर, मतंगेश्वर मन्दिर, पन्ना में स्थित पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पाण्डव जल प्रपात, रेन्हे जल प्रपात, कलिंजर स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा, ओरछा में स्थित ओरछा वन्यजीव अभ्यारण्य, ओरछा का किला, चन्देरी का किला, झाँसी स्थित रानी महल, झाँसी का किला, केन घड़ियाल अभ्यारण्य, दतिया स्थित दतिया महल, चित्रकूट में स्थित गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म स्थली राजापुर, रामघाट, गुप्तगोदावरी गुफा, सती अनुसुइया आश्रम, हनुमानधारा, कमदगिरि मन्दिर व परिक्रमा मार्ग, स्फटिकशिला श्री परमहंस धारकुण्डी आश्रम, ग्लास ब्रिज, महोबा स्थित रहिला सागर सूर्य मन्दिर, खाकरामठ, बुन्देलखण्ड का कश्मीर कहा जाने वाला चरखारी इत्यादि। इसके अतिरिक्त बुन्देलखण्ड का ग्रामीण जीवन, खान-पान, रहन-सहन आदि अपने आप में नैसर्गिक है, जो ग्रामीण पर्यटन के लिए जाने वाले पर्यटकों के लिए एक उपयुक्त पर्यटक गंतव्य हो सकता है।

---

*डॉ. महेन्द्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, वीरभूमि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महोबा, उत्तर प्रदेश।

सहित्य समीक्षा

सरकार (2022), ने अपने शोध पत्र में पाया कि पर्यटन को कई कारक प्रेरित करते हैं जैसे- सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व व्यवसायिक गतिविधियाँ और विश्व के अनदेखे हिस्सों के बारे में जानने की मूल मानवीय प्रवृत्ति आदि महत्वपूर्ण कारक हैं। पर्यटन न केवल देश की जीडीपी में वृद्धि करता है, बल्कि व्यवसाय का एक भाग होने के साथ ही लोगों को खुश रहने में भी सहायक होता है। पर्यटन का भारत जैसे विकासशील देश पर वित्तीय, सामाजिक, राजनीतिक एवं पर्यावरणीय संघर्ष पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का दूरगामी प्रभाव पड़ता है।

परमार और शाह (2021), ने अपने शोध पत्र में पर्यटन उद्योग से प्राप्त होने वाली राष्ट्रीय आय और रोजगार सृजन में वृद्धि का अध्ययन करते हुए पाया कि सरकार पर्यटन उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सरकार उच्च गुणवत्ता वाली सड़कें बनाने और संचार के बुनियादी ढाँचे का विकास करने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के साथ ही राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होती है एवं यह उपर्युक्त सभी कारक एक ऐसा देश बनाते हैं, जहाँ पर्यटकों के आने की संभावना अधिक होती है।

डॉ. चावला, झा और वर्मा (2019), ने अपने लेख में बताया है कि पर्यटन सदैव केवल मनोरंजन या शारीरिक स्फूर्ति या बौद्धिक कायाकल्प तक सीमित नहीं होता है, बल्कि यह गरीबी खत्म करने, बेरोजगारी कम करने, सभ्यताओं के बीच संवाद को बढावा देने और विभिन्न परम्पराओं की धाराओं को आपस में मिलाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में भी कार्य करता है। इसके साथ ही इन्होनें अपने अध्ययन में उत्तर प्रदेश पर्यटन उद्योग के सभी संभावित आयामों जैसे पर्यटक यहाँ क्यों आते हैं, उनके सामने आने वाली समस्याएँ क्या हैं, आदि को शामिल किया है।

सुन्दरम्मा, (2019) भारत में पर्यटन उद्योग कुशल और अकुशल दोनों प्रकार की श्रम शक्ति के लिए रोजगार सृजित करता है, दूरदराज़ ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार लाता है, विदेशी मुद्रा अर्जन, अवसंरचनात्मक विकास को प्रेरित करता है और भारतीय पारम्परिक कला व शिल्प को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पिछले दो दशकों से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास में पर्यटन उद्योग एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, जिसमें समावेशी आर्थिक विकास को सुदृढ़ बनाने की अपार संभावना उपलब्ध है।

अध्ययन की आवश्यकता

साहित्यावलोकन के पश्चात् यह स्पष्ट है कि बुन्देलखण्ड विशेष रूप से महोबा जिले के संदर्भ में पर्यटन उद्योग की समस्याओं, संभावनाओं से संबंधित पहलुओं पर शोध कार्य नहीं किया गया है। अतः शोधार्थी का यह परम दायित्व है कि वह महोबा जैसे पर्यटन उद्योग के लिए अपार संभावनाओं वाले गंतव्य पर शोध कार्य करे।

उद्देश्य

इस शोध पत्र का उद्देश्य बुन्देलखण्ड विशेष रूप से महोबा जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों का विवरण प्रस्तुत करना तथा महोबा जिले में पर्यटन उद्योग की संभावनओं एवं चुनौतियों का विश्लेषण करना है।

शोध विधि

यह शोध पत्र पूर्णतः द्वितीयक आकड़ों पर आधारित है। आकड़ों का संकलन संबंधित विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, वार्षिक रिपोर्ट पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रकाशन, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रकाशन, क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, झाँसी के प्रकाशन आदि से किया गया है। आकड़ों के विश्लेषण के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और ई-व्यूज जैसे सांख्यकीय सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है।

विश्लेषणात्मक अध्ययन

उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यटन नीति 2022 में नये पर्यटन गंतव्यों के विकास हेतु नवीन पर्यटन सर्किटों के विकास पर बल दिया गया है। इन पर्यटन सर्किटों में प्रमुख रामायण सर्किट, कृष्ण-बृज सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, वाइल्ड लाइफ एवं इको टूरिज्म सर्किट, बुन्देलखण्ड सर्किट, महाभारत सर्किट, शक्ति सर्किट, अध्यात्मिक सर्किट, सूफी कबीर सर्किट, जैन सर्किट, क्राफ्ट सर्किट, स्वतंत्रता संग्राम सर्किट एवं असेवित अन्य विभिन्न सर्किट आदि हैं। इन पर्यटन सर्किटों के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न पर्यटक गंतव्यों का अमूलचूल विकास करके पर्यटन उद्योग को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। बुन्देलखण्ड सर्किट के अन्तर्गत चित्रकूट, बाँदा, महोबा, चरखारी, हमीरपुर, कालिंजर, झाँसी, ललितपुर, जालौन और देवगढ़ आदि को शामिल किया गया है।

महोबा के प्रमुख पर्यटक स्थल

महोबा चन्देल राजपूतों की राजधानी थी, जिन्होंने 10वीं से 16वीं शताब्दी तक बुन्देलखण्ड क्षेत्र पर शासन किया था। महोबा को महोत्सव नगर कहा जाता है। महोबा का विकास एक सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में हुआ। महोबा का आल्हा गायन इसके गौरवशाली अतीत और आल्हा व ऊदल दो सगे भाइयों की वीर गाथाओं का वर्णन है, जो अपनी मातृभूमि के सम्मान की रक्षा के लिए लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए।चट्टानी द्वीपों के बीच स्थित अनेक झीलों के अतिरिक्त ऐतिहासिक, पुरातात्विक और धार्मिक स्थल भी उपलब्ध हैं। महोबा के प्रमुख पर्यटन स्थल निम्नलिखित हैं-

रहेलिया सूर्य मन्दिर

चन्देल शासक राहिल ने सन् 890-940 ई0 के दौरान एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था, जिसका वर्तमान नाम राहिल सागर है। यह महोबा के सबसे प्राचीन तालाबों में से एक है। राहिल सागर जिला मुख्यालय से दक्षिण-पश्चिम दिशा में अवस्थित है। इसी तालाब के किनारे पर ही चन्देल राजा ने तेलिया पत्थर से सुन्दर सूर्य मन्दिर बनवाया था। इस मन्दिर में लगभग 4 फीट की सूर्य देव की आराधना मुद्रा में बलुआ पत्थर की प्रतिमा रखी है। महोबा के इस पर्यटक स्थल पर उगते सूर्य और ढलते सूर्य मनमोहक दृश्य एवं यहॉं का प्राकृतिक सौन्दर्य पर्यटकों के मन को आकर्षित करने वाला है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशाल मेले का आयोजन किया जाता है।

गोखार गिरि

यह विन्ध्य पर्वत श्रृंखला में स्थिति एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। इसका नामकरण प्रसिद्ध संत गोरखनाथ के नाम पर है। यहाँ पर अनेक प्राकृतिक पानी के झरने एवं गुफाएँ अवस्थित हैं। इसकी एक गुफा में गोरखनाथ के शिष्य सिद्ध दीपकनाथ रहते थे। इसी कारण से यह स्थल तपोभूमि के रूप में भी प्रसिद्ध है। इस पर्वत की चोटी मर्दन तुंग नाम से प्रसिद्ध है। इस चोटी पर चढना बहुत मुश्किल है, जो इस पर्यटक गंतव्य को साहसिक पर्यटन के लिए एक आकर्षण का केन्द्र बनाता है। गोरखगिरि पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है।

शिव ताण्डव मन्दिर

यह मन्दिर महोबा में गोरखगिरि पर्वत के समीप स्थित है। यहाँ भगवान शिव की प्रतिमा नटराज स्वरूप में स्थिापित है। यह मूर्ति काले ग्रेनाइट के पत्थर में उत्कीर्ण की गयी है। नटराज स्वरूप में भगवान शिव की प्रतिमा इस क्षेत्र में सबसे दुर्लभ मूर्तियों मे से एक है। यह पर्यटन गंतव्य धार्मिक पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है।

चरखारी बुन्देलखण्ड का कश्मीर (चरखारी का किला)

चरखारी महोबा जिले का एक उपनगर है, जो जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चरखारी में एक विशालकाय किला है और इसी से लगा हुआ एक राजमहल भी है। राजमहल के चारों ओर नीलकमल से आच्छादित और एक-दूसरे से जुड़े हुए अनेक तालाब हैं, जिन्हें सागर कहा जाता है। सर्दियों में यह स्थल कश्मीर की लगभग विशेषताओं जैसे- झीलें (तालाब), दुर्ग, राजमहल, मन्दिर और सौदर्य का दर्शन सर्व सुलभ कराता है। इसलिए को बुन्देलखण्ड का कश्मीर कहा जाता है। चरखारी में भगवान कृष्ण के 108 मन्दिर अवस्थित हैं। इसके समीप बुन्देला राजाओं का आखेट स्थल टोला तालाब है। चरखारी में एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है।

कजली मेला

महोबा मे कीरत सागर (एक विशाल तालाब) के तट पर प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के एक दिन बाद ऐतिहासिक काजली मेले का आयोजन किया जाता है। पृथ्वीराज चौहान की सेना से विजय पाने के उपलक्ष मे इस मेले का आयोजन आरम्भ किया गया था। आज भी इस दिवस को विजय दिवस के रूप में मनाने के लिए इस मेले का आयोजन भव्यता से किया जाता है।

खाकरामठ

इसका निर्माण चन्देल शासक मदनवर्मन ने 1129 ई0 से 1164 ई0 के मध्य कराया था। दक्षिण भारत में शिवपूजा में काकरा आरती का प्रचलन रहा है। यह शिव मन्दिर होने के कारण काकरामठ नाम से जाना जाता था। यह बाद में परिवर्तित होकर खाकरामठ नाम से जाना जाने लगा। इसका आधार 42 फीट और चौड़ाई 103 फीट है। मुख्य द्वार पूर्व की ओर और दो द्वार उत्तर और दक्षिण दिशा में हैं। यह महोबा कस्बे में स्थित मदन सागर, जो एक बड़ा तालाब है, के मध्य में स्थित है। इस तक पहुँने के लिए एक तैरता हुआ पुल बनाया गया है। यहाँ पर पहाड़, तालाब, मन्दिर और अन्य प्राकृतिक मनोरम दृश्य पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं।

विजय सागर पक्षी अभयारण्य

विजय सागर पक्षी अभयारण्य, विजय सागर झील के तट पर स्थित है। इस झील का निर्माण चन्देल शासक विजय वर्मन ने सन् 1035 ई0-1060 ई0 के मध्य करवाया था। यह पक्षी अभयारण्य बाँदा-छतरपुर राजमार्ग पर जिला मुख्यालय से लगभग 5 कि0मी0 दूरी पर स्थित है। इस अभयारण्य क्षेत्र में ब्लैक नेकड क्रेन, हार्निबिल्स, कॉट्स, डार्टर्स, पेंटेड स्टार्क, ब्राह्मी बतख और लेस्सर सीटी बतख आदि के साथ ही सर्दियों में अनेक देशों से प्रवासी पक्षी भी विचरण करते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ प्राचीन बस्तियों के अवशेष भी स्थित हैं। विजय सागर पक्षी अभयारण्य में फ्लोरा, बांस, पलास, खैर, पीपल, बर्गद आदि के साथ वन क्षेत्र में पाये जाने वाले विभिन्न वृक्ष मौजूद हैं। इसका सुरम्य प्राकृतिक दृश्य पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षिक करने की क्षमता रखता है।

उर्मिल बाँध

उर्मिल बाँध महोबा के श्रीनगर से लगभग 8 कि0मी0 दूरी पर महोबा-नौगाँव मार्ग पर मुख्य मार्ग से लगभग 1 कि0मी0 दूरी पर स्थित है। यह उर्मिल नदी पर बना महोबा जिले का सबसे बड़ा बाँध है। यहाँ प्राकृतिक सौन्दर्य को निहारने और समय गुजारने के लिए काटेज की व्यवस्था है। यहाँ पर प्राकृतिक सौन्दर्य का आनन्द लेने के लिए पर्यटक आते हैं।

बेलाताल

बेलाताल एक विशाल और प्राचीन तालाब है, जिसका निर्माण चन्देल शासकों द्वारा कराया गया था। यह महोबा के एक उपनगर जैतपुर के समीप स्थित है। यहाँ पर चन्देल कालीन किले नामतः बादल महल और ड्योढ़ी महल के अवशेष स्थित है। किवदन्तियों के अनुसार बेलाताल की लड़ाई में ही पेशवा बाजीराव ने मस्तानी को देखा और उस पर मोहित हो गया। यहाँ पर जल से संबंधित खेलों का भी आयोजन होता है।

धार्मिक पर्यटक स्थल

महोबा मे अनेक धार्मिक पर्यटक गंतव्य स्थित हैं जैसे- बड़ी चन्द्रिका देवी मन्दिर, छोटी चन्द्रिका देवी मन्दिर ,काकुन हनुमान मन्दिर, श्रीनगर हनुमान मन्दिर आदि हिन्दू धर्म के स्थल स्थित हैं। इसके साथ ही जैन तीर्थंकर स्थल और मुस्लिम धर्म से संबंधित स्थल भी हैं। जो इन धर्मो को मानने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।

ग्रामीण पर्यटन

महोबा में बुन्देलखण्ड की अद्वितीय ग्रामीण विरासत अभी भी अपनी नैसर्गिक स्थिति में उपलब्ध होती है। प्राचीन समय में सामान और मानव आवागन का प्रमुख साधन बैलगाड़ी, तालाब, कुँआ, कृषि की प्रधानता और गाँवों का नैसर्गिक सौन्दर्य महोबा को ग्रामीण पर्यटन के अवसर उपलब्ध कराता है। वर्तमान बड़े शहरों महोबा में बुन्देलखण्ड की अद्वितीय ग्रामीण विरासत अभी भी अपनी नैसर्गिक स्थिति में उपलब्ध होती है। प्राचीन समय में सामान और मानव आवागन का प्रमुख साधन बैलगाड़ी, तालाब, कुँआ, कृषि की प्रधानता और गाँवों का नैसर्गिक सौन्दर्य महोबा को ग्रामीण पर्यटन के अवसर उपलब्ध कराता है। वर्तमान बड़े शहरों के पर्यटक शहरी चकाचौध, प्रदूषण और शोर-सराभे से दूर शान्त और स्वच्छ ग्रामीण जीवन जीने के लिए पर्यटन पर जाते हैं। इसलिए महोबा में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ा कर पर्यटन अवसरों को दोहन किया जा सकता है।

सांस्कृतिक पर्यटन

महोबा को महोत्सव नगर के रूप में जाना जाता है। यहाँ की सॉस्कृतिक विरासत अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है। महोबा में पारम्परिक आल्हा गायन, राई नृत्य और देवारी आदि विश्व प्रसिद्ध है। इन पर्यटन स्थलों के अतिरिक्त अन्य धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक आदि पर्यटन गंतव्य स्थित हैं। यह सभी पर्यटन गंतव्य महोबा जिले मे पर्यटन उद्योग के समक्ष अवसरों को उपलब्ध कराते हैं। जिसका दोहन करके महोबा के लोगो की आय और रोजगार में वृद्धि के द्वारा गरीबी, आर्थिक विषमता आदि जैसी समस्याओं के समाधान के साथ ही सार्वजनिक आय में अन्ततः वृद्धि की जा सकती है।

उपर्युक्त आयतचित्र में वर्ष 2015 से 2022 तक के महोबा जिले के पर्यटक आगमन को दर्शाया गया है। वर्ष 2015 में महोबा जिले में कुल पर्यटक आगमन 1093896 था, जिसमें घरेलू और विदेशी पर्यटक आगमन क्रमशः 1092384 तथा 1512 रहा है। वर्ष 2019 में कुल पर्यटक आगमन पूर्व वर्ष की तुलना में 3.80 प्रतिशत बढ़कर 1262402 हो गया, जिसमें घरेलू एवं विदेशी पर्यटक आगमन क्रमशः 1260010 व 2392 हो गया। कोविड-19 महामारी ने विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। महोबा जिले का पर्यटक उद्योग कोविड-19 महामारी के कारण लगे लॉकडाउन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ। वर्ष 2020 में महोबा जिले में कुल पर्यटक आगमन पूर्व वर्ष की तुलना में 78.62 प्रतिशत कम होकर मात्र 269925 हो गया, जिसमें घरेलू और विदेशी पर्यटक आगमन क्रमशः 269756 तथा 169 था। वर्ष 2021 और 2022 में कोई भी विदेशी पर्यटक महोबा जिले में नहीं आया।

उपर्यक्त आयतचित्र के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि महोबा जिले में घरेलू पर्यटन कोविड पूर्व काल तक धीरे-धीरे बढ़ा है, परन्तु कोविड-19 महामारी के कारण इसमें अत्यधिक कमी आयी, जो वर्ष 2022 तक भी कोविड-19 की पूर्व स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाया है। विदेशी पर्यटक आगमन वर्ष 2015 से 2019 तक लगभग स्थिर रहा है तथा कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में यह संख्या कम होकर मात्र 169 हो गयी, जो वर्ष 2021 और 2022 में शून्य रही है।

आयतचित्र-1

महोबा जिले में पर्यटक आगमन

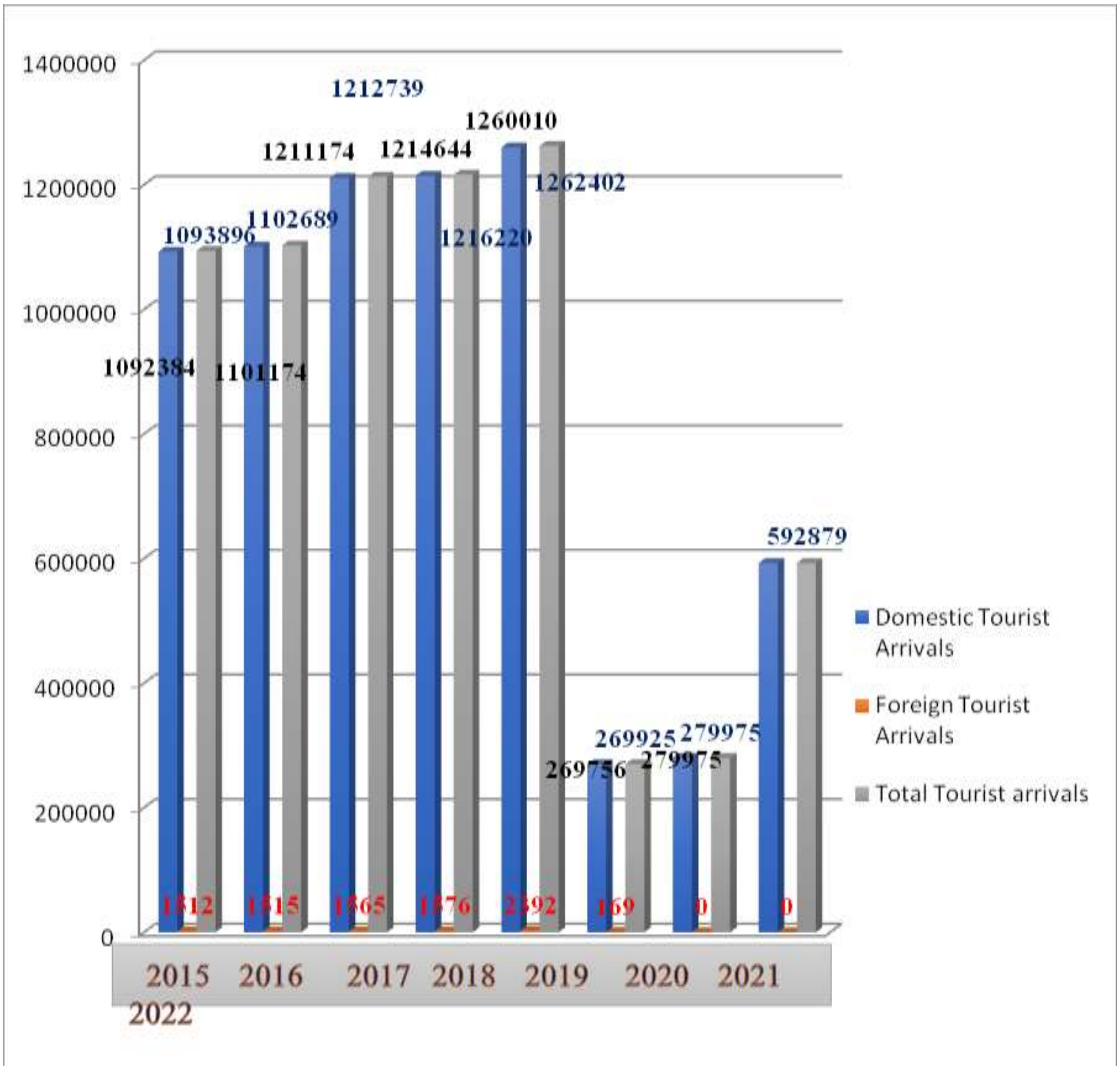

स्त्रोतः- उत्तर प्रदेश पर्यटक सांख्यिकी, 2023 पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ

महोबा जिले में पर्यटन उद्योग की समस्याएँ

1. महोबा में धार्मिक पर्यटक गंतव्यों की अधिकता है। इस समय आवश्यकता महोबा में पर्यटन उत्पादों के विविधीकरण की है। जिससे सभी प्रकार के पर्यटन को पसन्द मानने वाले लोग भी महोबा की ओर आकर्षित हो सकें।
2. महोबा में पर्यटन उद्योग की सबसे बड़ी चुनौती विभिन्न तालाबों में बढ़ता प्रदूषण का स्तर भी है।
3. यहाँ पर प्रशिक्षित एवं कुशल कामगारों जैसे- टूर गाइड आदि का अभाव है।
4. केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान चलाकर शहरों की साफ-सफाई पर ध्यान दिया है, परन्तु महोबा जैसे छोटे शहरों के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर सफाई का अभाव है।
5. महोबा के लिए अन्य बडे शहरों से प्रतिदिन और त्वरित रेल कनेक्टिविटी का अभाव है, इसके साथ ही महोबा की अन्य शहरों से हवाई कनेक्टिविटी नहीं है।
6. पर्यटकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यानाकर्षण की आवश्यकता है।
7. महोबा के में विश्वस्तरीय अधोसंरचना का अभाव है। यह एक सर्वप्रमुख कारण है, जिससे विदेशी ही नहीं बल्कि, घरेलू पर्यटक भी महोबा नहीं आते हैं।

8. महोबा के पर्यटक स्थलों का आकर्षक प्रचार- प्रसार नहीं किया गया है ।

निष्कर्ष

महोबा पर्यटन स्थलों की उपलब्धता की दृष्टि से समृद्ध स्थल है। यहाँ पर प्राकृतिक पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन, साँस्कृतिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन से संबंधित पर्यटन गंतव्य उपलब्ध हैं, जो महोबा को पर्यटक आकर्षित करने ओर पर्यटन उद्योग के विकास की अपार संभावना को परिलक्षित करता है। इसके साथ ही महोबा के पर्यटक स्थलों पर साफ-सफाई का अभाव, समुचित सुरक्षा का अभाव, यातायात और संचार कनेक्टिविटी का अभाव, विश्व स्तरीय अवसंरचना की अनुपलब्धता के साथ ही महोबा के पर्यटक स्थलों का समुचित प्रचार-प्रसार न होना आदि समस्याएँ हैं, जो इस उद्योग के विकास को अवरूद्ध कर रही हैं। महोबा जिले के पर्यटन उद्योग को कोविड-19 महामारी ने नकारात्मक रूप से प्रभावित किया हैं। महोबा जिले के पर्यटन उद्योग को कोविड-19 महामारी के नकारात्मक प्रभाव से वर्ष 2022 तक बाहर नहीं आ सका है।

महोबा में पर्यटन उद्योग को बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम पर्यटक उत्पादों के विविधीकरण की आवश्यकता है। इसके साथ ही पर्यटक स्थलों में विश्वस्तरीय बुनियादी ढ़ाचे का निर्माण करना, पर्यटकों की समुचित सुरक्षा को सुनिश्चित करना, महोबा की अन्य बड़े शहरों से कनेक्टिविटी में सुधार लाना, सभी पर्यटक स्थलों की सफाई को सुनिश्चित करना और महोबा में जल संरक्षण के लिए तालाबों की व्यवस्था प्राचीन काल से है, इनकी सफाई की सुनिश्चित करना आदि को अपनाकर महोबा के पर्यटन उद्योग का विकास किया जा सकता है।

सन्दर्भ सूची

Chawla, C., Jha, R.S & Mr. Verma, A. (2019). Prospects and Problems of Tourism Industry in Uttar Pradesh. The Research Journal of Social Science. Vol. 10 Number 6. ISSN: 0025-1348 (P), 2456-1356 (O).

Web: www.aensi,in/index_in_cosmos Retrieved on 15/12/2024.

Khan, S. (2013). Bundelkhand ke Dastabej. Bharat: Vikas Prakashan. ISBN : 9788186958216.

Pandey, R.P. (2016). Bundelkhand : Sanskriti Aur Sahitya. Bharat Kitabghar Prakashan. ISBN : 978938505447.

Parmar, A.A. and Shah, M. (2021). Role of Tourism Industry in Growth and Employment Generation of India. International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT). Vol.- 9, Issue- 12, ISSN: 2320-2882.

Web:- www.ijrt.org Retrieved on 10/07/2024.

Rain, M.A. (2020). Bundelkhand ki Prodyogiki. Sanskriti Book Rivers. ISBN : 9789388727907.

Sadaiv, S, (2020). Bharat Ke Prasidh Mandir, Tirath Aur Dham: भारत के प्रसिद्ध मंदिर, तीर्थ और धाम. (n.p.): Prabhakar Prakashan Private Limited.

Sharma, S.K. (2013). Uttar Pradesh : Paryatan, Devalaya Evam Mandir (उत्तर प्रदेश : पर्यटन, देवालय एवं मंदिर). (n.d.). (n.p.): Diamond Pocket Books Pvt Ltd. ISBN:9789356845985

Sundaramma, T.V. (2019). Development and Impact of Tourism Industry in India. International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI). Vol. 8, Issue- 7, ISSN (Online) 2319-7722, (Print) 2319-7724.

Web:- www.ijhssi.org Retrieved on 18/08/2023.

उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022. (2023). उत्तर प्रदेश सरकार. लखनऊ ।

उत्तर प्रदेश पर्यटक सांख्यिकी, 2023.(2023). पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ

https://bundelkhand.in/bundelkhand-regions-major-tourist-destinations/ Retrieved On 25/12/2024.

https://bundelkhand.xyz/bundelkhand/10-beautiful-places-to-see-in-mahoba/ Retrieved On 07/12/2024.

https://mahoba.nic.in/hi/i;ZVd_LFky/ Retrieved On 10/11/2024.

https://www.google.co.in/books/edition/Khajuraho_Paryatan_Book/SpYYEAAAQBAJ?hl=hi&gbpv=1&dq=mahoba+tourism+destinations&pg=PA105&printsec=frontcover Retrieved On 10/01/2025.

https://www.google.co.in/books/edition/Bundelkhand_Ki_Prodyogiki_Sanskriti/JXXYDwAAQBAJ?hl=hi&gbpv=1&dq=bundelkhand&printsec=frontcover Retrieved On 25/12/2024.

https://upforest.gov.in/web/forestnew/upfd_VijaySagar-hi.aspx Retrieved on 12/02/2025

https://www.uptourism.gov.in/hi/article/mahoba-circuit-2024 Retrieved on 27/01/2025

https://bdsup.org/hi/cqUnsy [k.M&i;ZVd-LFky Retrieved On 04/10/2024.

https://khabarlahariya.org/belataal-talaab-jaitpur-kila-fort-bajirao-mastani/ Retrieved On 04/10/2024.

https://khabarlahariya.org/belataal-talaab-jaitpur-kila-fort-bajirao-mastani/ Retrieved On 04/10/2024.

वर्ष-17, अंक – 01 जनवरी-जून – 2025 ISSN – 0974-0118

मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजातियोंमें कौशल विकास की चुनौतियाँ एवं संभावनाओं का अध्ययन

अक्षय*
डॉ. विनोद सेन**
संजीत कुमार***

सारांश

यह शोध मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजातिके कौशल विकास पर किया गया है। किसी भी व्यक्ति के जीवन और व्यवहार को परिभाषित करने के लिए उसकीसामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। वर्तमान में किसी भी व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति उसके कौशल विकास पर निर्भर करती है। राज्य के अधिकांश अनुसूचित जनजातीय नागरिकग्रामीण अंचलों में निवास करते है। इनकी आर्थिक स्थिति मुख्य रूप से वन संसाधन, कृषि, पशुपालन, शिकार, मनरेगा, प्रवास, निर्माण कार्य इत्यादि पर निर्भर करती है, यही सम्पूर्ण जनजाति अर्थव्यवस्था का आधार होता है। गैर-अनुसूचित जनजातीय समुदाय की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति अनुसूचित जनजातीय की तुलना में अधिक बेहतर है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु अनेकों प्रयास कर रहे है। इन्हीं प्रयासों में से एक है अनुसूचित जनजाति के लोगों में कौशल विकास की संभावनाओं की तलाश करना हैं। अनुसूचित जनजाति से संबंधित कौशल विकास की समस्याओं का अध्ययन करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस शोध के माध्यम सेअनुसूचित जनजातीय मे मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् (मेपसेट), प्रधानमंत्री कौशल योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना एवं कौशल विकास योजना की चुनौतियों का अध्ययन किया गया है। शोध कार्य द्वितीयक समंको पर आधारित है, जिसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार की जनजातीय वार्षिक रिपोर्ट, भारत की जनगणना 2011, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की रिपोर्ट, प्रकाशित पुस्तके, प्रकाशित शोध पत्र, प्रकाशित पत्रिका, जिला हेण्ड बुक-2011, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट इत्यादि का अध्ययन किया गया हैं।

बीज शब्द: जनजातीय कृषि, शिक्षा,कौशल विकास,व्यवसाय, दैनिक आय, बेरोजगारी

प्रस्तावना

अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) स्वदेशी है, इनकी अपनी विशिष्टता और भौगोलिकता अलग-थलग होती है। सदियों से अनुसूचित जनजाति जंगलों और पहाड़ी इलाकों में निवास करने के कारण सामान्यत विकास प्रक्रिया के दायरे से बाहर रहे है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने संविधान में आदिवासी समूहों को ‘‘अनुसूचित जनजाति’’ के नाम से संबोधित किया है। जनजाति एक सामाजिक समूह है जिसका निश्चित भू-भाग, वंश, अपनी संस्कृति, भाषा, व्यवहार, आजीविका, इत्यादि होती है। पूरी दुनिया में अनुसूचित जनजातियां लगभग 200 मिलियन है, यह वैश्विक आबादी का लगभग 4 प्रतिशत है। जनजातीय दुनिया के कई क्षेत्रों मे पाए जाते हैं। इनकी अधिकांश सामाजिक-आर्थिक स्थिति खराब होती है और यह गरीबी रेखा के नीचे ही अपना जीवन यापन करते है (राजकुमार और पलानी अम्मल 2016)। अनुसूचित जनजाति को भारत में अनेकों नामों से जाना जाता है, जो इस प्रकार है- आदिवासी, वनवासी, जनजातीय, जनजाति, आदिम जाति, जंगली इत्यादि। इन्हें ‘‘देशज’’ समाज भी कहा गया है (श्रीवास्तव, 2022) भारत में लगभग 550 जनजातियां निवास करती है।

*अक्षय, शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (म.प्र.)।

**विनोद सेन, सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (म.प्र.)।

***संजीत कुमार, शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (म.प्र.)।

भारत की जनगणना 1951 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या मे अनुसूचित जनजातीय 5.6 प्रतिशत थी (उमेश शर्मा और चन्द्र मणि), जो भारत की नवीनतम जनगणना 2011 में बढ़कर अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 104545716 हो गई, और कुल जनसंख्या 1210854977 का 8.6 प्रतिशत हो गई। मध्यप्रदेश राज्य के भौगोलिक दृष्टि से भारत के मध्य में स्थित होने के कारण ''मध्यप्रांत'' भी कहा जाता है। अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के हिसाब से सर्वाधिक मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ में निवासरत् है।इन सभी राज्यों की अपेक्षा मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक है (अक्षय और सेन, 2024)।

भारत की कुल जनजातीय जनसंख्या की 14.64 प्रतिशत अनुसूचित जनजातीय मध्यप्रदेश में निवास करती है। भारत में 10.45 करोड़ जनजातीय जनसंख्या है, वहीं मध्यप्रदेश में 1.53 करोड़ जनजातीय जनसंख्या है। भारत की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का 8.63 प्रतिशत है, और मध्यप्रदेश में कुल जनसंख्या मे जनजातीय जनसंख्या 21.09 प्रतिशत है। मध्यप्रदेश में जनजातीय क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का 30.19 प्रतिशत है। प्रदेश में 26 वृहद परियोजनाएं, 05 मध्यम परियोजनाएं, 30 माडा पॉकेट (मॉडीफाइड ऐरिया डव्हलपमेंट) एवं 6 लघु अंचल अस्तित्व में है। प्रदेश में कुल 52 जिलों में से 21 जनजातीय जिलें है । जिसमें 6 पूर्ण रूप से जनजातीय जिले है। प्रदेश के 15 जिलों को जनजातीय जिले के रूप में सम्मिलित किया गया है, और जिलों के अंदर जनजातीय विकास खण्डों के रूप में भी विभाजित किया गया है।

वर्तमान समय में 89 जनजातीय विकास खण्ड मौजूद है (कार्य, 2022-23)। मध्यप्रदेश की 46 जनजातीयां एवं उनके उप-जातियों निवास करती है, जो इस इस प्रकार है- अगरिया, आन्ध, बैगा, भत्तरा, भैना, भुंजिया, भील, बिंझवार, भील मीना, धनवार, हलबा, कारकू, खरिया, कमार, गदाबा, डामोर, कीर, खैरवार, बिआर इत्यादि जनजातीयां निवास करती है (जिला हैण्ड बुक, 2011)। राज्य के अधिकांश जनजातीय आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने के कारण ही कृषि और वन संबंधी आजीविका पर अत्यधिक निर्भर है। जिसके कारण जनजातीय में आर्थिक स्थिति बहुत खराब है।

कुछ जनजातीय समुदायों के पास खान-पान की सामग्री भी उपलब्ध नहीं होती। परन्तु पिछले कुछ दशकों से अनुसूचित जनजातीय की अर्थव्यवस्था और आजीविका की रणनीतियों में बदलाव देखने मिला है। जनजातीय नए आजीविका के विकल्पों के लिए धीरे-धीरे शहरी बाजारों पर निर्भर होते जा रहे है। ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित संसाधनों के कारण आय सृजन और रोजगार की तलाश में कई लोग अपने घर छोड़कर शहरों की ओर प्रवास कर अपना कौशल विकास कर रहे है। कौशल विकास एवं उद्यमिता, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर के अनुसार वर्तमान में दुनिया अब भारत की ओर देख रही है, इसलिए हमें अपने युवाओं को कौशल प्रदान कर उन्हें हुनरमंद बनाने की आवश्यकता है।

सरकार ग्रामीण युवाओं को अधिक कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में जनजातियों के विकास हेतु अनेकों प्रकार की योजनाएं संचालित कर रही है, साथ ही स्थानीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार प्राथमिकता दे रही है। जनजातीय युवाओं को कुशल बनने के लिए ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजित होना जनजातीय विकास के दिशा में एक छोटा सा कदम है (मंत्रालय, 2022)। कौशल विकास के माध्यम से जनजातियों को न केवल सशक्त बनाना है, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कौशल विकास को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है, परन्तु जनजातियों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनेकों प्रकार की चुनौतियों का सामना करना होता है। यह शोध पत्र मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजातियों के कौशल विकास की संभावनाओं और चुनौतियों का विश्लेषण करता है। इस शोध पत्र के माध्यम से मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति में मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् (मेपसेट), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, कौशल विकास योजना की चुनौतियाँ का अध्ययन किया गया है।

साहित्य का पुनरावलोकन/ पूर्व शोध साहित्य का पुनरावलोकन

भवर और सिंह (2024),ने ''रोजगार सृजन में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की भूमिका'' मे अपने शोध पत्र के माध्यम से बताया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए बहुत अच्छी योजना है, परन्तु यह योजना पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पा रही है। इसके लिए कौशल विकास केन्द्रो को संख्या में वृद्धि के साथ विकास हेतु बहुत अधिक कार्य करने की जरूरत है।

जोसेफ डेविल और श्रीधरन आर (2020), ने '' केरल के अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा शुरू की गई कौशल विकास प्रशिक्षण और स्वरोजगार योजना पर एक अध्ययन'' किया है। जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सूक्ष्म उद्यम प्रारंभ किए गए है। राज्य में अनुसूचित जनजाति के मध्य शिक्षा स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार अनेकों प्रयास कर रही है जिसके लिए छात्रों को छात्रवत्ति, नए विद्यालयों का निर्माण साईकल वितरण इत्यादि योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इसके बाद भी जनजातियों की शिक्षा स्थिति में सुधार नहीं देखा जा रहा है। जनजातियों के कौशल विकास की बात करे तो राज्य में 2012 से 2018 तक मात्र 5119 युवाओं को ही प्रशिक्षण प्रदान किया गया है जो जनजातियों की खराब कुशलता को दर्शाता है। इस शोध हेतु द्वितीयक समंकों को उपयोग में लिया गया है।

परमार और जैन (2019),ने आदिवासी युवाओं के आत्म सम्मान बढ़ाने के लिए '' जीवन कौशल प्रशिक्षण की प्रभावशीलता पर एक अध्ययन किया। यह अध्ययन जीवन कौशल शिक्षा के महत्त्व को बताता है। आदिवासी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संसाधनों के अभावों का प्रायः सामना करते रहे है। यह शोध कार्य प्रथमिक समंकों पर आधारित होने के कारण आदिवासियों में कौशल विकास की चुनौतियों को समझाने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। अध्ययन से ज्ञात होता है कि कौशल प्रशिक्षण न केवल व्यक्तियों को व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है बल्कि पहचान और सामुदायिकता की भावना भी जाग्रत करता है।

अग्रवाल और ठाकुर (2019), ने अपने शोध पत्र ''प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं की उत्पादकता पर योजना का प्रभाव ग्वालियर क्षेत्र'' पर प्रकाशित किया। शोध के अध्ययन से ज्ञात होता है कि राष्ट्र के विकास हेतु यह योजना लाभदायक है। इस योजना मे अकुशल श्रमिक को प्रशिक्षण प्रदान कर कुशल बनाया जाता है। जिससे रोजगार की गुणवत्ता बढ़ती है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।
अग्रवाल, मल्होत्रा, लोधी और अन्य (2007),के द्वारा झारखंड में आदिवासियों के लिए हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम: एक समीक्षा की गई। अध्ययन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पर किया गया और उनके द्वारा हस्तशिल्प वस्तुओं को बनाने की विधि, कौशल, बाजार मांग इत्यादि का अध्ययन किया गया है। जनजाति समुदाय हस्तशिल्प का कार्य परपंराग्रत रूप से करते आ रहे है। जनजातियों को कौशल प्रशिक्षण नही दिया जाता। इनके द्वारा बनाई गई अधिकांश वस्तुएं हाथों से बनाई जाती है। वस्तुओं को बनाने के लिए मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता। आदिवासी हस्तशिल्प वस्तुएं बना लेते है परन्तु वस्तुओं के विक्रय हेतु उचित बाजार व्यवस्था ना होने के कारण वस्तु का उचित मूल्य भी प्राप्त नही होता, जिस कारण अधिकांश आदिवासी वस्तुओं का निर्माण नहीं करना चाहते परन्तु उनके पास आजीविका चलाने हेतु दूसरे संसाधनों का अभाव है जिस कारण उन्हे ना चाहते हुए भी यह कार्य करना पड़ता है। आदिवासियों को हस्तशिल्प वस्तु निर्माण के कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता के साथ ही उचित बाजार की व्यवस्था करना आवश्यक है।

शोध का अन्तराल

पूर्व साहित्य का पुनरावलोकन करने के पश्चात् ज्ञात हुआ कि जिन शोधकर्ताओं के शोध पत्रों का अध्ययन किया गया। उसमें अनुसूचित जनजाति से संबंधित कौशल विकास के लगभग सभी पहलूओं पर शोध पत्र के माध्यम से शोधकर्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए है, परन्तुमध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति के कौशल विकास के संभावनाएं और चुनौतियों पर शोध कार्य नही किए गए। जिसके कारण भारत सरकार और राज्य सरकार को जनजातियों में कौशल विकास से संबंधित विकास करने में अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं। यह शोध कार्य मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति में कौशल विकास की संभवनाएं और चुनौतियों पर किया जा रहा है। जनजातियों के विकास हेतु कौशल विकास के संबंध में अध्ययन करना अतिआवश्यक हैं।

शोध की आवश्यकता

राज्य की बड़ी संख्या में जनजातीय आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत् है, जिनकी आजीविका का मुख्य साधन कृषि, वनोपज संग्रहण, निजी क्षेत्रों में रोजगार, अस्थायी रोजगार इत्यादि पर आधारित है। बदलते आर्थिक और सामाजिक स्थिति के कारण इन समुदायों को वर्तमान समय में आजीविका के लिए अनेकों प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जनजातियों के विकास हेतु अनेकों योजनाओं का कियांवयन किया जा रहा है। उसी में से मध्यप्रदेश के कितने जनजातीय युवकों को कौशल विकास योजना के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है, यह जांच करना आवश्यक है। जिन जनजातीय व्यक्ति के पास कौशल होता है, उनकी आजीविका बेहतर होती है और जिस व्यक्ति के पास कौशल नहीं होता उनकी आजीविका में अन्तर देखा जा सकता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए कौशल विकास एक महत्वपूर्ण साधन साबित हो सकता है, जो न केवल रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा बल्कि जनजातियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी सक्षम होगा।

शोध का उद्देश्य

इस शोध कार्य के निम्नलिखित उद्देश्य है-

1. अनुसूचित जनजातियों के लिए चलाई जा रही कौशल विकास योजनाओं की समीक्षा करना।
2. इन योजनाओं के लाभ और उनकी सफलताओं में बाधाओं का मूल्यांकन।

शोध की प्रविधि

यह शोध कार्य द्वितीयक समंको पर आधारित है। शोध कार्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जनजातीय रिपोर्ट, भारत की जनगणना 2011, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के रिपोर्ट, प्रकाशित पुस्तके, प्रकाशित शोध पत्र, प्रकाशित पत्रिका, जिला हेण्ड बुक-2011, वेबसाइट और संबंधित विषयों के इंटरनेट से स्त्रोत एकत्रित किए गए है।

अनुसूचित जनजाति हेतु कौशल विकास योजनाओं का अध्ययन

मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् (मेपसेट):- यह योजना मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु वर्ष 1981 में जनजातीय वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओ को विभिन्न तकनीकी एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में कुशलता का विकास कर उनके रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु की गई है **(विभाग, प्रशासकीय प्रतिवेदन, मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् (मेपसेट), 2017-18)**। वर्ष 1989 में संस्था के कार्यक्षेत्र में वृद्धि कर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजनो को इस योजना में शामिल

किया गया है**(कार्य, 2022-23)**। इस योजना का मूल उद्देश्य कुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। सभी स्तर के औपचारिक तकनीकी शिक्षा की व्यवस्थ जिसमें कुशल मजदूर तकनीशियन आदि भी हो। प्रशिक्षित एवं गैर प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना जिससे कि वे अन्य रोजगार को भी अपना सके। तकनीकी कौशल के विकास के लिए व्यापक आयोजन व उसके आवश्यक क्रियान्वयन की व्यवस्था करना। जनजातीय क्षेत्रों में तकनीकी कौशल के विकास के लिए अन्य कार्य करना जो आवश्यक एवं सहायक हो। प्रशिक्षण की योजना बनाना व जिन क्षेत्रों में प्रशिक्षण की अधिक आवश्यकता हो, वहां इस योजना का प्रबंध करना। आदिवासी क्षेत्रों में व्यवसायिक, तकनीकी एवं प्रशिक्षण का कार्य कर रही हो उनकी समय-समय पर निरीक्षण करना है। इस योजना के तहत प्रशिक्षणार्थीयों को सरकारी एवं निजी कम्पनियों में प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद प्लेसमेंट के रूप में रोजगार प्रदान किया जाता है-

तालिका क्रमांक:- 01 मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति हेतु संचालित रोजगार प्रशिक्षण एवं रोजगार की उपलब्धता

क्रमांक	वर्ष	प्रशिक्षणार्थीयों की संख्या	प्रशिक्षण उपरान्त रोजगार प्राप्त प्रशिक्षणार्थी	रोजगार प्राप्ती का प्रतिशत
1	16-2015	802	801	99.88
2	17-2016	1102	642	58.25
3	18-2017	1708	48	2.81
4	23-2022	7354	3089	42.00
कुल प्रशिक्षणार्थी		**10966**	**4580**	**41.76**

स्त्रोत- जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश, 2017-18, जनजातीय कार्य विभागमध्यप्रदेश, 2022-23.

मध्यप्रदेश में इस योजना के तहत जिन्हें प्रशिक्षण दिया गया है, उन्हें सिपेट भोपाल, एटीआईपीसी पीथमपुर, आटो कलस्टर महू, प्रतिभा सिन्टेक्स लिमिटेड, फरीदाबाद, नियोकार्प लिमिटेड पीथमपुर, टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड देवास, ई हेरेक्स टैक्नालॉजी प्रा. लि. भोपाल, बेसिक्स एकेडमी फार बेल्डिंग लाईफलांग एम्प्लायबेलिटी लिमिटेड एम्प्लायबेलिटी लिमिटेड नई दिल्ली, सेन्टम वक्र लिमिटेड नई दिल्ली, आई. टी. आर.सी. टेक्नालाजी प्राइवेट लिमिटेड इन्दौर इत्यादि के द्वारा आदिवासी युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर प्लेसमेंट के रूप में रोजगार प्रदान किया जाता है(विभाग, प्रशासकीय प्रतिवेदन, मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् (मेपसेट), 2017-18)। तालिका क्रमांक 01 से स्पष्ट हो रहा है कि प्रशिक्षण योजना के तहत वर्ष 2015-16 में मध्यप्रदेश के 802 जनजातीय युवकों को प्रशिक्षण दिया गया और प्लेसमेंट के रूप में 801 प्रशिक्षणार्थीयों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है, जो कि 99.88 प्रतिश होता है। वर्ष 2016-17 में 1102 जनजातीय युवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया और 642 युवाओं को रोजगार प्रदान किया जो कुल प्रशिक्षणार्थीयों का 58.25 प्रतिशत होता है। वर्ष 2017-18 में 1708 जनजातीय युवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिसमें से मात्र 18 युवकों को ही रोजगार उपलब्ध कराया गया है, जोकि कुल प्रशिक्षणार्थीयों का 2.81 प्रतिशत होता है। इससे ज्ञात होता है कि कुल प्रशिक्षणार्थीयों में से 97.19 प्रतिशत जनजातीय युवक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी बेरोजगार है। वर्ष 2022-23 में 7354 जनजातीय युवकों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें से 3089 प्रतिशत युवकों को प्रशिक्षण के बाद रोजगार उपलब्ध कराया गया जोकि कुल प्रशिक्षण का 42.00 प्रतिशत होता है। पूरे मध्यप्रदेश में देखा जाए तो 10966 जनजातीय युवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जिसमें से मात्र 4580 युवकों को प्रशिक्षण के बाद रोजगार प्राप्त हुआ है यदि इसे प्रतिशत में देखे तो 41.76 प्रतिशत होता है जोकि बहुत ही कम है। युवक प्रशिक्षण लेने के लिए रोजगार की प्राप्ति के उद्देश्य से आते है परन्तु उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं होता और उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना:- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को वर्ष 2015 में पायलट योजना के रूप में प्रारंभ किया गया था। यह युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसका प्रमुख उद्देश्य युवाओं को कौशल युक्त बनाना है। यह योजना युवाओं के लिए पूर्णत: नि:शुल्क रखी गई है(भवर और सिंह, 2024)। प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKY)कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजना है, जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। कौशल प्रमाणन योजना का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है, जो उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद करेगा। इस योजना में ऐसे युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिन्होंने शिक्षा छोड़ दी है। केन्द्र में प्रशिक्षण टीसी सॉफ्ट स्किल्स, उद्यमिता, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता इत्यादि में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षित युवाओं को प्लेसमेंट की सहायता प्रदान कर जीविकोपार्जन हेतु रोजगार प्रदान किया जाता है। जो रोजगार में जाना नहीं चाहते उन्हें स्वरोजगार करने की सलाह दी जाती है (https://www.pmkvyofficial.org)। इस पायलट योजना के तहत देश भर में लगभग 19.85 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया (India, 2021-22)।

वर्ष 2015 का पायलट योजना को सफलता मिलने के कारण केंद्रीय मंत्री के द्वारा वर्ष 2015-16 में PMKVY 2.0 का प्रारंभ किया गया। जिसके लिए 12000 करोड़ रूपये की राशि के परिव्यय के साथ देश के 1 करोड़ युवाओं को इस योजना के तहत कौशल प्रदान कराने की योजना बनाई गई (India, 2021-22)। योजना के लक्ष्य की पूर्ति करते हुए PMKVY 2.0 में 11000708 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया (Open Government Data (OGD) Platform India),और अपने लक्ष्य को पूर्ण किया गया।

भारत को दुनिया की कौशल राजधानी बनाने के उद्देश्य और PMKVY 1.0,PMKVY 2.0 की सफलता को देखते हुए कौशल भारत मिशन की यात्रा प्रारंभ रखी गई। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

PMKVY 3.0 का शुभारंभ किया गया **(https://www.pmkvyofficial.org)**। यह योजना और अच्छे से प्रसारित हो सके इसके लिए कुछ बदलाव किए गए है, जिसमें कौशल समीतियों की भूमिका बढ़ाने के लिए मजबूत दिशा-निर्देश दिए गए है, ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बीच के कौशल अंतराल को दूर किया जा सके। कौशल अंतराल को दूर करने के लिए जिला स्तर पर मांग का आकलन करना एक महत्वपूर्ण कदम में से एक है। PMKVY 3.0 के माध्यम से 2.52 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया(India, 2021-22)।

तालिका क्रमांक:- 02 मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षणार्थी की जानकारी

क्रमांक	वर्ष	मध्यप्रदेश के प्रशिक्षणार्थीयों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षणार्थी की संख्या	अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षणार्थीयों का प्रतिशत
1	16-2015	127138	6762	5.3
2	17-2016	51857	3053	5.8
3	18-2017	187711	11184	5.9
4	19-2018	154478	8290	5.3
5	20-2019	223483	14541	6.5
6	21-2020	95403	9810	10.2
7	22-2021	42145	7027	16.6
8	23-2022	21345	2764	12.9
कुल प्रशिक्षणार्थी		**903560**	**63431**	**7.02**

स्त्रोत:- State/UT-wise Number of Scheduled Tribes Candidates Trained under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) from 2015-16 to 2023-24 | Open Government Data (OGD) Platform India, https://www.data.gov.in/resource/stateuts-wise-trained-candidate-under-pradhan-mantri-kaushal-vikas-yojana-pmkvy-2015-16.Accessed on.18/11/2024.

तालिका क्रमांक:- 02 से स्पष्ट हो रहा है कि मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण तो दिया जा रहा है, परन्तु अपेक्षाकृत बहुत कम युवाओं को प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा है। वर्ष 2015-16 में मध्यप्रदेश राज्य के 127138 युवाओं का प्रशिक्षण दिया गया है, यदि अनुसूचित जनजाति के युवाओं में प्रशिक्षण की स्थिति देखे तो 6762 युवाओं को ही प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जोकि कुल प्रशिक्षणार्थीयों का 5.3 प्रतिशत है। वर्ष 2016-17 में राज्य के अन्तर्गत 51857 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें से 3053 अनुसूचित जनजाति के युवक सम्मिलित थे, जो कुल प्रशिक्षण प्राप्तकर्ताओं का 5.8 प्रतिशत होता है। वर्ष 2017-18 में राज्य के 187711 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें से 11184 जनजातीय युवकों ने प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, यदि कुल प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता में से जनजातीय युवकों को देखा जाए तो 5.9 प्रतिशत युवकों को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। वर्ष 2018-19 में मध्यप्रदेश के 154478 युवाकों को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ वही अनुसूचित जनजाति के 8290 युवकों प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है जोकि कुल प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों का मात्र 5.3 प्रतिशत होता है। योजना में यह देखा गया कि प्रारंभ के वर्ष में अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षण में वृद्धि देखी गई है, परन्तु 2018-19 में कम युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्ष 2019-20 में मध्यप्रदेश के 223483 युवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, वहीं अनुसूचित जनजाति के 14541 युवकों ने प्रशिक्षण मे भाग लिया है, जो कुल प्रशिक्षणार्थीयों का 6.5 प्रतिशत होता है। इस वर्ष अनुसूचित जनजाति के युवकों के प्रशिक्षण में वृद्धि हुई है। वर्ष 2020-21 के अंतर्गत मध्यप्रदेश के 95403 युवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें अनुसूचित जनजाति के 9810 युवकों सम्मिलित हुए है। इस बार अनुसूचित जनजाति के 10.2 प्रतिशत युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। वर्ष 2021-22 के मध्य मध्यप्रदेश के 42145 युवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिसमें से 7027 अनुसूचित जनजाति युवकों को प्रशिक्षण की प्राप्ति हुई है, जो कुल प्रशिक्षण प्राप्तकर्ताओं का 16.6 प्रतिशत होता है। इस वर्ष योजना के प्रारंभ से अभी तक सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति के युवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्ष 2022-23 के अंतर्गत मध्यप्रदेश मे 21345 युवकों को इस योजना के तहत प्रशिक्षित किया गया, जिसमे 2764 अनुसूचित जनजाति के युवकों को प्रशिक्षण दिया गया है, जो मध्यप्रदेश के कुल प्रशिक्षण प्राप्तकार्ताओं में से 12.9 प्रतिशत है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं हेतु बहुत अच्छी योजना है। इस योजना को पूरे भारत के संदर्भ में देखा जाए तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर रही है, परन्तु मध्यप्रदेश राज्य में देखा जाए तो अन्य राज्यों की अप्रेक्षा कम युवकों को प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा है, वहीं मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति के युवकों के प्रशिक्षण की बात करें तो इस योजना के तहत अपेक्षाकृत बहुत कम यवकों को प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा है। तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रारंभिक के वर्षा में अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षण की गति धीमी थी, परन्तु 2019-20 के बाद अनुसूचित जनजाति के युवकों के प्रशिक्षण प्राप्तकर्ताओं के प्रतिशत में तेजी से वृद्धि देखी गई है।

टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना:- यह योजना अनुसूचित जनजातियों को स्व-रोजगार करने एवं आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए 2022 में प्रारंभ की गई । इस योजना के अन्तर्गत स्वरोजगार के लिए 10 हजार से 1 लाख रूपये तक की सहायता राशि बैंकों के माध्यम से प्रदान की जाती है। लाभार्थी को लाभ हेतु सरकार की कुछ सर्तो का पालन करना होता है जो इस प्रकार है- लाभार्थी की आयु 18 से 55 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का पहले से ऋण ना लिया हो, आयकर दाता नहीं होना चाहिए (विभाग 2022-2023)। योजना में लाभ लेने वाले लाभार्थीयों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को समाप्त किया गया है अर्थात योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी का साक्षर होना आवश्यक नही है, परन्तु लाभार्थी को लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों का होना आवश्यक है जो इस प्रकार आधारकार्ड, पेन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति

प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, एक फोटो, बैक पास बुक होना आवश्यक है। यह सभी दस्तावेज होने के बाद ही हितग्राही लाभ लेने हेतु योजना के अन्तर्गत एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकता है (परस्ते अखिल, 2024)। इस योजना के माध्यम से अभी तक मध्यप्रदेश में 490 हितग्राहियों को पात्र मानकर योजना का लाभ दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आवेदन करने वालों की संख्या कम है। प्रदेश में टंट्या मामा योजना के अन्तर्गत 31 जनवरी 2024 तक आवेदन करने वालो की संख्या 6011 थी जिन्होंने योजना का लाभ लेने के उद्देश्य से आवेदन किया है। योजना के अन्तर्गत बैकों के द्वारा 699 आवेदन को मंजूरी दी गई है और उसमें से मात्र 490 हितग्राहियों को पात्र मानकर लाभान्वित किया गया है (सिरसाम, 2024)। योजना का लाभ अप्रेक्षाकृत बहुत कम नागरिकों को मिला इसका प्रमुख कारण बैंक है। बैंक उन नागरिकों को ऋण देना चाहता है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो और अनुसूचित जनजातीय की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और इस योजना के माध्यम से जनजातियों की आर्थिक स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हुआ।

कौशल विकास योजनाओं के समक्ष चुनौतियाँ

राज्य के अनुसूचित जनजातीय अशिक्षित एवं नगरीय क्षेत्र से दूर निवास करने के कारण जनजातियों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही कौशल विकास योजनाओं का लाभ किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है यह पता नहीं चल पाता। राज्य के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र में व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र मात्र 47 ही है, जो राज्य में अनुसूचित जनजाति में कौशल विकास विकसित नहीं होने के कारण को दर्शाता है। राज्य में प्रशिक्षण केन्द्र है वह भी अधिकतर नगरीय क्षेत्रों में है। जिस कारण युवाओं को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कई मील का रास्ता तय करके आना पड़ता है। जहां प्रशिक्षण केन्द्र है वहां सबसे बड़ी समस्या बहार से आने वाले विद्यार्थियों के आवास की होती है। आवास व्यवस्था न होने के कारण जनजातीय बच्चें प्रशिक्षण लेना नहीं चाहते है। जिस कारण आज के आधुनिक युग में कुशल श्रमिक की अत्यधिक मांग होने के बाद भी जनजातीय श्रमिक कौशल प्रशिक्षण के अभाव में कुशल श्रमिक बनने से वंचित हो रहे है।

निष्कर्ष

राज्य के अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए सरकार निरतर कार्य कर रही है, इस बात से इंकार नही किया जा सकता परन्तु अभी भी जनजाति नागरिकों के विकास के लिए प्रर्याप्त कौशल योजनाओं का विकास नहीं किया गया। मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् की बात करे तो यह योजना मध्यप्रदेश के जनजातियों हेतु अच्छी है। इस योजना में सरकार के साथ निजी कंपनीयां भी अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए कार्य कर रही है। प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने पर निजी कंपनीयां अपने ही कंपनी में प्लेसमेंट के रूप में रोजगार प्रदान करा रही है, जिस कारण अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार युवकों को रोजगार के तलाश में दर-दर भटकना नही पढ़ रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ग्रामीण क्षेत्र हेतु बहुत अच्छी योजना है। इस योजना के तहत मध्यप्रदेश के युवाओ को प्रशिक्षण तो प्रदान किया जा रहा है, परन्तु प्लेसमेंट के रूप में रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। तालिका क्रमांक 02 के अनुसार PMKVY के तहत मात्र 7.2 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के युवकों को रोजगार दिया गया है। यह योजना के खराब स्तर को दर्शाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के केन्द्र नगरिय एवं जिला स्तर पर होने के कारण अनूसूचित जनजाति के युवकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने में अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें यातायात और आवास मुख्यत् कौशल विकास योजना को प्रभावित कर रहे है। मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा अनुसूचित जनजाति के स्वरोजगार एवं आर्थिक कल्याण विकास को ध्यान में रखते हुए टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना प्रारंभ की गई परन्तु इस योजना से अनुसूचित जनजाति के ज्यादा नागरिक लाभान्वित नहीं हो पा रहे है। इस योजना के तहत अभी तक मात्र 409 हितग्राही को लाभ हुआ है। अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए उन्हें कौशल प्रशिक्षण देना आवश्यक है। प्रशिक्षण केन्द्र अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में होना चाहिए और प्रशिक्षण की रूप रेखा अनुसूचित जनजाति के पारंपरिक व्यवसाय एवं कौशल को ध्यान में रखते हुए विकास हेतु कौशल विकास की रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ सूची

Agrawal, Mini and K.S Thakur. "Impact of Pradhan Mantri Kaushal Vikash Yojana on the Productivity of Youth in Gwalior Region, India." Intarnational Journal of Recent Technology and Engineering 8.4 (2019): 801-806.

Jayakumar, A. and P. Palaniyammal. "Socio-Economics Status of Scheduled Tribals in Kalrayan Hills." Intarantional Journal of Research Granthalayah 4.3 (2016): 22-30.

Kumbhare, Bharti. "Economics Development of Tribal is Madhya Pradesh." Intarnational Journal Of Creative Research Thoughts 2.8 (2014): 1-5.

Kusugal, Pallavi S. and S. Nagarajan. "Economic Status of Tribal Women: A Case Study." Intarnational Journal of Scientific Research 2.11 (2013): 117-118.

Meher, Rajkishor. "Livelihood Poverty and Morbidity: A Study on Health and Socio-Economic Status of The Tribal Population in Orisa." Journal of Health Managment 9.3 (2007): 342-367.

Naik, Rupla and K. Dasaratharamaiah. "Education and Socio-EconomicDevelopment of Tribal Women A Study." Intarnational Journal of Economics 7 (2019): 9-19.

Paray, Mohd Rafi. "Status of Tribal Women In India With Soecial Refrence to the Socio-Economics and Educational Condition." Elementary Education Online 18.4 (2019): 2284-2292. <http://ilkogretim-online.org>.

Singh, Bhawar Pratap and Bimlesh Singh. "Role of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana for Employment Generation In Madhya Pradesh." Intarnational Journal of Multidisciplinary Research (2024): 620-632. <www.theacademic.in>.

Agarwal, R., Malhotra, G., Nisa, S., Pruthi, M., Kumar, P., & Lodhi, P. (2020). Different Handicrafts Training Programmes for Tribal People in Jharkhand: A Review. Available at SSRN 3375916.

Keerti Parmar, & Kalpana Jain. (2019). Effectiveness of Life Skills Traning for Enhancing Self-Esteem Among Tribal Youths. Intarnational Journal of Research and Review, 436-440. www.ijrrjournal.com.

Government of Madhya Pradesh. (n.d.).For School of Good Governance and Policy Analysis,Government of Madhya Pradesh https://www.mpsdma.mp.gov.in/uploads/media/Balaghat.pdf. Accessed on 14/11/2024.

Ministry of Tribal Affairs. (n.d.).National Tribal Migration Support Portal Background Note,Government of India,https://shramshakti.tribal.gov.in/Docs/Tribal%20Migration%20Portal%20Background%20note%20docx.pdf. Accessed on 15/11/2024.

Skill India. (2021-22). Annual Report, Schemes & Initiatives, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojna. Ministryof Skill Development & Entrepreneurship,61-104.

Operations, D. O. (2011). Census of India 2011 - Madhya Pradesh - Series 24 - Part XII A - District Census Handbook, Balaghat. Balaghat: Directorate of Census Operations Madhya Pradesh. Retrieved March Wednesday, 2024, from https://censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog/678.

जनजातीय कार्य विभाग. (2017-18). प्रशासकीय प्रतिवेदन, मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् (मेपसेट). भोपाल: मध्यप्रदेश शासन.

जनजातीय कार्य विभाग. (2022-23). प्रशासकीय प्रतिवेदन, मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् (मेपसेट). भोपाल: मध्यप्रदेश शासन.

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय. (2022). जनजातिय युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रायोगिक परियोजना आज से मध्यप्रदेश के भोपाल में शुरू. Delhi: PIB. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1825206.

अक्षय और विनोद सेन. "मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजातीय के प्रवासी श्रमीकों की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का एक अध्ययन." South Indian Journal of Social Sciences 22.1 (2024): 104-112.

श्रीवास्तव, ए. आर. एन. जनजातीय संस्कृति. भोपाल: मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल, मध्यप्रदेश, 2023.

हसनैन, नदीम. जनजातीय भारत. जवाहर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2022.

मित्तल पं.,"जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है मध्यप्रदेश सरकार", (2021) .https://www.mpinfo.org/Home/ArticleDetails?newsid=211111S2&fontname=Mangal&LocID=32&pubdate=11/11/2021.

https://www.mpsdma.mp.gov.in/uploads/media/Balaghat.pdf.

सिरसाम घ.जनजातीय युवाओं के लिए रोजगार व विकास की तीन नई योजनाएं, (2024) https://www.mpinfo.org/Home/Frm_Minister_Depart_Info?newsid=20240131N45&fontname=Mangal&LocID=32&catId=99&pubdate=01/31/2024.

परस्तेअखिल,2024.https://www.mpinfo.org/DistrictHome/TodaysNews?newsid=20240625N116&fontname=Mangal&LocID=32&pubdate=06/25/2024. Accessed on 14/11/2024.

Open Government Data (OGD) Platform India. Accessed on 18/11/2024.

State/UT-wise Number of Scheduled Tribes Candidates Trained under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) from 2015-16 to 2023-24 | Open Government Data (OGD) Platform India. Accessed on 18/11/2024.

State/UTs-wise Trained Candidate under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) from 2015-16 to 2021-22 | Open Government Data (OGD) Platform India, पीएमकेवीवाई 3.0 के बारे में. Accessed on18/11/2024.

कोशी तटबंध के किनारे जल जमाव: जीवोपार्जन और आजीविका की संभावनाएं

आनंद विजेता*
मुकुन्द कुमार**

सारांश

कोशी नदी, जिसे "बिहार का शोक" भी कहा जाता है, अपने तटबंधों के कारण जल जमाव की गंभीर समस्या उत्पन्न करती है। यह शोध पत्र कोशी तटबंध के किनारे जल जमाव के प्रभावों का विश्लेषण करता है और इसके बावजूद स्थानीय समुदायों के लिए जीवोपार्जन और आजीविका की संभावनाओं की खोज करता है। अध्ययन में जल प्रबंधन, कृषि नवाचार, और वैकल्पिक रोजगार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

बीज शब्द: कोशी नदी, बिहार का शोक, जल जमाव, तटबंध, आजीविका, जल प्रबंधन, कृषि नवाचार, वैकल्पिक रोजगार

प्रस्तावना

कोशी नदी भारत के बिहार राज्य और नेपाल के कुछ हिस्सों में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इसके तटबंध, जो बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए गए थे, अक्सर जल जमाव का कारण बनते हैं, जिससे कृषि भूमि प्रभावित होती है और स्थानीय लोगों की आजीविका पर संकट उत्पन्न होता है। यह शोध पत्र इस समस्या के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का आकलन करता है और संभावित समाधानों पर प्रकाश डालता है। आत्मविश्वास अक्सर प्रतिकूल होता है क्योंकि अहंकारी या अपनी ही शक्ति पर निर्भीक निर्भरता। आत्मविश्वास एक ज्ञान कारक है जो एथलेटिक कौशल को बढ़ा या सुधार सकता है। अधिकांश खेल कार्यक्रमों में मानसिक अभ्यास शामिल होता है, जो कम कौशल स्तर पर एथलीटों के आवश्यक विकास में मदद करता पाया गया है।

समस्याकाविवरण

कोशीतटबंधकेकारणजलनिकासीकीअपर्याप्तव्यवस्थासेखेतोंमेंपानीजमाहोजाताहै, जिससेफसलउत्पादनमेंकमीआतीहै।इससेनकेवलखाद्यसुरक्षाप्रभावितहोतीहै, बल्किग्रामीणअर्थव्यवस्थाभीचरमराजातीहै।

कोशीतटबंधकाइतिहास

ब्रिटिशशासनकेदौरानकोशीनदीकीबाढ़ोंकोनियंत्रितकरनेकेलिएतटबंधबनानेकाविचारसामनेआयाथा।हालांकि, ब्रिटिशसरकारनेतटबंधनिर्माणसेपरहेजकिया।उनकीचिंताथीकिकोशीकातेजबहावऔरप्राकृतिकअस्थिरतातटबंधोंकोतोड़सकतीहै, जिससेऔरअधिकतबाहीहोगी।उनकामाननाथाकिटूटनेसेहोनेवालीक्षतिकीभरपाईकरनामुश्किलहोगा।इसलिए, उन्होंनेनदीकोउसकेप्राकृतिकरूपमेंबहनेदेनेकाफैसलाकिया।भारतकीआजादीकेबादस्थितिबदलगई। 1954 मेंभारतसरकारनेनेपालकेसाथकोशीसमझौताकिया, जिसकेतहतकोशीनदीपरबांधऔरतटबंधबनानेकीयोजनाबनी।इसकाउद्देश्यबाढ़नियंत्रण, सिंचाई, जलजमावसेनिजातपानेकेलिएऔरजलविद्युतउत्पादनथा। 1958 से 1962 केबीचनेपाल-भारतसीमाकेपासभीमनगरमेंकोशीबैराज (बांध) बनायागया, जिसमें 56 फाटकहैं।इसकेबादभारतनेनदीकेदोनोंओरतटबंधोंकानिर्माणशुरूकिया।पूरबमेंबीरपुरसेकोपरियातकलगभग 125 किमीऔरपश्चिममेंभारदहसेघोघोपुरतकलगभग 126 किमीलंबेतटबंध 1963-64 तकबनकरतैयारहुए।इनतटबंधोंकोनदीकीधाराकोनियंत्रितकरने, बाढ़सेसुरक्षाप्रदानकरने, जलजमावसेनिजातपानेकेलिएऔरकृषिभूमिकोउपजाऊबनानेकेलिएडिजाइनकियागयाथा।अभियंताओंनेअनुमानलगायाकियहतटबंध 9 लाखक्यूसेक (घनफीटप्रतिसेकंड) पानीकेबहावकोझेलसकेगाऔरइसकीआयु 25 वर्षहोगी।तटबंधोंकेबीचकीचौड़ाईकुछस्थानोंपर 20 किमीतकरखीगई।

*आनंद विजेता, सलाहकार, आपदा प्रबंधन, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

**मुकुन्द कुमार, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र।

जलजमावऔरतटबंधोंकाटूटनाऔरसमस्याएँ

तटबंधबननेकेबादसेयह 8 बारटूटचुकाहै, जिससेभारीतबाहीहुई।पहलीबारयह 1963 मेंटूटा, फिर 1968 मेंपांचस्थानोंपरक्षतिग्रस्तहुआ।अन्यप्रमुखघटनाएँ 1971, 1981, 1984, 1987, 1991, और 2008 मेंहुईं। 2008 मेंनेपालकेकुसहामेंतटबंधटूटनेसेबिहारके 50 लाखलोगप्रभावितहुएथे।टूटनेकामुख्यकारणनदीमेंगाद (सिल्ट) कातेजीसेजमावहै, जोजलस्तरकोबढ़ाताहैऔरतटबंधोंपरदबावडालताहै।गादकेकारणनदीकातलऊँचाहोतागया, जिससेतटबंधोंकोबार-बारऊँचाकरनापड़ा।तटबंधोंनेबाढ़कोकुछहदतकनियंत्रितकियाऔरसिंचाईवजलविद्युतकेलिएलाभपहुँचाया, लेकिनइनकेदुष्परिणामभीसामनेआए।तटबंधोंकेबीचबसेगाँवोंकोहरसालबाढ़, कटाव , जलजमावऔरविस्थापनकासामनाकरनापड़ताहै।जलजमावऔरगादकाफैलावरुकनेसेनदीकीप्राकृतिकभूमिनिर्माणप्रक्रियाबाधितहुई।पर्यावरणविदों कामाननाहैकितटबंधअस्थायीसमाधानहैं, जोदीर्घकालिकरूपसेनदीकीअस्थिरताकोबढ़ातेहैं।

वर्तमानस्थिति

आजभीकोशीतटबंधबिहारऔरनेपालकेलिएएकजटिलमुद्दाहै। 2024 मेंभारीबारिशकेकारणबैराजकेसभी 56 फाटकखोलनेपड़ेऔर 6.81 लाखक्यूसेकपानीछोड़ागया, जिससेबिहारमेंफिरसेबाढ़काखतराबढ़गया।तटबंधोंकीमरम्मत , जलजमावऔररखरखावएकसततचुनौतीबनीहुईहै।कोशीतटबंधकाइतिहासमानवप्रयासऔरप्रकृतिकीशक्तिकेबीचसंघर्षकीकहानीहै।यहबाढ़नियंत्रण केलिएबनायागयाथा, लेकिनगादजमाव, जलजमावऔरनदीकीअस्थिरताकेकारणयहबार-बारविफलहुआ।यहदर्शाताहैकिनदीप्रबंधनकेलिएकेवलइंजीनियरिंगसमाधानपर्याप्तनहींहैं; इसकेलिएव्यापकऔरप्रकृति-सम्मतनीतियोंकीजरूरतहै।

प्रश्नयहहैकिक्याइसजलजमावकोएकअवसरकेरूपमेंबदलाजासकताहै?

शोधपद्धति

इसअध्ययनमेंद्वितीयकडेटा (सरकारीरिपोर्ट्स, शोधपत्र) औरप्राथमिकडेटा (प्रभावितक्षेत्रोंकेकिसानोंसेसाक्षात्कार) काउपयोगकियागयाहै।कोशीक्षेत्रकेतीनगाँवों - सुपौल, मधेपुरा, औरसहरसा - सेजानकारीएकत्रकीगई।

विश्लेषण

1. कृषिपरप्रभाव: जलजमावकेकारणधानऔरगेहूँजैसीपारंपरिकफसलोंकीपैदावारमें 40% तककीकमीदेखीगई।
2. जीवोपार्जनपरप्रभाव: अधिकांशपरिवारोंकीआयमेंकमीआई, जिसकेकारणपलायनबढ़ा।

जलजमावसेउत्पन्नसंभावनाएं

मछलीपालन:

जलजमावकीपरिस्थितियोंमेंजलभराववालेक्षेत्रोंकोमछलीपालनकेलिएउपयुक्तबनायाजासकताहै।इससेस्थानीयसमुदायकेलिएरोजगारसृजनहोगाऔर मछलीउत्पादनसेआयकास्रोतमिलेगा।

कृषिऔरजलवायुअनुकूलकृषि:

1. जलजमाववालेक्षेत्रोंमेंतटीयऔरपानीसहिष्णुफसलोंकाउत्पादनकियाजासकताहै, जैसेकिचावल, दलहन, साग, औरजल-प्रेमीपौधे।
2. कोशीतटबंधकेजलजमाववालेक्षेत्रोंमेंमखानाऔरसिंघाड़ाकीखेतीकीसंभावनाओंकाअध्ययनऔरविस्तार।
3. सिंघाड़ाऔरमखानाकीखेतीकोस्थानीयकिसानोंकेलिएआर्थिकरूपसेलाभकारीऔरटिकाऊबनाना।
4. जलजमावकाउपयोगप्राकृतिकसंसाधनकेरूपमेंकरनाऔरपर्यावरणीयसंतुलनबनाएरखना।
5. ग्रामीणसमुदायकेलिएरोजगारसृजनऔरकृषिविविधीकरणकेअवसरप्रदानकरना।

मखानाऔरसिंघाड़ाकीखेतीकेफायदे:

मखाना:

1. मखानाएकजलोतरफसलहै, जोनदियोंऔरतालाबोंकेपानीमेंउगतीहै।
2. मखानाकोउगानेकेलिएस्थिरजलस्तरकीआवश्यकताहोतीहै, औरजलजमावकेकारणऐसेप्राकृतिकस्थितियाँआसानीसेउत्पन्नहोसकतीहैं।
3. मखानाकीखेतीसेकिसानअच्छीआयप्राप्तकरसकतेहैंक्योंकियहउच्चमूल्यवालीफसलहैऔरइसकीखपतभारतमेंहीनहीं, बल्किविदेशोंमेंभीहोतीहै।
4. मखानाकाउपयोगस्वास्थ्यवर्धकस्नैक्स, मिठाइयोंऔरविभिन्नआयुर्वेदिकउत्पादोंमेंकियाजाताहै, जोइसकीबाजारमांगकोबढ़ाताहै।

सिंघाड़ा:

1. सिंघाड़ाएकजलजमावक्षेत्रमेंउगनेवालीबहुवर्षीयफसलहै, जोपानीमेंउगतीहैऔरइसकेकंद (roots) कोखाद्यकेरूपमेंप्रयोगकियाजाताहै।
2. सिंघाड़ाकीखेतीपानीमेंहोतीहै, औरइसकेउत्पादनसेकिसानकोअतिरिक्तआयहोतीहै।
3. सिंघाड़ाकाउपयोगकच्चेरूपमेंऔरपकाकरकियाजासकताहै।यहकैलोरीमेंउच्चऔरपोषणसेभरपूरहोताहै, औरभारतीयबाजारोंमेंइसकीमांगअच्छीरहतीहै।
4. सिंघाड़ाकीखेतीजलमग्नक्षेत्रोंमेंभूमिकीआवश्यकताकोकमकरतीहैऔरपर्यावरणीयदृष्टिसेयहएकटिकाऊविकल्प है।
5. जलवायुअनुकूलखेतीजैसे "स्ट्रॉबेरी" और "वाटर-रेसिस्टेंटफसलें" जोपानीकेस्तरमेंउतार-चढ़ावसहनकरसकतीहैं।

जलवायुस्मार्टजलसंचयनऔरसिंचाईप्रणालियाँ:

1. जलजमावसेफसलकेलिएपानीकीअधिकताहोसकतीहै, लेकिनयहपानीसहीतरीकेसेसंचितऔरउपयोगकियाजासकताहै।इसकार्यकेलिएजलसंचयनकेतरीकोंकाअनुसंधानऔरकार्यान्वयनकियाजासकताहै, जैसेकितालाब, कुएंऔरजलाशयबनाना।

पर्यटनऔरइको-टूरिज्म:

2. जलजमावकेकारणजोप्राकृतिकसुंदरताउत्पन्नहोतीहै, उसेपर्यटकोंकेआकर्षणकेरूपमेंविकसितकियाजासकताहै।इससेस्थानीयस्तरपररोजगारऔरआयकीसंभावनाएंबढ़सकतीहैं।
3. पारंपरिककला, संस्कृतिऔरहस्तशिल्पउद्योगकोबढ़ावादेनेकेलिएइको-टूरिज्मकोएकविकल्पकेरूपमेंदेखाजासकताहै।

सौरऊर्जापरियोजनाएं:

1. जलजमावकेकारणउत्पन्नउपयुक्तस्थानोंपरसौरपैनललगाएजासकतेहैं, जहांदिनभरसूर्यकीपर्याप्तरोशनीमिलतीहै।यहऊर्जाउत्पादनकीनईदिशाखोलसकताहै।

कोशीतटबंधकेकिनारेखस, बांस, लेमनग्रासआदिसेआजीविकाएवंजीवकोपार्जन

फसलचयनएवंखेती

2. **खस (Vetiver)**: सुगंधिततेलऔरमृदासंरक्षणकेलिएउपयोगी।
3. **बांस (Bamboo)**: हस्तशिल्प, निर्माणसामग्रीऔरकागजउद्योगमेंमांग।
4. **लेमनग्रास (Lemongrass)**: सुगंधिततेलऔरहर्बलउत्पादोंमेंउपयोग।
5. **मेंथा (Mentha)**: औषधीयगुणोंसेयुक्तएवंउच्चबाजारमांग।

निष्कर्ष

कोशीतटबंधकेकिनारेजलजमावएकचुनौतीतोहै, परंतुउचितनीतियोंऔरनवाचारकेसाथइसेअवसरमेंबदलाजासकताहै।सरकारऔरस्थानीयसमुदायोंकोमिलकरजलप्रबंधनऔरवैकल्पिकआजीविकाकेलिएकदमउठानेचाहिए।

1. जलनिकासीकेलिएबेहतरनहरप्रणालीकाविकास।
2. मखानाऔरमत्स्यपालनकेलिएप्रशिक्षणऔरवित्तीयसहायता।
3. स्थानीयस्तरपरसहकारीसमितियोंकागठन।

सन्दर्भ सूची

सरकारी दस्तावेज , एनजीओ रिपोर्ट, बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग , कोशी बाढ़ प्रबंधन से संबंधित अध्ययन

यह समाचार लेख कोशी नदी के बदलते मार्ग और तटबंधों के कारण जल जमाव की समस्या पर चर्चा करता है, जो स्थानीय आजीविका को प्रभावित करता है।

पर्यावरण संवारती भारत की नदियां - India Water Portal (हिन्दी)

URL: hindi.indiawaterportal.org/node/54291

विवरण: कोशी नदी के हाल के बाढ़ प्रभावों और तटबंधों की स्थिति पर समाचार, जो जल जमाव और जीवोपार्जन के लिए चुनौतियों और अवसरों को दर्शाता है।

जल क्रांति अभियान - SATHEE (Chapter 04 Water Resources)

कोसी पर बाढ़ नियंत्रण के उपाय - India Water Portal

URL: hindi.indiawaterportal.org (विशिष्ट लेख का लिंक अनुपलब्ध, सामान्य स्रोत)

खेल परिधान अनुसंधान में नवीनतम प्रवृत्तियाँ: एक ग्रंथसूची विश्लेषण

सूरज कुमार *
डॉ. नेहा सिंह **
अनुपम कुमार सिंह ***
राहुल कुमार पासवान ****
शीतलटोपनो *****
प्रोफेसर. राजीव चौधरी ******

सारांश

खेल परिधान का विकास वस्त्र प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता व्यवहार और प्रदर्शन-आधारित डिजाइन नवाचारों में हुई प्रगति से प्रभावित हुआ है। यह अध्ययन खेल परिधान में उभरते शोध प्रवृत्तियों का पता लगाने के लिए ग्रंथसूची विश्लेषण (बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस) का उपयोग करता है, जिसमें कार्यात्मक डिजाइन, उपभोक्ता प्राथमिकताएं, स्मार्ट वस्त्र और स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) जैसे प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। डेटा को वेब ऑफ साइंस (WoS) डेटाबेस से संकलित किया गया और विद्वतापूर्ण नेटवर्क तथा उद्धरण पैटर्न को मानचित्रित करने के लिए VOSviewer जैसे ग्रंथसूची उपकरणों का उपयोग किया गया है। अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि प्रदर्शन-वर्धक सामग्रियों, दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए अनुकूल खेल परिधानों और उद्योग में नैतिक निर्माण प्रक्रियाओं पर बढ़ता जोर दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, हैलोक्रोमिक फैब्रिक्स और वस्त्र-आधारित सतही इलेक्ट्रोमायोग्राफी (sEMG) सेंसर सहित स्मार्ट वस्त्र, खेल विज्ञान में महत्वपूर्ण नवाचारों के रूप में उभर रहे हैं। हालांकि इन प्रगतियों के बावजूद, विविध एथलेटिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले समावेशी खेल परिधानों की उपलब्धता में अब भी कुछ अंतराल बने हुए हैं। यह अध्ययन भविष्य के खेल परिधान अनुसंधान में बायोमैकेनिक्स, सामग्री विज्ञान और स्थिरता के एकीकरण के महत्व को उजागर करता है। इस विश्लेषण से प्राप्त अंतर्दृष्टियाँ उन नवाचारों की नींव प्रदान करती हैं जो खेल परिधान डिजाइन में आराम, प्रदर्शन और समावेशिता को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं।

बीज शब्द: खेलपरिधान, ग्रंथसूचीविश्लेषण, स्मार्टवस्त्र, उपभोक्ताव्यवहार, स्थिरता, अनुकूलखेलपरिधान

प्रस्तावना

खेल परिधान का एक समृद्ध इतिहास है, जो खेलों के विकास और सामाजिक परिवर्तनों कि गहराई से जुड़ा हुआ है। इसे प्रारंभ में केवल कार्यक्षमता के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन धीरे-धीरे यह पहचान और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया। 19वीं सदी के अंत में, महिलाओं के एक्टिववियर में नए प्रयोग, जैसे ब्लूमर और छोटी स्कर्ट, आधुनिक स्पोर्ट्स पोशाक की नींव बने। 1930 के दशक तक, क्लेयर पॉटर और क्लेयर मैककार्डेल जैसे डिजाइनरों ने कपास और जर्सी जैसे व्यावहारिक कपड़ों के उपयोग से स्पोर्ट्सवियर में क्रांतिकारी बदलाव किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यह उद्योग तेजी से विकसित हुआ और आराम तथा गतिशीलता पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। 1970 और 1980 के दशक में एक्टिववियर की लोकप्रियता बढ़ी, जिसमें नाइकी और एडिडास जैसी कंपनियों ने प्रदर्शन को बेहतर बनाने वाले नए मटेरियल्स पेश किए। इसी दौरान, महिलाओं के लिए स्पोर्ट्स ब्रा डिजाइन की गई, जिससे खेलों में भागीदारी अधिक सुविधाजनक बनी, और स्पोर्ट्स जूतों में कुशनिंग व ग्रिप जैसी तकनीकों का विकास हुआ। 1990 के दशक में स्पोर्ट्सवियर में व्यावहारिकता को प्राथमिकता दी गई, जबकि 2000 के दशक की शुरुआत में फैशन और कार्यक्षमता के संयोजन से एथलीजर का उदय हुआ। 2010 के दशक में स्थिरता की ओर बदलाव हुआ, जिसमें पुनर्नवीनीकरण सामग्रियों और पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन पर जोर दिया गया। आज, स्पोर्ट्सवियर उन्नत तकनीकों, जैसे एआई और स्मार्ट फैब्रिक्स, को शामिल कर रहा है, जिससे प्रदर्शन और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के बीच संतुलन बना रहे है। स्पोर्ट्सवियर का यह विकास बदलते सामाजिक मूल्यों को दर्शाता है, जिसमें फैशन, कार्यक्षमता और स्थिरता का समावेश है, ताकि आधुनिक एथलीटों और उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके [Blue Associates Sportswear]।

*सूरज कुमार, शोधार्थी, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
**डॉ. नेहा सिंह, विभागाध्यक्ष, फैशन और टेक्सटाइल विभाग, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
***अनुपम कुमार सिंह, शोधार्थी, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
****राहुल कुमार पासवान, शोधार्थी, मैट्स विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
*****शीतलटोपनो, शोधार्थी, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
******डॉ. राजीव चौधरी, प्रोफेसर, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।

खेल परिधान एथलेटिक प्रदर्शन, आराम और समावेशिता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यधारा के खेल परिधान आमतौर पर फिट, कार्यक्षमता और सौंदर्यशास्त्र पर केंद्रित होते हैं, लेकिन दिव्यांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं को उद्योग में अब भी व्यापक रूप से अनदेखा किया जाता है। अनुकूलन योग्य परिधान (एडेप्टिव क्लोदिंग), विशेष रूप से खेल परिधान जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में, इष्टतम गतिशीलता, पहुंच (एक्सेसिबिलिटी) और आराम सुनिश्चित करने के लिए एक उपयोगकर्ता-केंद्रित डिज़ाइन दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। किसी व्यक्ति की आत्मसम्मान और पहचान पर परिधान का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि समावेशी डिज़ाइन सहायक उपकरणों से जुड़े कलंक (स्टिग्मा) को कम करने में सहायक हो सकते हैं। अनुकूल खेलों (एडेप्टिव स्पोर्ट्स) जैसे कि व्हीलचेयर रग्बी में, विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए खेल परिधान एक खिलाड़ी के अनुभव को काफी प्रभावित करते हैं। शोध से पता चलता है कि व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए परिधान साधारण खेल परिधानों की तुलना में अधिक आरामदायक और संतोषजनक होते हैं [Bragança et al., 2018]।

खेल परिधान, विशेष रूप से जूते, बुनियादी सुरक्षा से लेकर उच्च प्रदर्शन वाले उपकरणों तक विकसित हो चुके हैं, फिर भी फिट और आराम से संबंधित समस्याएं बनी हुई हैं। तकनीकी प्रगति के बावजूद, कई लोग अनुचित रूप से फिट होने वाले जूते पहनते हैं, जिससे पैरों से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। फुटवियर पर किए गए शोध मुख्य रूप से हाई हील्स पर केंद्रित रहे हैं, जिससे अनुपयुक्त खेल जूतों का एथलेटिक प्रदर्शन पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने में एक महत्वपूर्ण अंतर बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, फैशन ट्रेंड अक्सर फुटवियर के चयन को प्रभावित करते हैं, जिससे पैरों के आकार और जूतों की संरचना के बीच असंतुलन पैदा हो जाता है। चूंकि लगभग आधी आबादी अनुचित जूते पहनती है, इसलिए प्रदर्शन को बढ़ाने, चोटों को कम करने और खेलों में आराम सुधारने के लिए साक्ष्य-आधारित दिशानिर्देशों की आवश्यकता है [Branthwaite & Chockalingam, 2019]। बढ़ती जागरूकता के बावजूद, कई मौजूदा खेल परिधान डिज़ाइन दिव्यांग एथलीटों की विशिष्ट शारीरिक संरचना और गति पैटर्न को ध्यान में रखने में विफल रहते हैं। पारंपरिक साइजिंग सिस्टम अक्सर व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं की शारीरिक विविधताओं को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे असुविधा और गतिशीलता में बाधा उत्पन्न होती है [Kozey & Das, 2004]। अनुचित रूप से फिट किए गए खेल परिधान शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे अंततः प्रदर्शन और सामाजिक समावेशन (सोशल इनक्लूजन) प्रभावित होता है [Kabel et al., 2017]।

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कार्यात्मक परिधान (फंक्शनल क्लोदिंग) न केवल बायोमैकेनिकल और शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करे, बल्कि उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए चिकित्सा, जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलॉजी) और सामग्री विज्ञान (मटेरियल साइंस) जैसे क्षेत्रों में हुई प्रगति को भी समाहित करे [Curteza et al., 2014]।

वैश्विक खेल परिधान उद्योग ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसे स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति बढ़ती जागरूकता ने प्रेरित किया है। विभिन्न सक्रिय परिधान (एक्टिववियर) उत्पादों में, स्पोर्ट्स ब्रा शारीरिक गतिविधियों के दौरान स्तनों को सहारा देने और आराम बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालांकि इनका प्राथमिक उद्देश्य अत्यधिक स्तन गति को कम करना है, लेकिन विशेष रूप से अंडरबैंड और कंधे की पट्टियों पर पड़ने वाले दबाव को लेकर इसके शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर व्यापक चर्चा जारी है [Yick et al., 2022]। हालांकि, अब भी एक महत्वपूर्ण अंतर बना हुआ है, जहां ऐसा विशेषीकृत खेल परिधान उपलब्ध नहीं है जो कार्यात्मक और सौंदर्यात्मक (एस्थेटिक) दोनों अपेक्षाओं को पूरा कर सके [Bragança et al., 2015]। खेल परिधानों का विकास वस्त्र प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति से काफी प्रभावित हुआ है, विशेष रूप से स्मार्ट टेक्सटाइल्स के विकास से, जो पर्यावरणीय उद्दीपन (स्टिमुली) को पहचानने और उसके अनुसार प्रतिक्रिया देने में सक्षम हैं। ये टेक्सटाइल्स निष्क्रिय (पैसिव) और सक्रिय (एक्टिव) दो प्रकार के होते हैं, जहां निष्क्रिय टेक्सटाइल्स केवल सेंसर के रूप में कार्य करते हैं, जबकि सक्रिय टेक्सटाइल्स सेंसर और एक्टुएटर दोनों की भूमिका निभाते हैं और तापमान, नमी, pH तथा यांत्रिक तनाव (मैकेनिकल स्ट्रेस) जैसे बाहरी कारकों के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। इन नवाचारों में, हैलोक्रोमिक टेक्सटाइल्स ने काफी ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि ये pH में बदलाव के प्रति प्रतिक्रिया देते हुए रंग बदलने की क्षमता रखते हैं, जिससे एथलीटों के लिए वास्तविक समय (रियल-टाइम) में शारीरिक निगरानी संभव हो पाती है [Ribeiro et al., 2023]। हैलोक्रोमिक फैब्रिक्स एक गैर-आक्रामक (नॉन-इनवेसिव), विश्वसनीय और उपयोगकर्ता के अनुकूल विकल्प प्रदान करते हैं, जिससे एथलीटों की शारीरिक स्थिति को प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा के दौरान प्रभावी ढंग से मॉनिटर किया जा सकता है [Pakolpakçıl et al., 2020]।

बढ़ती हुई बुद्धिमान खेल परिधानों (इंटेलिजेंट स्पोर्ट्सवियर) की मांग के साथ, स्मार्ट टेक्सटाइल तकनीक में निरंतर अनुसंधान और नवाचार आवश्यक है। खेल विज्ञान में हैलोक्रोमिक टेक्सटाइल्स और उत्तरदायी सेंसर (रिस्पॉन्सिव सेंसर) का एकीकरण एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है, जो प्रौद्योगिकी और मानव प्रदर्शन के बीच की खाई को पाटता है [Trovato et al., 2022]।

टेक्सटाइल-आधारित सतही इलेक्ट्रोमायोग्राफी (sEMG) इलेक्ट्रोड्स के विकास ने मांसपेशी थकान (मसल फैटीग) आकलन की प्रक्रिया को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया है, जिससे खेल परिधानों के लिए गैर-आक्रामक (नॉन-इनवेसिव) और अनुकूलनीय समाधान संभव हो पाए हैं। संवाहक पॉलिमर (कंडक्टिव पॉलिमर्स), इलास्टोमर्स और नवीन सामग्रियों (इनोवेटिव मटेरियल्स) में हुई प्रगति सेंसर की सटीकता, स्थायित्व और आराम को बढ़ाती है, जिससे यह एथलेटिक प्रदर्शन निगरानी के लिए उपयुक्त बनता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), नैनोटेक्नोलॉजी और IoT (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) के एकीकरण से खेल विज्ञान में इनकी संभावनाएँ और अधिक बढ़ जाती हैं। अनुसंधान की प्रगति के साथ, टेक्सटाइल-आधारित sEMG नवाचार प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी (लैब टेक्नोलॉजी) और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों (रियल-वर्ल्ड

एप्लिकेशंस) के बीच की दूरी को कम करने के लिए तैयार हैं, जिससे खेल परिधानों का भविष्य पूरी तरह बदल जाएगा [Medagedara et al., 2024]।

खेल परिधानों में संपीड़न परिधान (कंप्रेशन गारमेंट्स) रक्त परिसंचरण (ब्लड सर्कुलेशन) को बढ़ाकर, हृदय गति को स्थिर करके और तेज़ स्वायत्त पुनर्प्राप्ति (ऑटोनॉमिक रिकवरी) को बढ़ावा देकर एथलीटों की रिकवरी में सहायता करते हैं। ये हेमोडायनामिक मापदंडों (हृदय और रक्त प्रवाह से संबंधित संकेतकों) और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र (ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम) की गतिविधि में सुधार करते हैं, जिससे व्यायाम के बाद शीघ्र पुनर्स्थापन में मदद मिलती है। हालांकि, इनका हृदय संबंधी कार्यप्रणाली (कार्डियोवास्कुलर फंक्शन) पर सटीक प्रभाव अभी भी अस्पष्ट है, जिससे इनके एथलेटिक प्रदर्शन में अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने हेतु और अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है [Piras & Gatta, 2017]।

ठंडे पानी में डूबना (कोल्ड-वॉटर इमर्शन) जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है, जहां परिधान थर्मल सुरक्षा प्रदान करते हैं लेकिन तैराकी के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। 12°C तापमान वाले पानी में आत्म-रक्षा के लिए तैरना संभव है, जब तक कि हाइपोथर्मिया प्रभावी न हो जाए, लेकिन परिधान पानी में घर्षण (ड्रैग) को बढ़ाते हैं और सहनशक्ति (एंड्यूरेंस) को कम कर सकते हैं। भविष्य के अनुसंधान को इन्सुलेशन (ऊष्मीय सुरक्षा) और गतिशीलता (मोबिलिटी) के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सर्वोत्तम रणनीतियों की खोज करनी चाहिए [Bowes et al., 2016]। उच्च तापमान में परिधान के रंग पर किए गए शोध से पता चला है कि काले वस्त्र सफेद वस्त्रों की तुलना में हीट स्ट्रेस को अधिक प्रभावी ढंग से कम कर सकते हैं, संभवतः बेहतर वेंटिलेशन और ऊष्मा विनिमय (हीट एक्सचेंज) के कारण। इन कारकों की समझ खेल परिधानों के उन्नत डिजाइनों को विकसित करने में मदद करती है, जिससे विभिन्न परिस्थितियों में आराम और प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है [Nguyen & Tokura, 2000] ।

खेल परिधान उद्योग नैतिक और उत्तरदायी (एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल) प्रथाओं की ओर विकसित हो रहा है। नाइकी (Nike) की यात्रा आलोचना से लेकर कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व (कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी) में नेतृत्व तक यह दर्शाती है कि कंपनियाँ श्रम स्थितियों और स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) में सुधार कैसे कर सकती हैं। आज, ब्रांड नैतिक प्रथाओं को केवल एक दायित्व (ऑब्लिगेशन) नहीं बल्कि सफलता के लिए आवश्यक मानते हैं। जैसे-जैसे जागरूकता बढ़ रही है, उद्योग निष्पक्ष श्रम, पारदर्शिता और स्थिरता पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिससे खेल परिधानों के लिए एक बेहतर भविष्य आकार ले रहा है [Zadek, 2004]।

ग्रंथसूची विश्लेषण

ग्रंथसूची विश्लेषण एक मात्रात्मक शोध विधि है, जिसका उपयोग विद्वतापूर्ण साहित्य का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। यह किसी विशेष अध्ययन क्षेत्र में प्रचलित प्रवृत्तियों (Trends) की पड़ताल करने और उभरते हुए विकास की पहचान करने में सहायता करता है [Kumar & Choudhary, 2024]। ग्रंथसूची विश्लेषण एक मात्रात्मक शोध तकनीक है, जो विद्वतापूर्ण साहित्य के निर्माण और प्रसार की जांच के लिए सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करती है। इसमें उद्धरण मीट्रिक्स (citation metrics), सह-लेखक नेटवर्क (co-authorship networks) और प्रकाशन स्रोतों (publication sources) सहित डेटा को व्यवस्थित रूप से एकत्रित और मूल्यांकित किया जाता है, जिससे शोध प्रभाव और विद्वतापूर्ण प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है। अकादमिक कार्यों के विकास और उनके प्रभाव क्षेत्र पर नज़र रखते हुए, यह दृष्टिकोण वैज्ञानिक उत्पादन और ज्ञान प्रसार के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। चूंकि शोध प्रकाशनों की मात्रा लगातार बढ़ रही है, इसलिए ग्रंथसूची विधियाँ अकादमिक योगदानों का मूल्यांकन करने और वैज्ञानिक शोध की दिशा को मार्गदर्शित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं [Jiang et al., 2023]।

वेब ऑफ साइंस (WoS) डेटाबेस एक प्रमुख शोध प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, जो प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला और मानविकी सहित विभिन्न विषयों में विद्वतापूर्ण जानकारी तक व्यापक पहुँच प्रदान करता है। इसे एक वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय उद्धरण सूचकांक (citation index) के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसमें उच्च प्रतिष्ठित स्रोतों से प्राप्त प्रकाशन शामिल होते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यह मंच होस्ट किए गए अकादमिक सामग्री की विश्वसनीयता और प्रमाणिकता बनाए रखता है [Wei et al., 2022] ।

विभिन्न ग्रंथसूची उपकरण, जैसे CiteSpace, VoSviewer, R में उपलब्ध "bibliometrix" पैकेज, और HistCite, साहित्य विश्लेषण के परिणामों को देखने और व्याख्या करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। ये उपकरण शोधकर्ताओं को विद्वतापूर्ण नेटवर्क का मानचित्रण करने, उभरते रुझानों की पहचान करने और उद्धरण पैटर्न का विश्लेषण करने में सहायता करते हैं, जिससे अकादमिक शोध परिदृश्य को समझना आसान हो जाता है [Wu et al., 2022] ।

शोध से संबंधित सामग्री एवं विधियाँ

डेटा का संग्रहण

वर्तमान अध्ययन में वेब ऑफ साइंस (WoS) डेटाबेस से 24 जनवरी 2025 तक प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके ग्रंथसूची विश्लेषण (Bibliometric Analysis - BA) किया गया। WoS को इसकी मान्यता प्राप्त विश्वसनीयता और अकादमिक शोध में व्यापक उपयोग के कारण चुना गया, क्योंकि इसे उच्च-गुणवत्ता की ग्रंथसूची संबंधी जानकारी का एक विश्वसनीय स्रोत माना जाता है।

वर्ष-17, अंक – 01 जनवरी-जून – 2025 ISSN – 0974-0118

प्रासंगिक डेटा की पहचान

शोधकर्ताओं ने वेब ऑफ साइंस (WoS) प्लेटफ़ॉर्म के खोज फ़ीचर का उपयोग करके, सावधानीपूर्वक चयनित कीवर्ड और मानकीकृत मानदंडों को लागू किया। इस प्रक्रिया के माध्यम से, डेटा सेट संख्या 344 को पहचाना और निकाला गया। यह व्यवस्थित दृष्टिकोण खेल परिधान (Sports Apparel) से संबंधित सटीक और प्रासंगिक डेटा प्राप्त करने में सहायक रहा।

डेटा स्क्रीनिंग और सफाई

प्राप्त 344 रिकॉर्ड में से, आठ को दस्तावेज़ प्रकार और भाषा मानदंड के आधार पर बाहर कर दिया गया। इसमें से पाँच रिकॉर्ड को हटा दिया गया क्योंकि वे संपादकीय सामग्री (Editorial Materials), समाचार लेख (News Items), और सम्मेलन सारांश (Meeting Abstracts) थे। इसके अतिरिक्त, तीन रिकॉर्ड को इसलिए हटाया गया क्योंकि केवल अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित अध्ययनों को विश्लेषण के लिए शामिल किया गया था।

समावेशन के लिए रिकॉर्ड मूल्यांकन

अगले चरण में, कुल 336 डेटासेट की गहन समीक्षा की गई। सभी डेटासेट अध्ययन के समावेशन मानदंडों को पूरा करते थे, जिससे उनकी प्रासंगिकता सुनिश्चित हुई।

डेटा विश्लेषण

इस अध्ययन का उद्देश्य खेल परिधान से संबंधित विशिष्ट सूचक शब्द (Keywords) की घटनाओं (Occurrences) का विश्लेषण करना था, ताकि इस क्षेत्र में प्रमुख शोध विषयों की पहचान की जा सके। इसके अतिरिक्त, यह अध्ययन इस क्षेत्र में ज्ञान के विकास और विस्तार को समय के साथ चित्रित करने पर केंद्रित था।

ग्रंथसूची विश्लेषण (Bibliometric Analysis - BA) का उपयोग करके साहित्यिक पैटर्न की जांच की गई और प्रकाशनों, लेखकों और सूचक शब्द (Keywords) के बीच संबंधों को मैप किया गया। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, VOSviewer 1.6.19 सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया गया, जिससे बड़े डेटा सेटों को संसाधित करने और दृश्य निरूपण (visual representations) उत्पन्न करने में सहायता मिली। इसमें नेटवर्क मैप, ओवरले मैप और डेंसिटी मैप जैसी तकनीकों का उपयोग किया गया, जिससे शोध परिदृश्य (Research landscape) का एक व्यापक अवलोकन प्राप्त हुआ। इन विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणों ने भविष्य के अध्ययन और प्रगति को दिशा देने में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की।

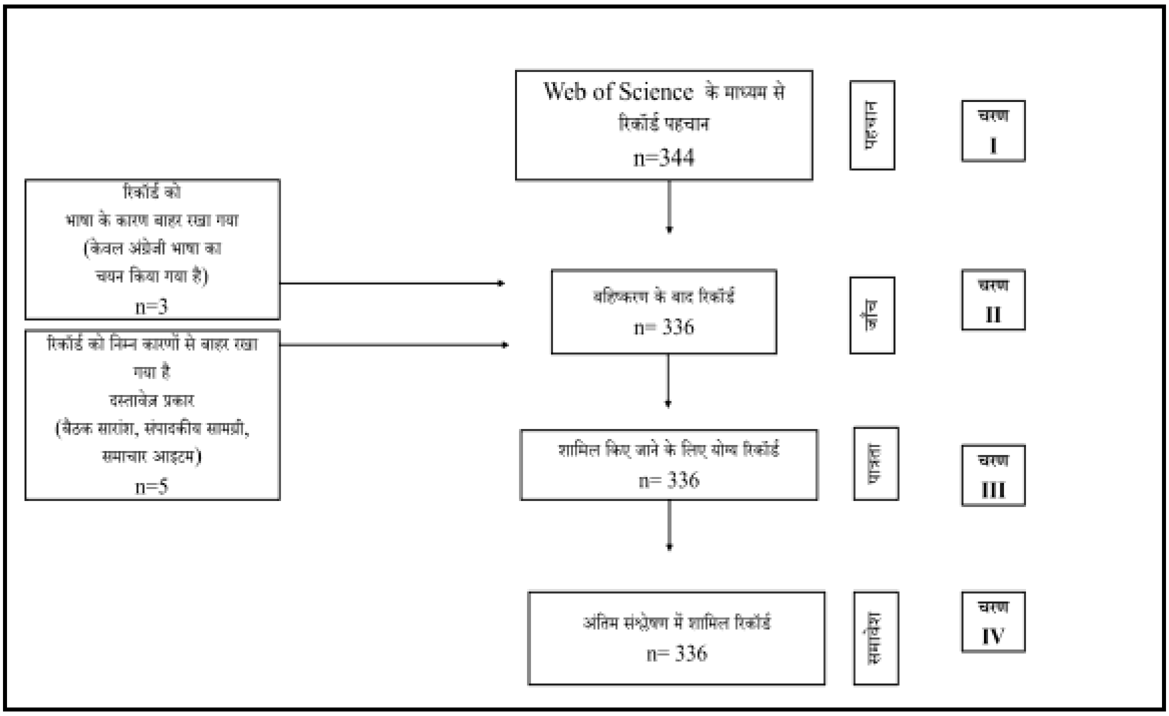

चित्र -1: खेल परिधान अनुसंधान के लिए डेटा चयन प्रक्रिया

तालिका-1: खेल परिधान अनुसंधान से जुड़े प्रमुख सूचक शब्द (Keywords) की सह-घटनाएँ

क्र. सं.	सूचकशब्द	घटना	कुललिंकशक्ति
1	प्रभाव (Impact)	4	17
2	व्यवहार (Behavior)	4	16
3	स्पोर्ट्सब्रा (Sports bra)	5	13
4	ब्रांड (Brand)	3	12
5	उपभोक्ता (Consumer)	3	12
6	भागीदारी (Participation)	3	11
7	अनुभव (Experience)	3	10
8	सोशलमीडिया (Social media)	3	10
9	ब्रांड्स (Brands)	2	9
10	उपभोक्ताव्यवहार (Consumer behavier)	2	9
11	संतुष्टि (Satisfaction)	2	9
12	प्रायोजन (Sponsorship)	3	9
13	विश्वास (Trust)	2	9
14	विशेषताएँ (Attributes)	2	8
15	कॉर्पोरेटसामाजिकउत्तरदायित्व (Corporate social responsibility)	2	8
16	खरीदारीकाइरादा (Purchase intention)	2	8
17	गुणात्मकअनुसंधान (Qualitative research)	2	8
18	महिलाएँ (Women)	2	8
19	स्तनसमर्थन (Breast support)	2	7
20	संस्कृति (Culture)	2	7
21	मांग (Demand)	3	7
22	खेलपरिधानब्रांड (Sports apparel brand)	2	7
23	मूल्य (Values)	2	7
24	आयोजन (Event)	2	6
25	अवकाश (Leisure)	2	6
26	धारणाएँ (Perceptions)	2	6
27	सामाजिककरण (Socialization)	2	6
28	खेलसामग्री (Sporting goods)	2	6
29	पूर्ववर्ती (Antecedent)	2	5
30	विपणन (Marketing)	2	5
31	शारीरिकगतिविधि (Physical -activity)	2	5
32	खेलउपभोग (Sport consumption)	2	5
33	3डीबॉडीस्कैनिंग (3D ody scanning)	2	4
34	डिजाइन (Design)	3	4

35	प्रतिगमनविश्लेषण (Regression analysis)	2	4
36	प्रतिक्रियाएँ (Responses)	2	4
37	खेल (Sports)	3	4
38	वस्त्रदबाव (Clothing pressure)	2	3
39	कार्यात्मकडिज़ाइन (Functional design)	2	3
40	स्वयं (Self)	2	3
41	खेलपरिधान (Sportwear)	2	3
12	कपास (Cotton)	2	2
43	फैशन (Fashion)	2	2
44	यांत्रिकगुण (Machenical properties)	2	2
45	सतहसंशोधन (Surface miodification)	2	2
46	परिधानउद्योग (Apparel industty)	3	1
Total		**109**	**312**

निष्कर्ष

1. प्रभाव (घटना: 4, कुल लिंक शक्ति: 17) "प्रभाव" शोध में किसी विशेष कारक द्वारा किसी विषय पर पड़ने वाले मापने योग्य प्रभाव को दर्शाता है। खेल परिधान और विपणन में, यह ब्रांडिंग, उपभोक्ता धारणा और कार्यक्षमता जैसे कारकों के उपभोक्ता व्यवहार व बाजार पर प्रभाव को समझने में मदद करता है।
2. व्यवहार (घटना: 4, कुल लिंक शक्ति: 16) "व्यवहार" उपभोक्ता, एथलीट या संगठनों के निर्णय लेने की प्रवृत्तियों को दर्शाता है, जो ब्रांड संदेश, उत्पाद विशेषताओं या सामाजिक रुझानों से प्रभावित होते हैं।
3. स्पोर्ट्स ब्रा (घटना: 5, कुल लिंक शक्ति: 13) स्पोर्ट्स ब्रा एक एथलेटिक परिधान है, जो व्यायाम के दौरान स्तनों को सहारा देता है और उनकी गति को कम करता है। शोध में इसके बायोमैकेनिक्स, सामग्री, आराम और प्रदर्शन पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है।
4. ब्रांड (घटना: 3, कुल लिंक शक्ति: 12) ब्रांड किसी कंपनी की पहचान, प्रतिष्ठा और ग्राहक निष्ठा को दर्शाता है। खेल परिधान क्षेत्र में ब्रांडिंग पर शोध उपभोक्ता विश्वास और प्राथमिकताओं पर केंद्रित होता है।
5. उपभोक्ता (घटना 3, कुल लिंक शक्ति: 12) उपभोक्ता वे होते हैं जो खेल उत्पादों को खरीदते हैं। शोध में उनकी जनसांख्यिकी, प्राथमिकताएँ और खरीदारी पैटर्न का अध्ययन किया जाता है।
6. भागीदारी (घटना: 3, कुल लिंक शक्ति: 11) खेल या शारीरिक गतिविधियों में सहभागिता को समझने से ब्रांडों को बेहतर उत्पाद विकसित करने और भागीदारी में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है।
7. अनुभव (घटना: 3, कुल लिंक शक्ति: 10) अनुभव उपभोक्ता की उत्पाद उपयोग से मिली धारणा और संतुष्टि को दर्शाता है, जिससे ब्रांड अपने उत्पाद व सेवाओं में सुधार कर सकते हैं।
8. सोशल मीडिया (घटना: 3, कुल लिंक शक्ति: 10) सोशल मीडिया ब्रांड संचार और विपणन में अहम भूमिका निभाता है। शोध यह विश्लेषण करता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म उपभोक्ता निर्णयों और ब्रांड निष्ठा को कैसे प्रभावित करते हैं।
9. ब्रांड्स (घटना: 2, कुल लिंक शक्ति: 9) खेल परिधान उद्योग में प्रतिस्पर्धा करने वाले विभिन्न ब्रांडों के नवाचार, उपभोक्ता विश्वास और विपणन प्रभावशीलता का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है।
10. उपभोक्ता व्यवहार (घटना: 2, कुल लिंक शक्ति: 9) यह अध्ययन करता है कि उपभोक्ता खेल उत्पादों का मूल्यांकन कैसे करते हैं और खरीद निर्णयों पर ब्रांड निष्ठा व मनोवैज्ञानिक प्रभाव कैसे पड़ता है।
11. संतुष्टि (घटना: 2, कुल लिंक शक्ति: 9) ग्राहक संतुष्टि किसी ब्रांड की सफलता और उपभोक्ता स्थायित्व को निर्धारित करती है। शोध में यह विश्लेषण किया जाता है कि उत्पाद की गुणवत्ता, फिटिंग, आराम और बिक्री के बाद की सेवाएँ संतुष्टि को कैसे प्रभावित करती हैं।
12. प्रायोजन (घटना: 3, कुल लिंक शक्ति: 9) प्रायोजन एक रणनीतिक विपणन उपकरण है, जहाँ ब्रांड एथलीटों, टीमों या आयोजनों के साथ साझेदारी करते हैं ताकि दृश्यता और विश्वसनीयता बढ़ाई जा सके। शोध उपभोक्ता दृष्टिकोण और ब्रांड निष्ठा पर इसके प्रभाव का अध्ययन करता है।

13. विश्वास (घटना: 2, कुल लिंक शक्ति: 9) उपभोक्ता-ब्रांड संबंधों में विश्वास महत्वपूर्ण कारक है। शोध में पारदर्शिता, उत्पाद गुणवत्ता और ग्राहक सेवा का उपभोक्ता विश्वास पर प्रभाव देखा जाता है।
14. विशेषताएँ (घटना: 2, कुल लिंक शक्ति: 8) विशेषताएँ उत्पाद की गुणवत्ता, डिज़ाइन और स्थायित्व जैसी विशेषताओं को दर्शाती हैं। उपभोक्ता की पसंद को प्रभावित करने वाली मुख्य विशेषताओं को समझना ब्रांडों को अपने उत्पादों में सुधार करने में मदद करता है।
15. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) (घटना: 2, कुल लिंक शक्ति: 8) CSR नैतिक व्यापार प्रथाओं, स्थिरता प्रयासों और सामाजिक योगदानों से जुड़ा होता है। शोध यह विश्लेषण करता है कि CSR उपभोक्ता विश्वास और ब्रांड प्रतिष्ठा को कैसे प्रभावित करता है।
16. खरीदारी इरादा (घटना: 2, कुल लिंक शक्ति: 8) यह किसी उपभोक्ता द्वारा किसी उत्पाद को खरीदने की संभावना को दर्शाता है। ब्रांडिंग, मूल्य निर्धारण और साथियों के प्रभाव जैसे कारक खेल परिधानों की खरीदारी प्रवृत्तियों को प्रभावित करते हैं।
17. गुणात्मक शोध (घटना: 2, कुल लिंक शक्ति: 8) यह शोध पद्धति साक्षात्कार, फोकस समूहों और अवलोकन अध्ययनों के माध्यम से गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त करने पर केंद्रित होती है। इसे उपभोक्ता प्राथमिकताओं और व्यवहार को समझने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
18. महिलाएँ (घटना: 2, कुल लिंक शक्ति: 8) खेल परिधान में महिलाओं पर शोध उनके विशेष आवश्यकताओं, जैसे फिटिंग, आराम और प्रदर्शन वृद्धि पर केंद्रित होता है।
19. स्तन समर्थन (घटना: 2, कुल लिंक शक्ति: 7) यह खेल ब्रा द्वारा प्रदान किए गए समर्थन स्तर को दर्शाता है। शोध बायोमैकेनिक्स, कपड़ा तकनीक और एथलीटों की सुविधा पर केंद्रित होता है।
20. संस्कृति (घटना: 2, कुल लिंक शक्ति: 7) संस्कृति उपभोक्ता प्राथमिकताओं, ब्रांड रणनीतियों और खेल सहभागिता प्रवृत्तियों को आकार देती है।
21. माँग (Occurrence: 3, कुल लिंक शक्ति: 7) बाजार माँग विश्लेषण ब्रांडों को बिक्री पूर्वानुमान, नए उत्पाद विकास और मूल्य निर्धारण रणनीतियों को अनुकूलित करने में मदद करता है।
22. खेल परिधान ब्रांड (घटना: 2, कुल लिंक शक्ति: 7) यह परिधान उद्योग का एक उप-भाग है, जो प्रदर्शन परिधान पर केंद्रित होता है। शोध में बाजार प्रवृत्तियों, उपभोक्ता निष्ठा और तकनीकी प्रगति की समीक्षा की जाती है।
23. मूल्य (घटना: 2, कुल लिंक शक्ति: 7) उपभोक्ता मूल्य खरीदारी व्यवहार को प्रभावित करते हैं। शोध नैतिक उपभोग और स्थिरता संबंधी चिंताओं की पड़ताल करता है।
24. आयोजन (घटना: 2, कुल लिंक शक्ति: 6) आयोजन उपभोक्ता सहभागिता और ब्रांड जागरूकता को बढ़ाते हैं, विशेष रूप से प्रायोजन और भागीदारी के माध्यम से।
25. अवकाश (घटना: 2, कुल लिंक शक्ति: 6) अवकाश गतिविधियाँ कैजुअल और प्रदर्शन-उन्मुख खेल परिधानों की माँग को प्रभावित करती हैं।
26. धारणाएँ (घटना: 2, कुल लिंक शक्ति: 6) उत्पाद की गुणवत्ता, ब्रांड प्रतिष्ठा और विपणन संदेश उपभोक्ता की धारणा को आकार देते हैं।
27. सामाजिकरण (घटना: 2, कुल लिंक शक्ति: 6) सामाजिक संपर्क खेल सहभागिता और ब्रांड जुड़ाव को प्रभावित करता है।
28. खेल सामग्री (घटना: 2, कुल लिंक शक्ति: 6) शोध सामग्री प्रगति, स्थायित्व और बाजार प्रवृत्तियों पर केंद्रित होता है।
29. पूर्ववर्ती कारक (घटना: 2, कुल लिंक शक्ति: 5) पूर्ववर्ती कारक वे तत्व होते हैं जो उपभोक्ता निर्णयों से पहले प्रभाव डालते हैं, जैसे कि विज्ञापन एक्सपोजर।
30. विपणन (घटना: 2, कुल लिंक शक्ति: 5) खेल परिधान में विपणन रणनीतियाँ डिजिटल मार्केटिंग, प्रभावशाली समर्थन और अनुभवात्मक अभियानों पर केंद्रित होती हैं।
31. शारीरिक गतिविधि (घटना: 2, कुल लिंक शक्ति: 5) शारीरिक गतिविधि का स्तर खेल परिधानों की मांग को प्रभावित करता है।
32. खेल उपभोग (घटना: 2, कुल लिंक शक्ति: 5) यह दर्शाता है कि लोग खेल में किस तरह संलग्न होते हैं, चाहे वे भाग लें या केवल देखें।
33. 3डी बॉडी स्कैनिंग (घटना: 2, कुल लिंक शक्ति: 4) खेल परिधानों के सटीक फिटिंग और कस्टमाइजेशन के लिए प्रयुक्त तकनीक।
34. डिज़ाइन (घटना: 3, कुल लिंक शक्ति: 4) खेल परिधानों के कार्यात्मकता और सौंदर्यशास्त्र का प्रमुख घटक।
35. प्रतिगमन विश्लेषण (Regression Analysis) (घटना: 2, कुल लिंक शक्ति: 4) चर के बीच संबंधों का विश्लेषण करने के लिए प्रयुक्त एक सांख्यिकीय विधि।
36. उपभोक्ता प्रतिक्रियाएँ (घटना: 2, कुल लिंक शक्ति: 4) ब्रांडिंग और विपणन अभियानों पर उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया।
37. खेल (घटना: 3, कुल लिंक शक्ति: 4) विभिन्न एथलेटिक गतिविधियों को समाहित करने वाली एक व्यापक श्रेणी।
38. वस्त्र दबाव (घटना: 2, कुल लिंक शक्ति: 3) आराम और प्रदर्शन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन।
39. कार्यात्मक डिज़ाइन (घटना: 2, कुल लिंक शक्ति: 3) उपयोगिता और एर्गोनोमिक सिद्धांतों पर केंद्रित डिजाइन।
40. आत्म-छवि (घटना: 2, कुल लिंक शक्ति: 3) खेल परिधान में आत्म-परिचय, आत्म-अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत धारणा का प्रभाव। उत्पाद चयन में उपभोक्ताओ का आत्म-संवेदन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

41. खेल परिधान (घटना: 2, कुल लिंक शक्ति: 3) खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए वस्त्र। इनमें खेल ब्रा, संपीड़न (कंप्रेशन) वस्त्र और उच्च प्रदर्शन वाले कपड़े शामिल हैं।
42. कपास (घटना: 2, कुल लिंक शक्ति: 2) कपास एक प्राकृतिक रेशा है जो सांस लेने योग्य, मुलायम और आरामदायक होता है। हालांकि, यह नमी प्रबंधन और लोच के मामले में सिंथेटिक फाइबर से कमजोर होता है।
43. फैशन (घटना: 2, कुल लिंक शक्ति: 2) खेल परिधान में शैली और कार्यक्षमता का मिश्रण। फैशन रुझान उपभोक्ताओं की पसंद को प्रभावित करते हैं।
44. यांत्रिक गुण (घटना: 2, कुल लिंक शक्ति: 2) वस्त्रों की ताकत, लचीलेपन, लोच और स्थायित्व का अध्ययन।
45. सतह संशोधन (घटना: 2, कुल लिंक शक्ति: 2) कपड़े की सतह को बेहतर बनाने की प्रक्रिया, जैसे नमी सोखने की क्षमता, एंटीबैक्टीरियल सुरक्षा और पराबैंगनी (UV) सुरक्षा।
46. परिधान उद्योग (घटना: 3, कुल लिंक शक्ति: 1) कपड़ा उद्योग का संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला, जिसमें डिजाइन, उत्पादन, वितरण और विपणन शामिल है। खेल परिधान क्षेत्र नवाचार और सतत विकास पहलों द्वारा संचालित होता है।

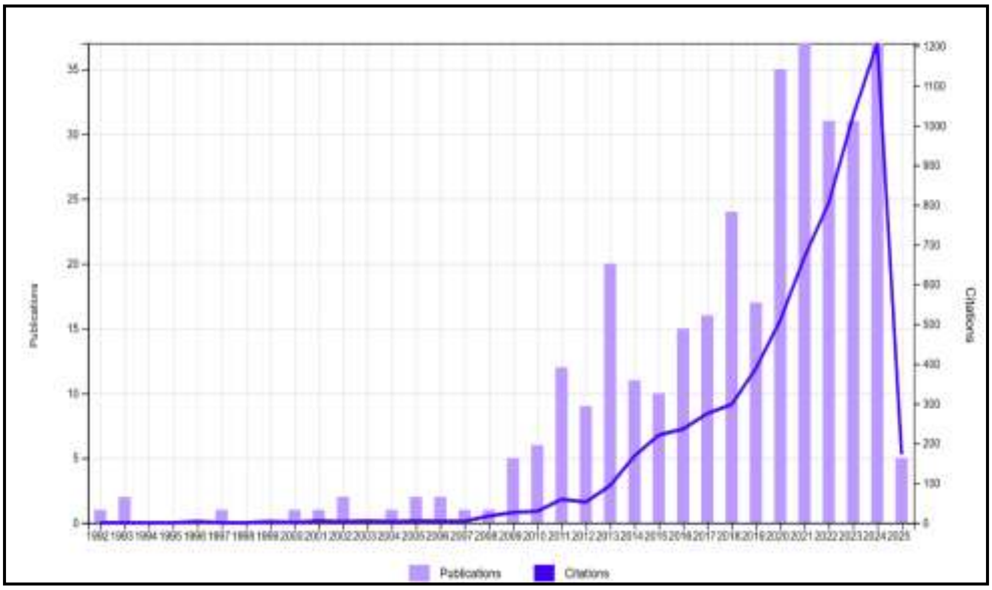

चित्र -2: 1992 से 2025 तक खेल परिधान अनुसंधान के प्रकाशन की आवृत्ति और उद्धरण मीट्रिक।

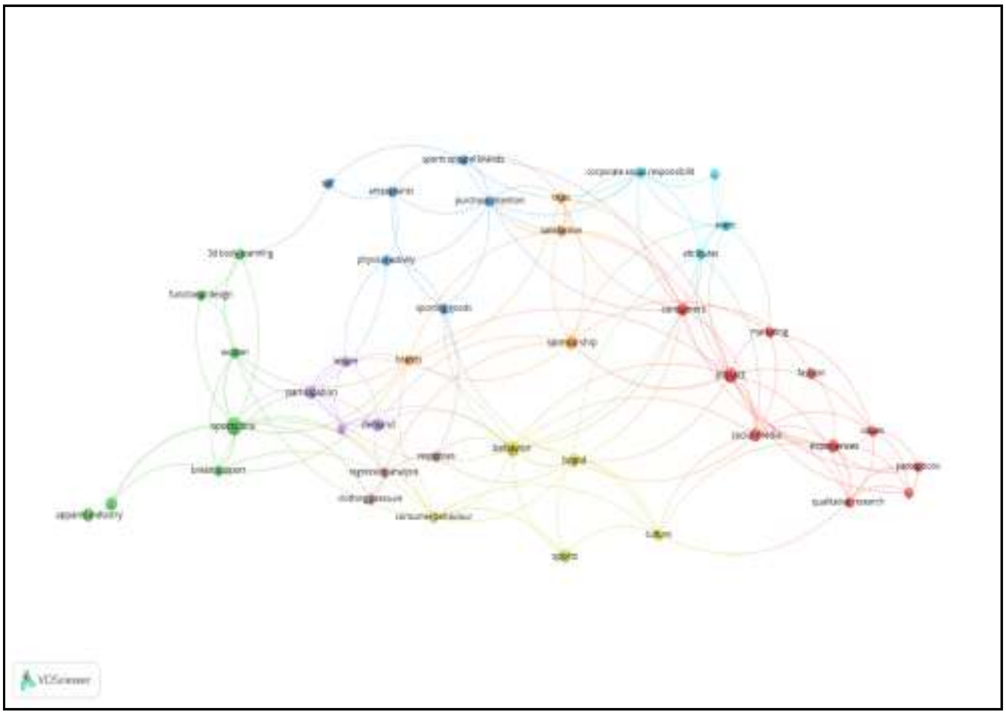

(स्रोत: लेखक द्वारा VOS Viewer 1.6.19 सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके तैयार किया गया)

चित्र 3 खेल परिधान अनुसंधान में प्रयुक्त प्रमुख सूचक शब्द (Keywords) के बायब्लियोमेट्रिक विश्लेषण का नेटवर्क दृश्य प्रस्तुत करता है। यह दृश्य विभिन्न शोध विषयों के आपसी संबंधों को दर्शाता है, जिससे उपभोक्ता व्यवहार, ब्रांड धारणा, खेल ब्रा डिज़ाइन और विपणन रणनीतियों जैसी अवधारणाएँ एक-दूसरे से कैसे जुड़ी हैं, यह स्पष्ट होता है। इन संबंधों की तीव्रता सह-अवस्थिति की सीमा को दर्शाती है, जिससे खेल परिधान क्षेत्र में प्रमुख शोध विषयों की पहचान करने में सहायता मिलती है।

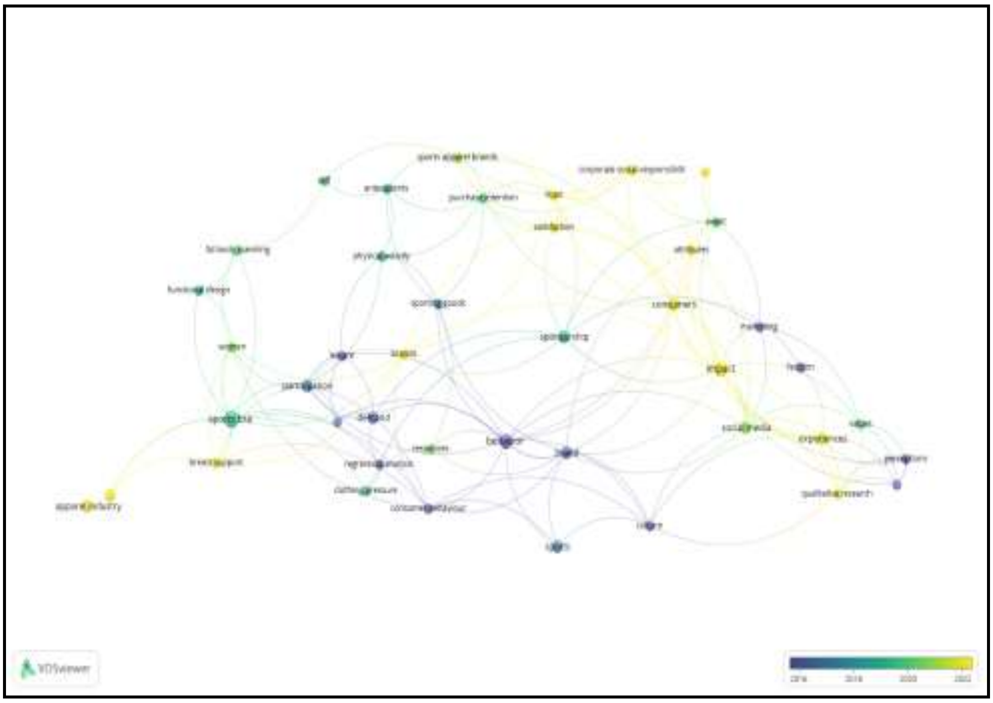

चित्र -4: खेल परिधान अनुसंधान का उपरिशायी या ओवरले विज़ुअलाइज़ेशन: सह-अस्तित्व वाले सूचक शब्द (Keywords) का नेटवर्क विश्लेषण (स्रोत: लेखक द्वारा VOS Viewer 1.6.19 सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके तैयार किया गया)

चित्र 4 उपरिशायी या ओवरले विज़ुअलाइज़ेशन प्रस्तुत करता है, जो खेल परिधान अनुसंधान में समय के साथ हुए परिवर्तनों को दर्शाता है। रंग ग्रेडिएंट विभिन्न शोध अवधियों को दर्शाता है, जिससे हाल के वर्षों में उभरते विषय स्पष्ट होते हैं। यह दृश्यात्मक प्रस्तुति अनुसंधान प्रवृत्तियों में बदलाव को पहचानने में सहायक है, जैसे कि टिकाऊ सामग्री में बढ़ती रुचि, वस्त्र डिज़ाइन में तकनीकी प्रगति, और उपभोक्ता व्यवहार पर सोशल मीडिया का प्रभाव।

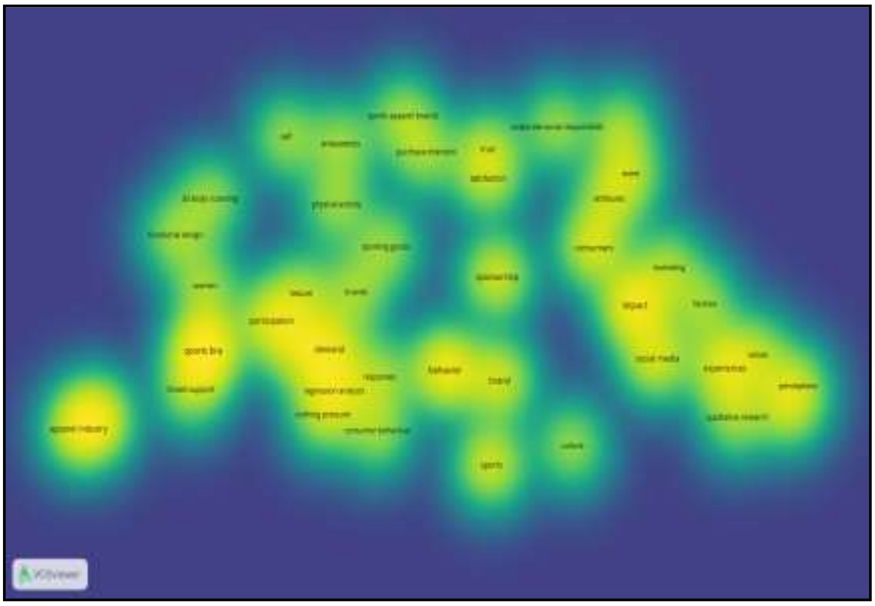

चित्र -5: खेल परिधान अनुसंधान का घनत्व विज़ुअलाइज़ेशन: सह-अस्तित्व वाले सूचक शब्द (Keywords) का नेटवर्क विश्लेषण (स्रोत: लेखक द्वारा VOS Viewer 1.6.19 सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके तैयार किया गया)

चित्र 5 सूचक शब्द (Keywords) के घनत्व का दृश्यात्मक निरूपण प्रस्तुत करता है, जो विशिष्ट विषयों में शोध गतिविधि की एकाग्रता को दर्शाता है। उच्च घनत्व वाले क्षेत्र उन विषयों को दर्शाते हैं, जिन पर व्यापक रूप से शोध प्रकाशित हुआ है, जैसे उपभोक्ता व्यवहार, ब्रांडिंग और खेल परिधान में तकनीकी नवाचार। इसके विपरीत, निम्न घनत्व वाले क्षेत्र संभावित शोध अंतराल को इंगित करते हैं, जो भविष्य में गहन अध्ययन के अवसर प्रदान कर सकते हैं।

परिणामों पर चर्चा

खेल परिधान (स्पोर्ट्स अपैरल) पर किए गए बिब्लियोमेट्रिक विश्लेषण से कई प्रमुख प्रवृत्तियाँ और उभरते शोध क्षेत्र सामने आए हैं। यह अध्ययन उपभोक्ता व्यवहार, कार्यात्मक डिजाइन, तकनीकी प्रगति, स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) और अनुकूली खेल परिधान (एडैप्टिव स्पोर्ट्सवियर) पर केंद्रित है, जो खेल परिधान उद्योग के विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं।

शोध से यह भी स्पष्ट होता है कि पर्यावरणीय परिस्थितियों का खेल परिधान डिजाइन पर प्रभाव महत्वपूर्ण है। अत्यधिक तापमान में वस्त्रों के प्रदर्शन पर हुए अध्ययनों से पता चला कि आम धारणा के विपरीत, काले वस्त्र सफेद वस्त्रों की तुलना में गर्मी के तनाव (हीट स्ट्रेन) को कम करने में अधिक प्रभावी हो सकते हैं (Nguyen & Tokura, 2000)। इसी तरह, ठंडे पानी में डूबने (कोल्ड-वाटर इमर्शन) पर हुए अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकला कि कपड़े थर्मल सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन साथ ही वे तैराकी प्रदर्शन को भी प्रभावित कर सकते हैं, जिससे इन्सुलेशन और गतिशीलता के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता होती है (Bowes et al., 2016)। ये निष्कर्ष दर्शाते हैं कि चरम परिस्थितियों में तापमान नियंत्रण और प्रदर्शन दक्षता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए नवाचारात्मक कपड़ा समाधानों की आवश्यकता है।

परिणाम यह भी दर्शाते हैं कि प्रदर्शन-केंद्रित परिधान नवाचार (परफॉर्मेंस-ड्रिवन अपैरल इनोवेशन) पर व्यापक शोध किया गया है। "स्पोर्ट्स ब्रा," "ब्रेस्ट सपोर्ट," और "क्लोदिंग प्रेशर" जैसे कीवर्ड की बार-बार उपस्थिति इंगित करती है कि एथलेटिक प्रदर्शन और आराम को बढ़ाने के लिए वस्त्रों की कार्यक्षमता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। खेल ब्रा पर शोध मुख्य रूप से समर्थन अनुकूलन, अत्यधिक स्तन गति को कम करने और अंडरबैंड व स्ट्रैप्स पर दबाव कम करने पर केंद्रित रहा है (Yick et al., 2022)। इसी प्रकार, संपीड़न परिधान (कंप्रेशन गारमेंट्स) व्यायाम के बाद पुनर्प्राप्ति (रिकवरी) बढ़ाने, रक्त संचार को बेहतर बनाने और हृदय कार्यों को स्थिर करने में उपयोगी पाए गए हैं, हालांकि उनके सटीक शरीर विज्ञान-संबंधी प्रभाव अभी भी शोध का विषय बने हुए हैं (Piras & Gatta, 2017)।

बुद्धिमान वस्त्रों (स्मार्ट टेक्सटाइल्स) और पहनने योग्य तकनीकों (वेयरेबल टेक्नोलॉजी) में भी शोध की बढ़ती प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से देखी गई है। "हेलोक्रोमिक टेक्सटाइल्स," "3D बॉडी स्कैनिंग," और "सतह संशोधन" (सरफेस मोडिफिकेशन) जैसे कीवर्ड उभरती हुई तकनीकों को इंगित करते हैं, जो खेल परिधान को अधिक कार्यकुशल और उपयोगकर्ता-अनुकूल बना रही हैं (Ribeiro et al., 2023)। हेलोक्रोमिक टेक्सटाइल्स पर हुए अध्ययनों में पाया गया कि ये वस्त्र pH में बदलाव के अनुसार रंग बदल सकते हैं, जिससे जलयोजन (हाइड्रेशन) और परिश्रम स्तर का वास्तविक समय में संकेत मिल सकता है (Pakolpakçıl et al., 2020)। इसके अतिरिक्त, 3D बॉडी स्कैनिंग तकनीक ने खेल परिधान की फिटिंग में सुधार किया है, जिससे आराम और प्रदर्शन दक्षता से जुड़ी चिंताओं को हल किया जा सकता है (Trovato et al., 2022)। वहीं, वस्त्र-आधारित इलेक्ट्रोमायोग्राफी (sEMG) इलेक्ट्रोड जैसी सेंसर तकनीकों के एकीकरण ने एथलीट निगरानी को और उन्नत किया है, जिससे मांसपेशी थकान और बायोमैकेनिक्स का वास्तविक समय में मूल्यांकन संभव हो सका है (Medagedara et al., 2024)।

खेल परिधान उद्योग में स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) और नैतिक मुद्दों (एथिकल कंसिडरेशन) पर भी शोध बढ़ा है, जो "कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी," "मूल्य" और "नैतिक प्रथाओं" जैसे कीवर्ड की उपस्थिति से स्पष्ट होता है। स्थायी निर्माण (सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग) की ओर बढ़ता रुझान उपभोक्ताओं की पारदर्शिता, निष्पक्ष श्रम शर्तों और पर्यावरण-अनुकूल सामग्रियों की मांग को दर्शाता है (Zadek, 2004)। शोध ने यह भी उजागर किया है कि जैव-अपघटनशील (बायोडिग्रेडेबल) वस्त्र, निम्न-कार्बन उत्पादन विधियाँ, और उत्तरदायी संसाधन प्रबंधन स्थिरता-संबंधी चिंताओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं (Curteza et al., 2014)। प्रमुख ब्रांड, जैसे Nike और Adidas, अपने उत्पादों में पुनर्नवीनीकरण सामग्रियों को शामिल कर रहे हैं, जिससे उद्योग में नैतिक और स्थायी उत्पादन के नए मानक स्थापित हो रहे हैं (Wei et al., 2022)।

हालांकि खेल परिधान में कई प्रगतियाँ हुई हैं, लेकिन दिव्यांग एथलीटों (एथलीट्स विद डिसएबिलिटी) के लिए अनुकूलित वस्त्र (एडैप्टिव क्लोदिंग) अब भी एक उपेक्षित क्षेत्र बना हुआ है। शोध निष्कर्ष बताते हैं कि "व्हीलचेयर उपयोगकर्ता," "अनुकूली खेल परिधान," और "समावेशी प्रदर्शन परिधान" से जुड़े अध्ययन की भारी कमी है। पूर्व में हुए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि पारंपरिक खेल परिधान आकार निर्धारण (साइज़िंग) व्हीलचेयर एथलीटों की शारीरिक संरचनात्मक भिन्नताओं के अनुरूप नहीं होता, जिससे गतिशीलता बाधित होती है, असुविधा बढ़ती है और प्रदर्शन दक्षता प्रभावित होती है (Bragança et al., 2015)। इसके अतिरिक्त, खराब-फिटिंग वाले अनुकूली खेल परिधान न केवल एथलीटों के प्रदर्शन को बाधित करते हैं, बल्कि उनके सामाजिक समावेश (सोशल इंक्लूजन) को भी सीमित करते हैं, जिससे शारीरिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी कम हो जाती है (Kabel et al., 2017)। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक उपयोगकर्ता-केंद्रित डिज़ाइन दृष्टिकोण (यूजर-सेंट्रिक डिज़ाइन) आवश्यक है, जिसमें बायोमैकेनिक्स, सामग्री विज्ञान और एर्गोनॉमिक्स के सिद्धांतों को एकीकृत किया जाए, ताकि दिव्यांग एथलीटों के लिए सर्वोत्तम आराम और गतिशीलता सुनिश्चित की जा सके (Kozey & Das, 2004)।

निष्कर्ष

यह बिब्लियोमेट्रिक विश्लेषण खेल परिधान (स्पोर्ट्स अपैरल) के क्षेत्र में अनुसंधान प्रवृत्तियों और उभरते विषयों का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करता है। यह अध्ययन उपभोक्ता व्यवहार, ब्रांड जुड़ाव, कार्यात्मक डिज़ाइन और तकनीकी प्रगति की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है, जो खेल परिधानों के भविष्य को आकार दे रही है। स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) और नैतिक विनिर्माण (एथिकल मैन्युफैक्चरिंग) पर बढ़ता जोर उद्योग की जिम्मेदार उत्पादन प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जबकि डिजिटल मार्केटिंग ब्रांड और उपभोक्ताओं के बीच संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

इसके अलावा, स्मार्ट टेक्सटाइल और उन्नत प्रदर्शन सामग्री (एडवांस्ड परफॉर्मेंस मैटेरियल्स) का समावेश तकनीक और एथलेटिक वियर के संगम को दर्शाता है, जो आराम, कार्यक्षमता और वास्तविक समय की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने में सहायक है। हालांकि, अनुकूली परिधान (एडैप्टिव क्लोदिंग) के क्षेत्र में अनुसंधान की कमी देखी गई है, जो खेल परिधान डिज़ाइन में अधिक समावेशिता (इनक्लूसिविटी) की आवश्यकता को इंगित करता है।

भविष्य के अनुसंधान को बुद्धिमान (स्मार्ट), टिकाऊ (सस्टेनेबल) और अनुकूली (एडैप्टिव) खेल परिधान समाधान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो विभिन्न प्रकार के एथलीटों की जरूरतों को पूरा कर सके। प्रौद्योगिकी नवाचार और उपभोक्ता आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटकर, खेल परिधान उद्योग अपने विकास को जारी रख सकता है और एथलेटिक वियर में उन्नत प्रदर्शन, समावेशिता और स्थिरता प्रदान कर सकता है।

सन्दर्भ सूची

Blue Associates Sportswear. How sportswear has evolved in the last 30 years? Blue Associates Sportswear. Retrieved on 27/02/2025, from https://blueassociatessportswear.com/post/sportswear-evolution-a-30-year-journey-unveiled

Bowes, H., Eglin, C. M., Tipton, M. J., & Barwood, M. J. (2016). Swim performance and thermoregulatory effects of wearing clothing in a simulated cold-water survival situation. European Journal of Applied Physiology, 116(4), 759–767. https://doi.org/10.1007/s00421-015-3306-6

Bragança, S., Castellucci, I., Gill, S., Matthias, P., Carvalho, M., & Arezes, P. (2018). Insights on the apparel needs and limitations for athletes with disabilities: The design of wheelchair rugby sports-wear. Applied Ergonomics, 67, 9–25. https://doi.org/10.1016/j.apergo.2017.09.005

Bragança, S., Fontes, L., Arezes, P., Edelman, E. R., & Carvalho, M. (2015). The Impact of Work Clothing Design on Workers' Comfort. Procedia Manufacturing, 3, 5889–5896. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2015.07.898

Branthwaite, H., & Chockalingam, N. (2019). Everyday footwear: An overview of what we know and what we should know on ill-fitting footwear and associated pain and pathology. The Foot, 39, 11–14. https://doi.org/10.1016/j.foot.2019.01.007

Choudhary, R., Kumar, S. (2024). ICT Application Dynamics: In-Depth Bibliometric Exploration and Insights. In: Edwards, B.I., Tanko, B.L., Klufallah, M., Abuhassna, H., Chinedu, C.C. (eds) Reimagining Transformative Educational Spaces. Lecture Notes in Educational Technology. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-97-8752-4_5

Choudhary, R., (2024). The Scholarly Landscape of Sahaja Yoga Meditation and Meditation Studies: A Bibliometric Analysis. International Journal of Physical Education & Applied Exercise Sciences, 10(1), 5–12.

Curteza, A., Cretu, V., Macovei, L., & Poboroniuc, M. (2014). Designing Functional Clothes for Persons with Locomotor Disabilities. Autex Research Journal, 14(4), 281–289. https://doi.org/10.2478/aut-2014-0028

Jiang, S., Liu, Y., Zheng, H., Zhang, L., Zhao, H., Sang, X., Xu, Y., & Lu, X. (2023). Evolutionary patterns and research frontiers in neoadjuvant immunotherapy: a bibliometric analysis. International Journal of Surgery. https://doi.org/10.1097/JS9.0000000000000492

Kabel, A., Dimka, J., & McBee-Black, K. (2017). Clothing-related barriers experienced by people with mobility disabilities and impairments. Applied Ergonomics, 59, 165–169. https://doi.org/10.1016/j.apergo.2016.08.036

Kozey, J. W., & Das, B. (2004). Determination of the normal and maximum reach measures of adult wheelchair users. International Journal of Industrial Ergonomics, 33(3), 205–213. https://doi.org/10.1016/j.ergon.2003.05.001

Kumar, S., & Choudhary, R. (2024). Bibliometric Insights into Olympic Weightlifting Research Trends. Journal of Ravishankar University (PART-A), 30(1), 43–53. https://doi.org/10.52228/JRUA.2024-30-1-5 2

Medagedara, M. H., Ranasinghe, A., Lalitharatne, T. D., Gopura, R. A. R. C., & Nandasiri, G. K. (2024). Advancements in Textile-Based sEMG Sensors for Muscle Fatigue Detection: A Journey from Material Evolution to Technological Integration. ACS Sensors, 9(9), 4380–4401. https://doi.org/10.1021/acssensors.4c00604

Nguyen, M. H., & Tokura, H. (2000). The different effects of black and white Vietnamese Aodai folk costumes on rectal temperature and heart rate in women walking intermittently in hot and sunny environment. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 13(1), 27–38.

Pakolpakçıl, A., Osman, B., Özer, E. T., Şahan, Y., Becerir, B., Göktalay, G., & Karaca, E. (2020). Halochromic composite nanofibrous mat for wound healing monitoring. Materials Research Express, 6(12), 1250c3. https://doi.org/10.1088/2053-1591/ab5dc1

Piras, A., & Gatta, G. (2017). Evaluation of the Effectiveness of Compression Garments on Autonomic Nervous System Recovery After Exercise. Journal of Strength and Conditioning Research, 31(6), 1636–1643. https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000001621

Ribeiro, A. I., Vieira, B., Alves, C., Silva, B., Pinto, E., Cerqueira, F., Silva, R., Remião, F., Shvalya, V., Cvelbar, U., Padrão, J., Dias, A. M., & Zille, A. (2023). Halochromic Silk Fabric as a Reversible pH-Sensor Based on a Novel 2-Aminoimidazole Azo Dye. Polymers, 15(7), 1730. https://doi.org/10.3390/polym15071730

Trovato, V., Sfameni, S., Rando, G., Rosace, G., Libertino, S., Ferri, A., & Plutino, M. R. (2022). A Review of Stimuli-Responsive Smart Materials for Wearable Technology in Healthcare: Retrospective, Perspective, and Prospective. Molecules, 27(17), 5709. https://doi.org/10.3390/molecules27175709

Wei, N., Xu, Y., Li, Y., Shi, J., Zhang, X., You, Y., Sun, Q., Zhai, H., & Hu, Y. (2022). A bibliometric analysis of T cell and atherosclerosis. Frontiers in Immunology, 13. https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.948314

Wu, F., Gao, J., Kang, J., Wang, X., Niu, Q., Liu, J., & Zhang, L. (2022). Knowledge Mapping of Exosomes in Autoimmune Diseases: A Bibliometric Analysis (2002–2021). Frontiers in Immunology, 13. https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.939433

Yick, K.-L., Keung, Y.-C., Yu, A., Wong, K.-H., Hui, K.-T., & Yip, J. (2022). Sports Bra Pressure: Effect on Body Skin Temperature and Wear Comfort. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(23), 15765. https://doi.org/10.3390/ijerph192315765

Zadek, S. (2004). The path to corporate responsibility. Harvard Business Review, 82(12), 125–132, 150.

बॉलीवुड में महिला केंद्रित फ़िल्मों में महिला पात्रों की स्थिति का विश्लेषण

रश्मि पाल*
डॉ. सुनीता सिंह**

सारांश

मीडिया के द्वारा जनता से सीधा संवाद स्थापित होता है और इसे सामाजिक दर्पण भी कहते हैं। सिनेमा जगत में फ़िल्में संचार का अभिन्न अंग कही जाती हैं। ये फ़िल्में प्रचलित रूढ़िवादी धारणाओं को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालांकि अब महिला केंद्रित फ़िल्में ये दावा करती हैं कि वे महिलाओं की कहानियां उनकी नज़र से पेश कर रहीं हैं। इस शोध का उद्देश्य महिला केंद्रित फ़िल्मों में उनके पात्रों की स्थिति एवं प्रतिनिधित्व का विश्लेषण करना है। इस शोध कार्य को करने के लिए 10 महिला केंद्रित फ़िल्मों का चयन किया गया, जिसमें यह विशेष ध्यान रखा गया कि ये फ़िल्में शहरी पृष्ठभूमि और 2000-2020 के दशकों की हो। सामग्री विश्लेषण विधि का प्रयोग कर फ़िल्मों के महिला पात्रों का विश्लेषण उनकी शारीरिक छवि और उनकी निर्णायक क्षमता के आधार पर किया गया है। शोध में पाया गया कि अधिकांशतः महिला पात्र कि शारीरिक छवि प्रचलित छवि से मेल खाती है जैसे कि गोरी त्वचा, 'अच्छी' शारीरिक बनावट होना। यह भी पाया गया कि कुछ महिला पात्र अपने निर्णय स्वयं ले रही हैं, अपनी राय व्यक्त कर रही हैं, अपने लिए चीज़ें खुद चुन रही हैं और कुछ को सह अभिनेताओं के साथ चर्चा कर निर्णय लेते हुये देखा गया है। निष्कर्ष में पता चलता है कि विकसित परिवेश के बावजूद, लैंगिक मानदंडों के सामाजिकरण पर बॉलीवुड फ़िल्मों का प्रभाव महत्वपूर्ण बना हुआ है। ये फ़िल्में कुछ मापदंडो को तोड़ने का प्रयास करती हैं तथा जागरूक करने में सहायक हैं। फ़िल्मों में जेंडर का संवेदनशील चित्रण अधिक समावेशी और विविध प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करता है।

बीज शब्द: मीडिया, महिला चित्रण, शरीर की छवि, एजेंसी, समाज

प्रस्तावना

समकालीन समाज में मीडिया हमारी धारणाओं, मूल्यों और व्यवहारों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । यह संचार, सूचना, प्रसार और मनोरंजन के लिए एक प्रभावशाली घटक के रूप में कार्य करती है। हालाँकि, मीडिया और समाज के बीच का संबंध जटिल और बहुआयामी है, जिसमें विभिन्न सैद्धांतिक दृष्टिकोणों से एक महत्वपूर्ण विश्लेषण की आवश्यकता है। मीडिया और समाज के साथ इसके संबंध पर आलोचनात्मक रूप से विचार करने के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को स्वीकार करने की आवश्यकता है। कई अध्ययनों ने जांच की है कि टेलीविजन समाज, विशेष रूप से बच्चों और किशोरों को प्रभावित करता है, और इसके हानिकारक और लाभकारी दोनों प्रभाव हो सकते हैं (जॉनसन एट अल., 2002; डायट्स एंड स्ट्रैसबर्गर, 1991; क्यूरन एंड गुरेविच, 2005; स्टीव्स, 1987)।

एक ओर मीडिया विविध मुद्दों, समस्याओं मंच प्रदान करती है, दूसरी तरफ सूचनाओं का प्रसार करती है । मीडिया का समाज में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है । मीडिया समाज में जहां रूढ़ियों को बनाए रख सकती है वही उपभोक्तावाद को बढ़ावा देने और गलत सूचनाओं का प्रचार - प्रसार भी करती है। मीडिया के विभिन्न रूप है जिनकी समाज में अपनी-अपनी भूमिका है । फ़िल्म या सिनेमा भी इसी का हिस्सा है जो विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक इत्यादि पहलूओं से संबन्धित मुद्दों एवं समस्याओं पर चर्चा करती हैं, जिसका प्रभाव समाज पर पड़ता है । फ़िल्मों के संदर्भ में कई शोध कार्य भी हुए हैं, जो फ़िल्म और समाज के संबंधो का एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताते है । विभिन्न अध्ययन जैसे (लॉज़ेन एंड डोजियर, 2005; गिलपैट्रिक, 2010; कोलिन्स, 2011; इंग्लैंड एट अल, 2011 और बेन्शॉफ़ एंड ग्रिफिन, 2004) ने बताया कि फ़िल्मे कार्यशैली, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कमतर आँकती है, जो समाज में प्रचलित पितृसत्तात्मक सोच का परिणाम है । कार्यों और जिम्मेदारियों का निर्धारण जेंडर के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है। जैसे कि कैसे महिलाओं को 'अच्छी मां' 'अच्छी बेटी' और 'अच्छी बहू' के रूप में चित्रित किया जाता हैं ।

कई शोध यह बताते हैं कि समकालीन जगत में मीडिया में लैंगिक रूढ़िवादी चित्रणों जैसे आदर्श पुरुष आक्रामक, मांसल, सफल और यौन रूप से आकर्षक दिखाए जाते हैं और आदर्श महिलाओं का शारीरिक रूप से आकर्षक, विनम्र और यौन रूप से वस्तुनिष्ठ उल्लेख मिलता है (गोल्डिंग और मिडलटन, 1982; मार्टिंडेल, 1996; गुडॉल, 2016; बेकर, 2005)। वुड (1994) ने अपनी शोध में पाया कि मीडिया में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की कमी है।

*रश्मि पाल, शोधछात्रा, शिक्षा संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय।

**डॉ. सुनीता सिंह, सह प्राध्यापक, शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय।

सोनोवाल (2016) ने उल्लेख किया कि फ़िल्मों में महिलाओं का सामान्य प्रतिनिधित्व जैसे कि गृहिणी, बहन, मां या प्रियजन के रूप में है और वे ज़्यादातर पुरुष की सहायिका के रूप में दिखाई गयी हैं। महिला चरित्र को एक आदर्श घरेलू बेटी के रूप में दिखाया गया है (जो अपने भाइयों की देखभाल करती है, घर के कामों में अपनी माँ की सहायता करती है, और अपने पिता द्वारा चयनित पुरुष से शादी करती है)। इसके साथ ही एक अद्भुत पत्नी (जो सभी घरेलू कर्तव्यों के लिए जवाबदेह है, अपने पति, बच्चों की उत्कृष्ट देखभाल करती है) और एक अद्भुत माँ (जो निस्वार्थ है) जैसे चित्रण भी फ़िल्मों द्वारा दिखाये गए हैं (गोकुलसिंग एंड डिसानायके, 2004)। पेंडाकुर (2004) के अनुसार, ऐसी कई फ़िल्में हैं जो परंपरा को चुनौती देने का प्रयास करती हैं, उदाहरण के लिए दीपा मेहता द्वारा निर्मित फायर (1996), अर्थ (1998), और वाटर (2005) ।

समकालीन दशक में देखा जाये तो कई फ़िल्में संवेदनशील मुद्दों पर भी रिलीज हुई हैं और उन्होंने भारतीय समाज में सामाजिक संवाद को भी प्रभावित किया है। इसी संदर्भ में शोधकर्ताओं का उद्देश्य समाज में महिलाओं और मीडिया में योगदान देने के लिए मीडिया के विभिन्न रूपों के माध्यम से महिलाओं के प्रतिनिधित्व की जांच और अन्वेषण को प्रस्तुत करना है।

शोधकर्ताओं द्वारा तैयार किए गए शोध प्रश्न निम्नलिखित हैं

1. भारतमेंमहिलाकेंद्रितफ़िल्मोंमेंमीडियास्रोतोंमेंमहिलाओंकोकैसेचित्रितकियाजारहाहै?
2. मीडियामेंजेंडरकीकुछमुख्यधाराकीनिश्चितभूमिकाओंकाप्रचारकैसेकियाजाताहै?

उद्देश्य

सामग्री विश्लेषण के माध्यम से भारतीय मुख्यधारा बॉलीवुड में महिला केंद्रित फ़िल्मों में महिलाओं के चित्रण का विश्लेषण करना।

अनुसंधान प्रणाली

इस अध्ययन की प्रकृति गुणात्मक है, जो किसी स्थिति की जटिलता को प्रस्तुत करने के महत्व पर केंद्रित है (क्रेसवेल, 2012)। इस शोध पत्र का उद्देश्य बॉलीवुड में महिला केंद्रित फ़िल्मों में महिला पात्रों के चित्रण का विश्लेषण करना है। इस शोध अध्ययन में सामग्री विश्लेषण तकनीक का उपयोग करते हुए फ़िल्मों की कहानी में दर्शाए गए महिला पात्रों की विभिन्न तहों को समझने का प्रयास किया गया है। इस अध्ययन में पात्र की शारीरिक छवि एवं उसकी निर्णायक क्षमता के आधार पर उसका विश्लेषण किया गया है। इस शोध के लिए पाँच फ़िल्मों का चयन किया गया, जो 201१0 - 2020 के बीच रिलीस हुई। चयनित फ़िल्में महिला केन्द्रित है और फ़िल्मों का 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'द हिंदू' जैसे समाचार पत्रों में समीक्षा प्रकाशित हुई है।

अध्ययन के लिए चुनी गई फ़िल्में निम्नलिखित हैं

1. इंग्लिश विंगलिश
2. क्वीन
3. मर्दानी
4. थप्पड़
5. तुम्हारी सुलू

फ़िल्मों का विश्लेषण एवं चर्चा

फ़िल्मों में महिलाओं के शारीरिक छवि के संदर्भ में उन्हें कैसे चित्रित किया जा रहा है जिसमें उनकी त्वचा का रंग, कपड़े, बाल और शारीरिक छवि का प्रकार शामिल हैं। दूसरा, एजेंसी (निर्णायक क्षमता) है। फ़िल्मों का विश्लेषण एवं संबन्धित चर्चा निम्नलिखित विषयों के अंतर्गत किया गया है::

1. बॉडीइमेज (शारीरिकछवि)
2. एजेंसी

बॉडी इमेज (शारीरिक छवि)

मीडिया समाज में जेंडर आधारित विभिन्न शारीरिक छवि के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है (बोरजेकोव्स्की और बायर, 2005)। मीडिया सामान्यतः गोरी त्वचा में सुंदर दिखने की विचारधारा का प्रचार करता है। इस शोध के लिए चयनित फ़िल्मों में ज़्यादातर महिला पात्रों की त्वचा गोरी दिखाई गयी है। केवल कुछ की त्वचा का रंग गेहूंआ है, उदाहरण के लिए शिवानी शिवाजी रॉय (फ़िल्म-मर्दानी से) जो मुंबई पुलिस में एक वरिष्ठ निरीक्षक के रूप में काम कर रही हैं। सुलू (फ़िल्म- तुम्हारी सुलू से), अमृता (फ़िल्म- थप्पड़ से) जैसी महिला पात्रों को अपनी

त्वचा की देखभाल करते हुए दिखाया गया है, जो एक मुख्य विचारधारा का मापदंड है। लेकिन पुरुषों को अपनी त्वचा या शारीरिक देखभाल करते हुए कम दिखाया गया है।

महिलाओं को ज्यादातर कुर्तियों और साड़ियों में दिखाया गया है जिसका निर्धारण घटना, स्थान विशेष के संदर्भ में होता है, जो महिला पात्रों की छवि को भी निर्मित करती है। फ़िल्मों में पात्र जो माताओं के रूप में है, जैसे- शशि (फ़िल्म- इंग्लिश विंगलिश से) और सुलू (फ़िल्म- तुम्हारी सुलू से) ने अपनी पोशाकों के रूप में साड़ी पहनी है।

बालों को भी शारीरिक छवि का एक अभिन्न अंग माना गया है। बालों को लिंग और यौन प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है, परगामेंट (1999)। शशि और सुलू (जिन्हे माँ के रूप में दिखाया गया है) और शिवानी और अमृता जैसे कुछ किरदारों को ज्यादातर चोटी या बन में दिखाया गया है। कामकाजी महिला, गृहिणी और अन्य के रूप में उपयुक्त संदर्भ के अनुसार पात्रों को अलग-अलग केशविन्यास में दिखाया गया है।

चयनित फ़िल्मों में पात्रों को शारीरिक आकार के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं में अलग - अलग रूपों में दिखाया गया है। जो महिलाएं मां हैं जैसे- शशि को लंबा और पतला दिखाया गया है, वहीं सुलू को समाज के प्रचलित मानकों के विपरीत थोड़ा मोटा दिखाया गया है। शिवानी शिवाजी रॉय, अमृता और रानी जैसी महिलाओं को सामान्य रूप में दिखाया गया है। सिनेमा के माध्यम से समाज में यह प्रचारित किया जाता है कि महिलाओं की सुडौल शारीरिक बनावट आकर्षक और सुंदर होती है। महिलाओं पर हमेशा अच्छा दिखने और शारीरिक रूप से फिट रहने का दबाव होता है, जिसका प्रमुख कारक समाज में दूसरों के द्वारा सराहना और स्वीकृति पाने की इच्छा है।

एजेंसी

इस शोध में महिलाओं की एजेंसी (निर्णायक क्षमता), जैसे महिला द्वारा अपनी राय व्यक्त करना, अपनी चीज़ें खुद चुनना, निर्णय लेना और अन्य पहलुओं के संदर्भ में महिला पात्रों का विश्लेषण किया गया है। शोधार्थी ने पाया कि घर, बाहर और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जहां महिलाओं को दिखाया गया है; के संदर्भ में निर्णय लेने की बात आती है तो पितृसत्तात्मक समाज (जहाँ आमतौर पर पुरुष निर्णय लेते है) में महिलाओं को कुछ निर्णय लेते हुए पाया जाता है।

फ़िल्मों के अलग- अलग पड़ावों पर ये दिखाया गया है कि हर पात्र समय और जगह के अनुसार निर्णय लेते है। उदाहरण के लिए जब पुलिस की वरिष्ठ निरीक्षक के रूप में शिवानी शिवाजी रॉय को किसी विशेष मिशन के कार्यों के संबंध में अपने अधीनस्थों को आदेश देने की आवश्यकता पड़ती है, तब अपने दम पर कुछ निर्णय लेती है।

'तुम्हारी सुलू' में नायिका सुलू की बात करें तो देखा गया कि उसका पति घर के कुछ फैसले लेता है। जैसे सुलू के पति ने फैसला किया कि वे दूसरा टीवी नहीं खरीदेंगे और वह उपभोक्ता अदालत में मामला दायर करेंगे। इसके साथ ही जब एक रेडियो स्टेशन की बॉस मारिया सुलू को नौकरी देने की बात करती है, तो वह अपने पति से अनुमति मांगती है। पितृसत्तात्मक आधिपत्य यहाँ स्पष्ट रूप से देखा जाता है क्योंकि पति यह तय करता है कि पत्नी के लिए कौन सी नौकरी उपयुक्त है। इसके साथ ही देखा गया है कि घर में किसी भी तरह के निर्णय लेने में पितृसत्तात्मक आधिपत्य को भी ध्यान में रखा जाता है क्योंकि पुरुष परिवार का मुखिया होता है। फ़िल्म के दूसरे दृश्य में जब वही बॉस मारिया सुलू के पति से कहती है कि वह जो चाहे वो सवाल पूछ सकता है, तो पुरुष को थोड़ा झिझकते हुए दिखाया गया है। इस दृश्य से यह माना जा सकता है परिवेश बदलते ही एजेंसी बदल जाती है।

फ़िल्म 'थप्पड़' के दृश्य में प्रदर्शित परिवेश के अनुसार निर्णय स्वयं महिला पात्र के हाथों में है। फिल्म की नायिका अमृता ने गृहिणी बनना चुना और साथ में पड़ोस की लड़की को डांस सिखाना। जब अमृता के पति ने उसे पार्टी में सबके सामने थप्पड़ मारा, तो उसने अपने पति को छोड़ने का फैसला किया। इसमें दिखाया गया कि पुरुष कभी भी थप्पड़ मार सकते हैं या ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जो उन्हें सही लगता है। अमृता के परिवार के सदस्यों एवं उसके वकील द्वारा उसे तलाक न लेने की सलाह दी जाती है। और "सिर्फ़ एक थप्पड़" के लिए याचिका दायर करने पर बार- बार उसे ही सवालों के घेरे में रखा जाता है क्योंकि वे घरेलू हिंसा को 'सामान्य' घटना मान रहे थे। यह दिखाया गया है कि उसकी सास और माँ भी अमृता को समझाने की कोशिश करते है कि परिवार में सामंजस्य और रिश्ते बनाए रखने के लिए महिलाओं को बलिदान देने पड़ते है। इसीलिए उसे तलाक़ न लेने और आराम से अपने पति के साथ ही रहने के लिए कहा जाता है। यहाँ इस संदेश पर भी ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है कि एक पुरुष महिलाओं के साथ जिस भी प्रकार की हिंसा करता है, उसे स्वीकार करने के लिए महिलाओं का सामाजिककरण किया जाता है। दुबे (1988) भी इस प्रकार के सामाजीकरण का उल्लेख अपने लेख मे करतीं हैं। अमृता ने अपने दम पर फैसला लिया और खुद के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी कि रिश्ते में सम्मान पाना उसका अधिकार है।

फ़िल्म 'क्वीन' के पात्र रानी ने हमेशा अपने माता-पिता, शिक्षकों, मंगेतर और हर दूसरे व्यक्ति की बात मानी है। जब रानी अपने मंगेतर से अनुमति मांगती है कि क्या वह नौकरी कर सकती है तो वह बोलता है कि उसे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखा जाये तो महिलाएं भी पितृसत्तात्मक समाज का हिस्सा हैं तथा उन्हें एक पुरुष से पूछ कर ही कोई काम करना है या निर्णय लेना है।

फ़िल्म 'इंग्लिश विंगलिश' की मुख्य नायिका 'शशि' को आमतौर पर रात में अपने पति के घर आने और रात का खाना परोसने का इंतजार करते हुए दिखाया गया है। शशि का पति उसे मिठाई बनाने के लिए किए जाने वाले सभी कार्यों को बंद करने के लिए कहता है। वह

फैसला लेती है कि वह ये करना जारी रखेगी। उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है जिसने अपने दम पर अंग्रेजी सीखने के लिए कक्षाओं में शामिल होने का फैसला किया। यहाँ यह दिखाया गया है कि निर्णय नायिका द्वारा लिया गया था। इसके साथ ही नायिका शशि ने विभिन्न क्षेत्रों में एक पुरुष और महिला की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर भी सवाल उठाए तथा कैसे एक कार्य को पुरुष के लिए महिमामंडित किया जा रहा है और एक महिला के लिए जिम्मेदारी की सराहना नहीं की जा रही है। उसने कहा, "मर्द खाना बनाए तो कला है, औरत बनाए तो उसका फ़र्ज़ है" / यह कहते हुए खाना बनाने की सामाजिक जिम्मेदारी की ओर इशारा करने की कोशिश की है। यह समाज पर एक व्यंग्य भी है कि काम कि वे जिम्मेदारियाँ जिनके लिए महिलाओं को घर में मान्यता नहीं मिलती है क्योंकि समाज में वह उनके जेंडर से संबन्धित कार्य समझा जाता है तथा इसके विपरीत अगर वही काम पुरुष घर के बाहर पैसे के लिए करते हैं तो उन्हे सराहा जाता है एवं उन्हे परिवार मे मान्यता मिलती है। इस सरहाना और परिवार में मान्यता के पीछे वित्त एक प्रमुख कारण है जबकि महिलाओं को घर पर ऐसा करने का कोई वेतन नहीं मिलता है। जैसा कि ये फ़िल्में महिलाओं को मुख्य नायक के रूप में दर्शाती है, साथ ही उस दोहरे बोझ को भी संबोधित कर रही हैं, जिससे महिलाएं अपने दैनिक जीवन में गुजरती हैं। इस धारणा को फ़िल्मों और उनके पात्रों द्वारा महिमामंडित किया गया है, जो टेरे (2014) के अध्ययन के अनुरूप है।

निष्कर्ष

जैसा कि नारीवादी विद्वानों ने उल्लेख किया है कि अभी भी समाज में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण प्रचलित है। महिलाओं के लिए गोरी त्वचा सौंदर्य के मानदंड के रूप में समाज में स्वीकार किए जाते हैं (दासगुप्ता, 2018)। हालांकि समसामयिक फ़िल्मों में महिलाओं की शारीरिक छवि की बनावट में थोड़ा बदलाव आया है । इस शोध में पाया गया कि अधिकांश पात्र अपने जीवन में मजबूत निर्णय लेने वाले व्यक्ति के रूप में उभरीं हैं । फ़िल्मों मे महिलाओं के दृष्टिकोण से कहानी को शामिल करने की कोशिश की जा रही हैं। यह देखा जाता है कि निर्माता, निर्देशक, लेखकों और अभिनेताओं से संबंधित फ़िल्म निर्माण में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। परंतु फिर भी फ़िल्म निर्माण में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की भागीदारी अधिक है। इस शोध के संदर्भ मे चयनित फ़िल्मों मे देखा जाये तो कहानी, पटकथा और कथानक पुरुषों द्वारा भी लिखे गए थे और महिलाओं ने कहानी के पात्र को पर्दे पर सिर्फ निभाया है। हालांकि यह पाया जाता है कि ये फ़िल्में पितृसत्तात्मक समाज की धारणाओं को तोड़ने का प्रयास करती हैं, लेकिन एक लैंगिक असमानता अभी तक मौजूद है।

उन्होंने भारतीय दर्शकों के सामने प्रदर्शित किया है कि एक महिला शक्तिशाली, करियर-केंद्रित और महत्वाकांक्षी हो सकती है, साथ ही अपनी यौन जरूरतों को पूरा करने वाली स्त्री भी हो सकती है। समाज में पुरुषों और अन्य लिंग के संदर्भ में इन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है।

फ़िल्मों के निर्देशक, निर्माता समतवादी, प्रगतिशील सोच को बढ़ावा देते हुए विविधता को शामिल करने की कोशिश कर रहे है जिसमें जेंडर आधारित मुद्दों, विमर्शों समस्याओं को शामिल किया जाने लगा है। यह उन फ़िल्मों का समर्थन करके प्राप्त किया जा सकता है जो रूढ़िवादिता से दूर होती हैं, फ़िल्म निर्माण और कहानी कहने में लैंगिक समानता को बढ़ावा देती हैं, और दर्शकों के बीच मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देती हैं ताकि फ़िल्मों में दिखाए गए संदेशों का गंभीर रूप से विश्लेषण और चुनौती दी जा सके।

सन्दर्भ सूची

C. Martindale. "Newspaper stereotypes of African Americans." Images that injure: Pictorial stereotypes in the media (1996): 21-26.

C. N. Baker. "Images of women's sexuality in advertisements: A content analysis of Black-and White-oriented women's and men's magazines." Sex Roles (2005): 13-27.

D. Dasgupta. "Gender Portrayal in Age of Social Networking Sites: An Analytical Discussion." Amity Journal of Media & Communication Studies (2018): 42-48.

D. L., & Bayer, A. M. Borzekowski. "Body image and media use among adolescents." Adolesc Med Clin. (2005): 289-313.

D. Pergament. "It's not just hair: Historical and cultural considerations for an emerging technology." Chi.-Kent L. Rev (दि.न.).

English Vinglish. निर्दे. Gauri Shinde. निष्पा. Sridevi. 2012.

Goodall Hannah. "Media's Influence on Gender Stereotypes." Media Asia (2016): 160-163.

H. L. Steeves. " Feminist theories and media studies." Critical Studies in Media 1987: 95-135.

H. M., & Griffin, S. Benshoff. "Queer cinema: The film reader. ." 2004.

J. G., Cohen, P., Smailes, E. M., Kasen, S., & Brook, J. S. Johnson. “Television viewing and aggressive behaviour during adolesence and adulthood.” 2002: 2468-2471.

J. T. Wood. “Gendered media: The influence of media on views of gender.” Gendered lives: Communication, gender, and culture (1994): 231-244.

J. W. Creswell. Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Boston: Pearson, 2012.

J., & Gurevitch, M. Curran. “Mass media and society.” Odder Arnold 2005.

Katy Gilpatric. “Violent female action characters in contemporary American Cinema.” Sex Roles 2010: 734-746.

L. Dube. “On the Construction of Gender: Hindu Girls in Patrilineal India.” Economic and Political Weekly (1988): 11-19.

M. Pendakur. Indian popular cinema: Industry, ideology, and consciousness. . Hampton Press, 2003.

Mardaani. निर्दे. P.Sarkar. निष्पा. Rani Mukherjee. 2014.

Martha M. & Dozier, David M. Lauzen. “Maintaining the Double Standard:Portrayals of Age and Gender in Popular Film .” Sex Roles 2005: 437-446.

N.S. Tere. “Gender Reflections in Mainstream Hindi Cinema.” Global MediaJournal (2012): 1-9.

P., & Middleton, S. Golding. Images of welfare: Press and public attitudes to poverty. Robertson: Oxford, 1982.

. Images of welfare: Press and public attitudes to poverty. Robertson: Oxford, 1982.

Queen. निर्दे. Vikas Bahl. निष्पा. Kangana Ranaut. 2014.

R. R. Sonowal. “Representation of Women in Realistic Cinema.” ADR Journals (2016).

Rebecca L. Collins. “Content Analysis of Gender Roles in Media: Where Are We now and where should we go? .” Sex Roles 2011: 290-298.

Thappad. निर्दे. Anubhav Sinha. निष्पा. Taapsee Pannu. 2020.

Tumhari Sulu. निर्दे. S. Triveni. निष्पा. Vidya Balan. 2016.

W. H., & Strasburger, V. C. Dietz. “Children, adolescents, and television.” Current problems in pediatrics 1991: 8-31.

W., & Gokulsing, K. M. Dissanayake. Indian popular cinema: A narrative of cultural change. England: Trentham Books, 2004.

उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता का योग साधना से संबन्ध का अध्ययन

डॉ. शिव शंकर यादव*
डॉ. सुशील कुमार**

सारांश

वैज्ञानिक युग की इस चकाचौंध में मानव जितना विकास के लिए अग्रसर है व समयानुसार नूतन कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। वही अपने दैनिक कार्यों में इतना व्यस्त हो चुका है कि वह अपनी संतुलित जीवनचर्या को भूल चुका है। जिसके परिणामस्वरूप अनेक असाध्य रोगों से ग्रस्त हो रहा है जिसमें से है- मानसिक योग्यता का ह्रस, एकाग्रता क कमी, मानसिक तनाव, आदि इन समस्याओं से मानव असंतुश्ट व स्वयं में ही उलझा नजर आता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) 2019 द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, तकरीबन 7.5 प्रतिशत भारतीय किसी-न-किसी रूप में मानसिक विकार से ग्रस्त हैं। यूनिसेफ 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में तकरीबन 14 फीसदी बच्चे भी अवसाद में जी रहे हैं। जबकि NCRB के अनुसार 2021 में 13,792 लोगों ने मानसिक बीमारियों से जूझते हुए आत्महत्या की। इन सबसे उभरने के लिये मानव विभिन्न दवाइयों का सहारा लेता है जबकि इन सब समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए भारतीय संस्कृति की धरोहर योग साधना ''योग भगाए रोग'' अपनी अहम् भूमिका निभाती है। अतः शोधार्थी द्वारा बिहार राज्य के जनपद मधेपुरा के कक्षा 09 व 10 के 100 विद्यार्थियों को न्यादर्श रूप में शामिल किया तथा परिकल्पना परीक्षण के लिए सह-सम्बन्ध गुणांक की विचलन प्राप्तांक विधि का प्रयोग करते हुए निष्कर्ष में पाया कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एंव छात्राओं की मानसिक योग्यता का अधिक समय तक योग साधना के मध्य उच्च धनात्मक सह-सम्बन्ध है। जबकि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों की मानसिक योग्यता का योग साधना (लघु समय) के मध्य परिमित धनात्मक सह-सम्बन्ध है। जबकि छात्राओं की मानसिक योग्यता का योग साधना (लघु समय) के मध्य निम्न धनात्मक सह-सम्बन्ध है। अतः 30-45 मिनट का योग हर दिन आपके स्वास्थ्य को अच्छा रहने में मदद कर सकता इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि योग एक चमत्कार है और अगर इसे किया जाए तो यह आपके पूरे जीवन का मार्गदर्शन करेगा। प्रति दिन 30-45 मिनट योग आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन को बढ़ावा देने के द्वारा आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है।

बीज शब्द: योग साधना, मानसिक योग्यता, समयावधि

प्रस्तावना

वैज्ञानिक युग की इस चकाचौध में मानव जितना विकास के लिए अग्रसर है व समयानुसार नूतन कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। वही अपने दैनिक कार्यों में इतना व्यस्त हो चुका है कि वह अपनी संतुलित जीवनचर्या को भूल चुका है। जिसके परिणामस्वरूप अनेक असाध्य रोगों से ग्रस्त हो रहा है जिसमें से है- मानसिक योग्यता का ह्रस, एकाग्रता क कमी,मानसिक तनाव,आदि इन समस्याओं से मानव असन्तुश्ट व स्वयं में ही उलझा नजर आता है । इन सबसे उभरने के लिये मानव विभिन्न एलौपैथिक, होम्योपैथिक व आयुर्वेदिक दवाइयों का सहारा लेता है जबकि इन सब समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए भारतीय संस्कृति की धरोहर योग साधना अपनी अहम् भूमिका निभाती है। योग आज की दुनिया में एक अमूल्य उपहार हैं जो हमारे अंतर्मन और शरीर की एकता को बनाए रखता है। स्वस्थ होने की परिभाषा सिर्फ शरीर से नहीं जुड़ी होती बल्कि आपके स्वस्थ होने का मतलब मानसिक रोग तथा तनाव से दूर रहना है। ''योग भगाए रोग'' स्वामी अक्षय आत्मानन्द (2006) की पुस्तक काफी लोक प्रिय रही। चूँकि योग के संदर्भ में प्राचीन काल में ही ऋशि मुनियों ने अनेक कथन उद्घोषित किये थे जिनमें ''योग भगाए रोग'' एक महत्वपूर्ण कथन है। योग हमारे मन में शांति लाता है और पंचतत्वों से बने हमारे शरीर को प्रकृति से जोड़ता है। पातंजलि योग दर्शन के अनुसार- **"योगश्चित्तवृत्त निरोधः"** अर्थात् चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। सांख्य दर्शन के अनुसार- **"पुरुषप्रकृत्योर्वियोगेपि योगइत्यमिधीयते।"** अर्थात् पुरुष एवं प्रकृति के पार्थक्य को स्थापित कर पुरुष का स्व स्वरूप में अवस्थित होना ही योग है।

भगवद्गीता के अनुसार- **''सिद्ध्यसिद्ध्यो समोभूत्वा समत्वंयोग उच्चते।"** अर्थात् दुःख-सुख, लाभ-अलाभ, शत्रु-मित्र, शीत और उष्ण आदि द्वन्दों में सर्वत्र समभाव रखना योग है। आम तौर पर योग को स्वास्थ्य एवं फिटनेस के लिए थिरेपी या व्यायाम की पद्धति के रूप में समझा जाता है। हालांकि शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य योग के स्वाभाविक परिणाम हैं, परंतु योग का लक्ष्य अधिक दूरगामी है। योग ब्रह्माण्ड से स्वयं का सामंजस्य स्थापित करने के बारे में है। यह सर्वोच्च स्तर की अनुभूति एवं सामंजस्य प्राप्त करने के लिए ब्रह्माण्ड से स्वयं की ज्यामिती को सरेखित करने की कला है।

*डॉ. शिव शंकर यादव, सहायक आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)।
**डॉ. सुशील कुमार, विभागाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र विभाग, भू.ना. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा (बिहार)।

तथापि समाज के बुद्धिजीवियों में कुशाग्रबुद्धि की वर्धित शक्ति और गहन एकाग्रता के कारण मनुश्य बौद्धिक दासता के जंजाल में फंस गया है। वह गहन एकाग्रता के सशक्त नियंत्रण से बाहर आने में स्वयं को असमर्थ पाता है। उसकी चिन्ताएं और आशक्तियां उसे नहीं छोड़ती। बौद्धिक स्तर पर व्यक्तित्व के विकास के फलस्वरूप न केवल बुद्धि प्रखर होनी चाहिए अपितु इसमें कुशाग्र बुद्धि को गुलाम बनाने वाली शक्ति पर विजय पानें की मानसिक योग्यता भी शामिल होनी चाहिए। इसलिए स्वामी विवेकानन्द ने एकाग्रता और मानसिक योग्यता पर बल देते हुए कहा कि ये दो शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग है। अतः योग साधना में विशेशता है कि यह बुद्धि का एक व्यापक विकास कर सकती है। योग का मुख्य आधार प्रसन्नता की तलाश है लेकिन व्यक्ति प्रसन्नता की तलाश में बाध्य रूप में इन्द्रिय सुख में करते है जबकि प्रसन्नता तो हमारे अन्दर विद्यमान है जो मन को नियंत्रण रखने पर प्राप्त होती है। यह विचारों से विहीन स्थिति होती है। यह आनन्द ज्ञान, शांति, स्वतंत्रता और रचनात्मक की स्थिति होती है जो मन या चित्त स्तरों पर संचालित होती है अर्थात योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना है जो व्यक्ति स्वतत्व का समष्टि स्वतत्व के साथ मेल कराता है। पातंजली ने योग साधना को अष्टांग योग में वृहद बताते हुये कहा गया है कि व्यक्ति यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इन आठ चरणों का निरन्तर अभ्यास करे तो उसकी मानसिक योग्यता एवं एकाग्रता में भी वृद्धि हो सकती है।

शोध अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में थकना मना है और यह तभी संभव होगा जब आप समय प्रबंधन का अपने जीवन में बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर रहे हों। जिसने समय प्रबंधन के साथ शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य मध्य तालमेल बैठा लिया उसे सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। परन्तु जब तालमेल दहीं बैठ पाता तो तनाव उत्पन्न होजाता है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पा कुप्रभाव डालता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए योग एक बेहतर विकल्प के रुप में प्रयोग किया जा रहा है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिये योग साधना करना अति आवश्यक है। योग का शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक क्षमता से घनिश्ठ सम्बन्ध है। प्रत्येक व्यक्ति के अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का मुख्य आधार उसकी दैनिक व्यवस्थित दिनचर्या एवं पौश्टिक आहार होता है। जीवन को समृद्ध बनाने हेतु स्वस्थ्य मानसिक योग्यता को प्राप्त करना अति आवश्यक है क्योंकि व्यक्ति ही समाज की इकाई होता है। व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राश्ट्र का निर्माण होता है तथा जब व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ्य होगा तभी स्वस्थ्य समाज व स्वस्थ्य राश्ट्र का विकास सम्भव है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) 2019 द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 7.5 प्रतिशत भारतीय किसी-न-किसी रूप में मानसिक विकार से ग्रस्त हैं। साथ ही WHO के अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 तक भारत की लगभग 20 प्रतिशत आबादी मानसिक रोगों से पीड़ित होगी। मानसिक रोगियों की इतनी बड़ी संख्या के बावजूद भी अब तक भारत में इसे एक रोग के रूप में पहचान नहीं मिल पाई है, आज भी यहाँ मानसिक स्वास्थ्य की पूर्णतः उपेक्षा की जाती है और इसे काल्पनिक माना जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि जिस प्रकार शारीरिक रोग हमारे लिये हानिकारक हो सकते हैं उसी प्रकार मानसिक रोग भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। यूनिसेफ 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में तकरीबन 14 फीसदी बच्चे भी अवसाद में जी रहे हैं। जबकि NCRB के अनुसार 2021 में 13,792 लोगों ने मानसिक बीमारियों से जूझते हुए आत्महत्या की।

योग साधना के द्वारा जीवन का उचित दर्शन प्राप्त होने से भीतरी स्तर पर शुद्धियां आती है और भावनाओं को स्थिर करके व्यक्तित्व को सुदृढ़ किया जाता है। अभ्यान्तरिक चेनता से हमें अपने स्वयं के द्वन्द्वों को समूल समाप्त करने में सहायता मिलती है साथ ही दबी हुई भावनाएं और अति संवेदनशीलता भी कम होती है। योग से व्यक्ति अधिक कुशलतापूर्वक कार्य कर पाता है। चूंकि इसके द्वारा कार्य करने की कला सीख जाता है अपने आंतरिक आनंद की पृश्ठभूमि में कार्य का आनन्द उठाने लगता है इस प्रकार योग के नियमित अभ्यास से व्यक्ति में सृजन क्षमता, बुद्धिलब्धि विकसित करने में सहायता मिलती है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि योग से भावनाओं को संभाला जाता है व क्रोध पर नियंत्रण भी किया जा सकता है। इससे व्यक्तित्व का पूर्ण विकास के साथ मानसिक योग्यता में वृद्धि करना है।

विद्यालयों में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान देना भी आवश्यक है क्योंक विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं को हल नहीं किया गया और व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर इनका मार्गदर्शन नहीं किया गया तो शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पायेगी और उनका शारीरिक स्वास्थ्य व मानसिक योग्यता में अवरुद्ध उत्पन्न हो जायेगा। उक्त समस्या को मूर्त रुप देते हुए शोधकर्ता ने ***''उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता का योग साधना से संबन्ध का अध्ययन''*** में संकलित किया।

तकनीकी शब्दों का परिभाशीकरण

1. **उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी-** उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों से तात्पर्य कक्षा 09 व कक्षा 10 में अध्ययनरत् बिहार के उच्चतर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बिहार के विद्यार्थियों से है।
2. **मानसिक योग्यता-** मानसिक योग्यता का अर्थ है कि स्वयं में निर्णय लेने की क्षमता, अपने व्यवहार के तथ्यों और समझने की क्षमता, सीखने व ज्ञान रखने की शक्ति ही मानसिक योग्यता कहलाती है।
3. **योग साधना-** कुशल चित्त की एकाग्रता योग साधना है। अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग साधना है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों की मानसिक योग्यता का योग साधना से सम्बन्ध का अध्ययन करना।
2. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं की मानसिक योग्यता का योग साधना से सम्बन्ध का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पना

$H_0$1.1 उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों की मानसिक योग्यता का योग साधना (दीर्घ समय) से कोई सार्थक सह-सम्बन्ध नहीं है।

$H_0$1.2 उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं की मानसिक योग्यता का योग साधना (दीर्घ समय) से कोई सार्थक सह-सम्बन्ध नहीं है।

$H_0$2.1 उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों की मानसिक योग्यता का योग साधना (लघु समय) से कोई सार्थक सह-सम्बन्ध नहीं है।

$H_0$2.2 उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं की मानसिक योग्यता का योग साधना (दीर्घ समय) से कोई सार्थक सह-सम्बन्ध नहीं है।

शोध विधि: शोध समस्या की प्रकृति एवं विशय वस्तु को ध्यान में रखते हुए शोधार्थी द्वारा प्रयोगात्मक शोध विधि का प्रयोग किया गया।

न्यादर्श एवं न्यादशर्न विधि

शोधकर्ता ने जनपद मधेपुरा में संचालित बिहार बोर्ड के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् 100 विद्यार्थियों को उद्देश्यपूर्ण विधि का प्रयोग करते हुए न्यादर्श के रूप में शामिल किया। जिसमें (24 छात्र 30 मिनट से अधिक व 27 छात्र 30 मिनट या कम समय की योग साधना, 26 छात्राएं 30 मिनट से अधिक व 23 छात्राएं 30 मिनट से कम समय की योग साधना) हैं।

प्रयुक्त विधि एवं उपकरण

शोध के उद्देश्य व परिकल्पनाओं को दृश्टिगत रखते हुए शोधकर्ता ने रोमापाल एण्ड रामा तिवारी द्वारा निर्मित मानकीकृत **ए.पी.आर.सी**. आगरा द्वारा प्रकाशित 'जनरल मेण्टल एवेलिटी टेस्ट' नामक उपकरण का प्रयोग किया तथा योग साधना के लिए योग निर्देशक के माध्यम से स्वनिर्मित उपकरण का प्रयोग किया गया।

सांख्यिकीय विधियाँ

शोध समस्या की प्रकृति एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शोधार्थी द्वारा सह-सम्बन्ध गुणांक की विचलन प्राप्तांक विधि का प्रयोग किया गया।

प्रदत्तों का सांख्यिकीय विश्लेशण एवं परीक्षण

शोध परीक्षण के प्रशासन तथा अंकन के पश्चात् प्रदत्तों का संकलन तथा व्यवस्थापन किया गया, तत्पश्चात् प्रदत्तों का विश्लेशण एवं व्याख्या की जाती है।

H_1- **परिकल्पना परीक्षण**

उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं की मानसिक योग्यता एवं योग साधना

(दीर्घ समय) के प्राप्तांक तालिका सं. - 01

H_1	**चर/समूह संख्या**	**संख्या**	**सह-सम्बन्ध गुणांक परिणाम**	**परिणाम**
$H_0$1.1	छात्रों की मानसिक योग्यता	24	+.77	उच्च धनात्मक सह-सम्बन्ध
	योग साधना (दीर्घ समय)	24		
$H_0$1.2	छात्राओं की मानसिक योग्यता	26	+. 69	उच्च धनात्मक सह-सम्बन्ध
	योग साधना (दीर्घ समय)	26		

उपरोक्त तालिका सं**0-01** के अंकित मानों से स्पश्ट हो रहा है कि परिकल्पना $H_0$1.1 के छात्रों के सह-सम्बन्ध गुणांक का परिकलित मान +.77 प्राप्त हुआ। जो सह-सम्बन्ध गुणांक तालिका में उच्च धनात्मक सह-सम्बन्ध को दर्शाता है। अतः शून्य परिकल्पना $H_0$1.1 अस्वीकृत औ शोध परिकल्पना $H_0$1.1 स्वीकृत होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों की मानसिक योग्यता का योग साधना (दीर्घ समय) के मध्य उच्च धनात्मक सह-सम्बन्ध है।

परिकल्पना $H_0$1.2के छात्राओं के सह-सम्बन्ध गुणांक का परिकलित मान +. 69 प्राप्त हुआ। जो सह-सम्बन्ध गुणांक तालिका में उच्च धनात्मक सह-सम्बन्ध को दर्शाता है। अतः शून्य परिकल्पना $H_0$1.2अस्वीकृत शोध परिकल्पना $H_0$1.2स्वीकृत होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं की मानसिक योग्यता का योग साधना (दीर्घ समय) के मध्य भी उच्च धनात्मक सह-सम्बन्ध है।

H_2- **परिकल्पना परीक्षण**

उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं की मानसिक योग्यता एवं योग साधना

(लघु समय) के प्राप्तांक तालिका सं. – 02

H_2	चर/समूह संख्या	संख्या	सह-सम्बन्ध गुणांक परिणाम	परिणाम
$H_0$2.1	छात्रों की मानसिक योग्यता	23	+.46	परिमित धनात्मक सह-सम्बन्ध
	योग साधना (लघु समय)	23		
$H_0$2.2	छात्राओं की मानसिक योग्यता	27	+. 34	निम्न धनात्मक सह-सम्बन्ध
	योग साधना (लघु समय)	27		

उपरोक्त तालिका सं.-02 के विश्लेशण से स्पश्ट होता है कि परिकल्पना $H_0$2.1 के छात्रों के सह-सम्बन्ध गुणांक का परिकलित मान +.46 प्राप्त हुआ। जो सह-सम्बन्ध गुणांक तालिका में परिमित धनात्मक सह- सम्बन्ध को दर्शाता है। अतः शून्य परिकल्पना $H_0$2.1 अस्वीकृत तथा शोध परिकल्पना $H_0$2.1 स्वीकृत होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों की मानसिक योग्यता का योग साधना (लघु समय) के मध्य परिमित धनात्मक सह-सम्बन्ध है ।

परिकल्पना $H_0$2.2 के छात्राओं के सह-सम्बन्ध गुणांक का परिकलित मान +. 34 प्राप्त हुआ। जो सह-सम्बन्ध गुणांक तालिका में निम्न धनात्मक सह- सम्बन्ध को दर्शाता है। अतः शून्य परिकल्पना भ्02ण्2 स्वीकृत शोध परिकल्पना $H_0$2.2 अस्वीकृत होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं की मानसिक योग्यता का योग साधना (लघु समय) के मध्य निम्न धनात्मक सह-सम्बन्ध है।

कुमार, रवी (2016) ने ''स्वास्थ्य प्रबन्धन में योगा और आयुर्वेद'' शीर्शक पर शोध कार्य किया जिसमें निष्कर्षत: पाया कि योगाभ्यास करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक संतुलन, कार्यक्षमता, निर्णय क्षमता, तनाव अवसाद रहित, स्मरण शक्ति एवं एकाग्रता एवं बुद्धिलब्धि में अत्यधिक सार्थकता पायी गयी।

निष्कर्ष

उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों एवं छात्राओं की मानसिक योग्यता का योग साधना (दीर्घ समय) के मध्य उच्च धनात्मक सह-सम्बन्ध है ।उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों की मानसिक योग्यता का योग साधना (लघु समय) के मध्य परिमित धनात्मक सह-सम्बन्ध है। जबकि छात्राओं की मानसिक योग्यता का योग साधना (लघु समय) के मध्य निम्न धनात्मक सह-सम्बन्ध है।

योग एक कला है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ता है और हमें मजबूत और शांतिपूर्ण बनाता है। योग आवश्यक है क्योंकि यह हमें फिट रखता है, तनाव को कम करने में मदद करता है और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखता है और एक स्वस्थ मन ही अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है। योग एक व्यक्ति में शांति के स्तर को बढ़ाता है और उसके आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाने तथा उसे खुश रहने में मदद करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति एक अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में अधिक काम कर सकता है। आजकल जीवन बहुत तनावपूर्ण है और हमारे आसपास बहुत प्रदूषण है। यह कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण है। अतः 30 से 45 मिनट का योग हर दिन आपके स्वास्थ्य को अच्छा रहने में मदद कर सकता

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि योग एक चमत्कार है और अगर इसे किया जाए तो यह आपके पूरे जीवन का मार्गदर्शन करेगा। प्रति दिन 30 से 45 मिनट योग आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन को बढ़ावा देने के द्वारा आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है।

सन्दर्भ सूची

कुमार, रवी (2016); ‘‘स्वास्थ्य प्रबन्धन में योगा और आयुर्वेद’’, शोध गंगा, http://hdl.handle.net/10603/161492

गुप्ता, एस0पी0 (2015); उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान, इलाहाबाद : शारदा पुस्तर भवन, पृ0सं0-309.

विश्वनाथन के0 (2015); योग शिक्षा (प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा-डी0एल0एड0), राश्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिशद, नई दिल्ली : सेंट जोसेफ प्रेस, पृ0सं0-24-26.

सिंह, जुगलाल (2015); योग शिक्षा (एम0एड0 कार्यक्रम), राश्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिशद, नई दिल्ली : सेंट जोसेफ प्रेस, पृ0सं0-32.

गुप्ता, एस0पी0 (2014); अनुसंधान संदर्शिका, इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन, पृ0सं0-110, 325, 345.

नागराजन, करूणा (2014); ‘‘योग शिक्षा’’, नई दिल्ली : छब्ज्म्ए सेंट आफिस प्रेस, पृ0सं0-64.

सिंह, अरूण कुमार (2014); शिक्षा मनोविज्ञान, पटना : भारती भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, पृ0सं0-910.

निधि (2007-08); ‘‘योग दर्शन में शिक्षादर्शन और उनकी समसामयिकता’’, लघु शोध प्रबन्ध (एम0एड0) लॉयड इन्स्टीटयूट आफ मैनेजमेंट टैक्नोलॉजी, ग्रेटर नोएडा सम्बद्ध चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, पृ0सं0-10-13.

https://shodhganga.inflibnet.ac.in/simple-search?query=yoga&sort_by=score&order=desc&rpp=10&etal=0&start=10

https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97

https://www.onlymyhealth.com/hindi/diet-fitness/yoga

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/324835/9789241565707-eng.p

https://www.amarujala.com/photo-gallery/lifestyle/yoga-and-health/best-yoga-for-mental-health-how-to-make-your-mind-sharp-and-intelligent

https://translate.google.co.in/

https://en.wikipedia.org/wiki/Yoga

डांग जिले की आदिवासी महिलाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण की समस्याएँ और समाधान

डॉ. पिन्कल चौधरी*
जिज्ञासा चौधरी**

सारांश

महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल महिलाओं को सशक्त बनाना नहीं है, बल्कि यह परिवार, समाज, और राष्ट्र के विकास की दिशा में एक ठोस कदम है। जब हर महिला शिक्षित और आत्मनिर्भर होगी, तब हमारा राष्ट्र सशक्त और आत्मनिर्भर बनेगा। डांग जिले की आदिवासी महिलाओं की शिक्षा में सुधार और सशक्तिकरण एक समग्र दृष्टिकोण की मांग करता है जो महिलाओं की वास्तविकताओं को समझे और उन्हें बाधाओं से मुक्त कर उनके अधिकार दिलाए। न केवल बुनियादी ढाँचे का सुधार और सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण और संरचनाओं में भी परिवर्तन लाना होगा। इसके लिए भेदभाव की परतों को पहचानना, आर्थिक और सामाजिक समर्थन, सुरक्षा और संरचनात्मक सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण और महिला शिक्षकों की भागीदारी, सरकारी नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन, बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। डांग जिले ने लिंग अनुपात और महिला साक्षरता में प्रगति की है, लेकिन बाल लिंग अनुपात और अन्य सामाजिक मुद्दों पर सुधार के लिए सशक्त कदम उठाने की जरूरत है। आदिवासी महिलाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए गुजरात सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष योजनाएं लागू की गई है। शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति में सुधार, बुनियादी ढाँचे में सुधार, और माता-पिता व समुदाय को जागरूकता से महिला सशक्तिकरण की चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। साथ ही, क्षेत्रीय और सामाजिक-आर्थिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए स्थानीय स्तर पर सरकारी एवं बिन सरकारी संस्थाओं का योगदान भी सराहनीय है।

बीज शब्द: आदिवासी महिलाएं , महिला शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, डांग जिला, महिला साक्षरता, शिक्षक प्रशिक्षण, आर्थिक और सामाजिक समर्थन

प्रस्तावना

डांग जिला गुजरात राज्य के दक्षिणी भाग में 20.39° से 21.05° उत्तर अक्षांश और 73.29° से 73.51° पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। इसकी सीमाएं महाराष्ट्र राज्य से सटी हुई हैं। डांग जिला 1766 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यह गुजरात का सबसे कम आबादी वाला आदिवासी जिला है, जिसकी कुल जनसंख्या 2,28,291 है। डांग की जनसंख्या में लगभग 95% लोग अनुसूचित जनजाति और 0.43 % अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित हैं। डांग का साक्षरता स्तर 75.16% है, जो शिक्षा के प्रति यहां की जनता की रुचि को दर्शाता है (गुजरात राज्य जनगणना, 2011; डांग जिला पंचायत, 2024)।

जिले में मुख्य रूप से डांगी भाषा बोली जाती है, जो स्थानीय सांस्कृतिक पहचान को प्रकट करती है। जिले की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है। खेती यहां के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। लेकिन पथरीली भूमि, पहाड़ी इलाका और पानी संग्रह जैसे की डैम की कमी के कारण खेती और दैनिक जीवन में पानी की कमी रहती है। सापुतारा जैसे पर्यटन स्थलों के कारण लोगो को आर्थिक सहाय मिल जाती है। डांग जिला अपनी अनूठी आदिवासी संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और सीमित आबादी के कारण विशेष महत्व रखता है। यह क्षेत्र न केवल गुजरात की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है बल्कि यहां की जनजातीय परंपराएं और रहन-सहन भी विशिष्ट हैं।

तालिका 1: लिंग के अनुसार डांग जिले की जनसंख्या

विवरण	2001	2011
वास्तविक जनसंख्या	1,86,729	2,28,291
पुरुष	93,974	1,13,821
महिला	92,755	1,14,470

स्रोत: गुजरात राज्य जनगणना, 2011; डांग जिला पंचायत, 2024

*डॉ. पिन्कल चौधरी, सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग (केन्द्रीय शिक्षा संस्थान), दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली – 110007।
**जिज्ञासा चौधरी, शिक्षक, श्री खुदीराम बोस प्राथमिक शाला, सूरत, गुजरात - 395002।

तालिका 2: डांग जिला लिंग अनुपात

	2001	2011
लिंगानुपात प्रति)1000)	987	1006
बाल लिंग अनुपात)0-6 आयु(	974	964

स्रोत: गुजरात राज्य जनगणना, 2011; डांग जिला पंचायत, 2024

जैसे की तालिका 1 में दिखाया है, डांग जिले में महिलाओं की संख्या का अधिक होना एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन यह क्षेत्र अभी भी विकास और बुनियादी सेवाओं की कमी से जूझ रहा है। जनसंख्या में वृद्धि सामाजिक और आर्थिक दबाव को दर्शाती है। डांग जिले की जनसांख्यिकी विकास की संभावनाओं के साथ-साथ सामाजिक चुनौतियों का भी संकेत देती है। तालिका 2 में भी देख सकते है की बाल लिंग अनुपात में गिरावट चिंता का विषय है और इसके पीछे के कारणों (जैसे सामाजिक पूर्वाग्रह या स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता) को संबोधित करना होगा।सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महिला शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण पर अधिक ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में पहल

ब्रिटिश काल में भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नेतृत्व में विभिन्न सामाजिक धार्मिक आंदोलनों ने भारत में महिला शिक्षा पर जोर दिया। महात्मा ज्योतिबा फुले, पेरियार और बाबा साहेब अम्बेडकर भारत में निचली जातियों के नेता थे, जिन्होंने भारत की महिलाओं को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न पहल की है (सुगुना, 2011; कुमार और संगीता, 2013)। भारत के संविधान में भी महिला सशक्तिकरण को अनुच्छेद 46: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 21ए: राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उस तरीके से प्रदान करेगा जैसा राज्य कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है। (छियासीवाँ संशोधन अधिनियम, 2002) और अनुच्छेद 15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध भी भेदभाव को खतम करने की बात करता है। विश्व बैंक ने सुझाव दिया है कि महिलाओं का सशक्तिकरण सभी सामाजिक विकास कार्यक्रमों का एक प्रमुख पहलू होना चाहिए (विश्व बैंक, 2001)। महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा तक समान अवसर सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। क्योंकि भेदभाव को खत्म करने, शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने, निरक्षरता को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा ये विशेष उपाय किए गए हैं।

डांग जिले में महिलाओं की स्थिति

महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में अनेक सामाजिक, आर्थिक और संरचनात्मक चुनौतियाँ हैं। विशेष रूप से डांग जैसे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में ये बाधाएँ अधिक जटिल हो जाती हैं।डांगी आदिवासी महिलाओं की स्थिति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यंत दयनीय हैं। उनके लिए परिवार को दो वक्त का भोजन जुटाना भी एक बड़ी चुनौती है। डांग जिले में महिलाओं और बच्चों की स्थिति उनके अधिकारों और आवश्यकताओं की अनदेखी को दर्शाती है। डांग जिले में महिलाओं की स्थिति समाज के मानव विकास स्तर को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। इतनी चुनौतियों के बावजूत लड़कियों को सक्षम बनाया जाए तो वह परिवार और देश का नाम भी ऊँचा कर सकती है जिसका उदाहरण सरिता गायकवाड है जिन्हों ने एशियन गेम्स मे 400 मीटर की रिले दौड़ मेभारत को स्वर्ण पदक जीताया था।

महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में बाधाएँ एवं समस्याएँ

साक्षरता और शिक्षा

महिला साक्षरता में उल्लेखनीय सुधार (2001: 48.51%, 2011: 67.38%) ने महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक बदलाव का संकेत दिया है।महिला साक्षरता में तेजी से सुधार डांग जिले में महिलाओं की शिक्षा पर बढ़ते ध्यान को दर्शाता है। साक्षरता में सुधार सकारात्मक है, लेकिन पुरुषों और महिलाओं के बीच साक्षरता का अंतर अब भी बना हुआ है।

तालिका 3: डांग जिला लिंगवार साक्षरता दर

विवरण	**2001**	**2011**
औसत साक्षरता	**59.65**	**75.16**
पुरुष साक्षरता	70.68	83.06
महिला साक्षरता	48.51	67.38

स्रोत: गुजरात राज्य जनगणना, 2011

तालिका 4: डांग जिला में शाला में बच्चों का नामांकन

औसत नामांकन	64224
लड़कों	50.42 %
लड़कियां	49.58 %

स्रोत: यूडाइस+ 2024

डांग जिले में लड़कों और लड़कियों के नामांकन में समता होने के बावजूद, जनजातीय समुदाय और विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा के लिए कई चुनौतियाँ हैं।लड़कियों की साक्षरता दर लड़कों की तुलना में कम है, जो राष्ट्रीय साक्षरता दर में कमी लाती है। प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा तक लड़कियों का नामांकन दर पुरुषों की तुलना में काफी कम है।शिक्षा और साक्षरता दर के विस्तार में नामांकन का महत्वपूर्ण स्थान है। नामांकन दर को प्रभावित करने वाले कारक बाहरी और आंतरिक दोनों होते हैं। असर 2023 के अनुसार डांग जिले में 99.6% बच्चे (6-14 वर्ष) सरकारी स्कूलों में नामांकित हैं। लेकिन कक्षा 2 से 5 तक के 9.8 % बच्चे ही पढ़ सकते थे और 10.2 % अंकगणित कर सकते थे। कक्षा 6 से 8 में 21.7% पढ़ सकते थे और 17.3 % अंकगणित कर सकते थे। यह एक चिंता का विषय है और शिक्षा में गुणवत्ता लाकर और बेहतर बनाने की आवश्यकता है।

डांग जिले में ड्रॉपआउट दर से जुड़ी समस्याएँ

डांग जिले में शिक्षा की स्थिति को समझने के लिए ड्रॉपआउट और पुनरावृत्ति दर का विश्लेषण करना आवश्यक है।

डीआईएसई रिपोर्ट, एनयूईपीए (2010) के अनुसार 2008-09 के लिए डांग जिले में आहवा ब्लॉक में 7वीं कक्षा ड्रॉपआउट दर 88. 5 % रहा था। डीआईएसई रिपोर्ट 2021-22 में, ड्रॉप आउट अनुपात 17.55 प्रतिशत था, जिसमें से 17.19 लड़कियां और 17.91 लड़के थे। डीआईएसई रिपोर्ट 2022-23 के मुताबिक लड़कियों का ड्रॉपआउट दर 23.30 % है (यूडाइस 2022, 2023)। डांग जिले के स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे और सामाजिक जागरूकता दोनों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। बेहतर सुविधाओं और जागरूकता के माध्यम से शिक्षा के प्रति रुचि और नामांकन को बढ़ावा दिया जा सकता है।

डांग जिले जैसे ग्रामीण आदिवासी जिले में महिलाओं की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण में बहुत से कारक जिम्मेदार होते है जिनका बारीकी से अध्ययन करना जरूरी है। महिला सशक्तिकरण में बढ़ते कदम हमें बुनियादी सुविधाएँ तो दे सकते है, लेकिन उनकी जमीनी हकीकत को देखना और गुणवत्ता की पुष्टि करना अति आवश्यक हैं। इस अध्ययन में निम्नलिखित कारकों पर चर्चा की है।

बाहरीकारक

पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति: निर्देशन पद्धति और पाठ्यक्रम सामग्री छात्रों के लिए कम रुचिकर या कठिन हो सकती है। सांस्कृतिक अनुलक्षी और समकालीन पाठ्यक्रम बच्चों को शिक्षा में रुचि बनाए रखने में मदद करता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा फाउंडेशनल स्टेज NCFS-2022 और स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCFSE 2023 में भी शालाकीय पाठ्यक्रम को विद्यार्थीकेन्द्री और उनके सांस्कृतिक एवं प्रादेशिक संदर्भ में अनुकूल बनाने पर बल दिया है। शिक्षक को भी अध्यापन और गतिविधि स्थानिकरूप से अनुकूल बनाने की बात कही है। गाँव की लड़कियों और लड़कों को खेलकूद में ज्यादा रुचि होती है। पाठ्यचर्या खेलकूद अनुलक्षी या गतिविधि केन्द्री करने से भी लाभ मिल सकता है। साथ ही में, स्थानीय शिक्षक-शिक्षिकाओं की अनुपलब्धता लड़कियों को शिक्षण संस्थानों में सहज महसूस नहीं करने देती।

बुनियादी सुविधाओं की कमी

डांग जिला पंचायत द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में 2008-09 बुनियादी सुविधाएं 378 स्कूलों में से विद्युतीकरण 314 में, स्वच्छता 335 में पेय जल 254 में पायी गई थी। (डांग जिला पंचायत शिक्षा समिति की रिपोर्ट 2013)। रामी (2012) ने अपने अध्ययन में पाया की स्वच्छता सुविधाओं की स्थिति स्कूलों में बहुत खराब थी। उन्हों ने यह भी पाया की कुछ शौचालय उपयोग करने योग्य स्थिति में नहीं थे। पीने के पानी की सुविधाएं चिंताजनक थी, क्योंकि केवल 254 स्कूलों में पीने के पानी की सुविधाएं थी । डांग जिला शिक्षा निरीक्षक के अनुसार कक्षाओं की कमी के कारण ड्रॉप आउट अनुपात आंकड़े बढ़ सकते हैं (सैयद, 2021)। डांग जिले में सभी 489 स्कूलों मे से बालिकाओं के लिए अलग शौचालय की सुविधा 93.66% है (यूडाइस+2024)। स्कूलों में स्वच्छता और पानी की अपर्याप्तता बच्चों के नामांकन और उपस्थिति को बाधित करती है।शौचालयों की खराब स्थिति और अन्य बुनियादी ढांचे की उपेक्षा बच्चों के लिए स्कूल जाने के अनुभव को नकारात्मक बनाती है।साझा शौचालय होने के कारण, विशेष रूप से किशोरावस्था में, लड़कियाँ असहज महसूस करती हैं और स्कूल छोड़ देती है।

तालिका 5: डांग जिले में कुल और अलग से लड़कियों के लिए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या

विवरण	केन्द्र सरकार संचालित	शिक्षा विभाग, गुजरात सरकार संचालित	जनजातीय/ समाज कल्याण विभाग संचालित	स्थानीय निकाय/ एमएसबी	अनुदान सहायता विद्यालय	निजी (प्राइवेट)	कुल
कुल स्कूल	1	31	14	0	19	8	73
सिर्फ लड़कियों के लिए स्कूल	0	0	3	0	1	0	4

स्रोत: यूडाइस+ 2024; स्कूल आयुक्तालय, गुजरात सरकार (2023)

डांग जिले में कुल 41 माध्यमिक और 32 उच्चतर माध्यमिक शालाएँ है। तालिका 5 के उल्लेखनीय माहिती के अनुसार सिर्फ लड़कियों के लिए मात्र चार शालाएँ है। यह संकेत है की और शालाएँ और सुविधाओं की जरूरत है।

कक्षा में छात्र और शिक्षकों उपस्थिति

डांग जिले में पूरे गुजरात राज्य में सबसे अधिक बारिस होती है। अक्सर बारीस की ऋतु में भारी वर्षा में भूस्खलन और नदियों में पानी के कारण बच्चे और शिक्षक शाला तक पहुच नहीं पाते है। कई स्कूल में तो उन्हें पानी से गुजर कर जाना पड़ता हैं। ऐसे समय पर शिक्षकों की संख्या और उनकी अनुपस्थिति छात्रों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करती है।वैसी ही परिस्थिति ठंड के मौसम में और फसल कटाई के समय पर परिवार पलायन करने से छात्रों की अनुपस्थिति से होती है। कई बार शिक्षक बिन शैक्षिक गतिविधि जैसे की चुनाव, जनगणना, स्वास्थ्य संबंधी गतिविधि में शामिल होने के कारण कक्षा में अनुपस्थित रहते हैं। डांग जिले में कुल 2262 शिक्षको में से महिला शिक्षक 45.18 % है और 17.38 % शाला बिना महिला शिक्षिक वाली है। (डीआईएसई, 2024)। महिला शिक्षकों की कमी और असुविधा होने से महामारी जैसी समस्याओं के व्यक्त लड़कियां कई बार असहज महसूस करती है।

आंतरिककारक

माता-पिता की शैक्षिक पृष्ठभूमि:जनजातीय क्षेत्रों में माता-पिता अक्सर अशिक्षित होते हैं और काफी स्कूल जानेवाले बच्चें पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी होते है। अशिक्षित माता-पिता बच्चों की पढ़ाई को प्राथमिकता नहीं देते। शिक्षा की महत्ता और उसकी दीर्घकालिक लाभ की समझ का अभाव भी बच्चों के स्कूल छोड़ने का कारण बनता है।

गरीबीऔरपलायन:कृषि और पशुपालन से पर्याप्त आय न होने के कारण परिवार पलायन करते हैं। गरीबी और पारिवारिक आय बढ़ाने के लिए बच्चों को काम में शामिल करना।वे निर्माण मजदूरों के रूप में काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं या गन्ना काटने के लिए मजदूरों के रूप में चीनी उत्पादक क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। गरीब परिवार अपनी आय के संसाधनों को शिक्षा में लगाने से कतराते हैं। प्रवास और मौसमी कामकाज के कारण बच्चों की नियमित उपस्थिति बाधित होती है।जिससे बच्चों की शिक्षा बाधित होती है (सिंह और एबेनेज़र, 2013)।

सामाजिकदृष्टिकोण

माता-पिता बेटी की शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता है कि शादी के बाद उसे केवल गृहिणी बनना है।कई बार माता-पिता लड़कियों का विवाह कम उम्र में कर देते है। शिक्षा और अच्छे मातृत्व के बीच के संबंध को अभी भी समाज में पर्याप्त मान्यता नहीं मिली है। कुछ

माता-पित पर अपनी लड़कियों को अपने लड़कों की तरह औपचारिक शिक्षा के लिए विशेष रूप से उच्च स्तर पर भेजने के लिए अनिच्छुक होते हैं।

आर्थिकसीमाएँ

शहरी और शिक्षित महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के पास कम रोजगार और गतिशीलता के अवसर होते हैं। गरीब परिवारों में सीमित संसाधनों के कारण पहले लड़कों को स्कूल भेजा जाता है।लड़कियों को घर और खेती के काम में मदद करनी पड़ती है, जिससे उनकी शिक्षा बाधित होती है।बेटे को प्राथमिकता देने की प्रथा लड़कियों की शिक्षा के अवसरों को और कम कर देती है।

स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं

स्वास्थ्य सेवाओं की कमी बच्चों की स्थिति को और खराब बनाती है। डांग जिले के 311 गांवों के लिए केवल एक अस्पताल और लगभग 57 स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध हैं। यह स्वास्थ्य सुविधाओं की गंभीर कमी को दर्शाता है। जिला स्वास्थ्य कार्यालय के अनुसार, लगभग 70% आबादी कुपोषण से पीड़ित है। महिलाएं व्यापक त्वचा रोगों जैसे खुजली और पानी का दाद से भी ग्रस्त हैं। बच्चों में पोषण की कमी के कारण उनका समुचित विकास बाधित होता है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, कुपोषण, और आर्थिक अस्थिरता जैसे मुद्दे तत्काल ध्यान और समाधान की मांग करते हैं। महिलाओं और बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और पोषण कार्यक्रमों पर जोर देने की आवश्यकता है।

सुरक्षाऔरनिर्णयलेनेकीकमी:

महिलाओं के पास सुरक्षा, निर्णय लेने की स्वतंत्रता और गतिशीलता के सीमित अवसर हैं।विशेष रूप से आदिवासी और ग्रामीण महिलाओं के लिए, ये संकेतक और भी कम हैं।सामंती हिंसा, तस्करी, यौन शोषण, और घरेलू हिंसा महिला सशक्तिकरण की गंभीर बाधाएँ हैं। सामाजिक कलंक और परिवार द्वारा त्यागे जाने का डर महिलाओं को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आगे आने से रोकता है।

डांग जिले जैसे ग्रामीण आदिवासी जिले में महिलाओं की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए भेदभाव की परतों को पहचानना, आर्थिक और सामाजिक समर्थन, सुरक्षा और संरचनात्मक सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण और महिला शिक्षकों की भागीदारी, सरकारी नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन, बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। डांग जिले ने लिंग अनुपात और महिला साक्षरता में सुधार है, लेकिन बाल लिंग अनुपात और अन्य सामाजिक मुद्दों पर सुधार के लिए सशक्त कदम उठाने की जरूरत है। डांग जिले में ड्रॉपआउट दर को कम करने के लिए भी ठोश कदम उठाए गए है। डांग जिले में महिला सशक्तिकरण के लिए केन्द्रीय सरकार, गुजरात सरकार और विविध गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा विशेष कदम उठाएँ गायें हैं जिसकी चर्चा निम्न है।

डांग जिले में महिलाशिक्षाऔरसशक्तिकरण की समस्याओं का समाधान और सुझाव

महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने और उनके सशक्तिकरण के लिए कई चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है। यह केवल सुविधाएं प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक संरचनाओं और भेदभाव की गहरी परतों को भी संबोधित करना है।डांग जिले में लड़कियों के लिए शिक्षा में बाधाओं को दूर करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता है। जब स्कूल सुविधाएँ और समाज दोनों अनुकूल बनेंगे, तभी लड़कियों के नामांकन और शिक्षा को सशक्त किया जा सकेगा।

बाहरी कारकों से जुड़ी समस्याओं का समाधान:

शिक्षकों की उपस्थिति और प्रशिक्षण:राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी कहा गया है की ***"सर्वप्रथम, शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द और समयबद्ध तरीके से भरा जाएगा – विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में, जहा शिक्षक-बच्चों का अनुपात दर ज्यादा हो या जहा साक्षरता की दर निम्न हो, वहा स्थानीय शिक्षक या स्थानीय भाषा से परिचित शिक्षकों को नियुक्त करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।"*** (2.3, पृ. 12). शिक्षक को विध्यार्थियों को अच्छे से शिक्षा अधिगम में सामील करने की जरूरत है। शिक्षकों को जनजातीय समुदायों की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षित किया जाए। पाठ्यक्रम को अधिक सुलभ और प्रासंगिक बनाने के लिए संशोधन किया जाए। स्थानीय शिक्षक-शिक्षिकाओं की भर्ती करना भी जरूरी है।

बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ करना:

सभी स्कूलों में पीने का पानी, स्वच्छ शौचालय और साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए।विशेष रूप से लड़कियों के लिए अलग शौचालय और सैनिटेशन सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ।मध्याहन भोजन में विद्यार्थियों को पोषित खाना उपलब्ध करवाने की भी आवश्यकता है। शिक्षा क्षेत्र में अधिक निवेश और स्कूल सुविधाओं की नियमित निगरानी की जाए।

तालिका 6: डांग जिले की शालाओं में सुविधाएँ 2021-2022

	स्कूलों की संख्या	विद्युतीकरण	शौचालय	बालिकाओं के लिए अलग शौचालय	पेय जल
डांग	489	100%	92.23 %	93.66%	100 %

स्रोत: स्रोत: यूडाइस+ 2024

जैसे की तालिका 6 में दर्शाया है, डांग जिले के सभी स्कूलों में बिजली और पेय जल की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन बालिकाओं के लिए अलग शौचालय की समस्या अभि भी है।

बालिकाओं और शिक्षकों की शिक्षा में सक्रिय भागीदारी

शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए और प्रोत्साहन करने की आवश्यकता के लिए शिक्षा विभाग, गुजरात द्वारा शिक्षक की अनिवार्य उपस्थिति इसकी तरफ प्रसंशनीय कदम उठाए है। पुनरावृत्ति दर कम करने के लिए छात्रों को उनकी क्षमता के अनुसार अतिरिक्त सहायता और ट्यूशन प्रदान की जाए।छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति पर नियमित डेटा संग्रह और विश्लेषण किया जानेकी आवश्यकता है।ड्रॉपआउट दर के पीछे के कारणों का गहन अध्ययन किया जाए। शिक्षा तक पहुँच केवल स्कूलों की भौगोलिक उपलब्धता तक सीमित नहीं है। दूरदराज के इलाकों में स्कूलों की दूरी भी एक बाधा हैऔर छोटे बच्चों के नामांकन को प्रभावित करती है।

बालिकाओं की शिक्षा के लिए सरकारी पहल:

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी)

यह योजना अगस्त 2004 में भारत सरकार द्वारा कठिन क्षेत्रों में मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालय स्थापित करने के लिए शुरू की गई थी।डांग जिले में तीन केजीबीवी आहवा, वघई और सुबीर में कार्यरत है (समग्र शिक्षा,2024)।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)

राष्ट्रीय आदिवासी शिक्षा समिति की स्थापना एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)स्कूलों को बनाने, निधि समर्थन, रखरखाव, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए जनजातीय मामलों के जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई है। जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली आदिवासी बच्चों को उनके परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा प्रदान करना - जिसमें मूल्यों का समावेश, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, साहसिक गतिविधियाँ और शारीरिक शिक्षा का एक मजबूत घटक शामिल है। हाल डांग जिले में ईएमआरएस स्कूल आहवा, सापुतार, महाल, बरदीपाड़ा, मालेगाव, गोरखड़ी, चिंचली में स्थित है। (राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, 2024)

'राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना'

लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन योजनाएँ लागू की जाएँ विशेष शिष्यवृत्ति का प्रावधान है। जैसे की

केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना' मई, 2008 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को आठवीं कक्षा में उनके ड्रॉप आउट से रोकना और माध्यमिक स्तर पर अध्ययन जारी रखने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति प्रदान करना था। योजना के अंतर्गत कक्षा IX के चयनित छात्रों को प्रतिवर्ष 12000/- रुपये प्रति छात्र की एक लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं और राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में अध्ययन के लिए कक्षा X से XII में उनकी निरंतरता/नवीनीकरण सुनिश्चित किया जाता है (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता, 2024)।

डांग जिले में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) , एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) तथा जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) जैसी निवासी शालाएँ है जिसमे विद्यार्थियों को बेहतर पढ़ने के सुविधाएँ तथा स्वच्छ और उत्तम सुविधाएँ मिल जाती हैं। सरकारी छात्रवृत्ति के अलावा विशेष आर्थिक सहाय के लिए भी 'राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना' जैसी योजनाएँ उपलब्ध है। उसके अलावा कार्मेलाइट सिस्टर्स ऑफ चैरिटी - वेद्रुना 'ट्रस्ट' लड़कियों के लिए बोर्डिंग हाउस और बच्चों के लिए किंडरगार्टन और उपचारात्मक कक्षाएँ जैसी सुविधाएँ प्रदान कर रहा है।

बाहरी कारकों से जुड़ी समस्याओं का समाधान:

माता-पिता की जागरूकता:

माता-पिता को शिक्षा के महत्व और दीर्घकालिक लाभ के बारे में जागरूक करने के लिए सामुदायिक कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। सामुदायिक बैठकों और कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।सरकारी संस्थाएं और गैर सरकारी संस्थाएँ गाँवों में महिला सशक्तिकरणगैर औपचारिक शिक्षा गतिविधियाँ जैसे की सामाजिक जागरूकता, आय सृजन गतिविधियाँ, क्षमता निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, जल संचयन, साक्षरता कार्यक्रम आदि चला रहे है।

पलायन की समस्या का समाधान:

डांग के ग्राम्य विस्तार में ही रोजगार का अवसर प्रदान करना चाहिए और लोगों में जागरूकता फेलानी चाहिए। जिससे गाँव से पलायन की समस्या कम हो। प्रवासी परिवारों के बच्चों के लिए विशेष शिक्षण केंद्रों और मोबाइल स्कूलों की व्यवस्था की जाए।मौसमी काम के समय बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।कार्मेलाइट सिस्टर्स ऑफ चैरिटी - वेद्रुना 'ट्रस्ट' द्वारा डांग के आदिवासियों, विशेष रूप से आदिवासी महिलाओं और बच्चों, मुख्य रूप से लड़कियों के समग्र विकास को बढ़ावा दे रहा है। पिंपरी समुदाय की बहनों ने चिकित्सा और पोषण सहायता के माध्यम से गन्ने के खेतों में इन जरूरतमंद लोगों की सहायता करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

सामाजिकदृष्टिकोण बदलने की दिशा में:

लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन योजनाएँ शुरू की गई है ।बालिका शिक्षा के महत्व पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे है।सामाजिक समुदायों में लड़कियों की शिक्षा के महत्व पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएँ।माता-पिता को यह समझाने की आवश्यकता है कि लड़कियों की शिक्षा न केवल व्यक्तिगत बल्कि समाज के विकास के लिए भी आवश्यक है।

व्हाली दीकरी योजना: गुजरात सरकार संचालित यह योजना बेटियों की जन्म दर बढ़ाने, शिक्षा में ड्रॉपआउट अनुपात को कम करने और बाल विवाह की प्रथा को रोकने के उद्देश्य से लागू की गई है। पहली कक्षा में प्रवेश पर 4000 रुपये की सहायता, 9वीं कक्षा में प्रवेश पर 6000 रुपये की सहायता, 18 वर्ष की आयु में उच्च शिक्षा/विवाह सहायता के रूप में 1.00 लाख रुपये की सहायता मिलती है। (महिला एवं बाल विकास विभाग (डब्ल्यूसीडी), 2023).

स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान:

महिलाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलग अलग पहल के तहत सद्रध स्वास्थ्य सुविधाएँ दी जा रही है। चिरंजीवी योजना। के तहत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और सुरक्षित डिलीवरी की सुविधा प्रदान की जा रही है।जिसका लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार ले शकते है। भारत सरकार, राज्य सरकार तथा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नियमित स्वास्थ्य जांच तथा विशेषज्ञ द्वारा रोजमर्रा का भोजन बनाते समय पोषण तत्वों को बनाए रखने और एनीमिया से पीड़ित लड़कियों में हीमोग्लोबिन का स्तर जैसी समस्याओं के लिए मार्गदर्शन, लोह तत्व की कमी के लिए आयरन की दवाईया उपलब्ध किया जा रहा है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) जैसे विद्यालयों द्वारा मासिक स्वास्थ्य प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के द्वारा महिलाओं और किशोर लड़कियों के लिए मासिक स्वच्छता प्रबंधन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ावा दे रहा है।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुझाव:

महिलाओं की सुरक्षा के लिए सशक्त तंत्र बनाया जाना चाहिए।हिंसा के मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाए।सामाजिक भेदभाव और परंपरागत मान्यताएँ महिलाओं को औपचारिक शिक्षा और रोजगार में आगे बढ़ने से रोकती हैं।महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए बने कानूनों और नीतियों का क्रियान्वयन कमजोर है। ग्रामीण और अशिक्षित महिलाएँ अपने अधिकारों की जानकारी के अभाव में इन कानूनों का लाभ नहीं उठा पाती है।यौन और शारीरिक हिंसा के मामलों में सामाजिक कलंक महिलाओं को अपनी आवाज उठाने से रोकता है।बच्चों, महिलाओं तथा आदिवासी समुदाय में भारतीय संविधान, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, पॉक्सो एक्ट, और आयोग (NCST), साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण देना जरूरी है। भारतीय सरकार तथा गैर सरकारी संस्थान ऐसे जागरूकता कार्यक्रम चला रहे है।महिला सशक्तिकरण के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक अवसरों के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकार प्रदान किए जाएँ।

आर्थिकसशक्तिकरण:

महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाने चाहीएँ। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कौशल विकास केंद्र खोले जा रहे है। जनजातीय समुदाय में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष सरकारी नीतियाँ प्रभावी ढंग से लागू की गई हैं, जो निम्न है।

वन धन विकास कार्यक्रम (वीडीवीके)

जनजातीय मामलों का मंत्रालय भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राइफेड) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के माध्यम से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में जनजातीय महिलाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ जनजातीय लोगों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सहायता और समर्थन प्रदान करता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राइफेड) के माध्यम से महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में 2021-22 से 'प्रधानमंत्री जन जातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)' के तहत वन धन विकास कार्यक्रम (वीडीवीके) लागू किया है। (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, 2023)। डांग जिले मे पिंपरी, जामलापाड़ा, चिंचली, कुड़कस, डुंगरदा, सुसाद्रा, निशाणा, महाल, गरखड़ी, बरदीपाद, गलकुंड, शामगहान, सुबीर, पिपलदहाड़, पिपलादेवी, कालीबेल, वघई, साकरपाडा, जावडा और भेसकातरी में वन धन विकास केन्द्र है, जो महुवा के फूल, महुवा के बीज, इमली, शेहद, बाम्बू, लाख, गोंद, करंज के बीज जैसे लघु वन उपज (एम एफपी) का उत्पादन और संचालन सामील है। **(**ट्राइफेड-TRIFED, 2024)

आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई):

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) आदिवासी महिलाओं के लिए किसी भी आय सृजन गतिविधि को शुरू करने के लिए "आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई)" नामक एक विशेष योजना लागू की है। इस योजना के तहत, 2 लाख रुपये तक की परियोजना लागत का 90% तक ऋण 4% प्रति वर्ष की अत्यधिक रियायती ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है। आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एएसआरवाई) आदिवासी छात्रों को आसान ऋण प्रदान करती है, जिससे उन्हें अपनी पढ़ाई के दौरान ब्याज सब्सिडी के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलती है। इन योजनाओं का उद्देश्य उद्यमिता, शिक्षा और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करके आदिवासी आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है(महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, 2023; जनजातीय कार्य मंत्रालय, 2023)।

बड़ौदा ग्रामीण परामर्श केंद्र (बीजीपीके) - बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) द्वारा क्रेडिट परामर्श, वित्तीय साक्षरता और कृषि उत्पादों की कीमतों, वैज्ञानिक खेती आदि की जानकारी जैसी अन्य सेवाएं प्रदान करके ग्रामीण समुदाय की मदद करने के लिए बड़ौदा ग्रामीण परामार्श केंद्र (बीजीपीके) शुरू की गए थे। बेरोजगार युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान (बीएसवीएस) की स्थापना एक और पहल है। इसके अलावा, बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाओं जैसे स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), स्वर्ण जयंती शहर रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), आदि के तहत अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग को वित्तपोषित करने पर विशेष जोर दिया जाता है (बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान, 2023)। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों आरएसवीवाई कार्यक्रम के तहत गैर सरकारी संगठनों और टीडीओ द्वारा महिलाओं को नागली(रागी) पापड़ी और अन्य नागली उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। महिलाओं को वस्त्र निर्माण, लकड़ी का काम, बांस शिल्प, धातु कार्य, और विद्युत मशीनरी की मरम्मत जैसे कौशल में प्रशिक्षित किया गया।प्रशिक्षण का उद्देश्य महिलाओं को अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने में सक्षम बनाना है।छोटे उद्योग (एसएसआई) इकाइयों का योगदान न केवल रोजगार सृजन में योगदान देती हैं बल्कि स्थानीय संस्कृति और कौशल को भी संरक्षित करती हैं (सिंधी, 2012)।

आगा खान ग्रामीण सहायता कार्यक्रम भारत (एकेआरएसपीआई)

आगा खान ग्रामीण सहायता कार्यक्रम भारत (एकेआरएसपीआई) ने डांग जिले के में गैर-कृषि उद्यमों को बढ़ावा देने विभिन्न एकीकृत विकास गतिविधियों के माध्यम से डांगी समुदाय के विकास के लिए काम कर रही है, सामूहिक और व्यक्तिगत व्यवसायों सहित जिले में 250 से अधिक उद्यमों को बढ़ावा दिया है। सामूहिक उद्यमों में से एक 14 हितधारकों के साथ एक सिलाई इकाई है जो अच्छी तरह से काम कर रही है। एक परिधान विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने के उद्देश्य से जो स्थानीय समुदाय की जरूरतों को पूरा कर सके, संगठन ने डोकपटल और चिंचिली गांवों में सामूहिक उद्यमों के रूप में दो और सिलाई इकाइयों को बढ़ावा दिया। (भट्ट, 2023). यह कार्यक्रम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और विभिन्न कृषि प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए आदिवासी महिलाओं द्वारा कृषि कार्यो को व्यवस्थित करने और उपज के लिए बेहतर कीमतें सुरक्षित करने में सक्षम बना कर उनके निर्णय लेने के प्रभाव को बढ़ाना और उनकी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देना है (क्षत्रिय, 2023).

आदिवासी महिलायें और नाहरी केन्द्र

ग्रामीण महिलाओं के पास उद्यम शुरू करने के लिए मानव और गैर-मानवीय संसाधन होने के साथ-साथ एक नवोन्वेषी दिमाग और प्रेरणा की आवश्यकता होती है। ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते रोजगार का एकमात्र समाधान उद्यमिता है। यह उनकी अपनी सामाजिक व्यवस्था के भीतर कई लोगों के लिए रोजगार पैदा करने में मदद करता है (साथियाबामा, 2010)। आदिवासी लोग दोपहर के भोजन को 'नाहरी' कहते हैं। डांग जिले में आने वाले पर्यटक नाहरी केंद्र में भोजन कर शकते है। आदिवासी महिलाओं के लिए नाहरी सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि आदिवासी महिलाओं के लिए आजीविका का साधन बन गई है। 2006 में, जय अंबे महिला मंडल ने गंगपुर गांव में एक रेस्तरां "नाहरी" शुरू किया था। गंगपुर में नाहरी केंद्र की सफलता के बाद, अब डांग जिले में 7 और वलसाड जिले में 5 सहित कुल 13 नाहरी केंद्र चल रहे हैं। (टाइम्स ऑफ इंडिया, 2015; दिव्य भास्कर , 2019).

निष्कर्ष

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, **"यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं, तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं।"**यह कथन महिलाओं के सशक्तिकरण के महत्व को स्पष्ट करता है और उनके योगदान को समाज और राष्ट्र के विकास के लिए अपरिहार्य बनाता है।महिलाएँ केवल परिवार तक सीमित नहीं हैं; वे समाज और राष्ट्र की समृद्धि की धुरी हैं।उनकी भागीदारी से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और सामाजिक विकास तेज़ी से होता है। साक्षरता दर को बढ़ाने और महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए समुदायों को भी जागरूक करना होगा।डांग जिले की आदिवासी महिलाओं के सामने सामाजिक समानता, लिंगानुपात, और बेरोजगारी जैसी समस्याएँ हैं।इन समस्याओं के समाधान के लिए वित्तीय सहायता, उद्योगों का समर्थन और प्रेरणादायक नेतृत्व आवश्यक है।डांग जिले में महिलाओं और आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संस्थान सक्रिय हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति में सुधार करना है।इन कार्यक्रमों का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके कौशल का उपयोग करके आय सृजन में सहायता करना है। महिला सशक्तिकरण केवल सेवा प्रदान करने तक सीमित नहीं है; यह उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अधिकारों को सुनिश्चित करने और भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास भी है।

सन्दर्भ सूची

असर (ASER).(2023). ऐन्यूअल स्टैटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (रुरल) 2022. https://asercentre.org/wp-content/uploads/2022/12/aserreport2022-1.pdfसे लिया गया है।

असर (ASER).(2023). गुजरात ग्राम्य 2022 https://img.asercentre.org/docs/ASER%202022%20report%20pdfs/District%20estimates/gujarat.pdf से लिया गया है।

असर (ASER).(2024). ऐन्यूअल स्टैटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023: बेयोन्ड बसिक्स. https://asercentre.org/aser-2023-beyond-basics/से लिया गया है।

एन.सी.ई.आर.टी. (2022). राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा फाउंडेशनल स्टेज 2022. नई दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद.

एन.सी.ई.आर.टी. (2023). स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023. नई दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद.

एनयूईपीए (NUEPA). (2011). डीआईएसई डेटा का गणना पश्चात सर्वेक्षण: प्रमुख निष्कर्ष। नई दिल्ली: NUEPA

एम. एच. आर. डी. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा निती २०२०. नई दिल्ली: भारत सरकार.

कुमार, जे. और संगीता (2013). स्टेटस ऑफ़ वीमेन एजुकेशन इन इंडिया. Educationia Confab, 2(4), 162-178.

क्षत्रिय, डी. एस. (2023). ट्राइबल वीमेन इन गुजरात'स डांग स्क्रिप्ट सक्सेस स्टोरी विथ मल्टी -करोड़ एग्रीकल्चर बिज़नेस. https://www.newindianexpress.com/good-news/2023/Jul/22/tribal-women-in-gujarats-dang-script-success-story-with-multi-croreagriculture-business-2597554.html से लिया गया है।

गृह मंत्रालय. (2011). गुजरात राज्य जनगणना-2011. जनगणना संचालन निदेशालय - गुजरात। Retrieved from censusgujarat.gov.in/ से लिया गया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय (2024)। जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना: भारत में जनजातीय कल्याण के लिए सरकारी पहल https://pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=153246&ModuleId=3&reg=3&lang=2 से लिया गया है।

टाइम्स ऑफ इंडिया (2015). डांग वीमेन फाइन्ड रूट टु एम्पावरमेंट थ्रू थे स्टमक. https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/dang-women-find-route-to-empowerment-through-the-stomach/articleshow/49787537.cmsसे लिया गया है।

ट्राइबल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (TRIFED) (2024). वन धन योजना. जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार https://trifed.tribal.gov.in/vandhan-kendras-listसे लिया गया है।

डांग जिला पंचायत. (2024). जिला आकड़ाकीय रूपरेखा 2023-24 . आकड़कीय शाखा जिला पंचायत कचेरी https://dangdp.gujarat.gov.in/dang/documents/ankda-ruprekha-24.pdfसे लिया गया है।

डांग जिला पंचायत. (2013). डांग जिला पंचायत, शिक्षा समिति की रिपोर्ट [विभिन्न मुद्दे], आहवा, डांग. Retrieved from dangdp.gujarat.gov.in/dang/english/ से लिया गया है।

दिव्य भास्कर (2019). महिलाओं के लिए आजीविका का साधन बनी 'नाहरी' https://www.divyabhaskar.co.in/local/gujarat/navsari/news/nahri-becomes-a-means-of-livelihood-for-women-132233533.htmlसे लिया गया है।

बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान (2023). https://www.bankofbaroda.in/baroda-swarojgar-vikas-sansthanसे लिया गया है।

भट्ट, जी. (2023). ट्राइबल वुमन स्टिच अ न्यू फ्यूचर इन गुजरात'स डांग. https://www.villagesquare.in/tribal-women-stitch-a-new-future-in-gujarats-dang/ से लिया गया है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (2023)। जनजातीय महिलाओं का सशक्तिकरण। https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1908008 से लिया गया है।
महिला एवं बाल विकास विभाग (डब्ल्यूसीडी) (2023). व्हाली दीकरी योजना. गुजरात सरकार। https://wcd.gujarat.gov.in/initiativedetails?id=232से लिया गया है।
यूडाइस+ UDISE+ (2024). स्कूल डाटा कैप्चर. https://udiseplus.gov.in/#/en/page/udiseसे लिया गया है।
रामी, जी. (2012). स्टेटस ऑफ़ प्राइमरी एजुकेशन इन दी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ गुजरात: ए केस स्टडी ऑफ़ दी डांग डिस्ट्रिक्ट. International Journal of Rural Studies (IJRS),19(1), 1-6.
राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति। (2024). एकलव्य मोडेल रेसीडेंसीयल स्कूल. जनजातीय कार्य मंत्रालय https://nests.tribal.gov.in/से लिया गया है।
विश्व बैंक (2001). एनजेंडेरीन्ग डेवलपमेंट: थ्रू जेन्डर एक्वालिटी इन राइट्स, रिसोर्सेज, एण्ड वॉयस। न्यू योर्क, ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
वेद्रुना (2024). सपोर्टिंग सुगरकेन फार्म वर्कर्स: ए नोबल इनिशिएटिव बाय - कार्मेलाइट सिस्टर्स ऑफ चैरिटी - पिंपरी, गुजरात. https://vedruna.org/en/supporting-sugarcane-farm-workers-a-noble-initiative-by-carmelite-sisters-of-charity-pimpari-gujarat/से लिया गया है।
सथियाबामा, के. (2010). रुरल वुमन एमपोवर्मेंट एण्ड एन्टरप्रेनरशिप। वर्किंग पेपर आइडी 2475. ईसोशलसाइन्स
समग्र शिक्षा (2024). कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV). https://samagrashiksha.ssagujarat.org/en/kgbvसे लिया गया है।
सिंधी, एस. (2012). जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण में संभावनाएँ और चुनौतियाँ।. IOSR Journal Of Humanities And Social Science (JHSS) 6(1,) 46-54.
सिंह, जे.जी.पी., और एबेनेज़र, डब्ल्यू.डी. (2013). गुजरात के डांग जिले की मौसमी प्रवासन वाली जनजातियों के बीच बच्चों की शिक्षा. IJSR - International Journal of Scientific Research, 2(8), 112-113.
सुगुना, एन. (2011). शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण. ZENITH: International Journal of Multidisciplinary Research, 1(8).
सैयद के. (2021). कक्षा कक्षों की कमी: डांग के ज्वेरल आदिवासी छात्र 11वीं कक्षा में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. August 22, 2021 https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/deficit-of-classrooms-several-tribal-students-of-dang-struggle-to-get-admission-in-class-11-7464858/ से लिया गया है।
स्कूल आयुक्तालय, गुजरात सरकार (2023). एजुकेशन स्टेटिस्टिक्स बुक स्टटिस्टिक ऑन सेकन्डरी एण्ड हायर सेकन्डरी इन गुजरात स्टेट 2022-23. http://www.cos.gujarat.gov से लिया गया है।
स्कूल आयुक्तालय, गुजरात सरकार (2023). शैक्षिक सांख्यिकी पुस्तक: गुजरात राज्य में माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षा पर आँकड़े- 2022-23 http://www.cos.gujarat.gov से लिया गया है।
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता (2024). 'राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना. भारत सरकार. https://dsel.education.gov.in/से लिया गया है।

डी-मार्ट खुदरा स्टोर के उपभोक्ता क्रय व्यवहार पर एक अध्ययन

डॉ. धर्मेन्द्र सिंह *
डॉ. हरजिन्दर पाल सिंह सलूजा **
विकास कुमार देवांगन ***

सारांश

खुदरा व्यापार एक ऐसा व्यापार है, जो उपभोक्ताओं को अंतिम उत्पाद के रूप में वस्तुएं एवं सेवाएं तक पहुँचाने में सहायक होता है। इसी तरह डी-मार्ट स्टोर भी एक खुदरा बाजार है, जो उपभोक्ताओं को अंतिम उत्पाद के रूप में वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करती है। डी-मार्ट स्टोर में उपभोक्ताओं को एक ही छत के नीचे सभी तरह के घरेलू उत्पाद, उचित मूल्य एवं अच्छी किस्म की वस्तुएं मिलती है। इस शोध पत्र में डी-मार्ट खुदरा स्टोर के उपभोक्ता क्रय व्यवहार पर अध्ययन कर उनकी समीक्षा की गई है। इस अध्ययन में दुर्ग शहर के संदर्भ में डी-मार्ट स्टोर के प्रति उपभोक्ताओं के क्रय व्यवहार को जानने का प्रयास किया गया है। यह शोध पत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों पर आधारित है। इसमें समंकों का संग्रहण विभिन्न प्रकाशनों एवं रिपोर्ट, गूगल फार्म व इंटरनेट आदि के माध्यम से किया गया है। इस शोध पत्र में सुविधानुसार निदर्शन पद्धति एवं सरल प्रतिशत विश्लेषण विधि का प्रयोग किया गया है। इस अध्ययन में 300 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। इस अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि खुदरा स्टोर डी-मार्ट के उपभोक्ता क्रय व्यवहार के प्रति उत्तरदाता काफी हद तक सहमत है, जिसमें डी-मार्ट स्टोर में उपलब्ध उत्पाद, वस्तुओं का उचित मूल्य एवं अच्छी किस्म के वस्तुओं आदि से उपभोक्ता काफी हद तक प्रभावित हुए है। डी-मार्ट स्टोर दुर्ग शहर में खुलने से उपभोक्ता अत्याधिक संतुष्ट है।

बीज शब्द: खुदरा स्टोर, डी-मार्ट, उपभोक्ता क्रय व्यवहार, कीमत, गुणवत्ता

प्रस्तावना

खुदरा उद्योग एक खुदरा बाजार है, जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। यह खुदरा उद्योग देश के अलग-अलग राज्यों में संचालित है। खुदरा उद्योग जैसे बिग बाजार, विशाल मेगा मार्ट, वी-मार्ट, डी-मार्ट, रिलायंस फ्रेश, सुपर बाजार आदि खुदरा बाजार है जहाँ उपभोक्ताओं को एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की घरेलू सामग्री, उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, फुटवेयर, कपड़े आदि उत्पाद की उपलब्धता होती है। इन स्टोरों पर उपभोक्ताओं को उचित कीमत व अच्छी किस्म की वस्तुएं एवं सभी तरह के घरेलू उत्पाद की उपलब्धता होती है। जिससे ग्राहकों को इधर-उधर भटकना नहीं पड़ता है। इससे उपभोक्ता की समय की बचत होती है। खुदरा स्टोर में उपभोक्ता वस्तुओं को भौतिक रूप से देखकर क्रय करते है। इस तरह डी-मार्ट खुदरा स्टोर के प्रति उपभोक्ताओं का क्रय व्यवहार सकारात्मक है।

खुदरा व्यापार एक उद्यम स्तंभ है, जो अंतिम ग्राहक के रूप में उत्पादों की बिक्री से संबंधित है। यह थोक विक्रेताओं या उत्पादकों और उत्पाद के ग्राहकों के बीच हाइपरलिंक है। खुदरा व्यवसायों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है- बड़े पैमाने पर और छोटे पैमाने पर। मुख्य अंतर यह है कि छोटे पैमाने के खुदरा व्यवसाय छोटी किस्म की वस्तुओं तक ही सीमित रहते है। इसके विपरीत बड़े पैमाने के खुदरा व्यवसायों में उत्पादों की व्यापक विविधता होती है। रिटेल वितरण चैनल का अंतिम चरण है। खुदरा आदान-प्रदान कई रूप ले सकते है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि उत्पाद किसी स्टोर से खरीदे जाए बल्कि खुदरा आदान-प्रदान फोन पर, पुट-अप या मेल सेवा, डोर-टू-डोर प्रमोशन आदि के माध्यम से भी हो सकता है। उदाहरण के लिए एक स्टोर, एक सुपरमार्केट, ग्राहक का निवास या शायद एक व्यापारिक मशीन।

डी-मार्ट का परिचय

डी-मार्ट एक सुपरमार्केट चेन है जहाँ आपको हर दिन इस्तेमाल किए जाने वाले जरूरतों का उत्पाद मिलता है। इस कंपनी की शुरूआत राधाकिशन दमानी के द्वारा मई 2002 को मुंबई से किया गया था। डी-मार्ट कंपनी को एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड द्वारा प्रमोट किया जाता है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड एक भारतीय खुदरा निगम है, जो भारत में हाइपरमार्केट की एक श्रृंखला संचालित करता है। डी-मार्ट एक ऐसा स्टोर है, जो अभी वर्तमान में बड़े-बड़े शहरों में स्थित है लेकिन इस कंपनी की बिजनेस मॉडल शानदार है जिस कारण लोगों का सस्ता सामान भी मिल जाता है और कंपनी अपना ढ़ेर सारा मुनाफा भी कमा लेती है। आपने कई सारे सुपर मार्केट का नाम सुन रखा होगा जैसे विशाल मेगा मार्ट, रिलायंस फ्रेश मार्ट, बिग बाजार आदि लेकिन अभी के समय में इन सभी की तुलना में डी-मार्ट काफी सस्ता और अच्छा घरेलू उत्पादों को प्रदान करता है। 31 मार्च 2019 तक डी-मार्ट में कुल 7,713 स्थायी कर्मचारी काम कर रहे थे और 33,597 कर्मचारी अनुबंध के आधार पर काम पर रखे गए थे।

*डॉ. धर्मेन्द्र सिंह, सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य विभाग), शासकीय एन.सी.जे. महाविद्यालय, दल्लीराजहरा, जिला-बालोद (छ.ग.)।
**डॉ. हरजिन्दर पाल सिंह सलूजा, प्राध्यापक (वाणिज्य), शासकीय वी.वाय.टी. स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
***विकास कुमार देवांगन, शोधार्थी, वाणिज्य विभाग, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव (छ.ग.)।

शोध साहित्य का अध्ययन

Vineeta Gangal and A Kumar (April 2013)ने अपने शोध पत्र में यह निष्कर्ष निकाला है कि बिग बाजार को मूल्य निर्धारण नीतियों के लिए अधिक पसंद किया जाता है एवं इसके संरक्षक रणनीतियों में विविधता पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि छात्रों एवं युवाओं का उच्च अनुपात है जो अपने आय के लिए अपने माता-पिता पर निर्भर रहते है। **(Gangal & Kumar, 2013)**

Neeraj Dubey and Richa Sinha (2017) ने अपने शोध पत्र में यह निष्कर्ष निकाला है कि बिग बाजार ने खुदरा उद्योग में स्वयं के लिए एक खुदरा स्टोर के रूप में एक विशिष्ट बाजार का निर्माण किया है, जो सभी वर्गों के ग्राहक एवं उनकी हर जरूरतों को उचित मूल्य पर पूरा करता है। इन्होनें बताया है कि केवल एक भारतीय ही एक भारतीय की भावना को समझ सकता है इसलिये इन्होनें ‘‘सब से सस्ता दिन‘‘ सभी वर्गीय परिवार वाले शहरी नागरिक शॉपिंग मॉल में स्थित बिग बाजार स्टोर में पूर्व लाभ पाने के लिए आनंद के माहौल के साथ जाते है। जिससे यह बिग बाजार बन गया और अपने प्रतियोगियों को हराया है। इन्होनें दुकानदारों की विजुअल मर्चेडाइजिंग और आवेग खरीददारी के बीच एक मजबूत संबंध को बताया है। **(Dubey & Sinha, 2017)**

Abdul Rahim Munshi (Aug 2018)ने अपने शोध पत्र में निष्कर्ष पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि वायुमंडलीय परिवर्तन उपभोक्ता के क्रय व्यवहार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। जिससे इस अध्ययन में समान परिणाम दिखाया गया है। डी-मार्ट स्टोर के संबंध में उत्पाद खरीद व्यवहार पर उत्पाद वर्गीकरण और भीड़ घनत्व के महत्व पर प्रकाश डाला है। वडोदरा क्षेत्र के अध्ययन क्षेत्र पर सिफारिशों के आधार पर इन परिणामों से डी-मार्ट स्टोर के उत्पाद वर्गीकरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भीड़ से बचने के लिए विशेष कतार डिजाइन लागू करना चाहिए ताकि भीड़ घनत्व को बनायें रखा जा सके। **(Munshi, 2018)**

Neeraj Dubey and Richa Sinha (2018)ने अपने शोध पत्र में निष्कर्ष निकाला है कि विशाल मेगा मार्ट ने खुदरा उद्योग में एक खुदरा स्टोर के रूप में अपने लिए एक विशिष्ट बाजार तैयार किया है जो सभी वर्गो के ग्राहकों को उचित मूल्य पर उनकी हर जरूरत को पूरा करता है। अध्ययन से यह पता चलता है कि खुदरा विक्रेताओं को खुदरा स्टोर में चीजों को इस तरह से प्रदर्शित करना चाहिए कि ग्राहक अधिक ध्यान दे और उत्साहित हो। इससे ग्राहकों की अनियोजित खरीददारी हो सकती है, जिससे बिक्री के साथ-साथ स्टोर का मुनाफा भी बढ़ेगा। विशाल मेगा मार्ट को ग्राहकों को अत्याधिक आसानी वस्तुओं को प्रदान करने के लिए स्टोर के लेआउट को व्यवस्थित करना चाहिए। इससे स्टोर की बिक्री पर सकारात्मक और उत्साहजनक प्रभाव पड़ सकता है। स्टोर कर्मचारी का व्यवहार ग्राहक के खरीददारी निर्णय को प्रभावित कर सकता है। विशाल मेगा मार्ट को कर्मचारियों के लिए प्रभावी प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम विकसित करना है ताकि वे अच्छे ग्राहक संबंध बनाए रखने पर काम करना जारी रख सकें। **(Dubey & Sinha, 2018)**

Harsha S.Parecha and Mahesh C. Dabre (June 2019)ने अपने शोध पत्र में यह निष्कर्ष निकाला है कि डी-मार्ट शॉपिंग सेंटर के प्रति उपभोक्ता का सकारात्मक रूझान यहाँ के अधिकारी एवं कर्मचारी के सहायक होने के कारण दिखाई दे रहा है। इस मार्ट ने अपनी स्थिरता एक विशाल श्रृंखला के रूप में दिखाई है। अमरावती शहर के उपभोक्ता डी-मार्ट में विभिन्न प्रकार के समानों को खरीदने के लिये सप्ताह में एक या दो बार आते है और भारी मात्रा में खरीददारी करते है। यहाँ के उपभोक्ताओं की डी-मार्ट के कार्य शैली, उत्पाद श्रृंखला एवं प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के प्रति सकारात्मक धारणा दिखाई देती है। इस प्रकार डी-मार्ट की सफलता के लिये यहाँ के उपभोक्ता अहम भूमिका निभा रहे है। **(Parecha & Dabre, 2019)**

अध्ययन के उद्देश्य

1. डी-मार्ट खुदरा स्टोर के उपभोक्ता क्रय व्यवहार पर अध्ययन करना।
2. डी-मार्ट उपभोक्ताओं का जनसांख्यिकीय विश्लेषण का अध्ययन करना।
3. डी-मार्ट द्वारा उभोक्ताओं को उचित कीमत, अच्छी किस्म की वस्तुएं एवं उत्पाद की उपलब्धता का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पना

शून्य परिकल्पना (H_{01}) - आयु, आय, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय एवं वैवाहिक स्थिति के आधार पर उपभोक्ताओं के संतुष्टि स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

वैकल्पिक परिकल्पना (H_{11}) - आयु, आय, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय एवं वैवाहिक स्थिति के आधार पर उपभोक्ताओं के संतुष्टि स्तर में सार्थक अंतर है।

शून्य परिकल्पना (H_{12}) - आय के आधार पर उपभोक्ताओं के उपभोग सामग्री (खाद्य सामग्री, दैनिक अनिवार्य वस्तुएं, घरेलू उपकरण, श्रृंगार सामग्री, फुटवेयर एवं खेल सामान, परिधान) के चयन में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

वैकल्पिक परिकल्पना (H_{12}) - आय के आधार पर उपभोक्ताओं के उपभोग सामग्री (खाद्य सामग्री, दैनिक अनिवार्य वस्तुएं, घरेलू उपकरण, श्रृंगार सामग्री, फुटवेयर एवं खेल सामान, परिधान) के चयन में सार्थक अंतर है।

शोध प्रविधि

इस अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक समंकों का संकलन प्रश्नावली, गूगल फार्म, साक्षात्कार व अवलोकन के माध्यम से किया गया है। द्वितीयक समंकों का संकलन विभिन्न स्त्रोतों जैसे कंपनी की वेबसाइट, प्रकाशित लेख एवं शोध पत्र, इंटरनेट आदि के माध्यम से किया गया है। इस अध्ययन में 300 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। इस अध्ययन में समंकों का संग्रहण के लिए सुविधानुसार निदर्शन विधि का प्रयोग किया गया है। सामान्य प्रतिशत विश्लेषण विधि का प्रयोग किया गया है। परिकल्पना परीक्षण के लिए काई वर्ग परीक्षण एवं क्रुस्कल वैलिस परीक्षण का प्रयोग किया गया है। यह अध्ययन दुर्ग शहर के डी-मार्ट स्टोर के उपभोक्ताओं तक सीमित है।

समंकों का विश्लेषण एवं परिकल्पना परीक्षण

तालिका क्रमांक 01

उत्तरदाताओं की जनसांख्यिकीय विश्लेषण

क्र.	विवरण		संख्या	प्रतिशत	माध्य	प्रमाप विचलन
1.	आयु समूह	25 वर्ष से कम	31	10.3	2.51	0.883
		25-35	132	44.0		
		35-45	89	29.7		
		45 वर्ष या उससे अधिक	48	16.0		
योग			**300**	**100**		
2.	लिंग	पुरूष	183	61.0	1.39	0.489
		महिला	117	39.0		
योग			**300**	**100**		
3.	शिक्षा	हाईस्कूल	9	3.0	3.23	0.840
		हायर सेकेण्डरी स्कूल	52	17.3		
		स्नातक	100	33.3		
		स्नातकोत्तर या उससे अधिक	139	46.3		
योग			**300**	**100**		
4.	वैवाहिक स्थिति	विवाहित	154	51.3	1.49	0.501
		अविवाहित	146	48.7		
योग			**300**	**100**		
5.	मासिक आय	20000 रूसे कम .	119	39.7	1.96	0.962
		20000-40000	101	33.7		
		40000-60000	54	18.0		
		60000 रूया उससे अधिक .	26	8.7		
योग			**300**	**100**		

स्त्रोत:- प्राथमिक समंक

आयु समूह

तालिका क्रमांक 01 से स्पष्ट होता है कि 300 उत्तरदाताओं में से 25 वर्ष से कम आयु वर्ग के उत्तरदाताओं की संख्या 31 है जिसका प्रतिशत 10.3 है, 25-35 वर्ष के आयु वर्ग उत्तरदाताओं की संख्या 132 है जिसका प्रतिशत 44.0 है, 35-45 वर्ष के आयु वर्ग उत्तरदाताओं की संख्या 89 है जिसका प्रतिशत 29.7 है, 45 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग उत्तरदाताओं की संख्या 48 है जिसका प्रतिशत 16.0 है। इससे स्पष्ट विदित होता है कि सबसे ज्यादा 25-35 वर्ष के उपभोक्ता डी-मार्ट में खरीददारी करने आते है। इसका मध्यमान 2.51 एवं प्रमाप विचलन का मान 0.883 है।

लिंग

तालिका क्रमांक 01 से स्पष्ट होता है कि लिंग के आधार पर 300 उत्तरदाताओं में से पुरूषों की संख्या 183 है जिसका प्रतिशत 61.0 है, जबकि महिला की संख्या 117 है जिसका प्रतिशत 39.0 है। इससे स्पष्ट विदित होता है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष डी-मार्ट स्टोर में खरीददारी करते है। इसका मध्यमान 1.39 एवं प्रमाप विचलन का मान 0.489 है।

शिक्षा

तालिका क्रमांक 01 से स्पष्ट होता है कि शिक्षा के आधार पर 300 उत्तरदाताओं में से हाईस्कूल शिक्षा स्तर के उत्तरदाताओं की संख्या 9 है जिसका प्रतिशत 3.0 है, हायर सेकेण्डरी स्कूल शिक्षा स्तर के उत्तरदाताओं की संख्या 52 है जिसका प्रतिशत 17.3 है, स्नातक शिक्षा स्तर के उत्तरदाताओं की संख्या 100 है जिसका प्रतिशत 33.3 है, स्नातकोत्तर या उससे अधिक उत्तरदाताओं की संख्या 139 है जिसका प्रतिशत 46.4 है। इससे स्पष्ट विदित होता है कि ज्यादातर उपभोक्ता स्नातकोत्तर या उससे अधिक शिक्षित वर्ग के डी-मार्ट में खरीददारी करते है। इसका मध्यमान 3.23 एवं प्रमाप विचलन का मान 0.840 है।

वैवाहिक स्थिति

तालिका क्रमांक 01 से स्पष्ट होता है कि वैवाहिक स्थिति के आधार पर 300 उत्तरदाताओं में से विवाहित उत्तरदाताओं की संख्या 154 है जिसका प्रतिशत 51.3 है, अविवाहित उत्तरदाताओं की संख्या 146 है जिसका प्रतिशत 48.7 है। इससे स्पष्ट विदित होता है कि ज्यादातर अविवाहित उपभोक्ताओं की तुलना में विवाहित उपभोक्ता डी-मार्ट में खरीदी करते है। इसका मध्यमान 1.49 एवं प्रमाप विचलन का मान 0.501 है।

मासिक आय

तालिका क्रमाक 01 से स्पष्ट होता है कि उपभोक्ताओं की मासिक आय के आधार पर 300 उत्तरदाताओं में से 20000 रू. से कम आय वाले उत्तरदाताओं की संख्या 119 है जिसका प्रतिशत 39.7 है, 20000-40000 रू. आय वाले उपभोक्ताओं की संख्या 101 है जिसका प्रतिशत 33.7 है, 40000-60000 रू. आय वाले उत्तरदाताओं की संख्या 54 है जिसका प्रतिशत 18.0 है, 60000 रू. या उससे अधिक की आय वाले उत्तरदाताओं की संख्या 26 है जिसका प्रतिशत 8.7 है। इससे स्पष्ट विदित होता है कि डी-मार्ट में ज्यादातर 20000 रू से कम आय वाले उपभोक्ता यहाँ खरीदी करते है। इसका मध्यमान 1.96 एवं प्रमाप विचलन का मान 0.962 है।

परिकल्पना परीक्षण

शून्य परिकल्पना (H_{01}) - आयु, आय, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय एवं वैवाहिक स्थिति के आधार पर उपभोक्ताओं के संतुष्टि स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

वैकल्पिक परिकल्पना (H_{11}) - आयु, आय, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय एवं वैवाहिक स्थिति के आधार पर उपभोक्ताओं के संतुष्टि स्तर में सार्थक अंतर है।

तालिका क्रमांक 02

आयु के आधार पर उपभोक्ताओं के संतुष्टि स्तर का सार्थकता परीक्षण

आयु	25 वर्ष से कम	25-35	35-45	45 वर्ष या उससे अधिक	योग
N	31	132	89	48	300
माध्य रैंक **(Mean Rank)**	132.47	147.29	149.23	173.32	

स्त्रोत:- एसपीएसएस 26 से प्राथमिक समंक का परिकलित मान

तालिका क्रमांक 03

लिंग के आधार पर उपभोक्ताओं के संतुष्टि स्तर का सार्थकता परीक्षण

लिंग	**पुरूष**	**महिला**	**योग**
N	183	117	300
माध्य रैंक **(Mean Rank)**	153.40	145.49	

स्रोत:- एसपीएसएस 26 से प्राथमिक समंक का परिकलित मान

तालिका क्रमांक 04

शिक्षा के आधार पर उपभोक्ताओं के संतुष्टि स्तर का सार्थकता परीक्षण

शिक्षा	हाईस्कूल	हायर सेकेण्डरी स्कूल	स्नातक	स्नातकोत्तर या उससे अधिक	योग
N	9	52	100	156	300
माध्य रैंक **(Mean Rank)**	104.22	165.20	138.75	156.45	

स्रोत:- एसपीएसएस 26 से प्राथमिक समंक का परिकलित मान

तालिका क्रमांक 05

वैवाहिक स्थिति के आधार पर उपभोक्ताओं के संतुष्टि स्तर का सार्थकता परीक्षण

वैवाहिक स्थिति	**विवाहित**	**अविवाहित**	**योग**
N	154	146	300
माध्य रैंक **(Mean Rank)**	159.44	141.07	

स्रोत:- एसपीएसएस 26 से प्राथमिक समंक का परिकलित मान

तालिका क्रमांक 06

आय के आधार पर उपभोक्ताओं के संतुष्टि स्तर का सार्थकता परीक्षण

आय	**20000 रूसे कम .**	**20000-40000**	**40000-60000**	**60000 रूया . उससे अधिक**	**योग**
N	119	101	54	26	300
माध्य रैंक **(Mean Rank)**	153.98	151.11	154.18	126.58	

स्रोत:- एसपीएसएस 26 से प्राथमिक समंक का परिकलित मान

तालिका क्रमांक 07

क्रुस्कल-वैलिस परीक्षण (H-Test)

H_{01}	Particular	P-Value	H-Value	Degree of freedom	Results
H_{01a}	आयु के आधार पर संतुष्टि स्तर	0.119	5.853	3	Accept
H_{01b}	लिंग के आधार पर संतुष्टि स्तर	0.427	0.632	1	Accept
H_{01c}	शिक्षा के आधार पर संतुष्टि स्तर	0.049	7.878	3	Rejected
H_{01d}	वैवाहिक के आधार पर संतुष्टि स्तर	0.044	4.047	1	Rejected
H_{01e}	आय के आधार पर संतुष्टि स्तर	0.369	3.148	3	Accept

स्रोत:- एसपीएसएस 26 से प्राथमिक समंक का परिकलित मान

H_{01a}: - तालिका क्रमांक 07 से यह स्पष्ट होता है कि P का मान 0.119 है जो सार्थकता स्तर 0.05 से अधिक है, **$P \geq (0.05)$**इसलिए शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर दिया गया है और वैकल्पिक परिकल्पना को अस्वीकार किया गया है। आयु एवं संतुष्टि के लिए H का मान 5.853 है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आयु के आधार पर उपभोक्ताओं की संतुष्टि स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

H_{01b}: - तालिका क्रमांक 07 से यह स्पष्ट होता है कि P का मान 0.427 है जो सार्थकता स्तर 0.05 से अधिक है, **$P \geq (0.05)$**इसलिए शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर दिया गया है और वैकल्पिक परिकल्पना को अस्वीकार किया गया है। लिंग एवं संतुष्टि के लिए H का मान 0.632 है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि लिंग के आधार पर उपभोक्ताओं की संतुष्टि स्तर में सार्थक अंतर नहीं है।

H_{01c}: - तालिका क्रमांक 07 से यह स्पष्ट होता है कि P का मान 0.049 है जो सार्थकता स्तर 0.05 से कम है, **$P \leq (0.05)$** इसलिए शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया गया है और वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार किया गया है। शिक्षा एवं संतुष्टि के लिए H का मान 7.878 है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षा के आधार पर उपभोक्ताओं की संतुष्टि स्तर में सार्थक अंतर है।

H_{01d}: - तालिका क्रमांक 07 से यह स्पष्ट होता है कि P का मान 0.044 है जो सार्थकता स्तर 0.05 से कम है, **$P \leq (0.05)$**इसलिए शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया गया है और वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार किया गया है। वैवाहिक एवं संतुष्टि के लिए H का मान 4.047 है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वैवाहिक स्थिति के आधार पर उपभोक्ताओं की संतुष्टि स्तर में सार्थक अंतर है।

H_{01e}: - तालिका क्रमांक 07 से यह स्पष्ट होता है कि P का मान 0.369 है जो सार्थकता स्तर 0.05 से अधिक है, **$P \geq (0.05)$**इसलिए शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर दिया गया है और वैकल्पिक परिकल्पना को अस्वीकार किया गया है। आय एवं संतुष्टि के लिए H का मान 3.148 है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आय के आधार पर उपभोक्ताओं की संतुष्टि स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शून्य परिकल्पना (H_{02}) - आय के आधार पर उपभोक्ताओं के उपभोग सामग्री (खाद्य सामग्री, दैनिक अनिवार्य वस्तुएं, घरेलू उपकरण, श्रृंगार सामग्री, फुटवेयर एवं खेल सामान, परिधान) के चयन में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

वैकल्पिक परिकल्पना (H_{12}) - आय के आधार पर उपभोक्ताओं के उपभोग सामग्री (खाद्य सामग्री, दैनिक अनिवार्य वस्तुएं, घरेलू उपकरण, श्रृंगार सामग्री, फुटवेयर एवं खेल सामान, परिधान) के चयन में सार्थक अंतर है।

तालिका क्रमांक 08

उपभोक्ताओं की आय एवं उपभोग सामग्री (खाद्य सामग्री) के चयन में सार्थकता परीक्षण

रैंक / आय	1	2	3	4	5	6	योग
20000सेकम	50	21	17	12	10	9	**119**
20000-40000	46	18	12	13	7	5	**101**

40000-60000	25	4	8	10	4	3	**54**
60000उससे अधिक	7	2	6	11	0	0	**26**
योग	**128**	**45**	**43**	**46**	**21**	**17**	**300**

स्त्रोत:- प्राथमिक समंक

तालिका क्रमांक 09

उपभोक्ताओं की आय एवं उपभोग सामग्री (दैनिक अनिवार्य वस्तुएं) के चयन में सार्थकता परीक्षण

रैंक / आय	1	2	3	4	5	6	योग
20000 रूसे कम .	21	31	27	20	8	12	**119**
20000-40000	17	33	25	16	1	9	**101**
40000-60000	4	9	18	10	8	5	**54**
60000 रूया उससे अधिक .	4	5	16	0	1	0	**26**
योग	**46**	**78**	**86**	**46**	**18**	**26**	**300**

स्त्रोत:- प्राथमिक समंक

तालिका क्रमांक 10

उपभोक्ताओं की आय एवं उपभोग सामग्री (घरेलू उपकरण) के चयन में सार्थकता परीक्षण

रैंक / आय	1	2	3	4	5	6	योग
20000 रूसे कम .	17	35	32	20	7	8	**119**
20000-40000	15	29	30	9	9	9	**101**
40000-60000	8	17	10	10	4	5	**54**
60000 रूया उससे अधिक .	6	10	2	3	3	2	**26**
योग	**46**	**91**	**74**	**42**	**23**	**24**	**300**

स्त्रोत:- प्राथमिक समंक

तालिका क्रमांक 11

उपभोक्ताओं की आय एवं उपभोग सामग्री (श्रृंगार सामग्री) के चयन में सार्थकता परीक्षण

रैंक / आय	1	2	3	4	5	6	योग
20000 रूसे कम .	10	15	21	30	26	17	**119**
20000-40000	14	8	19	31	14	14	**101**
40000-60000	3	11	13	9	9	9	**54**

60000 रूया उससे अधिक .	3	5	2	2	6	8	**26**
योग	**30**	**39**	**55**	**72**	**55**	**48**	**300**

स्त्रोत:- प्राथमिक समंक

तालिका क्रमांक 12

उपभोक्ताओं की आय एवं उपभोग सामग्री (फुटवेयर एवं खेल सामान) के चयन में सार्थकता परीक्षण

रैंक / आय	1	2	3	4	5	6	योग
20000 रूसे कम .	9	14	11	21	41	23	**119**
20000-40000	3	9	6	20	43	20	**101**
40000-60000	8	6	4	11	14	11	**54**
60000 रूया उससे अधिक .	4	0	0	5	11	6	**26**
योग	**24**	**29**	**21**	**57**	**109**	**60**	**300**

स्त्रोत:- प्राथमिक समंक

तालिका क्रमांक 13

उपभोक्ताओं की आय एवं उपभोग सामग्री (परिधान) के चयन में सार्थकता परीक्षण

रैंक / आय	1	2	3	4	5	6	योग
20000 रूसे कम .	11	3	12	16	27	50	**119**
20000-40000	6	4	9	12	27	43	**101**
40000-60000	6	7	2	4	14	21	**54**
60000 रूया उससे अधिक .	3	4	0	4	5	10	**26**
योग	**26**	**18**	**23**	**36**	**73**	**124**	**300**

स्त्रोत:- प्राथमिक समंक

तालिका क्रमांक 14

काई-वर्ग परीक्षण (Chi-Square Tests)

H_{02}	Particular	P-Value	χ^2-Value	Degree of freedom	Results
H_{02a}	आय एवं खाद्य सामग्री	0.022	27.520	15	Rejected
H_{02b}	आय एवं घरेलू उपकरण	0.001	37.617	15	Rejected
H_{02c}	आय एवं दैनिक अनिवार्य वस्तुएं	0.673	12.086	15	Accept
H_{02d}	आय एवं श्रृंगार सामग्री	0.084	23.014	15	Accept
H_{02e}	आय एवं फुटवेयर एवं खेल सामान	0.282	17.634	15	Accept

H_{02f}	आय एवं परिधान	0.200	19.315	15	Accept

स्रोत:- एसपीएसएस 26 से प्राथमिक समंक का परिकलित मान

H_{02a}: - तालिका क्रमांक 14 से स्पष्ट होता है कि P का मान 0.022 है, जो सार्थकता स्तर 0.05 से कम है, **P ≤ (0.05)**इसलिए शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया गया है और वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार किया गया है। आय एवं खाद्य सामग्री के लिएχ^2का मान 27.520 है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आय के आधार पर उपभोक्ताओं के उपभोग सामग्री (खाद्य सामग्री) के चयन में सार्थक अंतर है।

H_{02b}: - तालिका क्रमांक 14 से स्पष्ट होता है कि P का मान 0.001 है, जो सार्थकता स्तर 0.05 से कम है, **P ≤ (0.05)**इसलिए शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया गया है और वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार किया गया है। आय एवं घरेलू उपकरण के लिए χ^2 का मान 37.617 है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आय के आधार पर उपभोक्ताओं के उपभोग सामग्री (घरेलू उपकरण) के चयन में सार्थक अंतर है।

H_{02c}:- तालिका क्रमांक 14 से स्पष्ट होता है कि P का मान 0.673 है, जो सार्थकता स्तर 0.05 से अधिक है, **P ≥ (0.05)**इसलिए शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर दिया गया है और वैकल्पिक परिकल्पना को अस्वीकार किया गया है। आय एवं दैनिक अनिवार्य वस्तुएं के लिए χ^2 का मान 12.086 है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आय के आधार पर उपभोक्ताओं के उपभोग सामग्री (दैनिक अनिवार्य वस्तुएं) के चयन में सार्थक अंतर नहीं है।

H_{02d}: - तालिका क्रमांक 14 से स्पष्ट होता है कि P का मान 0.084 है, जो सार्थकता स्तर 0.05 से अधिक है, **P ≥ (0.05)**इसलिए शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर दिया गया है और वैकल्पिक परिकल्पना को अस्वीकार किया गया है। आय एवं श्रृंगार सामग्री के लिए χ^2 का मान 23.014 है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आय के आधार पर उपभोक्ताओं के उपभोग सामग्री (श्रृंगार सामग्री) के चयन में सार्थक अंतर नहीं है।

H_{02e}:- तालिका क्रमांक 14 से स्पष्ट होता है कि P का मान 0.282 है, जो सार्थकता स्तर 0.05 से अधिक है, **P ≥ (0.05)**इसलिए शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर दिया गया है और वैकल्पिक परिकल्पना को अस्वीकार किया गया है। आय एवं फुटवेयर एवं खेल सामान के लिए χ^2 का मान 17.634 है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आय के आधार पर उपभोक्ताओं के उपभोग सामग्री (फुटवेयर एवं खेल सामान) के चयन में सार्थक अंतर नहीं है।

H_{02f} :- तालिका क्रमांक 14 से स्पष्ट होता है कि P का मान 0.200 है, जो सार्थकता स्तर 0.05 से अधिक है, **P ≥ (0.05)**इसलिए शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर दिया गया है और वैकल्पिक परिकल्पना को अस्वीकार किया गया है। आय एवं परिधान के लिए χ^2 का मान 19.315 है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आय के आधार पर उपभोक्ताओं के उपभोग सामग्री (बर्तन एवं परिधान) के चयन में सार्थक अंतर नहीं है।

निष्कर्ष

इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है, कि दुर्ग शहर के संगठित खुदरा स्टोर डी-मार्ट में विभिन्न तरह के उपभोक्ता यहाँ वस्तुओं की खरीदादरी करने आते है। डी-मार्ट में ज्यादातर 25-35 आयु वर्ग के उपभोक्ता, लिंग के आधार पर पुरूष वर्ग के उपभोक्ता, शिक्षा के आधार पर स्नातकोत्तर या उससे अधिक शिक्षित उपभोक्ता, वैवाहिक स्थिति के आधार पर विवाहित उपभोक्ता एवं आय के आधार पर 20000-400000 रू. आय वर्ग के उपभोक्ता यहाँ उत्पाद क्रय करने आते है। परिकल्पना परीक्षण से पता चलाता है कि उपभोक्ता की आयु, लिंग एवं आय में उपभोक्ता की संतुष्टि स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है, अर्थात् उपभोक्ता की संतुष्टि स्तर में आयु, लिंग एवं आय से किसी भी तरह से प्रभाव नहीं पड़ता है जबकि उपभोक्ता की विवाह एवं आय से उपभोक्ता की संतुष्टि स्तर में सार्थक अंतर है।

अर्थात् उपभोक्ता की संतुष्टि स्तर में विवाह एवं आय से प्रभाव पड़ता है। इससे पता चलता है कि डी-मार्ट में शिक्षित वर्ग के एवं विवाहित उपभोक्ता यहाँ सबसे ज्यादा उपभोक्ता खरीदी करने आते है। इसी तरह उपभोक्ता की आय एवं उपभोक्ता की उपभोग सामग्री का परीक्षण किया गया है। इससे पता चलता है कि उपभोक्ताओं की आय के आधार पर उनकी उपभोग सामग्री (खाद्य सामग्री, घरेलू उपकरण) के चयन में सार्थक अंतर है अर्थात् उपभोक्ता की आय से उनकी उपभोग सामग्री (खाद्य सामग्री, घरेलू उपकरण) के चयन पर प्रभाव पड़ता है, जबकि उपभोक्ताओं की आय के आधार पर उनकी उपभोग सामग्री (दैनिक अनिवार्य वस्तुएं, श्रृंगार सामग्री, फुटवेयर एवं खेल सामग्री, परिधान) के चयन में कोई सार्थक अंतर नहीं है अर्थात् उपभोक्ता की आय से उनकी उपभोग सामग्री (दैनिक अनिवार्य वस्तुएं, श्रृंगार सामग्री, फुटवेयर एवं खेल सामग्री, परिधान) के चयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार उपभोक्ताओं की आय से उत्पाद के चयन पर प्रभाव पड़ता है। दुर्ग शहर में डी-मार्ट स्टोर खुलने से यहाँ की उपभोक्ता बहुत अधिक संतुष्ट है। यहाँ उपभोक्ताओ को एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की घरेलू सामग्री, उचित कीमत, अच्छी गुणवत्ता एवं सभी उत्पाद की उपलब्धता आसानी से प्राप्त हो जाती है। उपभोक्ताओं को इधर-उधर भटकना नहीं पड़ता है। इससे कि डी-मार्ट के प्रति उपभोक्ताओं का क्रय व्यवहार संतोषजनक है।

सन्दर्भ सूची

Dubey, N., & Sinha, R. (2017). Factor Affecting Consumer Buying Behavior in Big Bazaar Retail Store. G- Journal of Education, Social Science and Humanities, 2 (1), 1-8.

Dubey, N., & Sinha, R. (2018). Factor affecting consumer buying behavior in Vishal mega mart Retail Store. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCE RESEARCH IDEAS AND INNOVATIONS IN TECHNOLOGY, 4 (3), 714-723.

Gangal, V., & Kumar, A. (2013). Big Bazaar: A Study of Consumer Behavior towards Organized Retail. INDIAN JOURNAL OF APPLIED RESEARCH, 3 (4), 336-338.

Parecha, H. S., & Dabre, M. C. (2019). A Study on the Consumer Buying Behaviour of D-Mart Shopping Center with Special Reference to Amravati City. International Journal of Social Sciences &Humanities, 9 (5), 36-40.

Rahim, A. M. (2018). IMPACT OF STORE ATMOSPHERICS ON CONSUMER BUYING BEHAVIOR AT D-MART STORE. International Journal of Research in Humanities, Arts and literature, 6 (8), 467-473.

https://upgradethinking.com/d-mart-ka-malik-kaun-hai/

https://khatabook.com/blog/retail-trade/

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के विकासात्मकप्रभाव एवं चुनौतियों का अध्ययन

डॉ. गिरीश शास्त्री *

सारांश

जहां जल है वहीं जीवन है। जीवित रहने के लिए मानव ने जब संसाधनों कीखोज करनी शुरू की तब जल की प्राथमिकता सदैव प्रथम रही। प्राचीनकाल में जल आपूर्ति केलिए मानव ने झरनों, झीलों, नदियों और समुद्र का सहारा लिया। जब मानव बस्तियों ने व्यापकआकार लेना शुरू किया तो जल की उपलब्धता कठिन होती चली गयी। इस समस्या के समाधान केरूप में मानव ने जल आपूर्ति हेतु जल की नहर को विकसित किया जो कि आज भी प्रचलन मेंहै तथा अति-प्रासंगिक भी है। भारत कृषि प्रधान देश है तो ऐसे में पानी की उपलब्धताका इसके सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। राजस्थान जैसे शुष्क राज्यमें पानी की किल्लत है क्योंकि 'इन्दिरा गांधी नहर परियोजना' राजस्थान राज्य के उत्तर-पश्चिमभाग में ही बहती है तथा पूर्वी राजस्थान में कोई नहर न होने से एक बड़े भू-भाग में पानीकी किल्लत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इस क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधानएक अन्य नहर के माध्यम से जिसका नाम 'पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना' है, के द्वाराही संभव है।पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (Eastern Rajasthan Canal Project - ERCP) राजस्थान की सबसे बड़ी नहर परियोजनाहै। इसके तहत पूर्वी राजस्थान के 13 जिले झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर एवं टोंक को साल 2051 तक पेयजल औरसिंचाई का पानी मिलना है। इन 13 जिलों में राजस्थान की लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या हैजिन्हें पीने का पानी उपलब्ध होगा तथा सिंचाई आपूर्ति संबंधी संसाधनों की कमी पूर्तिहो सकेगी।

प्रस्तुत शोध विषय 'पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के विकासात्मकप्रभाव एवं चुनौतियों का समीक्षात्मक अध्ययन' में शोधार्थी ने पूर्वी राजस्थान नहरपरियोजना (ईआरसीपी) का पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की जनसंख्या के जनजीवन पर पड़नेवाले प्रभाव इसके संभावित लाभ और चुनौतियों का समीक्षात्मक अध्ययन किया है जिसे मूर्तरूप देने के लिए गुणात्मक विधि का प्रयोग किया गया है। शोध को आधार प्रदान करने केलिए वैयक्तिक अध्ययन, साक्षात्कार तथा डेस्क रिव्यू प्रणाली का प्रयोग किया है। तथ्यसंकलन हेतु प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों डेटा का उपयोग किया है।

शोध अध्ययन के दौरान शोधार्थी ने पाया कि जिस तरह इन्दिरा गांधी नहरसे पश्चिमी राजस्थान की तकदीर बदल गई, उसी तरह ईआरसीपी से पूर्वी राजस्थान की में विकासके नये आयाम स्थापित होंगें लाखों किसानों के साथ-साथ आम लोगों को भी फायदा होगा। परन्तुपूर्वी राजस्थान नहर परियोजना वर्तमान में त्रिशंकु कोण में फंसी है जबकि क्षेत्र कीआवश्यकता और विकास के लिए यह अतिआवश्यक है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के संबंधमें राज्यों और केन्द्र के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन हो जिसमें इस परियोजना कोसाकार करने और इसके संबंध में उपजे संघर्ष का समाधान करने का मुख्य एजेंडा हो।

बीज शब्द: ईआरसीपी, राजस्थान में जल आपूर्ति, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ईआरसीपी और विकास

प्रस्तावना

मानव का अस्तित्व जल से जुड़ा है। जहां जल है वहीं जीवन है। ''यह पृथ्वी के जीवमंडल के अस्तित्व का आधार है। मानव सभ्यता का क्रमिक विकास जल स्रोतों के सहारे संभव हो सका है। पृथ्वी पर जल का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जब तक जल रहेगा तब तक पृथ्वी पर जीवन रहेगा।'' जीवित रहने के लिए मानव ने जब संसाधनों की खोज करनी शुरू की तब जल की प्राथमिकता सदैव प्रथम रही। प्राचीनकाल में जल आपूर्ति के लिए मानव ने झरनों, झीलों, नदियों और समुद्र का सहारा लिया। मानव ने अपनी बसावट नदियों, झरनों और समुद्र के समीपवर्ती इलाकों में की ताकि सरलता से जल की उपलब्धता हो सके। इसी क्रम में जब मानव बस्तियों ने व्यापक आकार लेना शुरू किया तो जल की उपलब्धता कठिन होती चली गयी। इस समस्या को दूर करने के लिए मानव ने कृतिम झीलों का निर्माण शुरू किया। परन्तु कृतिम झीलों का निर्माण भौगोलिक विशेषता व्याप्त स्थानों पर ही किया जा सकता था। इस समस्या के समाधान के रूप में मानव ने जल आपूर्ति हेतु जल की नहर को विकसित किया जो कि आज भी प्रचलन में है तथा अति-प्रासंगिक भी है। डी.डी. ओझा अपने आलेख में लिखते हैं कि ''उपलब्ध ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाणों से पता चलता है कि ई.पू चौथी शताब्दी से ही देश के कई क्षेत्रों में छोटे-छोटे समुदाय जल संचय और वितरण की कारगर व्यवस्था करते रहे। नंद के शासन में (363-321 ई.पू.) शासकों ने नहरें और समुदाय पर निर्भर सिंचाई प्रणालियाँ बनाई। मध्य भारत के गौड़ शासकों ने सिंचाई और जल आपूर्ति की न केवल बेहतर प्रणालियाँ बनाईं, बल्कि उनके रख-रखाव के लिये आवश्यक सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएँ भी विकसित की थीं।''

*डॉ. गिरीश शास्त्री, सहायक आचार्य, मल्टीमीडिया एवं जनसंचार विभाग, इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय।

भारत विविधताओं से भरा देश है। इन विविधताओं में भी भारतने अपने संदेश में माना है कि ''प्रत्येक वस्तु में चेतना है। प्रकृति भी हमारा स्वरुपहै। प्रकृति के संरक्षण के लिए उसी के अनुरूप हमें अपने मूल्य निश्चित करने चाहिए।''भारत मेंयहां परंपरा, खान-पान, रहन-सहन, पहनावा, भाषा इत्यादि विविधताओं के साथ-साथ भौगोलिकविविधता भी व्याप्त है। वर्षमें अधिकांश दिनों तक बर्फ से ढके लद्दाख से लेकर दक्षिणके पठार तथा थार के शुष्क मरुस्थल से लेकर अति वर्षा वाले उत्तर-पूर्वी क्षेत्र कीभिन्न-भिन्न स्थानीय परिस्थितियों और जलवायु से कोई अपरिचित नहीं है। भारत में भौगोलिकविविधता होने से कहीं बहुत अधिक पानी की उपलब्धता है तों कहीं पानी की उपलब्धता लगभगशुन्य है। ''जहां राजस्थान में औसत वर्षा 100 मिमी. है वहीं चेरापूंजी में 11000 मिमी.वर्षा होती है। भारत में जल प्राप्त करने के साधनों पर निर्भरता स्थान के साथ परिवर्तितहोती रहती है।''चूंकि भारत कृषि प्रधान देश है तो ऐसे में पानी की उपलब्धता का इसके सामाजिक और आर्थिकविकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इस पानी की उपलब्धता को सभी स्थानों पर समान बनायेरखने के लिए सबसे उपयुक्त नहर योजना है।

इसी क्रम में 'इन्दिरा गांधी नहर परियोजना'की शुरूआत की गयी जो कि विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना भी है। इसे राजस्थान की 'मरूगंगा' भी कहा जाता है। राजस्थान में बीकानेर प्रदेश के महाराजा गंगासिंह ने सन् 1927 में बीकानेर और समीपवर्ती क्षेत्रों में पानी की किल्लत को दूर करने हेतु इस नहरका निर्माण करवाया जिसे 'गंग-नहर' नाम दिया गया। बाद में इसका नाम 'राजस्थान नहर' तथाकालान्तर में इसका नाम 'इन्दिरा गांधी नहर परियोजना' कर दिया गया। यह नहर राजस्थान केरेगिस्तानी जिलों, यथा चुरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, नागौर, बाड़मेर, और जैसलमेरमें सिंचाई और पानी आपूर्ति के उद्देश्य से वर्तमान में विरलित है। इस नहर से यह भावनाविकसित हो सकी कि ''खुद को जीवित, विकसित और समृद्ध बनाये रखने के लिये अपने प्राकृतिकसंसाधनों पर निर्भरता बनाये रखना ताकि आत्मनिर्भरता की ताकत बढ़े। प्राकृतिक संसाधनोंके साथ जीवंत और गहरे रिश्ते कायम करता हुआ ऐसा समाज स्वतः इन पर सामुदायिक-सामाजिकअधिकार प्राप्त करता गया।''तथापिराजस्थान जैसे शुष्क राज्य में पानी की किल्लत है क्योंकि 'इन्दिरा गांधी नहर परियोजना'राजस्थान राज्य के उत्तर-पश्चिम भाग में ही बहती है तथा पूर्वी राजस्थान में कोई नहरन होने से एक बड़े भू-भाग में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में राजस्थानराज्य की राजधानी जयपुर में भी जल आपूर्ति के लिए समीपवर्ती टोंक जिले में स्थित बीसलपुरबांध के पानी को पाइपलाइन मे माध्यम से सम्पूर्ण जयपुर में जल आपूर्ति की जा रही है।ऐसेमें इस क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान एक अन्य नहर के माध्यम से जिसका नाम 'पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना' है, के द्वारा ही संभव है।

वर्तमान में जिस ''अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है उसी अनुपात में औद्योगिक और घरेलु क्षेत्र में पानी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। बढ़ती मानवीय क्रियाओं के कारण पानी का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। जिससे भू-गर्भ व सतही जल संसाधनों में भी कमी होती जा रही है। इसलिए पानी व पानी की गुणवत्ता का प्रबन्धन एक आवश्यकता बन गई है।'' नहर प्रणाली इसी समस्या का समाधान है। नहर प्रणाली द्वारा पानी की आपूर्ति करने से एक बड़े भू-भाग में रहने वाले लोग लाभान्वित होते हैं।

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, (Eastern Rajasthan Canal Project - ERCP) राजस्थान की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। इसके तहत पूर्वी राजस्थान के 13 जिले झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर एवं टोंक को साल 2051 तक पेयजल और सिंचाई का पानी मिलना है। इन 13 जिलों में राजस्थान की लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या है जिन्हें पीने का पानी उपलब्ध होगा तथा सिंचाई आपूर्ति संबंधी संसाधनों की कमी पूर्ति हो सकेगी।

जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार के अनुसार, राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 342.52 लाख हेक्टेयर है जो संपूर्ण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 10.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसमें देश में उपलब्ध कुल सतही जल की 1.16% और भूजल की 1.72% मात्रा ही यहाँ पाई जाती है।

राज्य जल निकायों में केवल चंबल नदी के बेसिन में अधिशेष जल की उपलब्धता है परंतु इसके जल का सीधे तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि कोटा बैराज के आस-पास का क्षेत्र मगरमच्छ अभयारण्य के रूप में संरक्षित है।

ईआरसीपी का उद्देश्य मोड़दार संरचनाओं की सहायता से अंतर-बेसिन जल अंतरण चैनलों को जोड़ने तथा मुख्य फीडर चैनलों को जल आपूर्ति हेतु वाटर चैनलों का एक नेटवर्कतैयार करना है जो राज्य की 41.13% आबादी के साथ राजस्थान के 23.67% क्षेत्र को कवर करेगा।

शोध के उद्देश्य

प्रस्तावित शोध विषय 'पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के विकासात्मक प्रभाव एवं चुनौतियों का अध्ययन' के शोध उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

1. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) का पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की जनसंख्या के जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को निरूपित करना।
2. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के संभावित लाभ और चुनौतियों का अध्ययन करना।
3. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) की आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता एवं दूरगामी प्रभावों को रेखांकित करना।

शोध प्रश्न

प्रस्तावित शोध विषय 'पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के विकासात्मक प्रभाव एवं चुनौतियों का अध्ययन' को पूर्ण करने हेतु शोधार्थी के समक्ष कुछ प्रश्न खड़े होते हैं। जो कि निम्नलिखित हैं-

1. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) में विशेष क्या है ?
2. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के लाभ क्या है ?
3. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के समक्ष क्या-क्या चुनौतियां हैं ?
4. आधुनिकीकरण के दौर में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) की क्या प्रासंगिकता है ?

शोध विधि और तथ्य संकलन

प्रस्तावित शोध विषय 'पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के विकासात्मक प्रभाव एवं चुनौतियों का अध्ययन' को मूर्त रूप देने के लिए गुणात्मक विधि का प्रयोग किया गया है। शोधको आधार प्रदान करने के लिए निम्न शोध प्रविधियों और शोध उपकरणों का उपयोग किया गया है-

1. वैयक्तिक अध्ययन - इस विधि के माध्यम से पूर्वी राजस्थान के निवासियों पर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक संदर्भ में प्रभाव आदि पर विस्तृत अध्ययन किया गया है।
2. साक्षात्कार - साक्षात्कार के माध्यम से 'पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना' के प्रभाव और चुनौतियों को समझने का प्रयास किया गया है। साक्षात्कार हेतु विचारकों, शोधार्थियों, राजनेताओं तथा पर्यावरण विशेषज्ञों तक पंहुचने का प्रयास किया गया है।
3. डेस्क रिव्यू प्रणाली - इस विधि के माध्यम से विभिन्न स्रोतों से प्राप्त तथ्यों का शोध उद्देश्यों के अनुसार रिव्यू किया किया गया है।

तथ्य संकलन

तथ्य संकलन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक डेटा का उपयोग किया जाएगा।

1. प्राथमिक डेटा - इसमें वैयक्तिक अध्ययन, साक्षात्कार और प्रिंट माध्यम आदि से प्राप्त सामग्रियों को शोध का आधार बनाया गया है।
2. द्वितीयक डेटा - इसमें डेस्क रिव्यू प्रणाली से प्राप्त तथा व्यक्तिगत आलेख, सार्वजनिक आलेख, डायरी, संस्मरण, जीवन वृत्त, पत्र, शोध रिपोर्ट आदि के माध्यम से प्राप्त तथ्यों को शोध में शामिल किया गया है।

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना : परिचय और पृष्ठभूमि

आज ''वन क्षेत्रों की अंधाधुंध कटाई, भूमिगत जल का बेतहाशा दोहन, परम्परागत जल स्रोतों की निरंतर उपेक्षा, समुचित जल प्रबन्धन का अभाव आदि के कारण इस बढ़ती जल मांग से गंभीर जल संकट उत्पन्न होता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान के सर्वेक्षणों के अनुसार भारत में अगले 20 वर्षों में जल की मांग 50 प्रतिशत बढ़ जायेगी, जिसकी पूर्ति करना गंभीर समस्या होगी।'' इस समस्या को दूर करने के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की संकल्पना की गयी। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के तहत पूर्वी राजस्थान के 13जिले झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर एवं टोंक को साल 2051 तक पेयजल और सिंचाई का पानी मिलना है। इसमें मानसून के समय पार्वती, कालीसिंध, मेज नदी के बरसाती अधिशेष (जरूरत से ज्यादा) पानी को बनास, मोरेल, बाणगंगा और गंभीर नदी तक लाने की योजना है। जिसके तहत पूर्वी राजस्थान की 11 नदियों को आपस में जोड़ा जाना भी प्रस्तावित है। योजना के तहत 6 बैराज और एक बांध बनाया जाना है। इसमें बारां जिले की शाहबाद तहसील में कुन्नू नदी पर कुन्नू बैराज, बारां जिले की किशनगढ़ तहसील में कुन्नू नदी पर रामगढ़ बैराज, बारां की ही मंगरौल तहसील में पार्वती नदी पर महलपुर बैराज, कोटा जिले की पीपलदा तहसील में नवनेरा बैराज, बूंदी जिले की इंद्रगढ़ तहसील में मेज नदी पर मेज बैराज, सवाई माधोपुर जिले की चौथ का बरवाड़ा तहसील में बनास नदी पर राठौड़ बैराज बनाए जाने प्रस्तावित हैं। इसके अलावा सवाई माधोपुर की खंडार तहसील में डूंगरी बांध का निर्माण किया जाना है। इसी बांध में ईआरसीपी योजना के लिए पानी इकट्ठा किया जाएगा। इस बांध की भराव क्षमता 2099 एमसीएम होगी।

शोधार्थी ने अपने अध्ययन में पाया कि वर्ष 2017 में तत्कालीन राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार के उपक्रम वेप्कॉस लिमिटेड की ओर से तैयार डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) 19 नवंबर 2017 को भेजी। इसके बाद केन्द्रीय जल आयोग के सामने राजस्थान की ओर से 18 जनवरी 2018 को परियोजना के बारे में विस्तार से बताया गया। तब से ही यह योजना केन्द्रीय जल आयोग में विचाराधीन है। नवंबर 2017 में बनी डीपीआर उस समय राजस्थान रिवर बेसिन अथॉरिटी के चेयरमैन श्रीराम वेदिरे की देखरेख में बनी थी।

डीपीआर में इस योजना की अनुमानित लागत 37,247.12 करोड़ रुपए है। इस काम को 7 साल में पूरा करना था। वर्ष 2018 में राजस्थान में कांग्रेस सरकार आने के बाद से राज्य सरकार इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग कर रही है। किसी भी योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित होने से केन्द्र को 90 प्रतिशत और राज्य को 10 प्रतिशत पैसा ही खर्च करना होता है।

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना : उद्देश्य एवं लाभ

"पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना "एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य पूर्वी राजस्थान के कृषि, प्रदूषण निवारण, और जल संसाधन के विकास को बढ़ावा देना है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की आधिकारिक रिपोर्ट के अध्ययन में निम्न मुख्य उद्देश्य निहित हैं-

1. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का उद्देश्य दक्षिणी राजस्थान में बहने वाली चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों (कुन्नू, पार्वती, कालीसिंध) में वर्षा ऋतु के दौरान उपलब्ध अधिशेष जल का उपयोग राज्य के उन दक्षिण-पूर्वी ज़िलों में करना है जहाँ पीने के पानी और सिंचाई हेतु जल का अभाव है।
2. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को वर्ष 2051 तक पूरा किये जाने की योजना है जिसमें दक्षिणी एवं दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में मानव तथा पशुधन हेतु पीने के पानी तथा औद्योगिक गतिविधियों हेतु पानी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना है।
3. इसमें राजस्थान के 13 ज़िलों में पीने का पानी और 26 विभिन्न बड़ी एवं मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।
4. 13 ज़िलों में झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर शामिल हैं।

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की आधिकारिक रिपोर्ट के अध्ययन में निम्न मुख्य लाभ सामने आते हैं -

1. महत्त्वपूर्ण भू-क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।
2. इससे राज्य के ग्रामीण इलाकों में भूजल तालिका (Ground Water Table) में सुधार होगा।
3. यह लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को सकारात्मक रूप से परिवर्तित करेगा।
4. यह परियोजना विशेष रूप से दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे (Delhi Mumbai Industrial Corridor-DMIC) पर ज़ोर देते हुए इस बात की परिकल्पना करती है कि इससे स्थायी जल स्रोतों को बढ़ावा मिलेगा जो क्षेत्र में उद्योगों को विकसित करने में मदद करेंगे।
5. इसके परिणामस्वरूप राज्य में निवेश और राजस्व में वृद्धि होगी।
6. ईआरसीपी से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में 2.02 लाख हेक्टेयर नई सिंचाई भूमि बनेगी। साथ ही इन जिलों में पहले से बने 26 बांधों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा।
7. इससे 80,878 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है।
8. इस परियोजना में पेयजल के लिए 1723.5 एमसीएम (मिलियन घन मीटर) प्रावधान किया गया है। जो कुल उपलब्ध पानी का 49 प्रतिशत है। इससे इन 13 जिलों की 40% जनता यानी लगभग 3 करोड़ लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा।
9. ईआरसीपी में 13 जिलों के अंदर आने वाले उद्योगों सहित दिल्ली-मुंबई इंड्रस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआरसी) को 286.4 एमसीएम यानी कुल पानी के 8% उपयोग का प्रावधान है। इसके अलावा बचा हुआ 43 प्रतिशत पानी सिंचाई के लिए मिलेगा। इस पानी से सिंचाई के लिए धौलपुर जिले में 72,500 हेक्टेयर और दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, भरतपुर में 1,29,985 हेक्टेयर क्षेत्र में नया कमांड एरिया बन सकेगा।

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के समक्ष चुनौतियां

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) निःसंदेह क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है परन्तु इसके समक्ष कई चुनौतियां हैं जिन्हें शोधार्थी ने अध्ययन कर प्रस्तुत किया है। -

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की डीपीआर मध्यप्रदेश-राजस्थान अंतर राज्यीय स्टेट कंट्रोल बोर्ड की साल 2005 में बैठक में हुए निर्णयों के अनुसार बनी है। इस निर्णय के अनुसार 'राज्य किसी परियोजना के लिए अपने राज्य के कैचमेंट से प्राप्त पानी एवं दूसरे राज्य के कैचमेंट से प्राप्त पानी का 10 प्रतिशत प्रयोग इस शर्त के साथ कर सकते हैं- यदि परियोजना में आने वाले बांध और बैराज का डूब क्षेत्र दूसरे राज्य की सीमा में नहीं आता हो तो ऐसे मामलों में राज्य की सहमति जरूरी नहीं है।

इसी शर्त के आधार पर मध्यप्रदेश ने पार्वती की सहायक नदी नेवज पर मोहनपुरा बांध और कालीसिंध पर कुंडालिया बांध बनाया है। राजस्थान सरकार का दावा है कि इन बांधों की एनओसी उनसे बांध बनने के बाद 2017 में ली गई। लेकिन अब मध्यप्रदेश सरकार ईआरसीपी के लिए एनओसी नहीं दे रही जबकि राजस्थान तीनों शर्तों को पूरी करता है। जो कि निम्न हैं -

1. पहली- जलभराव क्षेत्र राजस्थान की जमीन पर है।
2. दूसरी- प्राप्त पानी राजस्थान के कैचमेंट का है।
3. तीसरी- मध्यप्रदेश के कैचमेंट क्षेत्र से प्राप्त पानी 10% से कम है।

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों के निर्णयों पर टिकी है। तथा दोनों राज्यों के अब अलग-अलग दावे हैं। शोधार्थी ने सरकारी पत्रावलियों और दस्तावेजों के विश्लेषण से निम्न तथ्य उद्धृत किये हैं।-

दिनांक 08 जुलाई 2019 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा। इसके जवाब में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने 27 जनवरी 2020 को एक पत्र लिखा। इसमें 50 की जगह 75 प्रतिशत जल निर्भरता के आधार पर डीपीआर बनाने की बात मध्यप्रदेश सरकार की ओर से की गई है। इसी तरह का एक और पत्र दिनांक 15 अप्रैल 2022 को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार को लिख दिया है।

मध्यप्रदेश सरकार के केन्द्र को पत्र लिखने के बाद दिनांक 10 मई 2022 को जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव ने राजस्थान के मुख्य सचिव को यह कहते हुए पत्र लिखा कि जब तक दोनों राज्यों में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना-ईआरसीपी को लेकर कोई समझौता नहीं होता तब तक ईआरसीपी का काम रोक दिया जाए।

केन्द्र सरकार के इस पत्र पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा, "केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान सरकार को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का काम रोकने के लिए कहा है। हमारी सरकार ने ईआरसीपी के लिए 9,600 करोड का बजट राज्य कोष (स्टेट फंड) से जारी किया है। जब इस प्रोजेक्ट में अभी तक राज्य का पैसा लग रहा है और पानी हमारे हिस्से का है तो केद्र सरकार हमें ईआरसीपी का काम रोकने के लिए कैसे कह सकती है?

इसी के तहत राज्य सरकार ने साल 2021-22 के बजट में नवनेरा, गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक और धौलपुर जिले में कालीनीर लिफ्ट परियोजना का काम शुरू करने के लिए 320 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। वहीं, साल 2022-23के बजट में राज्य सरकार ने नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक, महलपुर बैराज और रामगढ़ बैराज के लिए 9600 करोड़ रुपए जारी किए हैं। साथ ही राजस्थान सरकार ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम (ईआरसीपी कॉर्पोरेशन) बनाने की घोषणा की है। इस निगम में राजस्थान सरकार ने अब तक 08 नए कार्यालय गठित करने की मंजूरी दी है। इन कार्यालयों में 115 पद सृजित किए गए हैं। इस साल दिए गए बजट से नवनेरा बैराज और ईसरदा बांध पर काम शुरू किया गया है. इस पर 1130 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

केन्द्र सरकार की रोक के बाद राजस्थान सरकार ने मध्यप्रदेश सरकार से एनओसी देने के लिए पत्र लिखा है। साथ ही केन्द्र सरकार को लिखा है कि परियोजना की डीपीआर 25 अगस्त 2005 को हुई बैठक में लिए निर्णयों के अनुसार ही बनी है इसीलिए मध्यप्रदेश के एनओसी की जरूरत ही नहीं है। ऐसे राजस्थान सरकार की एक तरफ तो मध्यप्रदेश सरकार से एनओसी की मांग करती दिख है वहीं दूसरी ओर केन्द्र सरकार से एनओसी लागू ही नहीं होने की बात कहती है। यह पत्र पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से होने वाले लाभान्वितों को भ्रम में डालता है।

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना-ईआरसीपी को लेकर राजनीति और संघर्ष गांव स्तर पर पहुंच चुका है। लोगों ने ईआरसीपी के लिए अपने स्तर पर कई संघर्ष मोर्चे खड़े किए हैं। जो कि ईआरसीपी को राजनीतिक मुद्दा बनाने की ओर अग्रसर हैं।

शोध विश्लेषण

उद्देश्य क्रमांक 01 'पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) का पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की जनसंख्या के जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को निरूपित करना' के संदर्भ में शोधार्थी ने शोध प्रश्नों के माध्यम से पाया कि परियोजना का जनजीवन पर विकासात्मक प्रभाव में मुख्य भूमिका है, जिन्हे निम्न बिन्दुओं के माध्यम से विस्तार से समझा जा सकता है -

1. कृषि में वृद्धि - पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से पूर्वी राजस्थान में कृषि वृद्धि होगी। परियोजना के तहत किसानों को नियमित और पर्याप्त जल पहुंचाने की सुविधा प्राप्त हो रही है, जिससे निश्चित ही उनकी फसलों की उपज में वृद्धि संभव हो सकेगी।
2. रोजगार के अवसर - इस परियोजना के कारण नए बांधों और नहरों का निर्माण होगा, जिससे नौकरियों के अवसर उपलब्ध हो सकेंगें। यह स्थानीय लोगों के लिए आर्थिक सुधार का एक साधारण माध्यम भी है।
3. औद्योगिक और आर्थिक विकास - पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से पूर्वी राजस्थान के औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में नए उद्योग और व्यापारिक क्रियाकलाप विकसित हो सकेंगें।
4. सामाजिक परिवर्तन - पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ने सामाजिक परिवर्तन को भी अंजाम देना शुरू कर दिया है। इसके अंतर्गत किसानों को जल प्रबंधन में भागीदार बनाया गया है, जिससे स्थानीय समुदायों के सशक्तीकरण में सहायता मिल रही है।

उद्देश्य क्रमांक 02 'पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के संभावित लाभ और चुनौतियों का अध्ययन करना' के संदर्भ में शोधार्थी ने शोध प्रश्नों के माध्यम से पाया कि परियोजना के संभावित लाभ और चुनौतियों का अध्ययन किया है। जिसे शोधार्थी शोध पत्र के मुख्य भाग में विस्तार से लिखा है। इसके मुख्य बिन्दू निम्न है -

1. एक बड़ी चुनौती जो ईआरसीपी के साथ आती है, वह है प्रदूषण की समस्या। जल संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, खासकर उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, प्रदूषण को बढ़ा देता है, जिसके असर से जलवायु परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन से जुड़े चुनौती हो सकती हैं।
2. जल संसाधनों की सही प्रबंधन ईआरसीपी के साथ आने वाली चुनौतियों में से एक है। यह अनिवार्य है कि हम जल संसाधनों को संरक्षित रखें, उनका सही उपयोग करें, और जल संचयन के लिए सामर्थ्य विकसित करें।
3. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के अनुसरण में वाणिज्यिकीकरण का प्रभाव भी है। यह प्रभाव आर्थिक और सामाजिक संरचना पर भी पड़ता है, और उसके साथ आने वाली समस्याओं का सामना करना होगा।

4. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत, किसानों को जल प्रबंधन में भागीदार बनाया गया है, जिससे सामाजिक संरचना में बदलाव आया है। इससे आने वाले समय में सामाजिक संरचना को लेकर चुनौतियाँ और समस्याएँ उत्पन्न होगी।
5. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ विकासीय चुनौतियाँ भी हैं। यह परियोजना नए बांधों और नहरों का निर्माण करती है, जिसके पर्याप्त विकास और संरचना के लिए वित्तीय संकट की चुनौती है।
6. विद्युत आपूर्ति और प्राकृतिक संसाधनों की चुनौती पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ आने वाली एक और चुनौती है। जल संसाधनों के उपयोग के साथ, बिजली और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करने की जरूरत होती है।
7. इसके अलावा किसानों की शिकायतें और समस्याएं भी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के समक्ष चुनौती है।

उद्देश्य क्रमांक 03 'पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) की आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता एवं दूरगामी प्रभावों को रेखांकित करना' के संदर्भ में शोधार्थी ने शोध प्रश्नों के माध्यम से पाया कि परियोजना का आधुनिक प्ररिप्रेक्ष्य में निःसंदेह महत्व है तथा यह प्रासंगिक भी है। परियोजना की आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता को निम्न बिन्दुओं की सहायता से समझा जा सकता है -

1. इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करना है ताकि कृषि, जल संचयन, और पेड़-पौधों की खेती में सुधार किया जा सके। जिसकी प्रासंगिकता वर्तमान समय में है।
2. राजस्थान राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर राज्य में, पानी की अधिकता महत्वपूर्ण है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के माध्यम से, पानी की आपूर्ति में सुधार होने से कृषकों को जल संकट के समय में बेहतर सहायता मिल सकेगी।
3. यह परियोजना नहरों और खाद्य कैनालों के माध्यम से पानी का संचयन करने की सीख प्रदान करती है, जिससे योजनाबद्ध तरीके से पानी का उपयोग किया जा सकता है। यह सूखा से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कृषि क्षेत्र में वित्तीय सुधार करता है।
4. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत काम करने वाले लोगों को रोजगार का अवसर मिलता है, जिससे उनके आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इसके अलावा, यह परियोजना खेती क्षेत्र में वृद्धि के साथ साथ संबलता भी प्रदान करती है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी है।
5. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जल संसाधन के प्रबंधन की महत्वपूर्ण उपाय की ओर कदम रखती है। इसके माध्यम से पानी का वितरण सही तरीके से करने की सुनिश्चितता मिलती है।
6. इस परियोजना के माध्यम से जल संचयन के लिए निर्मित तालाबों में वन्य जीवन के लिए एक सुरक्षित आवास प्रदान किया जा सकता है, जो प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा को बढ़ावा देगा।

उक्त शोध उद्देश्यों के विश्लेषण के अलावा शोधार्थी ने प्रभावित क्षेत्र के निवासियों से साक्षात्कार पद्धति के माध्यम से संवाद स्थापित किया जिसके फलस्वरूप कुछ बिन्दू निकलकर सामने आये, जो कि निम्न हैं-

1. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ने राजस्थान की जलसंसाधन सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
2. ईआरसीपी ने किसानों के जीवन को बदल दिया है, और उन्हें नई उम्मीदें दिलाई है।
3. यह केवल एक परियोजना ही नहीं बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन भी है।
4. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार संभव हो सकेगा।
5. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का मुख्य लक्ष्य सशक्त जल संसाधन प्रबंधन है।
6. यह परियोजना राजस्थान के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
7. ईआरसीपी के प्रकल्पों ने प्राकृतिक संसाधनों के सही उपयोग के महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किए हैं।

निष्कर्ष

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से पूर्वी राजस्थान के निवासियों केसामाजिक-आर्थिक विकास में बढ़ोतरी होगी। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना वर्तमान में त्रिशंकुकोण में फंसी है जबकि क्षेत्र की आवश्यकता और विकास के लिए यह अतिआवश्यक है। अगर अगरकेन्द्र सरकार इस परियोजना का राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करती है तो यह राज्य सरकारदायित्व है कि इसे अपने संसाधनों से पूरा करे। लगभग 40 हजार करोड़ रुपए की परियोजनामें राज्य अब तक लगभग 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान कर चुका है। चूंकि राज्य का कुलबजट 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है, ऐसे में अगले बजट वर्ष में बचे हुए 30 हजार करोड़का प्रावधान राज्य सरकार को करना चाहिए। जिससे क्षेत्र की जनता लाभान्वित हो सके औरइस क्षेत्र को विकास के नये आयाम स्थापित करने के अवसर प्राप्त हों। पूर्वी राजस्थाननहर परियोजना के संबंध में राज्यों और केन्द्र के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन होजिसमें इस परियोजना को साकार करने और इसके संबंध में उपजे संघर्ष का समाधान करने कामुख्य एजेंडा हो।

सन्दर्भ सूची

सिंह, श्रीनिवास. (2008). पर्यावरण और जन-स्वास्थ्य. 20

ओझा, डी.डी. (2016). प्राचीन भारत में जल संसाधनों का प्रबन्धन. इंडिया वाटन पॉर्टल. https://hindi.indiawaterportal.org/articles/paraacaina-bhaarata-maen-jala-sansaadhanaon-kaa-parabanadhana

झा, रामनाथ. 2015. योग एवं चैतन्य विज्ञान. विद्यानिधि प्रकाशन. नई दिल्ली. पृष्ठ 195

कुमार, राजू. (2012). जल के व्यावसायीकरण से उत्पन्न जल संकट एवंज न असंतोष एक समाजशास्त्रीय अध्ययन. महात्मागांधी काशी विद्यापीठ. पेज 15

https://hindi.indiawaterportal.org/content/adaivaasai-kaa-taataparaya/content-type-page/49723

बिस्वास, ए.के. और जल्लाही, माहेम्मद. (1993). वाटर फॉर सर्टेनेबल डवलप में इन ट्वंटी फर्स्ट सेंचूरी.

मोदी, अनिता. (2007). बढ़ता जलसंकट गंभीर चुनौती, कुरूक्षेत्र

https://forestsclearance.nic.in/DownloadPdfFile.aspx?FileName=0_0_11123124812181TechnicalEstimatescanned.pdf&FilePath=../writereaddata/Addinfo/

https://nwda.gov.in/upload/uploadfiles/files/JV%20Apri%202023.pdf

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1898806

अग्रवाल, आशीष कुमार, एवं दुबे, शरद कुमार (2016). "पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का प्रभावः एक अध्ययन." आपूर्ति, 14(1), 15-24.

गुप्ता, मनीष कुमार, एवं शर्मा, विनय (2018). "ईआरसीपी के विकासात्मक प्रभाव का अध्ययनः पूर्वी राजस्थान के मामूली किसानों पर एक मानवाधिकारी दृष्टिकोण." आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन, 6(2), 37-48.

यादव, राजेश कुमार, एवं सिंह, अरुण कुमार (2020). "पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के चुनौतियों का विश्लेषणः एक अध्ययन. गृहविज्ञान, 18(2), 187-198.

वर्मा, संजय, एवं मिश्र, अनुपमा (2017). "पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के प्रभाव का मौद्रिक अनुसंधान." अर्थशास्त्री, 22(4), 127-138.

राजपूत, मोहन सिंह (2019). "पूर्वी राजस्थान नहर परियोजनाः विकास और संरक्षण के लिए चुनौतियाँ." सरकारी योजनाएँ और नीतियाँ, 7(3), 45-56.

प्रतीक कुमार, म. अ. (2023, 02 09). जल और बजट - 2023-24. Retrieved from India hindi water Portal: https://hindi.indiawaterportal.org/articles/jala-aura-bajata-2023-24

संखुवा, ड. आ. (2021, 10 25). राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की आंतरिक पत्रिका. Retrieved 10 10, 2023, from National Water Development Agency: https://nwda.gov.in/upload/uploadfiles/files/jalvikas01.pdf

संतोष. (2020). वैदिक साहित्य में जल संरक्षण एवं चेतना प्रबंधन . International Research Journal of Management Sociology & Humanity (IRJMSH), 228.

सुभाष, शर्मा, जल जीवन दिशा और दशा. पर्यावरण और विकास. सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, प्रथम संस्करण 2017, पृ0 63

बेदी और गुरनाम, पर्यावरण परिवर्तन एवं प्रभाव, पीयूष प्रकाशन दिल्ली, प्रथम संस्करण 2002, पृ0 11-15

मेघा सिंह, पर्यावरण अध्ययनः प्रकृति एवं महत्व, वंदना पब्लिकेशन नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2007, पृ0 31

https://www.drishtiias.com/hindi/daily-news-analysis/eastern-rajasthan-canal-project

https://www.kisantak.in/knowledge/story/eastern-rajasthan-canal-project-stuck-due-bjp-congress-politics-479719-2022-12-30

https://hindi.indiawaterportal.org/articles/paraacaina-bhaarata-maen-jala-sansaadhanaon-kaa-parabanadhana

https://hess.copernicus.org/articles/24/4691/2020/#section4

https://www.thehindu.com/hindi/editorial/clearing-the-water-the-hindu-editorial-in-hindi-on-piped-potable-water-to-rural-households/article67040016.ece

धातुकार: पूर्वमध्यकालीन उत्तरी भारत के सामाजिक-आर्थिक संदर्भ

डॉ. नैरंजना श्रीवास्तव*

सारांश

समाज, संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था के विकास में धातुकारों की प्रभावी भूमिका रही है। गुप्तों के बाद के समाज में धातुकारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के विषय में यात्रावृत्तांतकारों एवं तद्युगीन लेखकों द्वारा संदर्भतः प्रदान की गई जानकारी इस विषय में पथ-प्रदर्शक सिद्ध होती है। ह्वेनत्सांग ने अपनी यात्रा के दौरान पाया कि भारतीय वैज्ञानिक चिंतन की पांच मानक शाखाओं में दूसरी शाखा शिल्पस्थान नाम की थी। राजशेखर की काव्य मीमांसा ने भी प्रमुख विद्याओं में शिल्पशास्त्र को एक माना है। समस्त शिल्प कलाओं में धातुओं से जुड़ी कला जैसे ताम्रशिल्प, लौहशिल्प और स्वर्णशिल्प, बढ़ईगिरी तथा प्रस्तर कला के साथ शिल्प की पांच मुख्य शाखाएं थीं। आंध्र प्रदेश से ज्ञात ढालित कांस्य के एक पट्ट (1188 ईस्वीं) पर इन पांचो कलाओं को विश्वकर्मा के पांच पुत्रों, मनु, मय, त्वष्ट्र, दैवज्ञ, विश्वज्ञ द्वारा उपदिष्ट दिखाया गया है (सौजन्य से, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली)। इससे पता चलता है कि शिल्पकारों का जो भी सामाजिक स्तर रहा हो, उनमें धातुकार सदैव सम्मानित और प्रतिष्ठित रहे। ऋग्वैदिक समाज में शिल्पकार वैश्य वर्ण के सदस्य थे किंतु पश्चात्वर्ती कालों में उनके सामाजिक स्तर का निरंतर पतन होता गया। उत्तर वैदिक काल में वैश्य तथा शूद्रों के मध्य का विभेद धूमिल हुआ तथा सूत्रकाल में शिल्पकार जो पहले वैश्य समझ जाते थे, शूद्र तथा किन्ही स्थितियों में अछूत शूद्र अथवा अंत्यजों की श्रेणी में भी परिगणित किए जाने लगे। शिल्पकारों की यह स्थिति पूर्वमध्यकाल और उसके आगे भी जारी रही। शूद्र-कमलाकर में उद्धृत आदित्य पुराण के अनुसार तलवार और अन्य शास्त्रों का निर्माण करने वाली कुम्कुट जाति शूद्र तथा निषाद स्त्री की संतान थी। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार अपरार्क ने अन्य के साथ लोहार और सुनार के हाथ का भोजन करना भी ब्राह्मण के लिए वर्जित बताया है (पृ.1177-79)। लक्ष्मीधर भी इससे सहमति रखते हैं (नियत काल-कांड, पृष्ठ 262-63)। किंतु धातुकारों का वर्ग अंत्यज शूद्रों की श्रेणी में न होकर बहुधा सम्मानित शूद्रों की श्रेणी में ही रखा गया। किन्हीं परिस्थितियों में, जबकि वह गर्हित आचरण करने में प्रवृत्त हुए मात्र तभी उन्हें अछूत शूद्र माना गया, जैसे कि मध्य प्रदेश के लोहार जो माँस-भक्षण करते हैं (पालः 1978, 17)। प्रस्तुत शोधपत्र पूर्वमध्यकालीन साक्ष्यों के आलोक में धातुकारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का तथ्य-पूर्ण अनुमान करने का प्रयास करता है। यह महत्वपूर्ण विवेचन पूर्वमध्यकाल के अध्ययन को संपूर्णता प्रदान करने की दृष्टि से विशेष है क्योंकि धातुकार न मात्र ढांचागत उद्योगों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं बल्कि साम्राज्यों के शोभा-विस्तार के भी आनुषंगिक कारक हैं। उनके आर्थिक योगदान के साथ समाज द्वारा उन्हें प्रदान किए गए स्थान और सम्मान पर स्पष्टीकरण इतिहास की तार्किक जिज्ञासाओं में से एक है।

बीज शब्द: धातुकार, अर्थव्यवस्था, पूर्वमध्यकाल,बसाव

प्रस्तावना

अध्येय काल में श्रेणी समूह व्यावसायिक संगठनों से अधिक उपजातियों के रूप में जाने जाने लगे थे। स्मृतिचंद्रिका (III, व्यवहार कांड- भाग 1, 40) तथा वीरमित्रोदय (व्यवहार कांड, 12) में श्रेणियों का अर्थ 18 निम्न जातियों के रूप में किया गया है। भट्टोपाल (द्विवेदीः 1897, XXXIV.19) तथा वैजयंती (पृष्ठ 237, 1.179) के अनुसार भी श्रेणियाँ समान जाति व व्यवसाय वालों का समूह था। कान्हड़देप्रबंध (1.238) के अनुसार चार उच्च वर्ण के अतिरिक्त तत्कालीन समाज के 18 अन्य वर्ण श्रेणियाँ ही थीं। इन उल्लेखों से स्पष्ट होता है कि श्रेणियों को पहले की भांति आर्थिक संगठन से अधिक जातीय समूह माना जाने लगा था जो निश्चित रूप से व्यावसायिक स्तर पर इनकी क्रियाशीलता में कमी, व्यवसायों के स्थानीयकरण और सामंती युद्धों के द्वारा लाई गई सामाजिकार्थिक अस्थिरता के कारण हुआ होगा। लल्लन जी गोपाल ने श्रेणियों के पतन का मुख्य कारण पूर्वमध्यकालीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को माना है (1965, 82)।

शिल्पकारों को चातुर्वर्ण्य व्यवस्था में अधम और अंत्यज के स्तर तक पहुंचाने के पीछे श्रेणियों का यह सामाजिक पतन उल्लेखनीय रहा। ऋग्वैदिक समाज में अत्यंत सम्माननीय वैश्यवर्णी रथकारों को बौधायन धर्मसूत्र मिश्रित जाति का बताता है (1.9.17.6) जिसकी उत्पत्ति वैश्य पिता तथा शूद्रा माता से हुई थी। कौटिल्य ने अनुशंसा की है कि रथकार या तो शूद्र हो या चांडाल के अतिरिक्त किसी अन्य निम्न वर्ण को स्वीकार करें (अर्थशास्त्र III.7)।

*डॉ. नैरंजना श्रीवास्तव, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, कमच्छा, वाराणसी।

यह श्रेणियों की निरंतर पतनशील सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। यद्यपि गुप्तकालीन ग्रंथ अमरकोश और मुद्राराक्षस में (अमरकोश 2.35 पृष्ठ 267/मुद्राराक्षस अंक VI, 184) धातुकारों की उत्तम आर्थिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन है किंतु जैसा कि ब्रह्मवैवर्त और वृहद्धर्म पुराणों में वर्णित है, कांस्यकार तथा स्वर्णकार जैसी शिल्प श्रेणियाँ शूद्र वर्ण के अंतर्गत ही परिगणित होती रहीं तथा गोविंद केशव के भटेरा ताम्र पत्रों से पता चलता है, इनमें से कुछ (यथा पीतलकार श्रेणी) अत्यंत समृद्ध भी थी (एपिग्राफिया इंडिका ग्प्, पृ. 277ff) । जो भी हो, शिल्पकार श्रेणियाँ जो कभी वैश्य वर्ण की समझी जाती थीं, वर्ण की अधोगति के साथ-साथ शूद्र वर्ण में गिनी जाने लगीं। मनु और बौधायन धर्मसूत्रों में (क्रमशः III.112/I.II.4) वैश्यों तथा शूद्रों को समान माना गया है। अलबरूनी को भी वैश्य तथा शूद्र वर्णों में किसी भेद का दर्शन नहीं हुआ (सचाऊः1887, पृ. 136) यद्यपि आरंभ में शिल्पकार श्रेणियों के वैश्य वर्ण का होने और वैश्यों के सामाजिक पतन के कारण शिल्पकारों की भी सामाजिक स्थिति को पूर्वापेक्षया हानि हुई लेकिन साथ ही इसी कारणवश शूद्रों में सम्मिलित होने के बावजूद उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंची। वैश्यों, आदिवासी जनजातियों और मिश्रित जातियों के सम्मिलन से वर्धित शूद्र समाज के दायरे में, समय से, विभिन्न स्तरों की परिकल्पना की गई जिसमें वृहद्धर्म पुराण के अनुसार (उत्तरकाण्ड, अध्याय XIII.33-48, XIV.33-65) तीन स्तर थे, प्रथम 20 उत्तम संकर, द्वितीय 12 मध्यमसंकर और तृतीय 9 अधमसंकर या अंत्यज। शूद्रों की इसी स्तरीकृत व्यवस्था के अंतर्गत 18 श्रेणियों की भी गणना की गई जिन्हें जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति (43, पृ. 193) ने नारुआ (नारुकाह) अर्थात् छूत तथा कारुआ (कारूकाह) अर्थात अछूत जैसे दो भागों में बांटा है। समकालीन अभिलेखों में भी इन 18 श्रेणियों या प्रकृतियों का नामोल्लेख हुआ है (एपिग्राफिया इंडिका, वॉल्यूम-प्प्, पृ. 220; प्रोसीडिंग्स ऑफ़ दि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ़ बंगाल, 1877, पृ. 73; वागेलः 1911, 162 (L-11); 166 (L-10) तथा 193 (L-15) तथा कथाकोषप्रकरण में इन्हें 'अधम' अर्थात शूद्र कहा गया है (1949, पृष्ठ 116ff)। अलबरूनी ने अंत्यज के अंतर्गत जिन आठ श्रेणियों की गणना की उनमें कोई भी शिल्पकार नहीं थे (पृ.101)। वृहद्धर्म पुराण में स्वर्णकार को मध्यम संकर शूद्र वर्ण में रखा गया है (उत्तरकाण्ड, अध्याय XIII-33-48, XIV.33-65)। इससे स्पष्ट होता है कि पूर्वमध्यकाल में किन्ही अपवादों को छोड़कर शिल्पकारों को उनके कार्य के अनुरूप तथा कहीं न कहीं वैश्य वर्ण से उनके प्राचीन जुड़ाव के कारण सम्मान मिलता रहा। वे अन्य छूत-शूद्रों के साथ ब्राह्मणों के कुछ संस्कारों जैसे श्राद्ध का पालन करते थे तथा इस अवसर पर ब्राह्मण भोज भी करवाते थे। अत्रि स्मृति में श्राद्धी शूद्रों के वर्ग को इन दोनों कृत्यों की अनुमति दी गई है-

'शूद्रो अपि द्विविधो ज्ञेयो श्राद्धी चौवेतरस्यथा।
श्राद्धी भोज्योस्तयोरुक्तो अभोज्यास्त्वितरः स्मृतः'
(वैद्यः 1921, 252)

व्यावसायिक बसाव एवं आर्थिक स्थिति

व्यावसायिक बसाव की दृष्टि से श्रेणियों के रूप में संगठित शिल्पकारों के दो वर्ग थे। प्रथम वे, जो गांव में निवास करते थे तथा दूसरे वे जो शहरी क्षेत्रों में बसे थे। बौद्ध सूची जातक से 1000 लोहारों वाले गांव का पता चलता है जिसके महत्तर के पास अत्यधिक धन था तथा जो राजा का प्रिय था (कावेलः 1895- 1908, नंबर 387)।

शिल्पग्रामों की यह व्यवस्था पुराने समय से बाद तक भी जारी रही किंतु डी.डी. कोसांबी ने अपने अध्ययन में पाया कि पूर्वमध्यकाल में गांवों के शिल्पकारों की श्रेणियां कमजोर होती जा रही थीं जिसके स्थान पर वणिकों अथवा व्यापारियों का संघ मजबूत हो रहा था। वणिक संघ के विकास में सामंत राजाओं की भी अहम भूमिका रही (कोसांबीः 1975) क्रम से, इन वणिकों ने ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को अपने अनुकूल संचालित करना आरंभ कर दिया तथा वे मूल्य चुकाकर इच्छित वस्तुओं का निर्माण करवाने लगे, जिसके कारण वस्तुओं का कुल उत्पादन तो बढ़ा किंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन का ह्रास हुआ। पूर्वमध्यकाल में उच्च और निम्न वर्ग के लोगों में बढ़े सामाजिक अंतर का एक कारण व्यापारिक संघों के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप को भी माना जाना चाहिए। व्यापारियों द्वारा चुनिंदा कारीगरों से इच्छित वस्तुओं का निर्माण करवाने के कारण इस समय के गांवों में लोहारों का ग्राम अथवा बढ़इयों के ग्राम की अवधारणा अनुपादेय हो गई तथा व्यापार के लिए उपयोगी वस्तुओं के निर्माण की दृष्टि से तथा श्रेणियों के आंतरिक प्रशासन के ढीला पड़ने की वजह से शिल्पकारों ने भी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन (कमोडिटी प्रोडक्शन) में समूह के बजाय व्यक्तिगत रूप से हिस्सा लेना अपने परिवार के भरण पोषण की दृष्टि से उचित समझा। वस्तुतः श्रेणियों के पतन के कारण संपूर्ण ग्राम का किसी एक शिल्प पर निर्भर रह पाना संभव भी नहीं रह गया था। शहरी क्षेत्रों की आवश्यकता भी चूँकि शहरी शिल्पकार पूरी कर दे रहे थे अतः इन ग्रामीण शिल्पियों को कृषक ग्रामों में ही विभिन्न आवश्यक शिल्पों के उत्पादन-प्रक्रिया का हिस्सा बनने को बाध्य होना पड़ा। मेधातिथि ने श्रेणी और गण का भेद बताते हुए श्रेणी के सदस्यों को एक व्यवसाय में रत तथा स्वतंत्र रूप से भी कार्य करने वाला बताया है जबकि गण के सदस्य सदैव एकत्रित रूप से ही कार्य करते हैं (VIII-2)। इस प्रकार कोसांबी ने अपने लेख में पूर्वमध्यकालीन शिल्पकार-ग्रामों को पतनोन्मुख बताया है जिसके स्थान पर गाँवों की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले बढ़ई, लोहार जैसे शिल्पियों का एक समूह कार्य कर रहा था जिसे अपनी सेवाओं के बदले ग्रामीण उपभोक्ताओं से जमीन, बीज आदि भरण-पोषण के निमित्त प्राप्त होती थी। हालाँकि इस व्यवस्था के चलते धातुकारों तथा अन्य शिल्पों की तकनीकी विकास की गति निश्चित रूप से अवरुद्ध हुई होगी क्योंकि समान व्यवसाय से जुड़े कर्मियों के सामूहिक बसाव का सकारात्मक प्रभाव उत्पादन की गुणवत्ता पर भी पड़ता है।

ग्रामीण शिल्पकारों के विपरीत शहर में रहने वाले शिल्पकारों का उद्यम अच्छी स्थिति में था। इनके अपनी गली, अपनी सड़क, व अपना क्षेत्र निर्धारित होते थे। मारु-गुर्जर देश में रचित भुवन देव के ग्रंथ अपराजित पृच्छा में श्रेणियों और प्रकृतियों को राजा द्वारा निवासित शहरी केन्द्रों में बसने का विधान किया गया है। यहाँ सुनार, ताम्रकार व लोहार नगर के सामाजिक आर्थिक जीवन के महत्वपूर्ण अंग थे (72.32- 48)। 12वीं शती के गुजरात की ही भूमि के एक अन्य ग्रंथकर हेमचंद्र ने धातु व्यवसायियों के संगठन को राज्य की महत्वपूर्ण राजनैतिक-आर्थिक

नीतियों के निर्धारण में प्रभावक कारक माना है। ये व्यापारी स्वर्ण- रजत-ताम्र-लौह धातुओं से संबंधित देशी और विदेशी व्यापार करते थे तथा नगर में रहते थे।

अग्नि पुराण, युक्ति कल्पतरु तथा शार्ङ्गधर पद्धति के विवरणों में तलवारों के विशेषज्ञतायुक्त निर्माण- केन्द्रों की चर्चा की गई है तथा कौटिल्य (II.XVIII), डायोडोरस (उद्धृत, पुष्पा नियोगीः 1962, 242) एवं शुक्र (शुक्रनीति,II, पृ. 196-197) ने आयुधों के निर्माण को पूर्णतया राज्य द्वारा एकाधिकृत बताया है। इससे अनुमान होता है कि सम्राट और सामंतों की प्रत्यक्ष निगरानी में शहरी लोहार तकनीकी रूप से उन्नत वस्तुओं का निर्माण कर रहे थे जबकि ग्रामीण लौहकारों के उत्पादन में इनकी तुलना में पर्याप्त भिन्नता थी। यही स्थिति संभवतः अन्य शिल्पों की भी रही होगी। जहाँ शहरी सुनार व ताम्रकारों द्वारा निर्मित वस्तुएं धनी व संभ्रांत वर्ग के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर बनाई जा रही थीं वहीं ग्रामीण धातुकारों का उपभोक्ता वर्ग इनसे पृथक् था जिसके कारण दोनों क्षेत्रों के उत्पादन भी भिन्न-भिन्न तकनीकी कुशलता तथा फिनिश वाले हुए।आज भी ग्रामीण स्वर्णकारों की आभूषण निर्माण प्रक्रिया शहरी स्वर्णकार की तुलना में सरल होती है। शहरों में सुंदर आभूषणों का मात्र प्राथमिक ढांचा ही बनता है। इसके बाद चितेरा उस पर डिज़ाइनों का उत्कीर्णन करते हैं। कुंदनसाज़ मूल्यवान पत्थरों को जड़ते हैं और मीनासाज़ मीना का काम करते हैं, आदि। किंतु ग्रामीण स्वर्णकारों को यह समस्त कार्य अकेले ही करने पड़ते हैं।

नगरों में निवास करने वाले शिल्पकारों के वास-स्थान के विषय में भी ग्रंथों में मंथन किया गया है। अर्थशास्त्र में धातुकारों तथा रत्नकारों को ब्राह्मणों के साथ शहर का उत्तरी भाग उनके बसाव के लिए आवंटित करने की बात कही गई है (II.4)। अग्निपुराण में स्वर्णकारों को नगर के दक्षिण-पश्चिमी भाग में रहने तथा मयमत में कान्स्य और पीतलकारों को शहर के बाहरी इलाके में रहने की व्यवस्था बताई गई है (अध्याय 10, 11, पृष्ठ 154-83)। मयमत के समय तक (उत्तरमध्यकाल) सामान्य तौर पर सभी कारीगरों को शहर के बाहरी इलाकों में बसने की व्यवस्था की जाने लगी थी (अध्याय 9, पृष्ठ 29) जिसका कारण उन्हें उनके उद्यम के विकास के लिए उचित वातावरण प्रदान करना रहा होगा।

धातुकारों के निवास की उपरोक्त व्यवस्था से स्पष्ट है कि शहरों में रहने वाले कारीगर अच्छी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में थे। वे संभ्रांतों के लिए आभूषणों का निर्माण करते थे जिसके लिए उन्हें सम्मान तथा धन दोनों की प्राप्ति होती थी। वृहद्कथाश्लोकसंग्रह में वैश्यालय के दूसरे तथा पांचवें प्रकोष्ठों में क्रमशः स्वर्ण और रजत तथा स्वर्ण और ताम्र का कार्य होना बताया गया है। यहां पर कथित धातुओं से सुंदर वस्तुओं का निर्माण करते थे जिससे शहरी विलास के आनंद को द्विगुणित किया जाता था। अतः निश्चित रूप से यहां के धातुकार अपनी कला में अत्यंत निपुण रहे होंगे (X.90-9)। मृच्छकटिक में भी इसी प्रकार वसंतसेना के निवास के छठे प्रकोष्ठ में स्वर्ण, रजतकारों की कार्यशाला का स्थित होना बताया गया है (मृच्छकटिक, भाग 4)। गुप्तकालीन ग्रंथ मुद्राराक्षस से पता चलता है कि विष्णुदास कुसुमपुर का प्रतिष्ठित स्वर्णकार था। हर्षचरित में बाणभट्ट के सहयात्रियों में स्वर्णकार भी एक था (हर्षचरित,I, पृ. 41-42)। शहरी श्रेणियाँ अपने विशेषज्ञ सदस्यों की प्रश्रेणियों (त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित, I, पृष्ठ 258) के माध्यम से उम्दा कारीगरी का प्रदर्शन कर अच्छी कमाई कर लेती थीं। इसी बात का संकेत शुक्र नीति में प्राप्त होता है। अर्थशास्त्र में जहाँ धातु (जैसे सोने, लोहे, ताम्र) की विविधता के आधार पर धातुओं के वेतन का निर्धारण होता था (अर्थशास्त्र, पुस्तक-2, अध्याय XXIV), वहीं शुक्रनीति में विधान है कि कारीगरी की जटिलता के आधार पर कारीगर को वेतन दिया जाए। उत्तम, मध्य तथा निम्न श्रेणी की कारीगरी पर सुनार को दिया जाने वाला वेतन क्रमशः 1/30, 1/60 तथा 1/120 था (बोसः 1961, 240)। इसी प्रकार, चांदी के कारीगर को दिया जाने वाला भाग उत्तम, मध्य और निम्न श्रेणी की कारीगरी के अनुसार क्रमशः 1/2, 1/4, 1/8 था। स्वर्णकार व रजतकार को स्वर्ण व रजत में कटक के निर्माण पर क्रमशः 1/240 तथा 1/16 भाग वेतन की प्राप्ति होती थी।

स्वर्ण के प्रगलन के लिए प्राप्त वेतन 1/480 था। अपने कला कौशल के प्रदर्शन से इन स्वर्णकारों में से चुनिंदा को मुख्य सड़क पर दुकान के संचालन के लिए स्थान भी दिया जाता था तथा सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार को राजकीय स्वर्णकार के पद पर स्थापित किया जाता था। इस प्रकार शहर के स्वर्णकारों की स्थिति ग्रामीण सुनारों की तुलना में कहीं बेहतर होती थी जिसे वह अपने प्रदर्शन के बल पर और भी सुधार सकने में समर्थ थे। किंतु श्रेणियों की विश्वसनीयता और आंतरिक संगठन में आई कमी के कारण श्रेणी के रूप में स्वर्णकार समूह की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनकी अपेक्षा श्रेणियों के मुखिया तथा कुछ स्वतंत्र शिल्पकार ही धनी व संपन्न हो सके थे (पालः 1978, 132)। समकालीन अभिलेखों में कांस्यकार (इंडियन एटीक्वेरी. XLI, पृ. 20ff (एपिग्राफिया इंडिका, IX, गोविंदकेशव का अभिलेख) तथा पीतलहार (एपिग्राफिया इंडिका, वॉल्यूम IV, पृष्ठ 153ff) का बहुधा उल्लेख मिलता है। चंदेल अभिलेखों में पाल्हण नामक पीतलकार को अभिलेखों के उत्कीर्ण करने का श्रेय दिया गया है तथा समयान्तराल से उसके पद की उन्नति भी देखने को मिलती है जो उसकी कला में सिद्धहस्तता के सापेक्ष रही। उसे पीतलकार (सेमरा ताम्रपत्र, विक्रम संवत 1223), शिल्पिन् (इच्छावर पत्र, विक्रम संवत 1228), विज्ञानिन् (महोबा ताम्रपत्र, विक्रम संवत 1230) तथा वैदग्धि विश्वकर्मन् (पचार ताम्रपत्र, विक्रम संवत 1233), चरखरी ताम्रपत्र, विक्रम संवत 1236) तक की उपाधियां प्रदान की गई हैं जो क्रम से महत्तर होती जाती हैं। राय बहादुर हीरालाल ने इन अभिलेखों के अपने अध्ययन में पाया कि लेखों की लिखावट में कोई विशेष अंतर नहीं दृष्टिगोचर होता (एपिग्राफिया इंडिका, वॉल्यूम XX, पृष्ठ 128)। अतः ऐसा माना जा सकता है कि इस पाल्हण नामक पीतलकार को प्रस्तुत उपाधियां या तो उसकी कला में निपुणता को देखते हुए दी गईं अथवा उसका सामाजिक स्तर इतना ऊंचा उठ चुका था कि कारीगरी में महारत के बिना भी उसे यह पदवियाँ देने की आवश्यकता हो आई होगी। जो भी हो, इतना अवश्य कहा जा सकता है की ताम्रकारों या पीतलकारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति स्वर्णकारों से बहुत भिन्न नहीं थी। किंतु नगरों में ताँबे और पीतल का काम करने वालों को सोने का काम करने वालों की अपेक्षा कम धनराशि का भुगतान किया जाने का नियम था। कौटिल्य ने जहाँ स्वर्ण और चांदी के धरण बनाने वाले को क्रमशः 1/8, 1/16 भाग प्रदान करने का प्रावधान किया है वहीं ताम्र-पीतल की वस्तुओं के निर्माण पर उनका मानदेय 1/20 भाग था (IV.1, म्युनिख पांडुलिपि)। शुक्रनीति में ताम्र, जस्त व यशद धातुओं के कारीगर को 1/4 भाग भुगतान प्रदान करने का नियम बताया गया है (IV.633-59)। इनके वेतन-भाड़े के विषय में प्रबंध

चिंतामणि का एक विवरण उद्धरणीय है जिसके अनुसार एक युवक एक कान्स्यकार की कार्यशाला में 20 विशोंपक प्रतिदिन के वेतन पर कार्य करता था (देवीः 1987,पृ. 113)।

नगरीय लौहकारों की आर्थिक स्थिति यद्यपि स्वर्णकारों के समान नहीं थी किंतु उनका कौशल अन्य सभी धातुओं से बढ़कर राज्य की सुदृढ़ता के लिए उपादेय और उत्पादक रही है। कौटिल्य ने धातुओं के अनुसार उनके कारीगरों का वेतन निर्धारित किया है जिसके अनुसार लौह शिल्पियों को प्रति उत्पादन दो काकिणी दी जाती थी, यह अन्य धातुओं की तुलना में प्राप्त न्यूनतम वेतन था। किंतु शुक्र ने कार्य के संपादन के अनुसार उसका भुगतान निश्चित करते हुए उत्तम, मध्यम आदि स्तरों के कार्य पर 1/2, 1/4 तथा 8 भाग वेतन बताया। किंतु नगर के विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में लौह शिल्पियों को वेतन न देकर बीज और अनाज आदि प्रदान कर उनकी सेवाएं ली जाती थीं। डी.डी. कोसांबी के अनुसार उन्हें प्रति कृषक 1.75 प्रतिशत अनाज, 1 से 3 पाउंड बीज की प्राप्ति होती थी, जिसके बदले वे पूरे गाँव का लौह उपकरण ठीक करते थे। नए उपादान के निर्माण के लिए उन्हें धातु प्रदान करने के साथ ही अतिरिक्त भुगतान भी किया जाता था।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में: पूर्वमध्यकाल में धातुकारों की स्थिति का आकलन किया जाना संभव है। हिंदू जातीय व्यवस्था में धातुकारों के स्थान के निर्धारण में उनकी आर्थिक स्थिति का विशेष योगदान था और कई परिस्थितियों में यह आर्थिक स्थिति नगरीय निवास तथा उन बाजारों पर निर्भर करती थी जहां धातुकार अपनी कला का लाभदायक प्रदर्शन कर सकते थे। नवीन अध्ययन अब इस बात पर विशेष बल देते हैं कि पूर्व मध्यकाल की आर्थिक व्यवस्था नवीन राजनैतिक संरचना से प्रत्यक्षतः प्रभावित हुई और यह परिवर्तन सामंती ढांचे से बढ़कर नगरीय एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के मध्य स्पष्ट विभाजन के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। इस दृष्टि से, धातुकारों के वर्ग, जिसने नगर और ग्राम्य व्यवस्थाओं के मध्य की परिवर्तित परिस्थितियों को सर्वाधिक प्रभावी रूप से अभिव्यक्त किया, की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है।

वस्तुतः धातुकारी, मूलभूत संरचनात्मक उद्योगों और नागरिक जीवन-शैली का आधार है जिसके लिए तकनीकी कौशल और तैयार बाजार का अत्यधिक महत्व होता है। समकालीन साहित्य में देशी बाज़ारों के जो विस्तृत वर्णन प्राप्त होते हैं उनसे स्पष्ट है कि गुप्तों के बाद का समाज धातु उत्पादों के निर्माण और खपत की दृष्टि से पर्याप्त सक्रिय था। कथासरित्सागर में पौंड्रवर्धन के बड़े बाज़ार का वर्णन आया है। दूबकुंड प्रस्तर अभिलेख में भी दूबकुंड के बेहतरीन बाज़ार का उल्लेख प्राप्त होता है जहां की व्यापारिक गतिविधियां काफी सघन थीं। शहरों के कुछ मुख्य बाज़ार महाजनों की देखरेख में कार्य करते थे। अण्हिलवाड़ के एक बड़े बाजार की गतिविधियों का जो समकालीन चित्र प्राप्त होता है उसके अनुसार यहां 84 बाजार थे जो विशिष्ट उत्पादन में व्यापार के लिए एक दूसरे से पृथक्-पृथक् बसाए गए थे। इनमें सुनार, चांदी के कारोबारी और अन्य शिल्पियों के लिए भी अलग-अलग बाज़ार मौजूद थे। बाज़ारों की यह स्थिति इस युग में व्यापार वाणिज्य की उत्तम अवस्था की परिचायक है।अपने राजस्व की वृद्धि के लिए इनमें से कुछ बाज़ारों का निर्माण स्वयं राजा भी करवाते थे जैसा कि प्रबंध चिंतामणि से सूचित होता है (पृ.45)। इन बड़े बाज़ारों के अतिरिक्त प्रमुख गांवों में छोटे बाज़ार या हाट भी होते थे (एपिग्राफिया इंडिका, IX, 277ff/ XXII, 150ff, इंडियन एंटीक्वेरी, LVIII, 161ff) जहां ग्रामीण वर्ग की आवश्यकता के सामान मिलते थे। यहीं ग्रामीण लोहार बड़े नगरीय केन्द्रों से उत्पादित वस्तुओं, जैसे युद्ध के हथियार, स्मृति-स्तंभ, इमारती बीमें आदि से इतर ग्रामीणों की दैनन्दिन आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे थे।

व्यापार और वाणिज्य के कारण संपन्नता को प्राप्त समकालीन शासक, सामंत और महाजन वर्ग का जीवन धन- वैभव के प्रदर्शन को अत्यधिक महत्व देता हुआ दिखाई देता है। समकालीन कलासाक्ष्यों एवं साहित्य से पता चलता है कि पीतल, तांबे, स्वर्ण, रजत, सीसा और टिन की बनी वस्तुओं, जैसे बर्तन-आभूषण और आसन- पर्यंकादि का पर्याप्त प्रचलन था जो आभिजातीय प्रदर्शन के माध्यम थे (मानसोल्लास, 3.8.1049-1129; कर्पूरमंजरी, 14, 3.13 ; राजतरंगिणी, 3.1146-1147, 1185-86, 7.1691, 7.265; एपिग्राफिया इंडिका, I, 307 और आगे)। साहित्य में राजाओं, सामंतों और धनी-वर्ग के ऐश्वर्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति का वर्णन प्राप्त होता है (मानसोल्लास, III123-129; राजतरंगिणी VII-928-31, 881-83, 895, 994, 946-49; कुट्टनीमतम्, श्लोक 61-70; मोहराजपराजय- अंक III, 53ff आदि)। समकालीन मुस्लिम लेखक भारतीय राजाओं के महंगे हार और जड़ाऊ कर्णाभूषण पहनने के शौक का विस्तार से वर्णन करते हैं (इलियट- डाउसन, वा. 2, 11)। बहुमूल्य धातुओं से अपने महलों और मंदिरों तथा देव मूर्तियों को सज्जित करने के इसी शौक ने आक्रांता तुर्कों को भयंकर लूटपाट के लिए प्रेरित किया। आसारुद बिलाल में ज़करिया अल काज़विनी ने सोमनाथ मंदिर में 200 मन भार वाली सोने की चेन का उल्लेख किया है जिसे बजाकर मंदिर के कर्मचारियों को समय का ध्यान कराते थे तथा महमूद गजनवी के द्वारा नगरकोट के किले में नष्ट की गई वस्तुओं की सूची में 30 ×15 यार्ड के एक छोटे रजत आवास का भी वर्णन हुआ है। चंदेल अभिलेखों में घरों और मंदिरों के विभिन्न हिस्सों को स्वर्ण और रजत से मंडित करने का प्रसंग आया है जो महलों और देवालयों से समीकृत किया जा सकते हैं।

निष्कर्ष

इससे प्रमाणित होता है कि अध्येय युग में व्यापार और वाणिज्य की स्थिति में वैसा विस्मयकारी परिवर्तन नहीं हुआ जैसी की मान्य अवधारणा रही है। इस युग की अर्थव्यवस्था का निराशाजनक पक्ष मात्र यही था कि अब धन के निवेश से अधिक उसके संचय पर बल दिया जाने लगा था जिससे स्थानीय शिल्प और उद्योग धंधों का तकनीकी और व्यावसायिक विकास अवरुद्ध हुआ। शासक वर्ग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े शिल्पकार तथा उनके उद्योगों को जहां विकास के अपेक्षाकृत अधिक अवसर प्राप्त थे वहीं ग्रामीण क्षेत्र के उद्योग तथा शिल्प अपनी पुरानी तकनीक पर ही कार्य कर रहे थे।

नगरीय और ग्रामीण केन्द्रों में विभाजित धातुकारों की इस बसावट का सीधा असर उनके कार्य की उत्पादकता, तकनीकी कौशल और सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर पड़ा। यह स्थिति यद्यपि धातुकारों के हित में नहीं मानी जा सकती फिर भी उत्पादन में आई तेज़ी और विलासितापूर्ण जीवन के प्रति बढ़ते अनुराग ने पूर्वमध्यकाल के धातुकारों को व्यस्त रहने के पर्याप्त अवसर दिए होंगे, ऐसा अनुमान करना अनुचित नहीं।

सन्दर्भ सूची

अग्रवाल वी.एस.,1953, हर्षचरितः एक सांस्कृतिक अध्ययन, पटना

इलियट एच. एम. व जे. डाउसन, 1866-77, हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया एज़ टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टीरिया, 8 जिल्दों में, लंदन, (पुनर्मुद्रित) इलाहाबाद, जिल्द 2 (पुनर्मुद्रित) परिचय एम. हबीब, टिप्पणी एस. आर. होदीवाला और परिशिष्ट के. ए. निज़ामी, अलीगढ़ 1952

उपाध्याय भगवत शरण,1954, (दो खण्डों में) कालिदास का भारत, काशी, भारतीय ज्ञानपीठ

कावेल ई.बी., 1895-1908, द जातक

कावेल (अनु.), 1961, हर्षचरित, वाराणसी, मोतीलाल बनारसीदास

कोनो स्टेन, 1901, राजशेखर्स कर्पूर मंजरी, वाराणसी, मोतीलाल बनारसी दास

कोसांबी डी.डी., 1975, ऐन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ़ इंडियन हिस्ट्री, बाम्बे, पॉपुलर प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड

काँगले आर.पी., 1986, द कौटिलीय अर्थशास्त्र, (तीन खण्डों में), दिल्ली, मोतीलाल बनारसीदास

गोपाल लल्लन जी, 1965, द इकोनामिक लाइफ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, वाराणसी, मोतीलाल बनारसी दास

ग्यानी एस.डी., 1964, अग्नि पुराणः ए स्टडी, वाराणसी, चौखंबा पब्लि.

द्विवेदी एस.डी., (संक.), 1895, वृहत्संहिता की टीका, वाराणसी

देवी सुशील मालती,1987, इकोनामिक कंडीशन ऑफ़ एंशिएंट इंडिया फ्रॉम ए. डी. 750-1200, दिल्ली, रामानंद विद्या भवन

नियत काल-कांड, वॉल्यूम III, 1950, गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज, बड़ौदा नं. CXV

नियोगी पुष्पा ,1962, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ़ नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम 10-12 सेंचुरी ए.डी., कोलकाता, प्रोग्रेसिव पब्लिशर्स

पाल एम.के.,1978, क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्समैन इन ट्रेडीशनल इंडिया, नई दिल्ली, कनक पब्लिशर्स

पीटरसन डॉ. पीटर,1987, शार्ङ्गधर पद्धति दिल्ली, चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान

बोस ए. एन.,1961, सोशल एंड रूरल इकोनॉमी ऑफ़ नॉर्दर्न इंडिया, सरका 600 बी.सी. टू 200 ए.डी., कोलकाता, वॉल्यूम 1, पुस्तक II, अध्याय III

मुनि जिनविजय (संपा.),1949, कथाकोषप्रकरण, बॉम्बे

कोनो स्टेन, 1901, राजशेखर्स कर्पूर मंजरी, वाराणसी, मोतीलाल बनारसी दास

वागेल जे.,1911, एंटीक्विटीज ऑफ़ द चंबा स्टेट्स, कोलकाता

वैद्य चि. वि.,1921, हिस्ट्री ऑफ़ मेडिवल हिन्दू इंडिया, पूना, द ओरिएंटल बुक सप्लाइंग एजेन्सी

शास्त्री हरगोविंद, 'अमरकोश', काशी, संस्कृत ग्रंथ माला

सचाऊ इ.सी., (संकलित),1887, अबु अल रिहान मोहम्मद इब्न अहमद अलबरूनी, 'किताब उल हिंद', लंदन, (अनुवाद 1910, लंदन)

संदेसरा बी.जे. (संक.), 1967, भूलोकमल्लसोमेश्वरविरचितः मानसोल्लास, बड़ौदा, गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज, नंबर 28

उच्च और निम्न उपलब्धि वाले खिलाड़ियों के बीच आत्मविश्वास का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. आलोक कुमार सिंह*
डॉ. महेंद्र प्रताप गौड़**
डॉ. दिलीप कुमार चौधरी***
डॉ. राकेश प्रसाद****

सारांश

वर्तमान अध्ययन में खिलाड़ियों की उपलब्धियों के आधार पर उनके आत्मविश्वास की तुलना करने की योजना बनाई गई थी। अध्ययन का संचालन करने के लिए, 50 इंटर-कॉलेज (कम उपलब्धि वाले) खिलाड़ी (औसत उम्र 21.12 वर्ष) और 50 राष्ट्रीय (उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले) खिलाड़ी (औसत उम्र 24.14 वर्ष) जिन्होंने अपने इंटर-कॉलेज (कम उपलब्धि) और राष्ट्रीय (उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले) का प्रतिनिधित्व किया किसी भी खेल आयोजन में उपलब्धि) को एक नमूने के रूप में चुना गया था। नमूनों का चयन मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में कार्यरत इंटर-कॉलेज और राष्ट्रीय खिलाड़ियों से किया गया था। पांडे (1983) द्वारा तैयार आत्मविश्वास सूची का उपयोग चयनित विषयों के आत्मविश्वास का आकलन करने के लिए किया गया था। नतीजे बताते हैं कि उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों का आत्मविश्वास कम उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों की तुलना में काफी अधिक था।

बीज शब्द: आत्मविश्वास-(कम उपलब्धि और उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी)

प्रस्तावना

आत्मविश्वास एक प्रसिद्ध कारक है जो एथलेटिक प्रदर्शन को बढ़ा या सुधार सकता है। अधिकांश खेल कार्यक्रमों में मानसिक अभ्यास शामिल होता है। यह कम कौशल स्तर पर एथलीटों के आवश्यक विकास में मदद करने के लिए पाया गया है। यह पाया गया है कि आत्मविश्वास का कारक वह है, जिसे एथलीट और कोच अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रासंगिक मानते हैं। आत्मविश्वास वह गुण है जो व्यक्ति को अपने विचारों, क्षमताओं और निर्णयों पर विश्वास रखने की शक्ति देता है। यह सफलता की कुंजी है जो हमें चुनौतियों का सामना करने, नई चीजें सीखने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। आत्मविश्वास केवल बाहरी व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारी आंतरिक सोच, धैर्य और मानसिक दृढ़ता से भी जुड़ा होता है। जब कोई व्यक्ति आत्मविश्वास से भरपूर होता है, तो वह कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होता है और असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ता है। आत्मविश्वास से न केवल हमारी व्यक्तिगत और पेशेवर ज़िंदगी में सुधार होता है, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य और समाज में हमारी प्रतिष्ठा को भी बढ़ाता है। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमें अपने सकारात्मक गुणों को पहचानना, खुद पर भरोसा करना और नकारात्मक सोच से बचना आवश्यक है। नियमित अभ्यास, ज्ञान की वृद्धि और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत बना सकते हैं।

आत्मविश्वास अक्सर प्रतिकूल होता है क्योंकि अहंकारी या अपनी ही शक्ति पर निर्भीक निर्भरता। आत्मविश्वास एक ज्ञान कारक है जो एथलेटिक कौशल को बढ़ा या सुधार सकता है। अधिकांश खेल कार्यक्रमों में मानसिक अभ्यास शामिल होता है, जो कम कौशल स्तर पर एथलीटों के आवश्यक विकास में मदद करता पाया गया है।

एथलीटों को मानसिक रूप से कल्पना और आत्मविश्वास दोनों का अभ्यास करने की आवश्यकता है। कई कारक कल्पना को प्रभावित करते हैं, जिनमें दैहिक चिंता, प्रेरणा, भावनाएँ और आत्मविश्वास शामिल हैं। यह पाया गया है कि आत्मविश्वास का एक कारक वह है जिसे एथलीट और कोच अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रासंगिक मानते हैं। कुछ अध्ययनों में पाया गया कि कई लोग और एथलीट व्यायाम और शारीरिक फिटनेस (उपयुक्तता) बढ़ाने के लिए आपातकाल का उपयोग करते हैं क्योंकि आपातकाल उनके व्यायाम की सफलता में मदद करती है (हॉल 2001)

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एथलीटों के प्रदर्शन और कल्पना को लागू करना मानक प्रक्रिया है। गैर-एथलीटों की तुलना में उच्च आत्मविश्वास वाले विशिष्ट एथलीटों द्वारा इस पद्धति का अधिक उपयोग किया जाता है।

*डॉ. आलोक कुमार सिंह, सहायक आचार्य, शारीरिक शिक्षा विभाग, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश।
**डॉ. महेंद्र प्रताप गौड़, सह-आचार्य, शारीरिक शिक्षा विभाग, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश।
***डॉ. दिलीप कुमार चौधरी, सहायक आचार्य, शारीरिक शिक्षा विभाग, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश।
****डॉ. राकेश प्रसाद, सहायक आचार्य, शारीरिक शिक्षा विभाग, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश।

आत्मविश्वास सबसे अधिक उद्धृत मनोवैज्ञानिक कारकों में से एक है जिसे कई लोग सफल प्रदर्शन की कुंजी मानते हैं। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में, किसी व्यक्ति के आत्मविश्वास की डिग्री प्रदर्शन को प्रभावित करती है।

साहित्य की समीक्षा

फ़ारूक अहमद और इलाज़ीज़बदाह्मद (2002) ने पूर्वकाल क्रूसिएट लिगामेंट चोटों वाले फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए आत्मविश्वास के स्तर और प्रतिस्पर्धा की चिंता पर मनोवैज्ञानिक पुनर्वास कार्यक्रम पर एक अध्ययन किया। नमूने में दो समूहों (नियंत्रण और प्रयोगात्मक) का उपयोग करके लागू प्रायोगिक पद्धति के आठ फुटबॉल खिलाड़ियों को शामिल किया गया था, प्रस्तावित कार्यक्रम ने सकारात्मक रूप से आत्मविश्वास के स्तर में सुधार किया, संज्ञानात्मक और शारीरिक चिंता के आयामों को कम किया और आत्मविश्वास में वृद्धि की, जो खेल प्रतिस्पर्धा की चिंता का सकारात्मक आयाम है।

वुडमैन टिम और हार्डी लाल (2003) ने खेल प्रदर्शन पर संज्ञानात्मक चिंता और आत्मविश्वास के सापेक्ष प्रभाव पर मेटा-विश्लेषण पर एक अध्ययन किया। आत्मविश्वास माध्य प्रभाव का आकार $r=0.24$ ($p<0.001$) था। एक युग्मित नमूना टी-परीक्षण से पता चला कि आत्मविश्वास माध्य प्रभाव आकार का परिमाण संज्ञानात्मक चिंता माध्य प्रभाव आकार की तुलना में काफी अधिक था।

(मैमासिस और डॉकजानिस) जॉर्ज (2004) जूनियर्स की प्रतिस्पर्धा-पूर्व चिंता, आत्मविश्वास और टेनिस प्रदर्शन पर मानसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रभाव। अध्ययन में जिसमें एमटीपी खिलाड़ी (N=5) थे, परिणामों ने पोस्टटेस्ट (पश्च परीक्षण) में हस्तक्षेप समूह के लिए आत्मविश्वास में वृद्धि का संकेत दिया। आत्मविश्वास की तीव्रता और समग्र टेनिस प्रदर्शन महत्वपूर्ण हैं।

कैस क्रिस्टजन और राउडसेप्लेनार्ट (2004) ने बीच वॉलीबॉल के एथलेटिक प्रदर्शन में संज्ञानात्मक और दैहिक चिंता और आत्मविश्वास का एक अध्ययन किया। 66 पुरुष बीच वॉलीबॉल खिलाड़ियों का अध्ययन मूल तीव्रता पैमाने और जोन्स और स्वेन खिलाड़ियों के प्रदर्शन की दिशा पैमाने पर मानक रेटिंग स्केल का उपयोग करके वीडियो रिकॉर्ड से स्कोर किया गया था, आत्मविश्वास मध्यम सकारात्मक (R= 0.27 से 0.51) सहसंबंध था विभिन्न कौशल घटक और बीच वॉलीबॉल के कौशल के योग के साथ आत्मविश्वास के प्रदर्शन के महत्वपूर्ण भविष्यवक्ता थे, लेकिन 42% भिन्नता के लिए जिम्मेदार थे।मार्टेंस (Martens, 1977) के अनुसार, "आत्म-विश्वास वह विश्वास है जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं और सफल होने की संभावना के प्रति रखता है।" खेलों में आत्म-विश्वास का अर्थ है कि खिलाड़ी अपनी खेल क्षमता, निर्णय लेने और प्रदर्शन को लेकर सकारात्मक सोच रखते हैं। वुडमैन और हार्डी (2003) के अनुसार, जिन खिलाड़ियों में उच्च आत्म-विश्वास होता है, वे दबाव की स्थितियों में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। इसके विपरीत, आत्म-विश्वास की कमी खिलाड़ी को मानसिक रूप से कमजोर बना सकती है, जिससे उनका प्रदर्शन प्रभावित होता है।

रतनकोसेस रोवोवालाबॉल (2009) ने महिला और पुरुष एथलीटों में छवि और आत्मविश्वास के बीच संबंधों का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन किया। विषयों का चयन 71 पुरुष और 49 महिला एथलीटों के उद्देश्यपूर्ण नमूने द्वारा किया गया था। पुरुषों और महिलाओं में आपातकाल और आत्मविश्वास के उपायों के बीच औसत अंतर निर्धारित करने के लिए टी-टेस्ट और एनोवा परीक्षण का उपयोग करके डेटा का विश्लेषण किया गया था। परिणाम पुरुषों और महिलाओं के बीच कल्पनाशीलता और आत्मविश्वास (आर=0.71) के संबंध में एक महत्वपूर्ण सहसंबंध दिखाते हैं।

परिकल्पना

यह अनुमान लगाया गया था कि कम उपलब्धि वाले और उच्च उपलब्धि वाले खिलाड़ियों के बीच आत्मविश्वास में महत्वपूर्ण अंतर होगा।

कार्यप्रणाली

उपर्युक्त परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित पद्धतिगत कदम उठाए गए।

नमूना

वर्तमान अध्ययन का संचालन करने के लिए, 50 कम उपलब्धि वाले खिलाड़ियों (औसत उम्र 21.12 वर्ष) और 50 उच्च अचीवर्स खिलाड़ियों (औसत उम्र 24.14 वर्ष) को यादृच्छिक रूप से चुना गया था; सभी खिलाड़ी छत्तीसगढ़ में चल रहे इंटर-कॉलेज और राष्ट्रीय टूर्नामेंट के प्रतिभागी थे।

उपकरण

पांडे (1983) द्वारा तैयार की गई सूची का उपयोग चयनित विषयों के आत्मविश्वास का आकलन करने के लिए किया गया था। यह सूची हिंदी में है और इसमें 60 प्रश्न हैं। सूची में प्रश्नों की प्रकृति मिश्रित है, यानी, 18 प्रश्न सकारात्मक शब्दों वाले हैं जबकि 42 प्रश्न नकारात्मक शब्दों वाले हैं। सत्यता की विश्वसनीयता और वैधता संतोषजनक है।

प्रक्रिया

आत्म-विश्वास पर आधारित वर्तमान अध्ययन के लिए, प्रश्नावली विधि द्वारा डेटा (आकाडे) एकत्र किया गया है और लेखक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मूल्यांकन की गई है।

परिणाम

स्कोरिंग के बाद, डेटा (आकाडे) को उनके संबंधित समूहों के अनुसार सारणीबद्ध किया गया। इन दोनों समूहों के बीच अंतर निर्धारित करने के लिए 'टी' परीक्षण का उपयोग किया गया था।परिणामतालिका 1 मेंप्रस्तुतकिएगएहैं।

तालिकाक्रमांक 1
कम उपलब्धि वाले और के बीच आत्मविश्वास की तुलना
उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी

चर Variable	***कम उपलब्धि वाले खिलाड़ी*** (N=50)		***उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी*** (N=50)		t	महत्व का स्तर Level of Significance
	Mean माध्यिका	S.D.	Mean माध्यिका	S.D.		
आत्मविश्वास	17.85	7.71	21.38	7.05	2.83	0.01

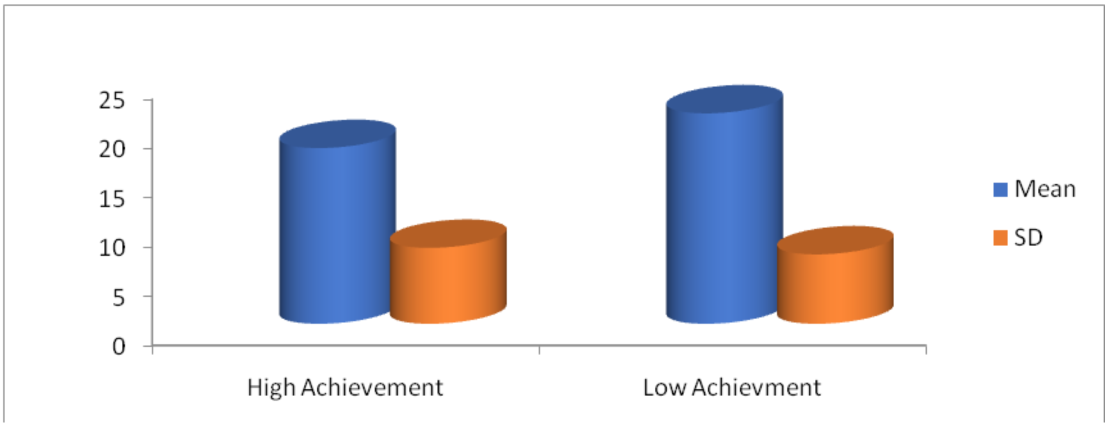

तालिका 1 में रिपोर्ट किया गया मान 2.83 है, जो महत्व और औसत मान के 0.01 स्तर पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है। यह इंगित (प्रस्तुत) करता है कि उच्च उपलब्धि वाले खिलाड़ी (माध्यिका = 21.83) अपने समकक्षों की तुलना में अपनी क्षमताओं के बारे में काफी अधिक आत्मविश्वास रखते हैं, अर्थात, कम उपलब्धि वाले खिलाड़ी (माध्यिका = 17.85)

निष्कर्ष

आत्मविश्वास की सामाजिक-मनोवैज्ञानिक अवधारणा निर्णय, क्षमता, शक्ति आदि में आत्मविश्वास से संबंधित है, जो कभी-कभी अत्यधिक प्रकट होती है। आत्मविश्वास एक यथार्थवादी विश्वास है कि आप अपने हाथ में लिया गया कार्य पूरा कर सकते हैं। वर्तमान अध्ययन के परिणामों को इस तरह से समझाया जा सकता है कि उच्च उपलब्धि वाले खिलाड़ी उस विशेष खेल के मोटर कौशल से संबंधित घटकों पर कम उपलब्धि वाले खिलाड़ियों के बराबर हैं। फिर भी, ऐसी प्रतियोगिता में उनका अनुभव कम उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों की तुलना में कहीं अधिक है। इससे कम उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों की तुलना में अधिक उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों में अधिक आत्मविश्वास पैदा होता है; विश्लेषण के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों में आत्मविश्वास कम उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों की तुलना में काफी अधिक होता है।एक खिलाड़ी को प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल करने के लिए

आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। इष्टतम उच्च उपलब्धि के लिए आत्मविश्वास का स्तर आवश्यक है। आत्मविश्वास की कमी और अति आत्मविश्वास के कारण प्रदर्शन में गिरावट आती है। हर खिलाड़ी का आत्मविश्वास अलग-अलग होता है। एथलीट और इवेंट (प्रतियोगिता) दर इवेंट (प्रतियोगिता) अनुभव, कौशल में निपुणता और सामाजिकता समर्थन से खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ता है। प्रदर्शन और एथलीटों का आत्मविश्वास सहसंबद्ध है।

सन्दर्भ सूची

फ़ारूक अहमद और इलाज़ीज़बदाह्मद (2002) पूर्वकाल क्रूसिएट लिगामेंट चोट के फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए आत्मविश्वास के स्तर और प्रतिस्पर्धा की चिंता पर मनोवैज्ञानिक पुनर्वास कार्यक्रम, वर्ल्ड जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स साइंस पेज (138-143) अंक, (2078-4724) आईडीओएसआई प्रकाशन 2010.

वुडमैन टाइम और हार्डी लाल (2003) खेल प्रदर्शन पर संज्ञानात्मक चिंता और आत्मविश्वास का सापेक्ष प्रभाव एक मेटा-विश्लेषण जर्नल ऑफ एप्लाइड साइकोलॉजी पृष्ठ (443-457) खंड 21। अंक, 2003.

मैमासिस और डॉकजानिस जॉर्ज (2004) ने जूनियर्स की पूर्व-प्रतिस्पर्धी चिंता, आत्मविश्वास और टेनिस प्रदर्शन पर मानसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभावों की जांच की। जर्नल ऑफ़ एप्लाइड साइकोलॉजी (118-137) खंड 16. अंक 2, 2004.

कैस क्रिस्टजन और राउडसेप्लेनार्ट (2004) बीच वॉलीबॉल ओनियन्स प्रकाशन डेटा के एथलेटिक प्रदर्शन में संज्ञानात्मक और दैहिक चिंता और आत्मविश्वास, 1 जून 2009 खंड 98 अंक, 1 पृष्ठ (439-449).

सिंह, ए. (2016)। इनडोर गेम और आउटडोर गेम खेलने वालों के बीच आत्मविश्वास का तुलनात्मक अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड हेल्थ, 3(1), 248-250।

रतनकोसेस और रोवोवालाबॉल (2009) महिला और पुरुष एथलीटों में छवि और आत्मविश्वास के बीच संबंधों का मूल्यांकन करते हैं। जर्नल ऑफ़ एप्लाइड साइकोलॉजी (216-225) खंड 14. अंक, 2009.

पाडे डी.डी. पांडे आत्मविश्वास इन्वेंटरी (पीएससीआई); 1983

सिंह आलोक कुमार आत्मविश्वास का तुलनात्मक अध्ययन हॉकी खिलाड़ियों और फुटबॉल खिलाड़ियों के बीच. जोहर एपल विज्ञान. 2014; 2(1):62-66. यहां से उपलब्ध: www.johronline.com.

बी, एसके, पी, एमके। आत्म-अवधारणा पर एक तुलनात्मक अध्ययन आदिवासी और गैर-आदिवासी माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के बीच वायनाड जिला. जे रेस ह्यूमनिट सोसायटी विज्ञान। 2022; 10(5):8-11.

आत्मविश्वास [इंटरनेट]। विकिपीडिया, मुफ़्त विश्वकोश। यहां से उपलब्ध: https://en.wikipedia.org/wiki/Self-confident#Children.

डमैन, टी., &हार्डी, एल. (2003) - खेल प्रदर्शन पर संज्ञानात्मक चिंता और आत्म-विश्वास का सापेक्ष प्रभाव: एक मेटा-विश्लेषण। खेल और व्यायाम मनोविज्ञान की पत्रिका।

वीनबर्ग, आर. एस., &गोल्ड, बी. (2019) - खेल और व्यायाम मनोविज्ञान: अवधारणाएँ और अनुप्रयोग। मैकग्रा हिल एजुकेशन।

गुप्ता, पी. (2015) - खेल मनोविज्ञान और भारतीय खिलाड़ी। नई दिल्ली: नेशनल पब्लिशिंग हाउस।

मिश्रा, आर. (2020) - खेलों में मानसिक प्रशिक्षण और आत्म-विश्वास का प्रभाव। खेल विज्ञान शोध जर्नल, खंड 8, अंक 2, पृष्ठ 45-58।

शर्मा, एस. (2018) - भारतीय एथलीटों में आत्म-विश्वास और प्रदर्शन का तुलनात्मक अध्ययन। भारतीय खेल मनोविज्ञान पत्रिका, खंड 12, अंक 1, पृष्ठ 22-35

जांजगीर का लघु-विष्णु मंदिर: एक अध्ययन (हसदेव नदी घाटी के विशेष संदर्भ में)

नीलिमा मरकाम *

सारांश

छत्तीसगढ़ राज्य का आधुनिक जांजगीर, प्राचीन कलचुरी काल में जाजल्ल्पुर के नाम से विख्यात था. अभिलिखित प्रमाणों में 'जाजल्लपुर' नगर, रतनपुर राज्य के हैहयवंशी राजा जाजल्लदेव प्रथम (ईस्वी सन् 1090-1120) ने बसाया था। जांजगीर नाम इसी जाजल्लपुर का अपभ्रंश माना जाता है, इसके साथ ही जांजगीर, दन्तकथाओं की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध और रोचक है. एक दन्तकथा का उल्लेख बेगलर ने भी किया है, जिसके अनुसार- शिवरीनारायण और जांजगीर के मंदिर निर्माण में प्रतियोगिता थी, क्योंकि भगवान नारायण ने घोषणा की थी कि जो मंदिर पहले पूर्ण होगा, वे उसी में प्रविष्ट होंगे. शिवरीनारायण का मंदिर पहले पूरा हुआ और नारायण ने उसमें प्रवेश किया, फलस्वरूप जांजगीर के मंदिर को उसी स्थिति में अधूरा छोड़ दिया गया. हसदेवनदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है. यह नदी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ीनदी महानदी की सहायक नदियों में प्रमुख है.जल प्रवाह की दृष्टि से हसदेव नदी का छत्तीसगढ़ में तीसरा स्थान है. जांजगीरमेंदो वैष्णव मंदिर उपस्थित हैं विशाल विष्णुमंदिर तथा लघु-विष्णु मंदिर. विशाल विष्णु मंदिरके समक्ष, उत्तर पार्श्व में सड़क को पार करने केपश्चात् लघु-विष्णु मंदिर है जो विशाल विष्णु मंदिर की तुलना में आकार मेंछोटा है. मंदिर में विष्णु के विभिन्न स्वरूपों के साथ-साथ शिव के स्वरूपों को भी दर्शाया गया है जिनमें षष्टभुजी वीणाधारी शिव तथा अष्टभुजी नृत्यरत (नटराज) शिव की प्रतिमा को विशेष कलात्मक आकृति से प्रदर्शित किया गया है।

बीज शब्द: हसदो, हसदेव, जांजगीर, विष्णु मंदिर,जाजल्लपुर, कलचुरी, कोरबा.

प्रस्तावना

मानव अपनी भावनाओं को सकारात्मक रूप देने के लिए कला का निर्माण करता है जिसका परिचय हमें स्थापत्य के रूप में प्राप्त होता है. प्राचीन भारत में स्थापत्य का अति महत्वपूर्ण स्थान रहा है, मूलतः मंदिर स्थापत्य जिसका ना केवल व्यवहारिक महत्त्व है अपितु इसके साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, व्यवसायिक तथा सांस्कृतिक पक्ष भी जुड़ा होता है. रामगढ़ पर्वत एवं उससे लगे हुए क्षेत्रों से हमें कलचुरी राजवंश के कलात्मक अवशेषों की जानकारी प्राप्त होती है. कलचुरीयों द्वारा मंदिरों में किए गए निर्माण का संबंध यहाँ के भौगोलिक वातावरण अथवा पर्यावरण से किया जा सकता है जिनमें नदियों तथा उनकी शाखाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. इन्हीं में से एक पुरातात्त्विक स्थल है जांजगीर, इस स्थल पर एक लघु विष्णु मंदिर स्थित है जो कलचुरियों की वास्तुकला का एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत करता है।

किसी भी समाज के अस्तित्व में रहने के लिए जलमार्ग सदैव सेही अत्यंत आवश्यक रहें हैं. मनुष्य अपने अस्तित्व केआरंभ से ही अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नदियों या किसी भी प्रकार केजलस्रोतों पर बसता रहा है. जल से संबंधित प्राचीनसाहित्यिक तथा पुरातात्विक स्रोतोंमें नदियों, तालाबों और झीलों का वर्णन मिलता हैजिनमें नदियाँ सबसे पवित्र मानी जाती हैं***(श्रीमदभगवतगीता याथरूप, 7, 4).***प्राचीन काल से ही नदियों केकिनारे जीवन व्यतीत करना मनुष्य का स्वभाव रहा है क्योंकि स्वच्छ एवं प्रचुर जल कीउपलब्धता मानव जीवन की पहली आवश्यकता रही है. विश्व कीसभी प्राचीन सभ्यताओं का जन्म नदी घाटियों में हुआ है. नदियाँसदैव मानव सभ्यताओं की पोषक रही हैं एवं उनके विकास में सदैव सहायक रही हैं।

हसदेवनदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियोंमें से एक है. यह नदी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी महानदी की सहायक नदियों में प्रमुख है.जल प्रवाह की दृष्टिसे हसदेव नदी का छत्तीसगढ़ में तीसरा स्थान है.हसदेव नदी का उद्गमकोरिया जिले के जनपद सोनहत से 5 किमी की दूरी पर स्थित मेंड्राकला ग्राम पंचायत सेहोता है. हसदेव नदी वर्तमान में (अब मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर) कोरिया जिले केमनेंद्रगढ़ तहसील की रामगढ़ और बालमघाट की पहाड़ियोंसेनिकलकर उत्तर-पश्चिम से दक्षिण की ओर बहती हुई कोरिया, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपाजिले से होकर शिवरीनारायण के आगे 9 कि. मी. दूरी पर महुआडीह के समीप महानदी मेंजाकर समाहित हो जाती है।

*नीलिमा मरकाम,शोध छात्रा, इतिहास विभाग, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (म.प्र.) ।

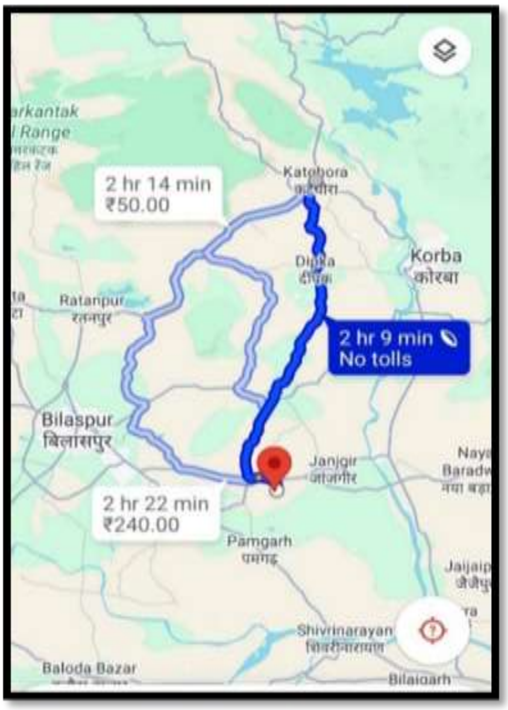

(22◦0'21.967"N उत्तरी आक्षांश से 82◦34'19.49"Eदक्षिणी देशांतर)छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित जनपद पंचायत कटघोरा सड़क मार्ग से 80 किलोमीटर की दूरी पर हसदेव नदी पर जिला जांजगीर स्थित है. प्राचीन यात्रापथ पर स्थित जांजगीर, वाराणसी को रामेश्वरम् से जोड़ा करता था. एक अन्य प्राचीन मार्ग का सोनहत, मातिन, पाली, बलौदा, जांजगीर तथा शिवरीनारायण से गुजरने की जानकारी भी मिलती है. जांजगीर की प्राचीनता के स्पष्ट प्रमाण यहाँ के मंदिर हैं. अभिलिखित प्रमाणों के अनुसार 'जाजल्लपुर' नगर की स्थापना रतनपुर राज्य के हैहयवंशी राजा जाजल्लदेव प्रथम ने की तथा इस स्थान पर एक विशाल विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था. जांजगीर नाम इसी जाजल्लपुर का अपभ्रंश माना जाता है. जे. डी. बेग्लर के अनुसार यह स्थान निश्चय ही प्राचीन है तथा प्राचीनकाल में इस स्थान पर अनेक मंदिर रहे होंगे, इस तरह बेग्लर ने वर्तमान मंदिरों के अतिरिक्त अन्य मंदिरों के अस्तित्व तथा मंदिरों की संभावना व्यक्त की है.

इस स्थान पर वैष्णव संप्रदाय से संबंधित भगवानविष्णुके दो मंदिरअस्तित्व में हैं जो प्रस्तर निर्मिततथा एक विशाल तालाब केनिकट स्थितहैं. यह स्थान सड़क मार्ग पर स्थित होने के कारण यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन के लिए अधिक संख्या में आते हैं. इन मंदिरों का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किया जाता है.

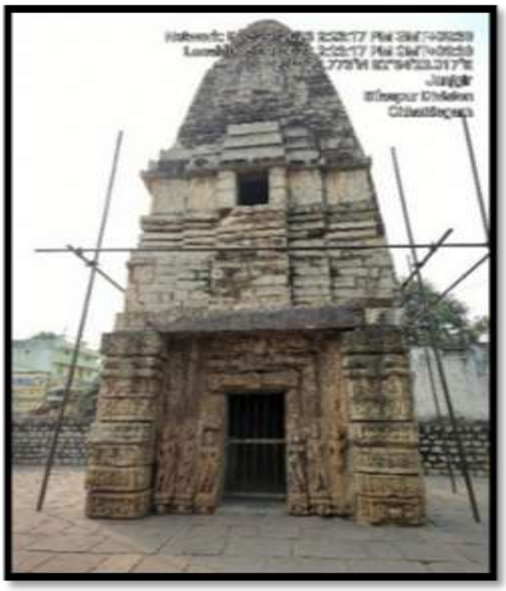

लघु विष्णु मंदिर

वास्तुकला प्राचीन काल से ही भारतीय कला का एक अभिन्न अंग रही है. वास्तुकला को एक उत्कृष्ट कला माना जाता है. भारतीय परंपरा में वास्तुकला की उत्पत्ति वेदांग से मानी जाती हैं. कुछ विद्वान वास्तुकला को चार उपवेदों में से एक मानते हैं (बाजपेयी, 2015). भारतीय वास्तुकला के प्रारंभिक चरण के उदाहरण सिंधु सभ्यता से मिलते हैं. इन वर्षों में, भारतीय स्थापत्यकला में अनेक शैलियाँ तथा उनके रूप विकसित हुए हैं जैसे गांधार कला शैली, मथुरा शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली, बेसर शैली आदि. वास्तुशिल्प भवन निर्माण की कला है, जो कल्पना, सामग्री, कौशल, स्थान और निर्माणकर्ताओं के संगम से पैदा होती है जिस कारण बाद में, भारतीय महाद्वीप के महान राजवंशों के उत्थान और पतन का प्रभाव भारतीय वास्तुकला पर पड़ा.

मध्य भारत में मूर्ति पूजा को दिए गए महत्त्व और व्यक्तिगत ईश्वर में विश्वास के कारण मंदिरों का निर्माण हुआ. भारतीय उपमहाद्वीप में ब्राम्हण आस्था की बढ़ोतरी के लिए बड़ी संख्या में क्षेत्रीय शैलियों के अनुरूप स्थापत्य एवं कला का निर्माण किया गया है. इसी प्रकार प्राचीन छत्तीसगढ़ (दक्षिण कोसल) क्षेत्रके मंदिर अधिकतर उत्तर भारतीय नागर शैली में बने हैंकिन्तु शरभपुरियों के काल से यह शैलीस्थानीय दक्षिण कोसल शैली का अद्भुत समन्वय दर्शाती है. स्थानीय दक्षिण कोशल शैली कीमुख्य विशेषताएं मंडप और विमान (मिश्र, 2008)के साथ रचना और तोरणों कीव्यवस्था हैं जो इस क्षेत्र में बने अधिकांश मंदिरों में पाई जाती हैं (पाण्डेय, 2002). शरभपुरीयकला शैली का सर्वोत्तम विकसितस्वरूप ताला ग्राम से प्राप्त हुआ है. शरभपुरियों के पतन के पश्चात् पांडुवंशियोंका काल आरंभ हुआ, जिनके शिलालेखप्राचीन छत्तीसगढ़ क्षेत्र से अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं. पाण्डुवंशी शासक इन्द्रबल नेइन्द्रपुर (रायकवार, 2015) (खरोद) की स्थापना की.अड़भार का भग्नावशेष शिवमंदिर, शिवरीनारायण का केशव नारायण मंदिरएवं खरौद का शबरी मंदिर भीपाण्डुवंशियोंके काल में ही निर्मित हुए थे.

प्राचीन छत्तीसगढ़ क्षेत्रमें अधिकांश मंदिर कलचुरियों के काल में निर्मित किये गये थे. प्राचीन राजवंश कलचुरि, जिन्हें पुराणों में हैहय का वशंज माना गया है. कलचुरिराजवंश ने इस क्षेत्र मेंलगभग नौवीं से अठारहवीं शताब्दी ई. तक शासन किया.बाण शासक विक्रमादित्य नेप्राचीन छत्तीसगढ़ (दक्षिण कोसल) क्षेत्रके पाली में स्थित एक प्रसिद्ध महादेव मंदिर का निर्माण कराया था, जिसका पुनर्निर्माणकलचुरि शासक जाजल्लदेव प्रथम ने करवाया था.

एकदन्तकथा का उल्लेखबेग्लर ने भीकिया है, जिसके अनुसार – "शिवरीनारायण और जांजगीर के मंदिर निर्माण मेंप्रतियोगिता थी, क्योंकि भगवान नारायण ने घोषणा की थी कि जो मंदिर पहलेपूर्ण होगा, वे उसी में प्रविष्ट होंगे. शिवरीनारायण का मंदिर पहले पूर्ण हुआ तदुपरान्त नरनारायण ने उसमें प्रवेश किया, फलस्वरूप जांजगीर के मंदिर को उसी स्थिति में अधूरा छोड़ दिया गया" (त्रिपाठी, 2023).

दोअन्य रोचक दंतकथाएं भी जांजगीर में प्रचलित हैं, ये दोनों कथाएं महाबली भीम सेसंबंधित हैं.एककथा के अनुसार "मंदिर से लगे तालाब को भीम ने पांच बार फावड़ा चला कर खोदा था, इसलिए तालाब का नाम भीमा तालाब हुआ".इसकेअतिरिक्त दूसरी कथा में महाभारत युद्ध में भीम ने कौरव सेना के जिन हाथियों कोपूँछ पकड़ कर, घुमाकर फेंका था, उनमें से चार यहाँ आकर गिरे और भीम उन पर सवार हुए. इस मंदिर के निर्माण से संबंधित एक अन्यकिंवदंतियों के अनुसार भीम को इस मंदिर का शिल्पी कहा जाताहै – 'एक बार विश्वकर्मा और भीम के बीच एक रात में मंदिर की होड़ हुई, उस समय मंदिरबनने आरंभ हुए. भीमद्वारा मंदिर का निर्माण करते हुए छेनी-हथौड़ी नीचे गिर जाती थी तब भीम का हाथीगिरे उपकरण लाकर पुनः भीम को दे देता था.यहीक्रमनिरंतर चलतारहा, किन्तु एक बार भीम की छेनी छिटक कर निकटस्थ तालाब में चली गई, जब तक हाथीतालाब से छेनी निकालकर ला पाता, तब तक सबेरा होचुका था. गुस्सेमें आकर भीम ने हाथी के दो टुकड़े कर दिए जिस कारण मंदिर अधुरा रहा' (लाल, 1916).

जांजगीर मेंदो वैष्णव मंदिर उपस्थित हैं विशाल विष्णु मंदिर तथा लघु-विष्णु मंदिर. विशाल विष्णु मंदिरके समक्ष, उत्तर पार्श्व में सड़क को पार करने केपश्चात् लघु-विष्णु मंदिर है जो विशाल विष्णु मंदिर की तुलना में आकार मेंछोटा है. मंदिरनागर शैली मेंनिर्मित हैएवं मंदिरपूर्वाभिमुखी है तथा इसके सम्मुख भाग में अलंकृत द्वारशाखा है. द्वारशाखा त्रिशिखाई है जिसके निचले भाग में नदी देवीतथा द्वारपालों का अंकनकिया गया है. मंदिर के तल विन्यास में गर्भगृह एवं अन्तराल भाग हीशेष निर्मित है तथा उर्ध्व विन्यास में जंघा, शिखर तथा आमलकनिर्मित हैं (लाल, 1916). इसके अतिर्कित मंदिर का अधिष्ठान समतल है, किन्तु उस पर भारी ढलाई की गई है | सजावट के उद्देश्य से पार्श्व दीवारों को दो भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात् तलजंघा और उपरी-जंघा. मुख्य आले (रथिका-बिम्ब) उत्तरी तथा दक्षिणी दीवारों पर पाए जाते हैं, जिनके दोनों ओर अन्य आले तथा भित्तियों में उभार हैं, जो सभी मूर्तियों से जड़े हुए हैं, जिनमें मुख्य रूप से देवताओं की प्रतिमा अंकित हैं.

इस मंदिर के माध्यम सेइस क्षेत्र की भव्य वास्तुकला एवंकलाकाविभिन्न आयाम परिलक्षित होताहै.

गर्भगृह

मंदिर का गर्भगृह आयताकार है तथा गर्भगृह के चारों ओर भित्ति स्तम्भ हैं, जो अलंकरण विहीन हैं. गर्भगृह में मूलदेवता अनुपस्थित है किन्तु स्थापत्य के खंडित अंशों को संरक्षण की दृष्टि से स्थित किया गया है, जिनमें इंद्राणी मूर्ति (संभवतः) स्थानक मुद्रा में स्थित है, जिसके समीप सेविकाओं की मूर्ति क्रियाशील रूप में है. यह खंड अधुरा है, संभावित यह किसी घटना क्रम का हिस्सा हो सकता है. इसके अतिरिक्त गर्भगृह में गज मूर्ति तथा अमलक का खंडित भाग तथा मंदिर स्थापत्य के भग्नावशेष रखे हुए हैं.

प्रवेशद्वार

प्रवेशद्वार में ललाटबिम्ब त्रिशाखाई है. प्रथम शाखा के मध्य में शिव प्रतिमा (हरिहर) स्थापित है. शिव प्रतिमा के दाईं ओर कुबेर तथा बाईं ओर नरसिंह प्रतिमा का अंकन किया गया है. इसी प्रकार द्वितीय शाखा के मध्य में षष्ठभुजी नृत्यरत शिव (नटराज) प्रतिमा का अंकन है, जिनके दाईं तथा बाईं ओर मृदंगवादक को दर्शाया गया है. इसके अतिरिक्त तृतीय शाखा के मध्य में गंधर्व एवं विद्याधर की प्रतिमा स्थापित है, इन प्रतिमाओं के दाईं ओर नागवल्लरी तथा बाईं ओर पुष्पवल्लरी का अंकन है.

द्वारशाखा

द्वारशाखात्रिशाखाई है, प्रथम द्वारशाखा में नागवल्लरी, द्वितीय द्वारशाखा में पुष्पवल्लरी तथा तृतीय द्वारशाखा में पुनः नागवल्लरी का अंकन है. प्रथम तथा द्वितीय शाखा की नागवल्लरी को देखकर यह ज्ञात होता है कि वैदिक धर्म में प्रारंभ से ही नागों को विशेष स्थान दिया गया है. अथर्ववेद में यक्षों तथा गंधर्व-अप्सराओं के साथ नागों का उल्लेख मिलता है. नागों को अथर्ववेद में देवजन से संबोधित किया गया है. यजुर्वेद में भी नागपूजा का प्रसंग मिलता है. प्रवेशद्वार के बाहर नदी देवियां – बाईं ओर मकर-वाहिनी गंगा तथा दाईं ओर कुर्म-वाहिनी यमुना, दोनों नदी देवियों को स्थानक मुद्रा में भारवाहक के साथ अंकित किया गया है. गंगा के शीर्ष में छत्र का अंकन किया गया है. छत्र के ऊपर विष्णु की प्रतिमा स्थानक मुद्रा में स्थित है, साथ ही दोनों नदी देवियों से लगे हुए सेविका तथा नागकन्या को दर्शाया गया है. इसके अतिरिक्त यमुना नदी के शीर्ष के ऊपर मध्य पंक्ति में गणेश की प्रतिमा स्थानक मुद्रा में स्थित है तथा गणेश प्रतिमा के ऊपर संभवतः नारदमुनि को दर्शाया गया है. दोनों नदी देवियों के समीप द्वितीय तथा तृतीय शाखा में विष्णु द्वारपालों को भारवाहक के साथ स्थानक मुद्रा में प्रदर्शित किया गया है.

द्वारशाखा के दाईं तथा बाईं ओर स्तंभ स्थापित है जिसकोविभिन्न पंक्तियों से अलंकृत किया गया है.सर्वप्रथम स्तंभ के प्रथम पंक्ति में भारवाहक का अंकन, द्वितीय पंक्ति मेंकीर्तिमुख, तृतीय पंक्ति में पद्मासन मुद्रा में उपासक-गण, चतुर्थ पंक्ति मेंगंधर्व, पंचम पंक्ति में हमशा, षष्ठपंक्ति में मृदंगवादक तथासप्तमपंक्ति में व्याल आदिका अंकन किया गया है.

जंघा

उत्तर दिशा – उत्तरी दिशा में जंघा को दो पंक्तियों में विभाजित किया गया है. प्रथम पंक्ति में षष्टभुजी वीणाधारी शिव की प्रतिमा है जो दो लघु स्तंभों के मध्य ताक पर स्थापित हैं. इसी प्रकार द्वितीय पंक्ति में दो लघु स्तंभों के बीच अष्टभुजी नृत्यरत शिव की प्रतिमा स्थित है. दोनों प्रतिमाओं के दाईं तथा बाईं ओर भित्ति स्तंभ पूर्णरूप से अलंकरण विहीन है.

दक्षिण दिशा – दक्षिणी दिशा में भी जंघा का विभाजन दो पंक्तियों में किया गया है. ऊपर से प्रथम पट्टिका के मध्य दो लघु स्तंभों के बीच में चतुर्भुजी कुबेर की प्रतिमा पद्मासन मुद्रा में स्थापित है. द्वितीय पट्टिका के मध्य दो लघु स्तम्भों के बीच अष्टभुजी नृत्यरत शिव की प्रतिमा स्थापित है. इसी प्रकार इन प्रतिमाओं के समीप दाईं ओर को पुनः दो पंक्तियां निर्मित हैं, ऊपर से प्रथम पंक्ति में गौण देवता (अस्पष्ट) प्रतिमा को दर्शाया गया है तथा द्वितीय पंक्ति में नृत्यरत गणेश प्रतिमा स्थापित है.

पश्चिम दिशा – पश्चिमी दिशा मेंभी जंघा को दो पंक्तियों में विभाजित किया गया है. प्रथम पंक्ति में विष्णु प्रतिमा को पद्मासन मुद्रा में दो लघु स्तंभों के मध्य स्थापित किया गया है. द्वितीय पंक्ति में विष्णु की प्रतिमा स्थानक मुद्रा में स्थापित है, जिनके दाईं तथा बाईं ओर एक-एक उपासक गण को बैठे हए दर्शाया गया है.

निष्कर्ष

1. प्राचीन काल में जांजगीर महत्वपूर्ण व्यापारिक तथा धार्मिक स्थल था.
2. मंदिर में विष्णु के विभिन्न स्वरूपों के साथ-साथ शिव के स्वरूपों को भी दर्शाया गया है जिनमें षष्टभुजी वीणाधारी शिव तथा अष्टभुजी नृत्यरत (नटराज) शिव की प्रतिमा को विशेष कलात्मक आकृति से प्रदर्शित किया गया है.
3. गर्भगृह में खंडित स्थापत्य अवयव अवस्थित रूप में प्राप्त होते हैं, इन खंडित भाग एवं भग्नावशेष को देखकर प्रतीत होता है कि ये सभी संभावित रूप से जंघा के अंग रहें होंगे.
4. मंदिर स्थापत्य में मूर्ति-कला के संहिताबद्ध होने से मूर्तिकला को नए आयाम प्राप्त हुए. अवतारों की कल्पना दृढ़ हो जाने से विष्णु तथा शिव के प्रस्तुत विषय में विस्तार होता चला गया. विष्णु के दस अथवा चौबीस अवतारों के अतिरिक्त उनके 24 रूपों का अंकन यहाँ के मंदिरों में देखने मिलते हैं.
5. इस मंदिर में विशाल स्तंभों के रूप में एक अपरंपरागत (असाधारण) वास्तुशिल्प विशेषता है, जो मुख्य द्वार के पार्श्वों पर लगे हुए अनेक अनुभाग (विभाजन) में विभाजित हैं. इन अनुभागों में विभिन्न रचनाओं की सजावट की गई है जो पारंपरिक गज-याली तथा नर-याली के अतिरिक्त नृत्य और संगीत जैसे विभिन्न दृश्य प्रस्तुत करती है.
6. मंदिर, राजा के द्वारा विष्णु को समर्पित है किन्तु किन्हीं कारणवश राजा इस भव्य मंदिर के शिखर भाग को शेष मंदिर के साथ स्थापित नहीं कर पाया जिस कारण आज हमें यह लघु विष्णु मंदिर के रूप में प्राप्त होता है. स्थानीय लोग इससम्पूर्ण मंदिर को उक्त मंदिर (विशाल विष्णु)का शेष शिखर भाग मानते हैं.
7. धार्मिक रूप से इस क्षेत्र के विस्तार का महत्वपूर्ण कारण भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति हो सकती है. कलचुरि शासक अपने राज्य के इस क्षेत्र को सांस्कृतिक रूप से ब्राह्मणवादी संस्कृति की मुख्य धारा में लाना चाहते थे, क्योंकि वर्तमान में यह भूमि अनेक समुदायों द्वारा बसाई गई है.
8. मंदिर का मार्ग हसदेव नदी के निकट स्थित होने के कारण यह अनुमानित होता है कि यह स्थान धार्मिक के साथ-साथ एक व्यापारिक स्थल भी रहा होगा.
9. एस. एन. मानवानी ने अपनी पुस्तक " इवोलूशन ऑफ़ आर्ट एंड आर्केटेक्चर इन सेन्ट्रल इंडिया" इस मंदिर का लिखित अध्ययन एक **"शिव मंदिर"** रूप में किया है (मनवानी
10. , 1988), किन्तु छत्तीसगढ़ के पुरातत्ववेत्ता के. पी. वर्मा ने (वर्मा,2014) अपने अध्ययन में इसे **"लघु-विष्णु"** मंदिरमाना है. शोधार्थी के स्वयं के सर्वेक्षण के अनुसार, मंदिर के गर्भगृह में मूलदेवता अनुपस्थित है इसके अतिरिक्त गर्भगृह का भू-स्थल पूर्णरूप से समतल है जिस पर योनिपट तथा शिवलिंग होने का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है. अत: यह संपूर्ण लघु मंदिर संभावित रूप से विष्णु को समर्पित होगा, जो वर्तमान में जांजगीर क्षेत्र में 'लघु-विष्णु' मंदिर के रूप प्रसिद्ध है.

अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि जांजगीर क्षेत्र में ऐसे अन्य मंदिरों के प्रमाण एवं भग्नावशेष प्राप्त होने की प्रबल संभावना हैं. अतएव विवेच्य क्षेत्रों में पुरातात्विक सर्वेक्षण की नित्यंत आवश्यकता है. फलस्वरूप क्षेत्रीय इतिहास लेखन के कार्य को गति प्राप्त होगी, जिससे दक्षिण कोसल तथा प्राचीन भारतीय इतिहास समृद्ध होगा.

सन्दर्भ सूची

श्रीमद भगवतगीता याथरूप, भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट, मुंबई, 7, 4.

बाजपेयी, के.डी., भारतीय वास्तुकला का इतिहास, अवध पब्लिशिंग हाउस, लखनऊ, 2015.

मिश्र, रमानाथ, भारतीय मूर्तिकला का इतिहास, ग्रन्थ शिल्पी (इंडिया), दिल्ली, 2008.

पाण्डेय, एस. के., दक्षिण कोसल, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं वास्तुशिल्प (प्रारम्भ से 13 वीं सदी ई. तक), मध्यप्रदेश हिंदी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 2002.

रायकवार, जी.एल., ताला का पुरावैभव, रायपुर, 2015.

त्रिपाठी, बी. एवं अन्य, निगमश्री प्राच्यविद्या के विविध आयाम (प्रो. लक्ष्मी शंकर निगम अभिनंदन ग्रंथ), भारती प्रकाशन, वाराणसी, 2023.

लाल, हीरा, इंस्क्रिप्सन्स इन द सेंट्रल प्रोविंसेस एण्ड बरार, गवर्मेंट प्रेस नागपुर, नागपुर, 1916.

मनवानी, एस. एन., एवोलुसन ऑफ़ आर्ट आर्किटेक्चर इन सेंट्रल इंडिया, अगम कला प्रकाशन, दिल्ली 1988.

वर्मा, कामता प्रसाद, छत्तीसगढ़ की स्थापत्य कला (मध्य छत्तीसगढ़ के विशेष सन्दर्भ में), भाग 1, संचलनालय, संस्कृति एवं पुरातत्व छत्तीसगढ़, रायपुर, 2014.

महिलाओं द्वारा संचालित सामुदायिक मीडिया का वैयक्तिक अध्ययन (अप्पन समाचार और खबर लहरिया के विशेष संदर्भ में)

डॉ. शिवेंद्र कुमार मिश्रा*
डॉ. भावना उपाध्याय**

सारांश

प्रस्तुत अध्ययन मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश एवं बिहार की महिलाओं द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र खबर लहरिया औरबिहार में ग्रामीण महिलाओं द्वारा प्रसारित 'अप्पन समाचार' पर केन्द्रित है। सामुदायिकमीडिया एक सहभागी मीडिया है, जो मुख्यधारा मीडिया पर असंतोष से विकसित हुआ है, इसकीसामग्री नागरिक लोकतंत्र और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के सिद्धांतों के आधार पर कार्य करतीहै, महिला सशक्तिकरण के लिए अप्पन समाचार के प्रयास से सीमित लोग ही अवगत है। अप्पन समाचार के प्रसारण का पूरा संचालन महिलाएं ही करती हैं। पत्रकारिता के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करना और समाचार वाचन अपनी बोली में सहज होता है। सामुदायिक मीडिया का सर्वश्रेठ उदाहरण है,'अप्पन समाचार'। इसके अतिरिक्त यह अध्ययन खबर लहरिया अखबार पर केन्द्रित है,जो महिलाओं द्वारा क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित होती है खबर लहरिया महज एक अखबार नहीं हैं, वरन जागरूकता की जीती जागती मिसाल है, जो महिलाओं की आत्मनिर्भरता की कहानी खुद बयां कर रही हैं। खबर लहरिया को अद्भुत ख्याति देने में महिलाओं की अवर्णनीय दृढ़ इच्छा शक्ति को जाता है तो वहीं अखबार अपनी बोली में पढ़ने से पाठकों को सहज लगती हैं। इस शोध पत्र के माध्यम से महिला सशक्तिकरण व समाचार माध्यमों के अंर्तसंबंधों का विश्लेषण किया गया है। इन माध्यमों द्वारा विकास संचार के विषयवस्तु के अतिरिक्त मानव विकास के विभिन्न विषयों को समायोजित किया गया है।

बीज शब्द: सामुदायिक मीडिया, अप्पन समाचार, खबर लहरिया, सहभागिता , महिला सशक्तिकर

प्रस्तावना

संचार मानव जीवन का आधार है, मानव जीवन में सकारात्मक विकास व आपसी सामंजस्य स्थापना करने के लिए संचार की आवश्यकता सर्वोपरि है। संचार के आधार पर ही मानव समाज के निर्माण की कल्पना की जा सकती है,जिससे समाज का अस्तित्व कायम है। प्रसिद्ध अंतरिक्ष विज्ञानी व विचारक डां विक्रम साराभाई ने अपने लेख "टेलीविजन फॉर डेवलपमेंट" में लिखा कि किसी विकासशील देश में विकास का प्राथमिक चरण ''सूचना का संसार" है। प्रसारण में एक नए युग का सूत्रपात तब हुआ जब 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने हवाई तरंगों पर सरकार के एकाधिकार को गलत बताते हुए ''जनता की संपत्ति'' (Airways Are Public Property) के रूप में निरूपित किया।

सामुदायिक मीडिया की जवाबदेही उस समुदाय के रूप में सुनिश्चितकी जाती है,जिस समुदाय में सेवाएं देती है। सामुदयिक मीडिया लोकप्रिय आंदोलनो का परिणामहै, यह एक ऐसा क्षेत्र है जो राजनीति और व्यवसाय से मुक्त है, और यह नागरिक सहभागिताऔर सामूहिक स्वामित्व पर केन्द्रित है। (यूनेस्को)सामुदायिक मीडिया की संकल्पना के आधार पर भारत मेंभी प्रोद्योगिकी के विकास के साथ सर्वप्रथम भारत सरकार द्वारा टेलिविजन के शुरूआत केबाद सामुदायिक टेलिविजन की शुरूआत की गई, इसके बाद ग्रामवानी , खबर लहरिया, सामुदायिकरेडियो , गांव कनेक्शन, सीजीनेट स्वरा, साइबरमोहल्ला और वीडियो सेवा प्रमुख सामुदायिक मीडिया प्लेटफार्म है।

सामुदायिक संकल्पना एकजुटताको बढ़ावा देती है, और सामुदायिक संबंधों में सुधार करती है। सामुदायिक रेडियो एकरेडियो स्टेशन है समुदाय के सदस्यों द्वारा बिना किसी बाधा के सामुदायिक हितों को ध्यानमें रखकर संचालित किया जाता है (गॉर्डन, 2006)। सूचना प्रौद्योगिकी की विस्तारीकरण ने ''सामुदायिक मीडिया" का विकास किया। जिसका मुख्य उद्देश्य समुदाय मे जागरुकता का प्रसार करना है। सामुदायिक मीडिया का तात्पर्य ऐसी संचार प्रणाली से है,जो एक विशेष समुदाय के उत्थाव व समुदाय को मानव विकास की प्रक्रिया में शामिल करना है। सामुदायिक मीडिया के अंतर्गत समाचार पत्र, सामुदायिक रेडियो, सामुदायिक टेलिविजन,सामुदायिक इंटरनेट जैसे माध्यम सम्मिलित है।

*डॉ. शिवेंद्र कुमार मिश्रा, सहायक प्राध्यापक, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, जागरण लेकसिटी यूनिवर्सिटी, भोपाल (म.प्र.)।
**डॉ. भावना उपाध्याय, सहायक प्राध्यापक, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, जागरण लेकसिटी यूनिवर्सिटी, भोपाल (म.प्र.)।

सामुदायिक मीडिया का प्रमुख उद्देश्य संचार के द्वारा समुदाय विशेष में जनजागरुकता का प्रचार-प्रसार करना है, जिससे समुदाय मानव विकास की प्रक्रिया में शामिल हो सके। इसे प्रजातांत्रिक माध्यम भी कहते है,क्योंकि यह संविधान में वर्णित लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अवधारणा को स्पष्ट रुप से प्रतिबिंबित करता है।

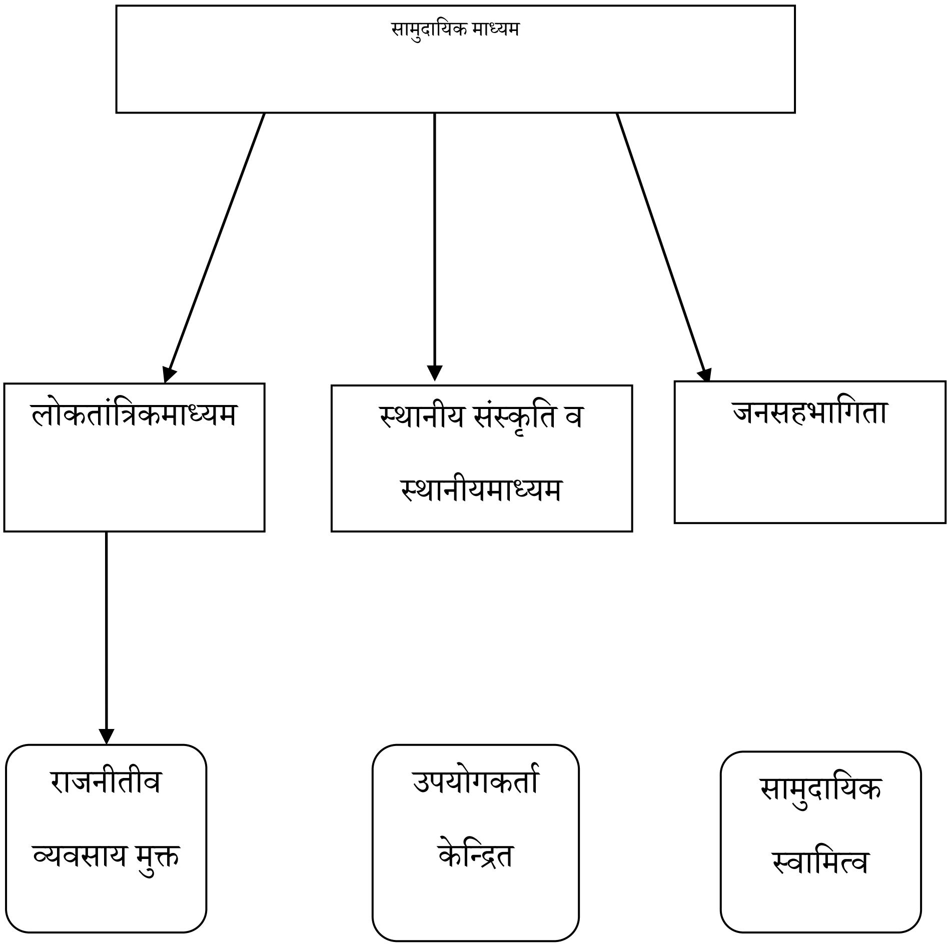

रेखा-चित्र क्रमांक- **1** सामुदायिक मीडिया सहभागिता मॉडल

सामुदायिक माध्यमों में खबर लहरिया अखबार का नाम सर्वोपरि है, वहीं सामुदायिक रेडियो ने अपनी खास पहचान भारत में स्थापित कर ली है, इसके अतिरिक्त टेलिविजन में भी सामुदायिक मीडिया का स्थान प्रुमख है बिहार राज्य में महिलाओं द्वारा संचालित 'अप्पन समाचार' का स्थान प्रमुखता से लिया जाता है। अप्पन समाचार की शुरुआत मुजफफरपुर जिले के पारु प्रखंड के रामलीलागाछ में 6 दिसंबर 2007 को हुई। एक गांव से शुरु हुआ ये चैनल आज कई गांवों में जागरुकता का प्रसार कर रहा है,वहां की समस्याओं के निदान के साथ विकास में नागरिकों की सहभागिता के लिए प्रेरित कर रहा है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. सामुदायिक मीडिया की प्रकृति व स्थापना के उद्देश्य का अध्ययन करना l
2. अप्प्पन समाचार द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की विषय वस्तु का अध्ययन करना l
3. खबर लहरिया अखबार की स्थापना व उद्देष्य का अध्ययन करना ।
4. स्थानीय बोली में स्थानीय खबरों के विषयवस्तु का अध्ययन।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन के लिए वैयक्तिक अध्ययन (केस स्टडी) शोध प्रविधि का उपयोग किया गया है । प्रस्तुत अध्ययन मुजफ्फरपुर जिले के पारू प्रखंड की ग्रामीण महिलाओं के द्वारा संचालित सामुदायिक टीवी चैनल 'अप्पन समाचार और खबर लहरिया अखबार पर केन्द्रित है। अध्ययन का प्रमुख केन्द्र बिंदु अप्पन समाचार व खबर लहरिया की स्थापना के उद्देश्य,प्रसारित कार्यक्रयों का विषयवस्तु का अध्ययन करना है।
वैयक्तिक अध्ययन के अंतर्गत किसी व्यक्ति, संस्था, समाज, समुदाय या किसी तंत्र के विषय में उसका वास्तविक इतिहास का क्रमबद्ध अध्ययन,वर्तमान परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए भविष्य की संभावनाओं का अध्ययन करते हैं। ऐसी जानकारी केवल अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार या अवलोकन से नहीं मिल पाती है। यह एक गहन अध्ययन विधि है क्योंकि इसके अंर्तगत किसी भी विषय के बारे में गहराई से जानने का प्रयास किया जाता है।
पी.वी.यंग के अनुसार- **''वैयक्तिक अध्ययन किसी सामाजिक इकाई चाहे वह एक व्यक्ति, परिवार, संस्था, सांस्कृतिक वर्ग अथवा समस्त जाति हो, के जीवन का अनुसंधान व उसकी विवेचना करने की एक पद्धति को कहते हैं।''**

मीडिया के संदर्भ में हम देखें तो वैयक्तिक अध्ययन, किसी मीडिया संस्थान चाहे वह समाचार पत्र हो, रेडियो, समाचार चैनल या वेब मीडिया या ऐसी संस्था जो जनसंचार से जुड़े मुद्दों पर काम करती हो। मीडिया संस्थानों के वैयक्तिक अध्ययन में भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है,जो सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रमें अपनाई जाती है। क्योंकि समाज का सीधा संबंध मानव विकास से है और मीडिया का संबंध भी मानव विकास से ही है।

विश्लेषण एवं व्याख्या -
खबर लहरिया का प्रारंभिक चरण एवं विकास यात्रा

इस ऐतिहासिक पहल की शुरुआत आठ दलित 'ग्रामीण महिला पत्रकारों' के सहयोग से हुई। महिलाओं के मुद्दों पर काम करने वाली गैर-सरकारी संस्था ''निरंतर'' ने खबर लहरिया अखबार के प्रकाशन का बीड़ा उठाया। निरंतर नामक संस्था की शुरुआत 1993 में हुई थी। तब से यह संस्था लगातार महिलाओं के जीवन से जुडे तमाम आर्थिक, समाजिक मामलों पर अपनी आवाज बुलंद करती आई है, इसका काम मुख्यतः महिलाओं के बीच शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना है। संस्था का मानना है कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिसका प्रयोग करके महिलाएं अपने अधिकारों को जान सकती हैं। यदि उनके पास जानकारी ही नहीं होगी, तो वे कभी नहीं जान पाएगी कि पुरुषवादी व्यवस्था में महिलाएं किस प्रकार शोषण का शिकार बनती है ? उनके शोषण के क्या कारण है और वे कैसे इसके खिलाफ अपनी आवाज उठा सकती हैं ? निरंतर द्वारा प्रकाशित पत्रिका पिटारा इसी उद्देश से शुरू हुई। खबर लहरिया भी एक ऐसा ही प्रयास है, जिसमें खबर के माध्यम से मुद्दों की भाषागत जटिलताओं को दूर करके उन्हे सहज, सरल शब्दों में पिरोकर नवसाक्षर महिलाओं तक पहुंचाया जाता है, जिससे साक्षरता जागरूकता में परिवर्तित हो। ग्रामीण महिलों के उत्थान हेतु 09 वर्ष पूर्व, 2002 में निरंतर ने ही 'पिटारा' अखबार की शुरूआत की। इसी तारतम्य को आगे बढ़ाते हुए निरंतर ने ही चित्रकूट में स्थानीय ग्रामीण महिलाओं की मदद से 'खबर लहरिया' नामक एक अखबार प्रकाशित किया । इस अखबार की सारी जिम्मेदारी शालिनी जोशी को सौपी गई। 08 पृष्ठों का यह समाचार पत्र स्थानीय बुदेंली बोली में प्रकाशित होता है, ताकि क्षेत्रीय बोली बोलने वाली महिलाएं इसे अच्छी तरह समझ सके। इसके पश्चात यह समाचार पत्र उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से भी प्रकाशित हुआ। 2009 के आंकडें के अनुसार चित्रकूट से अखबार की करीब 2500 प्रतियां और बांदा से 2000 प्रतियां निकलती थी। सर्वेक्षण में यह पाया गया कि एक अखबार की पाठक संख्या 10 है, जिससे पाठक की संख्या प्रकाशित प्रतियों से कई गुना अधिक है। 2010 में 'सीएसडीएस सेन्टर फार द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज' ने सर्वेक्षण में पाया कि खबर लहरिया की लगभग 5000 प्रतियां छपती है, तथा बांदा सहित चित्रकूट के 400 गांवों में इसकी पाठक संख्या 25 हजार से ज्यादा है। 2013 में जहां अखबार की 6000 कॉपी पाठाकों को वितरित की जाती है, वहीं इस अखबार के 80 हजार पाठक वर्ग है । इस अखबार की रिपोर्टिंग के लिए 40 ग्रामीण महिला रिपोर्टर सतत प्रयासरत है।
खबरलहरिया की मुख्य संपादक मीरा के अनुसार ''महिलाओं को अपनी स्वयं की पहचान स्थापित करना सबसे बड़ी समस्या है। शुरुआती दौर में महिलाओं से जुड़े मुद्दों को ही स्थान दिया जाता था। राजनीतिक और अन्य मुद्दों से कोई सरोकार नहीं था, लेकिन रीडरशिप सर्वे में पाया गया कि इस अखबार को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। यह अखबार से जुड़ी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लोगों में यह धारणा बन चुकी थी, कि अखबार पूरी तरह महिलाओं के लिए व महिलाओं के विषय से संबंधित था । जब कि वे इस अखबार में गांव की खबरों को भी स्थान देना चाहते थे। इस अखबार में नया मोड़ तब आया, जब 2004 में पंचायती चुनाव हुए। महिलाओं ने पंचायती चुनाव की रिर्पोटिंग की, लेकिन वे चुनावी प्रक्रिया से अनजान थी। उस वक्त निरंतर ने अखबार को बढाने में भरपूर सहयोग दिया और खबर लहरिया को एक ग्रामीण अखबार का दर्जा दिलाया । यह समाचार पत्र राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं विभिन्न मुद्दों के साथ-साथ ज्ञानवर्द्धक विषय सामाग्री प्रकाशित करता था, जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रसार संख्या में इजाफा हुआ। अब यह अखबार महिलाओं व पुरुषों के साथ-साथ पत्रकारों द्वारा भी गंभीरता से लिया जाने लगा है।
संस्था का मानना है, कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिसका प्रयोग करके महिलाएं अपने अधिकारों को जान सकती हैं । यूनेस्कों ने 8 सितंबर 2009 में अतंर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर महिला सशक्तिकरण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 'किंगसिंजोग' साक्षरता पुरस्कार दिया। जिसमें पुरस्कार स्वरूप 20 हजार डॉलर (लगभग 1 करोड़ रुपया) प्रदान किए गए। इस सम्मान ने अखबार से जुड़ी महिलाओं का उत्साह दुगना कर दिया , वे इसे और बेहतर बनाने में पूरी तन्मयता से जुड़ी है।

कठिन परिस्थितियां

इस अखबार के लिए प्रकाशन सामाग्री यहां की ग्रामीण औरतें ही जुटाती हैं। यातायात के साधनों की कमी भी इन्हें रोक नहीं पाती। उत्साह और साहस से भरी महिला संवाददाता दूर-दराज की गांवों में जाती हैं, और वहां गांव की समस्या का अवलोकन कर अपनी बोली में ही खबरें लिखती हैं।

विज्ञापनों का समावेश

विज्ञापन किसी भी समाचार पत्र की पूंजी की आधारशिला होती है। अब आपसी चर्चा के बाद महिलाएं इस अखबार के लिए विज्ञापन को स्वीकार कर रही हैं, लेकिन इसके लिए वे कठोर नियमों का पालन भी कर रही हैं। उदाहरण स्वरूप वे किसी भी विज्ञापन को अखबार में स्थान नहीं देंगी, जो जातिवाद, सिद्वांतवाद, हिंसा, अंधविश्वास को बढ़ावा दे। ये महिला पत्रकार अपने नियमों से कतई समझौता नहीं करती हैं। खबर लहरिया अपनी आत्मा को व्यावसायिकरण में नहीं झोंक सकती हैं, जैसा की आज कई मीडिया समूह लाभ के लिए समझौते पर समझौते कर रही हैं।

आश्चर्यजनक उत्थान व विस्तार योजना

खबरलहरिया की खबरों को देखे तो पता चलता है कि राष्ट्रीयऔर अंतरराष्ट्रीय, संपादक के नाम पत्र, राज्य तथा जिलास्तरीय समाचार के साथ-साथ फिल्म समीक्षा भी शामिल किया जाता है।

खबर लहरिया की विषय सामग्री आठ पेज के इस अखबार में भिन्न-भिन्न स्तंभों का समावेष होता था जिसमें

1. ताजा खबर
2. देश विदेश
3. महिला मुद्दा
4. मनोरंजन की खबरें
5. हमारा संदेश- संपादकीय

इसके अलावा पाठकों के लिए विशेषांक भी प्रकाशित करता है, जो ग्रामीण मुद्दों, महिला जागरूकता, देश व प्रदेश के मुद्दों के साथ विकास सबंधित होते है। इसके अलावा खबर लहरिया कुछ विशेष फीचर भी प्रकाशित करता है। जिसमे मुख्य रूप से निम्न विषयों को शामिल किया जाता है।

1. पंचायती राज
2. साक्षरता
3. महिला जागरूकता व सशक्तिकरण
4. मनरेगा
5. सरकारी योजनायें

खबर लहरिया की अवर्णनीय उपलब्धियां

इस अखबार ने यह तो सिद्ध कर दिया है,कि महिलाएं न सिर्फ गृहलक्ष्मी होती है, बल्कि अदम्य साहसी व जुझारू भी होती है। यही कारण है कि इस अखबार से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं ने दुनिया के पटल में यह साबित कर दिया है, कि वे किसी मामले में पीछे नहीं है। उनकी साहस, लगन और जागरूकता ने उन्हे सिर्फ राष्ट्रीय नहीं अतंराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलायी। खबर लहरिया को सन् 2004-05 के लिए ‘चमेली देवी जैन’ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

खबर लहरिया का वर्तमानपरिदृश्य -खबर लहरिया अखबार का प्रिंट संस्करण 2015 में बंद कर दिया गया , बुंदेली, अवधी व भोजपुरी भाषा में प्रकाशित होनेवाले अखबार अब डिजिटल प्लेटफार्म के जरिए देश ही नहीं विदेश तक पहचान बनाई है। अब समाचारइनके डिजीटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। अब खबर लहरिया का डिजीटली करण हो गया है। निरंतरसंस्था द्वारा चंबल मीडिया की स्थापना 2015 में की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य स्थानीयभाषा में डिजीटल विषयवस्तु प्रदान करना हैं। जिसमें एनीमेटेड फिल्म, डाक्यूमेंट्री, पॉडकास्ट और सार्ट वीडियो कंटेट स्थानीय लोगों के लिए उपलब्ध कराती है। वर्तमान मेंखबर लहरिया विभिन्न डिजीट प्लेटॅफार्म में उपस्थित है, लिंक्डइन में 2224, फेसबुकपर 2.1 लाख, इंस्टाग्राम पर 30 लाख और एक्स पर 25000 फॉलोअर है।महिला सशक्तीकरण के नए आयाम स्थापित कर सार्थक परिणाम दिखाया।दलित महिलाओं के संघर्ष परखबर लहरिया पर बनी डाक्यूमेंट्री ‘‘राइटिंग विथ फायर’’ को 2021-22 के लिए भारत की ओर से आस्कर के लिए नामांकित किया गया था। वर्तमान समय में खबर लहरिया समाचार पत्र ग्रामीण महिलाओं को पत्रकारिता के गुर सिखाने की एक पाठशाला में तब्दील होता जा रहा है। हमारी खबर, हमारी भाषा को ध्येय में केन्द्रित कर खबर लहरिया ने पत्रकारिता के नए मापदंड स्थापित किए है। क्षेत्रीय पत्रकारिता के मानक विषयों के साथ ही खबर लहरिया यू-ट्यूब, सोशल मीडिया के साथ ही एफ.बी लाइव के माध्यम से आधुनिक पत्रकारिता को भी प्रतिबिंबित कर रहा है। जहां ग्रामीण महिलाओं विशेषकर दलित महिलाओं को रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी एवं संपादन कला का प्रशिक्षण दिया जाता है। खबर लहरिया पर बनी डाक्यूमेंट्री ‘राइटिंग विथ फायर’ को 2021-22 के लिए भारत की ओर से आस्कर के लिए नामांकित किया गया है।

अप्पन समाचार का वैयक्तिक अध्ययन

अप्पन समाचार के प्रयास से सीमित लोग ही अवगत है। जो महज एक चैनल नहीं हैं, वरन जागरूकता की जीती जागती मिसाल है, जो ग्रामीण लड़कियों की आत्मनिर्भरता की कहानी खुद बयां कर रही हैं। अप्पन समाचार को ख्याति देने में महिलाओं की अवर्णनीय दृढ़ इच्छा शक्ति को श्रेयजाता है, तो वहीं अखबार अपनी बोली में पढ़ने से पाठकों को सहज लगती हैं। अप्पन समाचार की शुरुआत 6 दिसम्बर 2007 मुजफ्फरपुर के पारु प्रखंड से किया,गांव की लड़कियों द्वारा ही गांव की समस्याओं व विकास को समर्पित खबरें बनाई जाती है। बुलेटिन 45 मिनट का होता है जिसका प्रसारण गांव के हाट बाजार और टोले कस्बों में प्रोजेक्टर व पोर्टेबल टेलिविजन के जरिए प्रसारण किया जाता है। इसके संचालन में सबसे महत्वपूर्ण सहयोग संतोष सारंग का रहा।

अप्पन समाचार की विषयवस्तु

अप्पन समाचार विकासात्मक मुद्दों, किसानों की समस्या, पर्यावरण मुद्दों, मानवाधिकार के मुद्दों , कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का खुलासा, महिला सशक्तिकरण, बाल विवाह , लिंग भेद, भ्रूण हत्या बाल मजदूरी, लोकस्वास्थ्य व पोषण, साफ-सफाई संबंधी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है।

अप्पन समाचार में सहभागिता

महिला पत्रकारों के प्रशिक्षण की व्यवस्था मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। जिसमें महिला पत्रकारों को समय-समय पर 'मिशन आई इंटरनेशनल सर्विस' संस्था के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है। ग्रामीण रिपोर्टिंग के विभिन्न पहलुओं जैसे विकासात्मक व समस्यामूलक के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। इस प्रषिक्षण का ही सकारात्मक प्रभाव है, संदर्भित गांव में सूचनाओं के द्वारा विकास की परिभाषा गढ़ी जा रही है। ग्रामीण विकास से संबंधित नवाचार के प्रयास से ही महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिला है। विकास की राह से कोसों दूर इन गांवों में ग्रामीण लड़कियॉ पत्रकार की भूमिका का निर्वहन कर रही है, जिसके कारण अन्य ग्रामीण जन उत्साहित और अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करती है। निचले व हाषिए तबके में रह रहे लोगों के लिए लड़कियों द्वारा रिपोर्टिंग साहसिक व प्रोत्साहित करने वाली है। इस सामुदायिक मीडिया में रिपोर्टर, कैमरामैन, एंकर, वीडियो एडिटर, स्क्रिप्ट राइटर सहित अन्य सदस्य अनूसूचित जाति, जनजाति, व मूसहर समुदाय से संबंध रखता है। इस इलाके का प्रमुख भोजन चूहा है, जिसे पकड़कर ये अपना पेट भरते है। इसके अतिरिक्त कहार, मल्लाह, धोबी, कोरिया, बढ़ई अन्य समुदाय के लोग भी सामुदायिक मीडिया में अहम भूमिका निभाते है। गांव की खबरों का संकलन करने के लिए लड़कियॉ साईकल से रिपोर्टिंग करती है, कैमरा, ट्राइपोड, माइक का बेहतर प्रयोग करते है। महिला समाख्या के सहयोग से स्कूलों की छात्राओं को भी नागरिकता का प्रषिक्षण दिया जाता है, जिससे वहां की छात्रओं में मीडिया साक्षरता के बारे में जानकारी मिलती है।

रिपोर्टिंग शैली व जनमत का निर्माण

गांव में प्रोजेक्टर के जरिए नवाचार के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है। गांव की लड़कियों द्वारा पत्रकारिता के द्वारा गांव की आवाज को जन-जन तक पहुंचाकर विकास के नए आयाम स्थापित किया जा रहा है। गांव की समस्याओं को संवाददाता के तौर पर ग्रामीण लड़कियां बड़ी बेबाकी के साथ अपने कैमरे में कैद करती है। समस्याओं से नाता रखने वाली जनता भी बड़े ही सहज ढंग से महिलाएं रिपोर्टरों को अपनी समस्याओं व जिंदगी के जद्दोजहद के बारे में बताती है। इसका कारण वहां के लोगों से रिपोर्टरों का सहज होना व उनकी समस्याओं से अवगत होना है, साथ ही सामुदायिक मीडिया का उनकी बोली के साथ सामंजस्य भी संचार को प्रभावी बनाता है। मुजफ्फरपुर की जनता अपनी समस्याओं में सरपंच से लेकर अन्य जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र में ना आने को बताने से भी नहीं हिचकती, ये भी कहती है, गांव के सरपंच व मुखिया बने तो है, लेकिन ये शहरों में रहना पसंद करते है। गांव की समस्याओं से उनका कोई वास्ता नहीं होता। सामुदायिक मीडिया के दर्शक रिपोर्टरों का उत्साह वर्धन भी करते है, अपनी बोली में कहते है, ''हमें बहुत खुशी होती है, ऐसे प्रयास को देखकर! ग्रामीण लड़कियों को रिपोर्टर के तौर पर देखकर उनकी मॉ व पिता व परिवार भी गर्व व सम्मानित महसूस करता है।

लोकतंत्र की नींव का आधार अप्पन समाचार

देश में हुए लोकसभा व विधानसभामेंअप्पन समाचार टीम ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न गांवों मेंवोट की चोट नाम से कई कार्यक्रम आयोजित किए। अप्पन समाचार विशेष रूप से ग्रामीणोंद्वारा नागरिकों को मजबूत करने और शिक्षित करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं और मानवाधिकारोंपर कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने वाले कई कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।

अप्पन समाचार पत्र का प्रकाशन

अप्पन समाचार के प्रसारण के बाद अप्पन समाचार अखबार का भी प्रकाशन किया जाता है। जिसका उद्देश्य लोगों में जागरुकता लाना और समुदाय को विकास की ओर अग्रसर करना है। समाचार पत्र में जल प्रबंधन, विकलांगों की समस्याओं पर आधारित खबरों का प्रकाशन किया जाता है। यहां के अधिकतर गांवों में बिजली अभी तक नहीं पहुंची।

अप्पन समाचार का प्रसारण के साथ ही वहां महिलाओं में आत्मनिर्भरता का ब्यापक असर हुआ है। जो महिलाएं घर की चौखट से नहीं निकलती थी। आज उनके हाथ माइक, कैमरा है जो वहां जागरुकता का प्रसार का मापक भी है। अप्पन समाचार पर "अल-जज़ीरा टीवी चैनल" ने 24 मिनट की डाक्यूमेंट्री भी बनाई है। इंडिया है मेरी जान में अप्पन समाचार की सफलता को दिखाया गया है। इसके साथ ही नेटवर्क - 18 द्वारा 2008 में सिटीजन जर्नलिज्म का अवार्ड प्रदान किया गया। अप्पन समाचार की रिपोर्टर रिंकी कुमारी को एस.पी.सिंह पत्रकारिता का पुरस्कार भी 2013 में दिया गया। अप्पन समाचार पूर्ण रुप से विकासात्मक पत्रकारिता को समर्पित है। आज समाचार पत्रों और चौबीस घंटे पल-पल की खबरें देने वाले न्यू चैनलों की दौड़ में सिर्फ महानगरीय संस्कृति और हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल से जुड़े समाचारों की ही संख्या ज्यादा दिखाई देती है। जबकि भारत के विषय में कहते हैं, कि असली भारत गांवों में ही बसता है, फिर भी अखबारों की सुर्खियों में वह तभी नजर आता है जब कोई बड़ा अपराध घटित हुआ हो। मीडिया के इस तरह के वातावरण के बीच जब बुंदेली भाषा में दलित महिलाओं द्वारा प्रकाशित खबर लहरिया समाचार

पत्र जो कि गांव की पत्रकारिता को जीवंत रखे हुए है, ग्रामीण भारत या यूं कहे असल भारत की पत्रकारिता का प्रतिनिधित्व करता प्रतीत होता है। इसके साथ ही यह नारी सशक्तिकरण की एक उत्कृष्ठ मिसाल है।

महिलापत्रकारों की सुरक्षा का विषय-

मीडियाअप्पन समाचारएक मीडिया आंदोलन है जो वैकल्पिक मीडिया या नागरिक पत्रकारिता का मजबूत उपकरण है। महिलापत्रकार की टीम को कई अहम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी संदर्भ में कभी.कभीएमहिला पत्रकारों को अमर्यादित टिप्पणी, अश्लील शब्दों का सामना करना पड़ता है। जब भ्रष्टाचारपर कोई रिपोर्ट टीम द्वारा कवर की जाती है तो स्थानीय प्रशासन द्वारा दबाव भी डालाजाता है। एक दिनए अप्पन समाचार की एक टीम सरैया ब्लॉक में सार्वजनिक वितरण प्रणालीमें भ्रष्टाचार पर न्यूज स्टोरी इकट्ठा करने गई। बीडीओ खंड विकास अधिकारी ने टीम कोकहानी को कवर किए बिना वापस जाने के लिए मजबूर किया और इन लड़कियों के सामने कुछ कठोरशब्दों का इस्तेमाल किया । इस पंरिप्रेक्ष्य में सामुदायिक मीडिया की महिला पत्रकारोंको सुरक्षा या भयमुक्त वातावरण प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार की है। इसी प्रकारकी घटना सितंबर 2015 में खबर लहरिया के महिला पत्रकारों से भी हुआ थापुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार किया जिसने पिछलेनौ महीनों से खबर लहरिया के टीम के पांच सदस्यों को फोन पर परेशान किया था।

निष्कर्ष

आज समाचार पत्रों और चौबीस घंटे पल-पल की खबरें देने वाले न्यू चैनलों की दौड़ में सिर्फ महानगरीय संस्कृति और हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल से जुड़े समाचारों की ही संख्या ज्यादा दिखाई देती है । जबकि भारत के विषय में कहते हैं, कि असली भारत गांवों में ही बसता है, फिर भी अखबारों की सुर्खियों में वह तभी नजर आता है जब कोई बड़ा अपराध घटित हुआ हो। या फिर कोई बड़ी हस्ती गांव में पहुंचे। मीडिया के इस तरह के वातावरण के बीच जब बुंदेली भाषा में दलित महिलाओं द्वारा प्रकाशित खबर लहरिया समाचार पत्र जो कि गांव की पत्रकारिता को जीवंत रखे हुए है, ग्रामीण भारत या यूं कहे असल भारत की पत्रकारिता का प्रतिनिधित्व करता प्रतीत होता है। इसके साथ ही यह नारी सशक्तिकरण की एक उत्कृष्ठ मिसाल है।

एक तो पत्रकारिता का क्षेत्र महिलाओं के लिए पहले से ही चुनौतिपूर्ण है, उस पर से गांव की महिलाओं द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरना निश्चय ही काबिल-ए-तारीफ है। शहरके माहौल में जहां महिलाओं को अपनी स्वेच्छानुसार कहीं भी आने जाने की अनुमति होती है, उन्हें उन्मुक्त माहौल मिलता है वहीं गांव में पर्दाप्रथा जैसी रूढ़ियों और परम्पराओं के बीच काम करना भी चुनौतिपूर्ण है। जहां शहरी महिलाओं के पास संचार के विविध साधन मौजूद हैं वहीं ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के पास संचार के पर्याप्त साधन न होनें के वाबजूद खबरों को समय से प्रकाशित करने का दवाब होता है। शहरीय महिलाएं पत्रकार एक षिक्षित और सभ्य समाज के लिए काम करती हैं जबकि ग्रामीण महिला पत्रकार अषिक्षित, पिछड़े और विविध सुविधाओं के अभाव में रहने वाले समुदाय के लिए काम करती हैं। इस तरह ग्रामीण महिलाओं का पत्रकारिता करना समाज में बदलाव की मिसाल है।

1. भारत सरकार द्वारा सामुदायिकमीडियाके विस्तार के लिए विचार विमर्श कियाजाना आवश्य है।
2. सामुदायिक मीडिया लोकतांत्रिकमाध्यम का हस्ताक्षर बन चुका है, सरकार द्वारा उचित संसाधन प्रदान किया जाना चाहिए।
3. महिला पत्रकारों की सुरक्षा व सम्मान के लिए आवश्यक विधि निर्माणव आचार संहिता बनाई जानी चाहिए।
4. सामुदायिक मीडिया को विचारों की क्रांति के माध्यम से अब भी पिछड़े हुए ग्रामीण भारत में फैली रूढ़ियों और अंधविश्वासों को दूर करने में अपना योगदान देना चाहिए।
5. ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक मीडिया की विषयवस्तु क्षेत्रीय भाषाएँ एवं बोलियों पर होनी चाहिए।
6. विज्ञापन की विषयवस्तु ग्रामीण विकास के लिए सहायक हो साथ ही साथ सामाजिक, कानूनी जानकारी बढ़ाने वाली, और जागरूकता लाने वाली होनी चाहिए।
7. सामुदायिकमीडिया के उत्थान के लिए डिजीटल संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जिससे उनके प्रसारण, और प्रकाशन उच्च गुणवत्ता की होगी ।

सन्दर्भ सूची

Narula, U., & Hanson, J. (1990). New communication technologies in developing countries. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Narula, U. (1994). Development communication. New Delhi: Haranand Publication.

Quebral, N. C. (1975). Development communication: Where does it stand today. Media Asia.

Rogers, E. M. (Ed.). (1976). Communication and development: Critical perspectives. California: Sage Publications.

Rogers, E. M. (1983). Diffusion of innovations. New York: Free Press.

त्यागी, गु, अग्रवाल, नं&कुमार वि. (1997). उदीयमानभारतमेंशिक्षा. आगरा: पब्लिकेशन, पृष्ठ 98-99.

अमृतांज, इं. (2013,). गांवकाअप्पनटेलिविजन. कुरुक्षेत्र, पृष्ठ 12-15..

UNESCO. (n.d.). Community radio handbook. Retrieved from https://www.unesco.org/webworld/publications/community_radio_handbook.pdf

United Nations Democracy Fund. (n.d.). How UNDEF-funded award-winning local newspaper empowers rural women in India. Retrieved from https://www.un.org/democracyfund/news/how-undef-funded-award-winning-local-newspaper-empowers-rural-women-india

Chitrakoot documentary writing with fire on the struggle of Dalit women has been nominated for the Oscar award. Retrieved from https://www.jagran.com/uttar-pradesh/kanpur-city-khabar-lahariya-newspaper-chitrakoot-documentary-writing-with-fire-on-the-struggle-of-dalit-women-has-been-nominated-for-the-oscar-award-jagran-special-22453295.html

All-women channel a hit in Bihar village. Retrieved from http://www.dnaindia.com/india/report-all-women-channel-a-hit-in-bihar-village-1142791